दैनिक इबादत सम्पादकीय

किसान, उपभोक्ता और देश के हित में संतुलन की जरूरत

किसान एक सम्मानजनक पेशा है, इसे अन्नदाता का दर्जा दिया जाता है। उसकी आय बढ़े और खेती फायदे का व्यवसाय बन जाये, यह तो देश का हर नागरिक चाहता है। किसानों का जीवन बेहतर हो, इसके लिए पक्ष या विपक्ष सभी सरकारें काम कर रही हैं। भारतीय राजनीति की एक बड़ी सच्चाई यह है कि किसानों को नाराज करके कोई पार्टी सरकार नहीं बना सकती क्योंकि इस देश में आधी आबादी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। आंदोलन चलाने वाले अक्सर कहते हैं कि सरकार किसानों की दुश्मन है, वो किसानों का नुकसान कर रही है। जब उन पर आरोप लगाया जाता है कि ये आंदोलन सिर्फ दो राज्यों के किसानों का है तो उनका कहना होता है कि उनका आंदोलन पूरे देश के किसानों का है। अगर उनका आंदोलन पूरे देश के किसानों का है और जनता भी किसानों के साथ है तो किसानों को आंदोलन करने की जरूरत ही क्या है। वो उस पार्टी को सत्ता में ला सकते हैं, जो उनकी मांगों को पूरा करे। जो सरकार तीन महीने में बदलने वाली है, उसके खिलाफ आंदोलन करने की जरूरत क्या है। किसान संगठनों द्वारा जो मांगे सरकार के सामने रखी गई है, उन्हें मानना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी, किसान-मजदूरों के सभी कर्जों की माफी, बुजुर्ग किसानों के लिए दस हजार प्रतिमाह पेंशन, मनरेगा में 200 दिनों तक 700 रुपये की दिहाड़ी, मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक तथा विश्व व्यापार संघ के समझौतों को रद्द करना आदि ऐसी मांगे हैं, जिन्हें सरकार के लिए पूरा करना बहुत मुश्किल है। सरकार किसानों की मांगों को आंशिक रूप से मानने को तैयार है लेकिन किसान सभी मांगों के मानने पर अड़े हुए हैं। देश के सभी विपक्षी दल किसान आंदोलन के पक्ष में खड़े हुए हैं और किसानों की मांगों को मानने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। वास्तव में विपक्षी दल यह जानते हुए भी कि इन मांगो को पूरा करना संभव नहीं है, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि सभी फसलों पर अगर एमएसपी दी जाती है तो सरकार को लगभग तीस लाख करोड़ रुपए हर साल खर्च करने होंगे। अगर सभी किसानों और मजदूरों का पूरा कर्ज माफ करना है तो सरकार को इसके लिए दस से पंद्रह लाख करोड़ रुपए चाहिए। अगर बाकी मांगों को छोड़ दिया जाए तो इन दो मांगों को पूरा करने में ही सरकार का पूरा बजट खत्म हो जाएगा। क्या किसानों के पास इसका जवाब है कि जब पूरा बजट इन दो मांगों को पूरा करने में लग जाएगा तो सरकार देश कैसे चलाएगी ? दूसरी बात यह है कि अगर सरकार सभी फसलें खरीद लेती है तो उनको रखेगी कहां, क्योंकि सरकार के पास इतनी भंडारण क्षमता ही नहीं है। अगर सरकार सभी कर्ज माफ कर देती है तो वही किसान पांच साल बाद फिर कर्जमाफी की मांग करने लगेंगे। क्या कर्जमाफी से समस्या हल हो जाएगी ? अगर ऐसा होता तो कई बार सरकारें कर्जमाफी कर चुकी हैं लेकिन किसानों के कर्ज खत्म नहीं होते। किसानों को सरकार की क्षमता को देखते हुए अपनी मांग रखनी चाहिए।

सनातन और भारत विरोधी द्रमुक

संविधान के खिलाफ जाकर कोई भी सरकार अस्तित्व में नहीं रह सकती। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया बताते हुए यह जो कहा कि उसका विरोध नहीं, बल्कि पूरी तरह खात्मा कर दिया जाना चाहिए,उस पर भाजपा के साथ हिंदू संगठनों की तीखी प्रतिक्रिया होनी ही थी।

– डॉ. ओ.पी. त्रिपाठी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में द्रविड़ मुनेत्र कषगम यानी डीएमके पर बड़ा निशाना साधा है और इसरो के वैज्ञानिकों का अपमान करने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डीएमके ऐसी पार्टी है जो कोई काम नहीं करती लेकिन झूठा श्रेय लेने के लिए आगे रहती है। उन्होंने कहा कि इस पार्टी ने हमारी योजनाओं पर अपना स्टीकर लगाकर जनता के बीच अपना झूठा प्रचार करने का काम किया है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि डीएमके ने तमिलनाडु में इसरो लॉन्च पैड का श्रेय लेने के लिए चीन के स्टिकर चिपकाकर भारत के वैज्ञानिकों का अपमान किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी द्रमुक न केवल सनातन-विरोधी है, बल्कि भारत-विरोधी भी है। संविधान धार्मिक आस्था और पूजा-पद्धति की अनुमति तो देता है, लेकिन भारत-विरोध का कोई प्रावधान नहीं है। भारत-विरोध के मायने हैं कि आप देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और राष्ट्र के तौर पर अपमान कर रहे हैं। कोई साजिश रच रहे हैं। उन्हें चुनौती दे रहे हैं। यह सरासर देशद्रोह है और नई न्याय संहिता में इस अपराध की सजा स्पष्ट हो जाएगी। यह संहिता 1 मार्च से देश भर में लागू हो रही है। द्रमुक सरकार ने एक विज्ञापन छपवाया है, जो इसरो लॉन्च पैड से संबंधित था। विज्ञापन में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री स्टालिन के चित्र छपे थे। उनके बीच एक रॉकेट पर चीन का लाल झंडा छापा गया था। विज्ञापन सरकारी और देश के प्रधानमंत्री के चेहरे के साथ छापा गया था। तमिलनाडु अखंड और आजाद भारत का एक राज्य है। द्रमुक भी भारतीय निर्वाचन आयोग में पंजीकृत एक राजनीतिक पार्टी है। उसे उस जनता का जनादेश प्राप्त है, जो भारत के तमिलनाडु में रहती है। उसी जनता के टैक्स से सरकारें चलती हैं और सरकारी विज्ञापन छपवाए जा सकते हैं। तो सवाल है कि इसरो से जुड़े विज्ञापन में चीन का झंडा क्यों छापा गया? यह भारत देश, इसरो के वैज्ञानिकों, इसरो की अंतरिक्ष में उपलब्धियों का सार्वजनिक अपमान है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बेहद आक्रामक अंदाज में, तमिलनाडु में ही, यह मुद्दा उठाया और कहा कि द्रमुक सरकार ने तमाम हदें पार कर दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डीएमके वो पार्टी है, जिसके नेता अंतरिक्ष में भारत की प्रगति को सहन करने के लिए तैयार नहीं हैं। वे अंतरिक्ष में भारत की प्रगति देखना नहीं चाहते। डीएमके का वर्तमान चाल, चरित्र और चेहरा जानने के लिए, इतिहास के पन्ने पलटना जरूरी हो जाता है। अजादी से पहले जस्टिस पार्टी नाम की एक पार्टी थी। आजादी मिलने से पहले यह सत्ता में थी। जस्टिस पार्टी में धनी परिवारों के लोग शामिल थे लेकिन उनका एक ही एजेंडा था, यानी ब्राह्मण विरोधी एजेंडा और ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें जल्द ही ईवीआर कहा जाता था, जस्टिस पार्टी का हिस्सा थे। दरअसल, पहले वह कांग्रेस पार्टी का हिस्सा थे। वह कांग्रेस नेता थे. लेकिन वे 1925 में यह कहकर कांग्रेस से बाहर आ गये कि कांग्रेस ने केवल ब्राह्मणवादी हितों की पूर्ति की है। उन्होंने बाहर आकर एक आन्दोलन की स्थापना की जिसे आत्मसम्मान आन्दोलन कहा गया। इस तरह उन्होंने अपने राजनीतिक या सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की। तब, वह जस्टिस पार्टी का हिस्सा थे, भले ही वह सरकार में नहीं थे। 1939 में वे जस्टिस पार्टी के प्रमुख बने। 1944 में, उन्होंने जिसे हम आज द्रविड़ कड़गम कहते हैं, उसकी स्थापना की। द्रविड़ से उनका तात्पर्य सभी दक्षिण भारतीयों से है – कन्नडिगा, आंध्र लोग, मलयाली और तमिल। कजगम का अर्थ है एक संघ। इसलिए, उन्होंने संगठन की स्थापना की और उन्होंने 1944 में इसे एक सामाजिक आंदोलन कहा। उनके दिवंगत प्रमुख करुणानिधि और तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री अन्नादुराई, वे सभी द्रविड़ कड़गम का हिस्सा थे। वे सभी सदस्य थे और बाद में उन्होंने द्रविड़ कड़गम या डीके में कुछ वरिष्ठ पदों पर भी कार्य किया। उन्हें ईवीआर द्वारा प्रशिक्षित किया गया था।

ईवीआर पूर्णतयाः पृथकतावादी एवं अलगाववादी थे। जब भारत को आजादी मिली तो उन्होंने इसे शोक दिवस के रूप में घोषित किया और उन्होंने भारतीय ध्वज को जला दिया। यह उनकी पृष्ठभूमि है. वह पूर्णतः भारत विरोधी था। उनकी दूसरी विशेषता जिससे अब हम सब परिचित हैं, वह यह है कि वे हिंदू विरोधी हैं। वे उत्तर भारतीयों के भी विरोधी थे. क्योंकि उन्होंने कहा, उत्तर भारतीय आर्य जाति से आते हैं, इसलिए हम अलग हैं. वे हिन्दी के भी विरोधी थे। वास्तव में, वर्तमान समय में, डीएमके हिंदी के खिलाफ है क्योंकि यह सब ईवीआर से शुरू हुआ था। इसी से डीएमके और उनके नेताओं का चरित्र समझा जा सकता है। बेशक मुख्यमंत्री स्टालिन और द्रमुक की वैचारिकता वामपंथी हो सकती है, वे उसी के आधार पर वोट भी मांग सकते हैं, लेकिन सरकारी काम संविधान से ही संचालित होते हैं और संविधान किसी भी स्तर पर चीन के झंडे के सरकारी इस्तेमाल की इजाजत नहीं देता। यह संविधान का ही प्रावधान है कि विदेश, रक्षा, वित्त और संचार से जुड़े विशेषाधिकार भारत सरकार के पास ही होंगे। उस तरह द्रमुक सरकार ने संविधान का भी उल्लंघन किया है। संविधान के खिलाफ जाकर कोई भी सरकार अस्तित्व में नहीं रह सकती। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया बताते हुए यह जो कहा कि उसका विरोध नहीं, बल्कि पूरी तरह खात्मा कर दिया जाना चाहिए, उस पर भाजपा के साथ हिंदू संगठनों की तीखी प्रतिक्रिया होनी ही थी। इसके बाद भी वह अपने बयान पर कायम हैं। उदयनिधि के बाद उन्हीं की पार्टी यानी द्रमुक के एक अन्य नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री ए. राजा ने सनातन धर्म को एड्स और कुष्ठ रोग जैसा करार दिया। उन्होंने यह भी कहा कि सनातन धर्म केवल भारत के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। मुख्यमंत्री के मंत्री-पुत्र, द्रमुक के मंत्रियों-सांसदों ने सनातन धर्म को गालियां दीं, उसके समूल नाश की हुंकारें भरीं और उसके लिए भद्दे उपमान भी इस्तेमाल किए गए, तो भी उन्हें सहन कर लिया गया। अलबत्ता हर स्तर पर थू-थू कर द्रमुक नेताओं की खूब आलोचनाएं जरूर

की गईं। यदि तमिलनाडु वाकई सनातन-विरोधी है, तो वहां भगवान श्रीराम के प्राचीन और पूजनीय, विख्यात मंदिर क्यों हैं? उन मंदिरों में 'रामायण' के पाठ और पूजा लगातार क्यों होती रहती है? तमिल लोग भगवान शिव की आराधना के लिए काशी क्यों आते रहते हैं? किसी द्रमुक नेता ने बयान दिया कि चीन भारत का दुश्मन देश घोषित नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी चीन के प्रधानमंत्री को भारत आने का आमंत्रण दिया था। यह बयान हास्यास्पद है। यदि चीन दुश्मन देश नहीं है, तो क्या इसरो के प्रोजेक्ट पर उसका लाल झंडा लगने दें? दरअसल चीन को लेकर हमारे देश में कई तरह की सोच हैं। जब शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बनाए गए, तो हमारे प्रधानमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं तक नहीं भेजी थीं। उन्हें पता था कि किस तरह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया और किस तरह संविधान में संशोधन कर शी की ताजपोशी की गई। लेकिन केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन ने शी जिनपिंग को न केवल बधाई भेजी, बल्कि सोशल मीडिया पर भी एक बयान लिखा। वामपंथी दल और कांग्रेस की राजनीतिक सोच भी चीन के प्रति ऐसी रही है। बहरहाल अब मुद्दा चीन के लाल झंडे का है। केंद्र सरकार को डीएमके के भारत विरोधी कृत्य पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

(चिकित्सक एवं लेखक)

कांग्रेस और 'आप' – इस रिश्ते को क्या नाम दें ?

– राकेश सैन

देश में लोकसभा चुनावों की तैयारी को लेकर 'इंडी' गठजोड़ के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबन्धन हो चुका है। देश के अन्य हिस्सों जैसे दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और गोवा में दोनं दल मिल कर चुनाव लड़ेंगे जबकि पंजाब में एक-दूसरे के खिलाफ। इस अजीबो-गरीब गठजोड़ को देख कर हास्य अभिनेता कादर खान की उस फिल्म में कमेडी का स्मरण हो आया जिसमें प्रेमी की माँ और प्रेमिका का बाप भी एक दूसरे के चक्कर में पड़ कर शादी कर बैठते हैं। अब इस रिश्ते से प्रेमी अपनी प्रेमिका भाई हो गया और उसका अपना पिता उसका ससुर भी बन गया। प्रेमिका भी अपनी माँ को सासू कहे या मम्मी, उसे समझ नहीं आरहा था। परिवार में इन दोनों जोडियों के होने वाले बच्चों के सामने समस्या पैदा हो गई कि कौन किसको किस रिश्ते से पुकारे? इसी तर्ज पर उक्त राजनीतिक गठजोड़ को देख कर यह बात सत्य साबित हो गई है कि देश में नई तरह की राजनीति का वायदा करके आए अरविंद केजरीवाल ने वास्तव में नया कर दिखाया है। हालांकि इस तरह के बेमेल गठजोड़ अतीत में भी कुछ स्थानों पर होते रहे हैं परन्तु राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार यह बेर और केर का साथ चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ चले अन्ना हजारे आन्दोलन से ऊपजी आम आदमी पार्टी अब उसी के पक्ष में भुगतती दिखाई दे रही है। रोचक है कि चुनावों में प्रचार के दौरान पंजाब में कांग्रेस जहां भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार को कोसेगी और अरविंद केजरीवाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को उछालेगी वहीं दोनों दल दूसरे राज्यों में एक-दूसरे की पीठ खुजाएंगे। केंद्र में अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो यहां के सांसद चाहे वह कांग्रेस के हों या आप के एकसाथ सरकार में बैठेंगे और भाजपा सरकार बनी रहती है तो विपक्ष में गलबहियां डाले दिखेंगे, यानि हमीं से मुहब्बत हमीं से लड़ाई-अरे मार डाला दुहाई दुहाई। पंजाब में इस रिश्ते को फिक्स मैच या नूरा कुश्ती का नाम दिया जाने लगा है। कल 1 मार्च को पंजाब विधानसभा में शुरू हुए बजट सत्र के दौरान कांग्रेस ने पंजाब में शंभू सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन में मारे गए युवक को लेकर आप की सरकार को घेरा तो सत्तापक्ष ने कांग्रेस पर पलटवार किया। भाजपा ने इसे फिक्स मैच बता कर उपहास किया है और कहा है कि किसानों के खिलाफ दोनों अंदर से मिले हुए हैं। इस बेमेल खिचड़ी गठबन्धन को लेकर एक कहानी सुनाई जाने लगी है कि जैसे बाढ़ के समय जान बचाने के लिए अपनी दुश्मनी भुला कर हर तरह के जीव-जन्तु ऊंचाई वाली जगह पर एकत्रित हो जाते हैं परन्तु पानी उतरते ही उनकी मित्रता उसी बाढ़ के जल में प्रवाहित हो जाती है और फिर एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। लगता है कि देश में जिस तरह का राजनीतिक वातावरण बना हुआ है और भाजपा की विजय की अभी से भविष्यवाणी करने वालों की संख्या बढ़ रही है, शायद उसी के भय से आम आदमी पार्टी व कांग्रेस ने मिल कर भानूमती का कुनबा जुटाया है। देश के इतिहास में यह दूसरा चुनाव है जब भ्रष्टाचार को लेकर सरकार हावी है और विपक्षी दल रक्षात्मक मुद्रा में हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर तो काफी समय से इस तरह के केस चले आ रहे हैं परन्तु कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल व आप के कई बड़े नेताओं पर भी दिल्ली आबकारी घोटाले के छींटे पड़े हैं जो उन्हें बेचैन किए हुए हैं। आम आदमी पार्टी के कई नेता तो जेलों में कैद हैं और यहां तक कि उन्हें इन केसों में सर्वोच्च न्यायालय से जमानत तक नहीं मिल पा रही। ये वही केजरीवाल हैं जो सोनिया गांधी को मंच पर खड़े हो कर भ्रष्टाचारी बताते थे और दिल्ली की पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री दिवंगत शीला दीक्षित के कथित भ्रष्टाचार के सबूतों का पुलिंदा होने का दावा करते थे। दिल्ली विधानसभा चुनावों में उन्होंने दावा किया था कि सत्ता में आते ही इन सबको जेल की हवा खिलाई जाएगी। पर आज वही केजरीवाल कांग्रेस को परममित्र बताते नहीं अघाते। पंजाब में भी भगवंत मान की सरकार ने आते ही कथित भ्रष्टाचार उन्मूलन अभियान चला कर एक दर्जन के करीब पूर्व कांग्रेसी मंत्रियों व विधायकों के यहां सतर्कता विभाग की छापामारी करवाई और कईयों को जेल में भेजा परन्तु वर्तमान में न जाने किस कारण से उनका यह अभियान केवल पटवारियों-क्लर्कों तक सीमित हो कर रह गया। बड़े नेताओं के केस लम्बी तारीख पर डाल दिए गए हैं। पंजाब के बड़े कांग्रेसियों के भ्रष्टाचार पर न केवल भगवंत मान बल्कि उनके मंत्रियों व नेताओं तक ने बोलना कम कर दिया। जैसे कि बताया जा चुका है कि विरोधी दलों से गठजोड़ होना कोई नई बात नहीं है परंतु किसी दो दलों में एक स्थान पर तो गठबंधन हो और दूसरी जगह पर एक-दूसरे से भिड़ते दिखें तो अतीत में ऐसा राजनीतिक उदाहरण दुर्लभ ही है। कहने को दोनों दल दावा करते हैं कि वे देश में लोकतंत्र व संविधान बचाने के लिए एक दूसरे के साथ आए हैं अगर ऐसा है तो इतने पवित्र यज्ञ में पंजाब को क्यों आहूति डालने से वंचित कर दिया ? देशवासी अब आम आदमी पार्टी व कांग्रेस दोनं से पूछ रहे हैं कि इस रिश्ते को क्या नाम दें ?

(32, खण्डाला फार्म कालोनी, ग्राम एवं डाकखाना लिदड़ा, जालन्धर)

यूपी में बसपा का सूपड़ा साफ़ होने का खतरा

– बाल मुकुन्द ओझा

बसपा सुप्रीमो मायावती की सियासत तीन लोकों से न्यारी है। मायावती के बारे में तरह तरह की अटकलबाजियों का बाजार गर्म है। पिछले लोकसभा चुनाव में दस सीटें जीतने वाली बसपा के सांसद एक एक कर पार्टी छोड़ते जा रहे है। ये सांसद चाहते है बसपा किसी एक गठबंधन का हिस्सा बने मगर मायावती ने अकेले चलने का फैसला किया है जिससे पार्टी में बेचैनी व्याप्त है। यूपी में कांग्रेस और सपा में गठबंधन हो गया है। कांग्रेस ने बसपा को भी साथ आने का न्योता दिया है मगर बसपा ने कोई जवाब नहीं दिया है। राजनीतिक समीक्षकों का मानना है मायावती का अकेले चलने का निर्णय पार्टी के लिए खतरनाक हो सकता है। मायावती की अकेले चलो की घोषणा से इंडिया गठबंधन को बड़ा धक्का लगा है, साथ ही विपक्ष को एक करने की मुहीम को बसपा सुप्रीमों ने पलीता लगा दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों ने मायावती के ऐलान को आत्मघाती बताते हुए कहा इससे बसपा में फूट पड़ेगी। कभी यूपी में 30 प्रतिशत वोट हासिल करने वाली बसपा अब 13 प्रतिशत पर पहुँच गई है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि मायावती के इस कदम से चुनावों में अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा को फायदा होगा। कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है. अगर यूपी में सभी विपक्षी दल साथ नहीं आते हैं तो वोटों के बंटवारे से नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। यूपी सहित देशभर में बसपा के वोट बैंक में लगातार गिरावट आई है। मायावती की पार्टी का यूपी सहित देश के कई राज्यों में जनाधार है। हालाँकि यूपी में बसपा की कमजोर स्थिति किसी से छिपी नहीं है। मायावती इस समय एकला चलो की राह पर है। विपक्ष में होते हुए भी वह विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल नहीं होने का एलान हैरान करने वाला है। देश के उत्तर भारत में बसपा दलितों पर कुछ हद तक अपना प्रभाव रखती है। विशेषकर यूपी में दलितों के एक वर्ग विशेष सहित अल्पसंख्यक मतदाता मायावती को अपना नेता स्वीकार करते है। मगर पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बसपा का आधार घटा है। विधान सभा में बसपा का सूपड़ा साफ़ हो गया। मायावती ने उनकी पार्टी के सम्बन्ध में सपा नेताओं की टिप्पणियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए साफ़ किया की राजनीति में कब किसको किसकी जरुरत पड जाये यह याद रखना चाहिए ताकि बाद में शर्मिंदा न होना पड़े।

वह भी एक समय था जब मायावती का समर्थन पाने के लिए लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों में होड़ मची थी। भाजपा हो या समाजवादी पार्टी अथवा कांग्रेस मायावती का समर्थन पाने के लिए सभी बेचौन रहते थे। उस दौरान बहनजी किसी को भाव नहीं देती थी। यदि किसी को समर्थन देती तो अपनी शर्तों पर। उनके दरवाज़े पर विभिन्न विचारधारा वाले नेताओं की क़तार देखी जा सकती थी। यूपी विधानसभा चुनाव में बहनजी की पार्टी का भट्टा बैठ गया था और उनके अस्तित्व पर सवालिया चिन्ह लगने लगे थे। मायावती की पार्टी कोई आंदोलनकारी पार्टी नहीं है। इस पार्टी को कभी किसी मुद्दे पर धरना प्रदर्शन करते नहीं देखा गया। बसपा केवल बयानों तक सीमित रहती है। बसपा की पहचान केवल जातीय पार्टी की है। मुस्लिमों के साथ साथ दलित भी उनकी पार्टी से अलग हो गए है। मुस्लिमों का झुकाव सपा की तरफ और दलित भाजपा की झोली में चले गए है। गौरतलब है यूपी विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती एक बारगी सियासत के नेपथ्य में चली गयी थी। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने 2007 के विधानसभा चुनाव में जब अपने दम पर सरकार बनाई, तो उनको राष्ट्रीय मंच पर दलित राजनीति के सिरमौर के रूप में देखा गया था । लोग यहाँ तक कहने लगे थे मायावती एक दिन देश की प्रधानमंत्री बनने में कामयाब हो सकती हैं। लेकिन यूपी में 2012 के चुनाव के बाद से लगातार खराब प्रदर्शन करने वाली बसपा का बुरा दौर जारी है। मायावती की हार को दलित राजनीति की धार कमज़ोर होने के तौर पर भी देखा जा रहा है। गत यूपी चुनाव में बसपा सिर्फ एक सीट पर सिमट गई है और दलित और मुस्लिम गठजोड़ तिनके की तरह बिखर गया।

(वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर)

कविता

बाप कह नहीं पाता है !

मुझें बाप से खतरा
यह शब्द निकलते है।
जब बेटी के मुख से
तब मानवता मर जाती है।
रिश्तों के तार टूट जाते है।
भावनाओं का सागर
सुख जाता है।
सोचने की शक्ति
शून्य हो जाती है।
अरे पगली...
बाप से खतरा होता तो
न पालता तुझे
अठारह वर्ष तक
न सहता लोगों के ताने
न खाता दर दर की ठोकरे
कंधे में दर्द था
फिर भी तुझे बिठाया
खुद भूखा रहकर तुझे
सब कुछ खिलाया।
खतरा तो बाप को है
बेटी से
इज्जत मिटने का
सम्मान लूटने का
रिश्ते टूटने...
डर तो बहुत है बाप
पर कह नहीं पाता है।
बस सह जाता है।

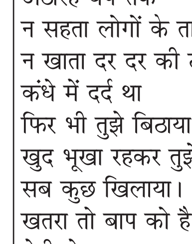

गुलाब कुमावत खीमेल
(सांचौर, राजस्थान)

बिहार को क्रिकेट ही नहीं बल्कि सभी खेलों में अपने जौहर दिखाने होंगे। बिहार सरकार को भी राज्य में खेलों के विकास के लिए इनवेस्ट करना होगा। सारे बिहार के समाज को सोचना होगा कि वे खेलों के संसार में किसी मुकाम पर क्यों नहीं पहुंच सके? आपको सारे बिहार में हॉकी के एक-दो एस्ट्रो टर्फ से ज्यादा हॉकी मैदान नहीं मिलेंगे। राष्ट्रीय नायक दादा ध्यान चंद के देश में इस तरह के राज्य भी हैं जहां पर एस्ट्रो टर्फ के मैदान ना के बराबर ही हैं।

बिहारी क्रिकेटर कब खेलेंगे टीम इंडिया से

– आर.के. सिन्हा

मौजूदा भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में बिहार के दो नव युवा खिलाड़ी ङ्कआकाशदीप और मुकेश कुमार ने शानदार प्रदर्शन करके अपनी प्रतिभा से क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। पर यह बिहार का दुर्भाग्य ही कहा जायेगा कि दोनों खिलाड़ी बिहार की टीम से नहीं खेलते। यह दोनों खेलते हैं बंगाल की टीम से रणजी ट्रॉफी में। इसकी वजह यह है कि बिहार में क्रिकेट मैनेजमेंट तार-तार हो चुका है। आकाशदीप का संबंध बिहार के रोहतास जिले से है। आकाशदीप ने रांची टेस्ट मैच में अपनी सधी हुई गेंदबाजी की बदौलत इंग्लैंड टीम के तीन खिलाड़ियों को आउट करके सनसनी मचा दी थी। उनके दादा निशान सिंह स्वाधीनता सेनानी थे। अब आकाशदीप 7 मार्च से शुरू होने वाले पांचवें और आखिरी टेस्ट मैच के लिए हिमाचल प्रदेश जाएंगे और भारतीय क्रिकेट टेस्ट टीम का हिस्सा बनेंगे। उनकी तरह ही मुकेश कुमार भी हैं। बिहार के गोपालगंज जिले में स्थित काकड़कुंड गांव के रहने वाले मुकेश कुमार का चयन टीम इंडिया में वेस्टइंडीज टूर के लिए किया गया था। मुकेश कुमार भी तेज गेंदबाज हैं। मुकेश आईपीएल में भी धमाकेदार प्रदर्शन कर चुके हैं। वह आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स टीम का हिस्सा थे। मुकेश कुमार दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज हैं। इसके साथ ही, वह बायें हाथ के बल्लेबाज भी है। इस तरह दोनों ही खिलाड़ी भोजपुरिया हैं। मुकेश के पिता कोलकाता में टैक्सी चलाते थे। साल 2019 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तब मुकेश ने बंगाल में ही खेलते-खेलते कई लोगों से संपर्क बनाया और अपने मेहनत के बल पर नई पहचान बनाई। अफसोस कि बिहार में क्रिकेट का मैनेजमेंट बहुत बुरी स्थिति में है। इसलिए बिहार के प्रतिभाशली खिलाड़ी अन्य टीमों का रुख करते हैं। पिछले महीने पटना में बिहार और मुंबई की टीमों के बीच रणजी ट्रॉफी का मैच हुआ तो बिहार की दो टीमें मैदान में आ गई। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में खेले गए रणजी ट्रॉफी के एलिट ग्रुप बी मुकाबले में मुंबई की टीम ने बिहार को एक पारी और 51 रन से हराया। पर यह खबर नहीं थी। खबर यह थी कि मुंबई की टीम जिस स्टेडियम में मैच खेल रही थी उसकी हालत बेहद खराब थी। वहां पर दर्शकों के लिए बैठने तक की जगह नहीं थी। मैच को देखने के लिए रोज हजारों दर्शकों को भारी कठिनाई में मैच देखना पड़ा। जब देश में एक से बढ़कर एक बहुत सारे स्टेडियम बन चुके हैं, तब सारे बिहार में एक भी कायदे का स्टेडियम नहीं है। यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानी जा सकती। इस बीच, ईशान किशन तो बीते कई सालों से भारतीय टीम में हैं। लेकिन वे भी झारखंड के लिए खेलतें है। उन्हें 2016 में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारत की टीम का कप्तान बनाया गया था। ईशान 2018 से इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा हैं। ईशान का जन्म बिहार के नवादा जिला में हुआ था। उनके जन्म के बाद उनका परिवार पटना शिफ्ट हो गया था। उन्हें भी झारखंड शिफ्ट होना पड़ा क्यों बिहार में क्रिकेट का कोई इंफ्रास्टक्कर नहीं है। क्रिकेट प्रेमियों को याद होगा कि संयुक्त बिहार के दौर में दिल्ली की टीम के कई बड़े खिलाड़ी बिहार से खेलने के लिए दिल्ली को छोड़ देते थे। इस लिहाज से रमेश सक्सेना का नाम सबसे पहले जेहन में आता है। उन्होंने एक टेस्ट मैच भी खेला। रमेश सक्सेना ने 1960-61 में अपना पहला प्रथम श्रेणी का मैच खेला था। उन्होंने 1966-67 में दिल्ली को अलविदा कह कर बिहार का रुख कर लिया था। रमेश सक्सेना के अलावा हरि गिडवाणी भी दिल्ली के बाद बिहार चले गए थे। उन्होंने लंबे समय तक बिहार की नुमाइंदगी की। यह दोनों क्लासिक बल्लेबाज थे। हरि गिडवाणी की पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में मिठाई की एक बहुत मशहूर दुकान भी है।

बिहार को क्रिकेट ही नहीं बल्कि सभी खेलों में अपने जौहर दिखाने होंगे। बिहार सरकार को भी राज्य में खेलों के विकास के लिए इनवेस्ट करना होगा। सारे बिहार के समाज को सोचना होगा कि वे खेलों के संसार में किसी मुकाम पर क्यों नहीं पहुंच सके? आपको सारे बिहार में हॉकी के एक-दो एस्ट्रो टर्फ से ज्यादा हॉकी मैदान नहीं मिलेंगे। राष्ट्रीय नायक दादा ध्यान चंद के देश में इस तरह के राज्य भी हैं जहां पर एस्ट्रो टर्फ के मैदान ना के बराबर ही हैं। सारे बिहार में दो-तीन भी स्वीमिंग पूल मिल जाए तो बड़ी बात होगी। हां, सेना और अर्ध सैनिक बलों के कुछ स्वीमिंग पूल जरूर हैं। पर वे तो सबके लिए नहीं होते। अब बताएं कि बिहार से कैसे खिलाड़ी निकलेंगे। उन्हें न्यूनतम सुविधाएं तो मिलनी ही चाहिए। बिहार में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्कर को विकसित करने को लेकर कोई बात भी नहीं होती। बिहार को अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से ही कुछ प्रेरणा ले लेनी चाहिए। अब योगी सरकार के काल खंड में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी क्रिकेट और अन्य खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करने लगे हैं। वहां खेलों के इंफ्रास्ट्रक्कर पर उचित ध्यान दिया जा रहा है। सफल खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों के साथ-साथ अच्छे तरीके से पुरस्कृत भी किया जा रहा है। पिछले एशियाई में भाग लेने वाली भारत की टोली में उत्तर प्रदेश से 36 खिलाड़ी थे। एशि?याई खेलों में उत्तर प्रदेश के एथलीटों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद सभी राज्य के खेलों से जुड़ी एसोसिएशन और कोच कसकर मेहनत करने लगे हैं। राज्य सरकार खेलों को गति देने को लेकर कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इस

तथ्य से लग सकता है कि अब गांवों के स्कूलों में भी कोचिंग की व्यवस्था शुरू हो गई है। जिन खिलाड़ियों ने एशियाई खेलों में पदक जीते थे, उनकी झोलियां भर गईं हैं इनामों से। बिहार ज्ञान का प्रदेश है। बिहारी सारे देश में अपने ज्ञान से सबको प्रभावित करते हैं। बिहार में पढ़ने-लिखने की बहुत समृद्ध परंपरा है। पर इतना ही काफी नहीं है। बिहार को खेलों में भी लंबी छलांग लगानी होगी। इसके लिए बिहार सरकार और बिहार के समाज को साथ एकजुट होकर प्रयास करने होंगे।

(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संपादकीय

टूटे न जीवन की डोर

जब 'परीक्षा पर चर्चा' कार्यक्रम में देश के करोड़ों छात्र-छात्राओं, शिक्षकों व अभिभावकों से दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम व वर्चुअल संवाद के जरिये प्रधानमंत्री परीक्षा भय से मुक्त होने की बात कर रहे थे, देश के कई भागों से छात्रों के आत्महत्या करने की खबरें आ रही थीं। जाहिर है अभिभावक व शिक्षक इन बच्चों के मानसिक द्वंद्व व वास्तविक दिक्कतों को नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके चलते इन बच्चों को मौत को गले लगाना अंतिम विकल्प नजर आ रहा है। निश्चित रूप से परीक्षा का भय इस कदर बच्चों पर हावी है कि उन्हें लगने लगता है कि परीक्षा में असफलता के बाद जीवन में कुछ शेष नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री ने इस संबोधन में इन तमाम चुनौतियों को संबोधित किया। उन्होंने गहरी बात कही किङ्क 'बच्चों के रिपोर्ट कार्ड को अपना विजिटिंग कार्ड न बनाएं।' यह एक हकीकत है कि अपने जीवन में शैक्षिक व रोजगारपरक लक्ष्यों को हासिल न कर पाने वाले अभिभावक अपने बच्चों से आईएएस, डॉक्टर व इंजीनियर बनने की उम्मीद पाल बैठते हैं। जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करते हुए यह नहीं सोचते कि बच्चे की क्षमताएं क्या हैं और हमारी उम्मीदों का बोझ वे किस सीमा तक बर्दाश्त कर पाएंगे। संगरूर में मेरिटोरियस स्कूल के हॉस्टल से एक छात्र के पिता को फोन जाता है कि तुम्हारे बच्चे के नंबर कम आए हैं। उसे हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। इसके तीन घंटे बाद खबर आई कि छात्र ने हॉस्टल के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। यहां इस फोन करने वाले शिक्षक की जवाबदेही तय की जानी चाहिए कि उसने ऐसा संवेदनहीन व्यवहार क्यों किया। क्या नंबर कम आने के लिये छात्र को हॉस्टल से निकाल देना समस्या का समाधान है? यह दबाव अभिभावकों पर बना तो छात्र तनाव में आ गया। क्या उन कारणों की पड़ताल नहीं की जानी चाहिए थी जिसकी वजह से छात्र के नंबर कम आए? नये दौर में संक्रमणकाल से गुजर रहे छात्रों को समझने में क्या शिक्षक जिम्मेदार भूमिका निभा रहे हैं?

वहीं दूसरी ओर कोचिंग बाजार का गढ़ बन चुके कोटा में छात्रों की आत्महत्या का सिलसिला थम नहीं रहा है। कोटा से फिर एक संभावना के अस्त होने की खबर आ रही है। वहां से बुरी खबर आई कि सोमवार को जेईई व नीट परीक्षा की तैयारी कर रही 18 साल की निहारिका ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले लिखे पत्र में उसने लिखा- 'मम्मी-पापा, मैं जेईई नहीं कर सकती, इसलिए सुसाइड कर रही हूं। आई एम लूजर, यही लास्ट ऑप्शन है।' जाहिर है बच्ची इतनी भयाक्रांत थी कि परीक्षा से पहले ही आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। जाहिर है इस फैसले में परिवार की उम्मीदों का बोझ ही शामिल होगा, जिसके चलते परीक्षा की विफलता को उसने जीवन का अंत मान लिया। आखिर क्यों मां-बाप बच्चों के साथ ऐसा सहज संवाद नहीं बना पाते कि इस आत्मघाती फैसले से पहले वह किसी तरह का विमर्श उनके साथ कर सके? क्यों हम बच्चों के सामने ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि उन्हें लगता है कि परीक्षा में उत्तीर्ण न हुए तो जीवन ही खत्म हो जाएगा? प्रश्न यह भी है कि उम्मीदों का कब्रगाह बनते कोटा भेजने से पहले क्या अभिभावकों ने सोचा है कि क्या जेईई में निकलना निहारिका का पैशन भी है? हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। ईश्वर उसे किसी निश्चित लक्ष्य के लिये रचता है। दुर्भाग्य से मां-बाप उसकी रुचि व रुझान को नहीं समझ पाते। अपनी इच्छाएं थोपकर उसे कैरियर की दिशा निर्धारित करने के लिये कह देते हैं। यहीं से उसके जीवन में द्वंद्व शुरू होते हैं। जो पाठ्यक्रम छात्र-छात्राओं के मन का होता है उसमें वे जीवन में आशातीत सफलता प्राप्त करते हैं, विशिष्टता हासिल करते हैं। दुर्भाग्य से हम 21वीं सदी के बच्चों को 19वीं सदी के हंटर से हांक रहे हैं। उनके अहसासों व उम्मीदों का खात्मा कर रहे हैं।

चुनाव आयोग की 'विमर्शिका'

चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी होगी कि वह सत्ता पर काबिज दल की सरकार से निरपेक्ष रहते हुए अपना कार्य पूरी निष्पक्षता व स्वतन्त्रता के साथ करे और सत्तारूढ़ दल के प्रधानमन्त्री से लेकर मन्त्रियों तक के लिए चुनावी नियम एक समान बनाये। इसे सभी दलों के लिए एक जैसी जमीन या 'लेवल प्लेयिंग फील्ड' का नाम दिया गया। अतः जब प्रधानमन्त्री से लेकर मन्त्री तक चुनाव प्रचार में उतरते हैं तो उनकी मुख्य हैसियत अपने दल के एक राजनैतिक कार्यकर्ता की होती है और उनके चुनाव प्रचार पर किया गया खर्चा उनकी पार्टी को वहन करना पड़ता है।

बाबा साहेब अम्बेडकर जो संविधान हमें सौंप कर गये हैं उसमें चुनावों की व्यवस्था के लिए पृथक चुनाव आयोग का गठन इस प्रकार किया गया कि यह पूरी प्रजातान्त्रिक प्रणाली की आधारभूत जमीन तैयार करे और प्रत्येक वयस्क नागरिक को मिले एक वोट के संवैधानिक अधिकार के उपयोग की गारंटी करते हुए नागरिकों की मनपसन्द सरकार का गठन करने में मदद करे। चुंकि भारत में राजनैतिक आधार पर प्रशासनिक व्यवस्था चलती है अतः चुनाव आयोग को ही सभी राजनैतिक दलों की नियामक संस्था बनाया गया और तय किया गया कि चुनाव घोषित होने के बाद सत्ता पर काबिज किसी भी राजनैतिक दल की सरकार की भूमिका अन्य राजनैतिक दलों के समकक्ष ही हो। चुनाव आयोग को चुनाव घोषित होने के बाद समूची प्रशासन प्रणाली का संरक्षक बनाते हुए संविधान में यह व्यवस्था की गई कि चुनाव प्रचार के दौरान सभी सत्ता व विपक्ष के दलों के लिए नियम एक समान होंगे और सभी की स्थिति चुनाव आयोग के समक्ष एक समान होगी।

चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी होगी कि वह सत्ता पर काबिज दल की सरकार से निरपेक्ष रहते हुए अपना कार्य पूरी निष्पक्षता व स्वतन्त्रता के साथ करे और सत्तारूढ़ दल के प्रधानमन्त्री से लेकर मन्त्रियों तक के लिए चुनावी नियम एक समान बनाये। इसे सभी दलों के लिए एक जैसी जमीन या 'लेवल प्लेयिंग फील्ड' का नाम दिया गया। अतः जब प्रधानमन्त्री से लेकर मन्त्री तक चुनाव प्रचार में उतरते हैं तो उनकी मुख्य हैसियत अपने दल के एक राजनैतिक कार्यकर्ता की होती है और उनके चुनाव प्रचार पर किया गया खर्चा उनकी पार्टी को वहन करना पड़ता है। बेशक उनका औहदा मन्त्री या प्रधानमन्त्री का रहता है परन्तु वह प्रचार के दौरान अपनी सरकार की तरफ से कोई नीतिगत घोषणा नहीं कर सकते उन्हें केवल पार्टी की नीतियों व कार्यक्रमों तक ही सीमित रहना होता है। ऐसा इसीलिए होता है कि क्योंकि विपक्षी दलों के हाथ में केवल अपनी पार्टी की नीतियों व कार्यक्रमों को ही लोगों को बताने की ताकत होती है। इसे ही 'लेवल प्लेयिंग फील्ड' कहा जाता है जिसे चुनाव आयोग सुनिश्चित करता है और ऐसा वह सीधे संविधान से शक्ति लेकर करता है। वह किसी भी सरकार के रहमो-करम पर निर्भर संस्था नहीं होती। मगर चुनाव प्रचार के दौरान हम देखते हैं कि राजनैतिक दलों में भयानक तौर पर आरोप-प्रत्यारोपों की बौछार चलती है। एक-दूसरे पर अनर्गल आरोप लगाना आम बात होती है। चुनाव प्रचार का एक स्तर बनाये रखने के लिए ही चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता को लागू करता है जिससे प्रत्येक दल का नेता मर्यादा में रह कर अपने विरोधी के खिलाफ आरोप लगा सके और संविधान की आत्मा के अनुरूप भारत की सामाजिक एकता को बनाये रख सके। मगर चुनाव आते ही साम्प्रदायिक आधार पर हिन्दू-मुस्लिम वोटों की गिनती शुरू हो जाती है और हिन्दू समुदाय में जातिगत आधार पर वोटों को गिनवाने की परंपरा जैसी शुरू हो जाती है। संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है और प्रत्येक वयस्क मतदाता को केवल नागरिक मानता है जिसके पास एक वोट का अधिकार होता है।

जाति या धर्म अथवा समुदाय या वर्ग के नाम पर कोई भी नेता नागरिकों से वोट नहीं मांग सकता है परन्तु हम देखते हैं कि

भारत में चुनाव आते ही साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण व जातिगत गोलबन्दी शुरू हो जाती है। हद तो यह है कि भारत में जातिगत आधार पर पार्टियां तक बताई जाती हैं और अल्पसंख्यकों व बहुसंख्यकों की पार्टियां तक गिनाई जाती हैं। चुनाव प्रचार में किसी न किसी बहाने सम्प्रदाय या जाति को केन्द्र में लाने के बहाने ढूंढे जाते हैं। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों की घोषणा करने से पहले सभी राजनैतिक दलों के लिए एक विमर्शिका (एडवाइजरी) जारी की है जिसमें कहा है कि अगर कोई स्टार प्रचारक या नेता या प्रत्याशी आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

हम जानते हैं कि पिछले वर्ष पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों से पूर्व भी आयोग ने ऐसी ही विमर्शिका जारी की थी मगर उसका कोई खास असर हमें दिखाई नहीं दिया। आदर्श आचार संहिता कोई चुनावी औपचारिकता नहीं होती बल्कि यह कानूनी प्रक्रिया होती है जिससे किसी भी दल का नेता ऊपर नहीं होता। अतः चुनाव आयोग को ही सोचना होगा कि वह इसके लागू करने में कैसी लापरवाही बरतता है और क्यों बरतता है। चुनावों के समय यदि चुनाव आयोग के रुतबे में गिरावट आती है तो इसका सीधा असर पूरी चुनाव प्रणाली की गुणवत्ता पर पड़ता है । हम जानते हैं कि पहले ही देश में ईवीएम मशीनों से मतदान कराये जाने को लेकर भयंकर विवाद छिड़ा हुआ है। चुनाव आयोग इस पर चुप्पी साधे बैठा है और शकांओं के निवारण से कन्नी काटता हुआ लग रहा है। हालांकि ईवीएम को जितना तूल दिया जा रहा है उसका निवारण भी इसी मशीन के साथ लगी दूसरी वीवीपैट या वोट रसीदी मशीन में है जिसकी सभी पर्चियों को गिनकर मामले को सुलझाया जा सकता है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने अब 85 वर्ष से ऊपर के नागरिकों के लिए डाकमतपत्रों या पोस्टल बैलेट की सुविधा देने का प्रस्ताव किया है। पहले यह आयु 80 वर्ष की थी। यह फैसला तार्किक लगता है क्योंकि भारत में अब औसत आयु 70 के करीब पहुंच रही है तो 80 वर्ष तक के नागरिक स्वयं मतदान केन्द्रों तक जा सकते हैं।

आज का इतिहास

- पश्चिम बंगाल में 1788 में कलकत्ता गजट का पहला प्रकाशन हुआ।
- सन 1930 में फ्रांस में आयी भयंकर बाढ़ से करीब 700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई।
- ब्रिटिश वायसराय, गवरनोर-जनरल एडवर्ड फ्रेदेरिक्क लिन्दले वुड और मोहनदास करमचंद गाँधी जी (महात्मा गाँधी) में सन 1931 में भेंट राजनीतिक कैदियों की रिहाई और नमक के सर्वजन उपयोग की छूट को लेकर मंत्रणा और इकरारनामे की घोषणा।
- नयी दिल्ली में सन 1951 में पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया गया।
- रोमानिया में 1977 में आये जबरदस्त भूकंप से लगभग 1541 लोगों की मौत हुई।
- संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों को अपनी परित्यक्ता पतनी एवं बच्चों को 1999 में जीवन निर्वाह भत्ता देने की घोषणा।
- तालिबान ने 2001 में मूर्तियों को ख़रीदने की ईरान की पेशकश ठुकराई।
- हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान् डॉ. मदन लाल मधु को 2008 में प्रतिष्ठित सम्मान मीडिया यूनियन ने स्वर्णाक्षर पुरस्कार से सम्मानित किया।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2008 में ईरान के ख़िलाफ़ नई पाबंदियाँ लागू की।
- राजस्थान के पोखरन से 2009 में 卐ब्रह्मोस मिसाइल卐 के नये संस्करण का परीक्षण किया गया।
- व्लादिमिर पुतिन ने 2012 में रूस के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता।
- 1856 में अंग्रेज़ी भाषा की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभासम्पन्न कवयित्री तोरु दत्त का जन्म।
- 1881 में प्राक्छायावादी युग के महत्त्वपूर्ण कवि रामनरेश त्रिपाठी का जन्म।
- 1886 में मद्रास के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी बलुसु संबमूर्ति का जन्म।
- हिंदी के लोकप्रिय साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु का 1921 में जन्म हुआ।
- 1922 में प्रसिद्ध गुजराती रंगमंच और फ़िल्म अभिनेत्री दीना पाठक का जन्म।
- 1980 में भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना का जन्म।
- 1980 में भारतीय फ़िल्म अभिनेत्री कामालिनी मुखर्जी का जन्म।
- मध्य प्रदेश स्थित विजयराघवगढ़ के राजकुमार और प्रसिद्ध साहित्यकार ठाकुर जगमोहन सिंह का 1899 में निधन।
- प्रसिद्ध भारतीय अधिवक्ता और राजनेता सत्येन्द्र प्रसन्न सिन्हा का 1928 में निधन।
- भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी और 'गदर पार्टी' के संस्थापक लाला हरदयाल का 1939 में निधन।
- भारतीय सांसद सुनील कुमार महतो का 2007 में निधन।
- भारत के राजनीतिज्ञों में से एक पी. ए. संगमा का 2016 में निधन।

गाजा में मानवता की हत्या

गाजा पट्टी के लोग रोटी के टुकड़े-टुकड़े को तरस रहे हैं। भूख, सब्र, मौत और कयामत का दूसरा नाम बन चुका है गाजा। इजराइल और हमास का हिंसक संघर्ष साढ़े चार महीने से पूरी तरह मानवता के लिए चुनौती बना हुआ है। गाजा में रोज मानवता की हत्या हो रही है। गाजा में मदद की बाट जोह रहे लोगों पर इजराइली डिफैंस फोर्स की कार्रवाई में 104 लोगों की मौत ने युद्ध के कारण अभूतपूर्व मानवीय संकट के स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। अब तक 30 हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा के अस्पतालों में डीहाइड्रेशन और कुपोषण के कारण?बच्चे दम तोड़ रहे हैं। महिलाओं की हालत बहुत दयनीय है। लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। इजराइली हमले में हर 10 मिनट में एक बच्चा दम तोड़?रहा है। निर्दोष?फिली?स्तीनियों की मौत मानवता का सबसे काला अध्याय है।

हालात कितने गंभीर हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र ने भी गाजा की दयनीय स्थिति को रेखांकित किया है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम ने चेतावनी दी है कि उत्तरी गाजा में इन दिनों अकाल के हालात हैं। गाजा के लोग भुखमरी से कुछ ही कदम दूर हैं, क्योंकि यहां खाने के लाले पड़ने लगे हैं। उधर, गाजा में कोई भी मदद पहुंचते ही लोग उसे लूटने में जुट जाते हैं, इस कारण 23 जनवरी से यहां कोई सहायता भी नहीं पहुंच रही है। गाजा पट्टी में गंभीर मानवीय आपातकाल सामने आने के बाद से वहां की मुख्य संयुक्त राष्ट्र सहायता एजेंसी इससे निपटने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। संयुक्त राष्ट्र ने अन्य देशों से भी सख्त जरूरत वाले हजारों फिलीस्तीनियों तक मदद पहुंचाने का आह्वान किया।

लगातार फिलीस्तीनियों की मौत को लेकर यद्यपि इजराइल पर दबाव बन रहा है लेकिन अभी तक युद्ध विराम के लिए किसी समझौते पर पहुंचने के आसार नजर नहीं आ रहे। हमास के नेताओं

का भी किसी समझौते को लेकर कोई स्पष्ट रुख सामने नहीं आया है। गाजा में सुरक्षा के डगमगाते हालात के बीच अकाल का खतरा पैदा हो गया है। इजराइल गाजा पट्टी में युद्ध अपराध कर रहा है लेकिन हैरानी की बात यह है कि पूरी दुनिया कोरी बयानबाजी कर दूर से तमाशा देख रही है। अमेरिका, ?ब्रिटेन और अन्य ?पश्चिमी देश तो खुद को मानवाधिकारों का अलम्बरदार मानते हैं और समय-समय पर उनके यहां की मानवाधिकार परिषदें अन्य देशों में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन की पूर्वाग्रह से ग्रसित रिपोर्टें जारी करती रहती हैं। आज सभी खामोशी धारण किए हुए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि अमेरिका और उसके मित्र देश दोहरा रवैया अपना रहे हैं। दुनिया भर में मानवाधिकारों को ढिंढोरा पीटने वाले देश?स्वयं मानवीय मूल्यों को हाशिये पर धकेल रहे हैं। इजराइल-हमास जंग का असर अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों पर भी पड़ रहा है। यह आरोप लगाया जा रहा है कि अमेरिका चुनावी लाभ के लिए पश्चिम एशिया में आक्रामकता दिखा रहा है। अमेरिका दुनिया में अपने वर्चस्व को बचाने तथा देश में चुनावों से पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन की छवि चमकाने के लिए इराक और सीरिया के खिलाफ भी आक्रामकता दिखा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत वैसिली नेबेंजिया ने अमेरिका पर अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने और ÷पश्चिम एशिया में अराजकता और विनाश के बीज बोने÷ का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका और उसके सहयोगियों की हिंसा फिलीस्तीनी क्षेत्रों से लेकर लेबनान, लाल सागर और यमन तक बढ़ गई है और यह ÷पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को विफल कर रही है।÷ उन्होंने सभी देशों से ÷इन संवेदनहीन कृत्यों की स्पष्ट रूप से निंदा करने का आह्वान किया जो इराक और सीरियाई अरब गणराज्य की संप्रभुता का उल्लंघन करते हैं।÷ रूसी राजदूत ने दावा किया कि अमेरिका ÷मौजूदा अमेरिकी प्रशासन की छवि को सही ठहराने के लिए आगामी राष्ट्रपति चुनाव से पहले अपने चुनाव प्रचार अभियान के तहत अपनी ताकत दिखाने का प्रयास कर रहा है।'

इजराइल-हमास जंग को लेकर खुद अमेरिका का समाज दो हिस्सों में बंट चुका है। अब जबकि रमजान का महीना शुरू हो रहा है इसलिए कुछ हफ्ते के लिए युद्ध विराम तो होना ही चाहिए और हमास को भी चाहिए कि वह 40 इजराइली बंधकों को रिहा कर दे। अभी तक युद्ध विराम समझौते का कोई प्रारूप सामने नहीं आया है। दुनिया भर के मुस्लिम संगठन चीख-चीख कर इजराइली हमलों को फिलीस्तीन की आजादी और जीने के अधिकार पर हमला करार दे रहे हैं। वह यह भी सवाल उठा रहे हैं कि बीते सालों में डेढ़ लाख से ज्यादा फिलीस्तीनियों को क्यों मार दिया गया। उनमें करीब 35 हजार बच्चों का कत्लेआम ?क्यों किया गया लेकिन मुस्लिम देश हमास को आतंकी नहीं मान रहे हैं। दरअसल आतंकवाद सम्पूर्ण मानवता के लिए घातक स्थिति है जिससे कोई भी देश अछूता नहीं है। युद्धरत देशों पर संयुक्त राष्ट्र का कोई अंकुश नहीं है। विश्व शांति का राग अलापने वाले बड़े देश ही युद्ध की आग को भड़का रहे हैं। दु?निया के बड़े मानवीय संकट को रोकने के लिए ठोक कदम उठाए जाने जरूरी हैं, अन्यथा मासूमों की लाशें ही बिछती रहेंगी।

वादों का झोला और वोट का खेला

अब तो आईटी का जमाना आ गया है। कम उम्र वाला वोटर सब बहुत हो गये हैं। नेता जी इसे भांप गए हैं। उस दिन पूरब वाले नुक्कड़ पर अपने जवान वोटरों से कह रहे थे, 'मैं जीता और मेरी पार्टी की सरकार बनी तो सच मानिये ई किताब-कॉपी से पढ़ने-लिखने का झमेला खत्म। मेरे ऊपर भरोसा कीजिए। आप सबके हाथ में लैपटॉप रहेगा।

वोट हथियाने का पुराना तरीका बदल गया है। पहले ठर्रा से काम चल जाता था। अब डिमांड जरा बदल गया है। वोटर 'सजग' हो गए हैं। जमाने की उछाल के साथ उनकी चाहत में भी उछाल आया है। नेता जी की मजबूरी बढ़ गई है। अब तो वोट लूटने वाला समय भी न रहा। 'करमजरु' शेषन ने ऐसा खेला खेला कि उसी वक्त से वोट के दिन गोली-बंदूक वाला खेला ही खत्म हो गया।

अब तो आईटी का जमाना आ गया है। कम उम्र वाला वोटर सब बहुत हो गये हैं। नेता जी इसे भांप गए हैं। उस दिन पूरब वाले नुक्कड़ पर अपने जवान वोटरों से कह रहे थे, 'मैं जीता और मेरी पार्टी की सरकार बनी तो सच मानिये ई किताब-कॉपी से पढ़ने-लिखने का झमेला खत्म। मेरे ऊपर भरोसा कीजिए। आप सबके हाथ में लैपटॉप रहेगा। वो भी बिना अधेली खर्च किये। बस सिरिफ बटनवा दबावे, घरी बेलचा को याद रखियेगा। बहुत लोग बहकायेंगे। लेकिन जरिको बहकियेगा नहीं।'

गांव के दूसरे मुहाने पर दूसरका पार्टी वाले नेता जी हाथ जोड़े मंच पर पहुंचे ही थे। तभी एक नौजवान दौड़ा-दौड़ा आया। मंच पर चढ़ गया। नेता जी के कान में कुछ फुसफुसाया। नेताजी कुर्ता की बांह ऊपर करते हुए धीरे से बोले, 'घबराओ नहीं । हमको मालूम है कौन-सा पासा कहां चलना है।' फिर जनता की ओर मुखातिब हो गए, 'सुना है खेलावन बाबू लैपटॉप देने की बात उधर कर रहे थे। लेकिन मेरे बात पर भरोसा कीजिए। आपका बुझावन कभी झूठ भरोसा नहीं दिलाता। जान लीजिए ई जो लैपटॉप है न उसको चलाने के लिए भोजन-पानी का इंतजाम करना पड़ता है। उसके बिना समझिये लैपटॉप बस बक्सा है। जानते है डेटा पैक उसका दाना पानी है। मैं आप सबको लैपटॉप के साथ तीन साल का डेटा पैक भी दिलवाऊंगा।' तालियों की गरगहाट में नेता जी की आगे की बात सुनाई नहीं दी। वे मुस्कुराते हुए झट से मंच से उतरे। गाड़ी में बैठे। साथ आये मीडिया वाले भी पीछे गाड़ी में लद गए। गाड़ी आगे बढ़ी। नेता जी कहने लगे, 'देखा न आप लोग। नहला पर दहला किस तरह मारा।'

एक अखबार वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, 'लेकिन नेता जी आप क्या-क्या बोल गए।'

अरे आप लोग बुड़बक रह गए। सब सही बोले। आम जनता को उसकी भाषा में समझाना पड़ता है न। वोट का खेला है सब। आप लोग नहीं समझियेगा। चलिए शहर चलकर हाई टी हो जाये।'

मीडिया वाले हाई टी का नाम सुनते ही दांत निपोड़ दिये, 'हां, हां नेता जी। आप बिल्कुल सही कह रहे।'

नेताओं की कमाई और देशप्रेम का जज्बा

भारत में नेता एक कम से कम रहम करते हैं भारत पर कि वो भारत में ही रहते हैं। कमाते हैं तो खर्च भारत में ही करते हैं। बड़े बंगले बनाते हैं, तो इंडिया में ही खर्च करते हैं, बड़ी कारें खरीदते हैं, तो भी भारत में ही खरीदते हैं। भारत की इकोनोमी को ही फायदा होता है। भारतीय नेता कितने देशप्रेमी हैं, यह बात हम समझ सकते हैं पाकिस्तान के नेताओं की हरकतें देखकर।

पाकिस्तान के ड्रामे बहुत शानदार माने जाते हैं। कुछ पाकिस्तानी ड्रामे टीवी पर आते हैं, कुछ पाकिस्तानी ड्रामे राजनीति में चलते हैं। पाकिस्तान में इमरान जीत गये सच में, पर फौज ने हरा दिया इमरान को सचमुच में। अब इमरान खान ने इंटरनेशनल मानीटरी फंड को खत लिख दिया कि हमारे मुल्क को और कर्ज न दिया जाये। यानी इमरान खान कह रहे हैं कि हमें भीख न दी जाये, जब तक मैं ही प्राइम मिनिस्टर न बन जाऊं। दरअसल, इमरान खान की एकमात्र डिमांड यही है कि मुझे पीएम बनाओ। अगर मैं पीएम नहीं, तो फिर मुल्क के होने या न होने का कोई मतलब नहीं है। यह अप्रोच कुछ इस तरह की है कि अगर प्रेमिका राजी न हो रही हो, किसी और से शादी कर रही हो प्रेमिका की, तो उसके चेहरे पर तेजाब डालकर उसे तबाह कर दो। यह प्रेम की तेजाबी एप्रोच है। इमरान खान अपने देश पाकिस्तान को इस तरह से प्रेम करते हैं।

नवाज शरीफ आमतौर पर लंदन रहते हैं, पर जब उन्हे पीएम बनने का सीन दिखाई पड़ता है, तो वह पाकिस्तान आ जाते हैं। ऐसे कई भारतीय हैं, जो अमेरिका जाकर देशप्रेमी हो जाते हैं। अमेरिका जाकर उन्हें याद आता है कि हाय उनका देश कितना महान है। और वो भारत के लिए आंसू बहाते हैं, पर एक भी रुपया भारत में लगाते नहीं हैं। पर ऐसे अमेरिकन देशभक्त भारत का ज्यादा कुछ न बिगाड़ पाते, पर पाकिस्तान के कई नेता पाकिस्तान जाकर पीएम हो जाते हैं, इसलिए पाकिस्तान का नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। पाकिस्तान मजबूत देश है, ऐसे नेताओं, तमाम तरह के आतंकियों के बावजूद पाकिस्तान बचा हुआ है नक्शे पर। बस नक्शे पर ही बचा हुआ पाकिस्तान, यह पाकिस्तान बचा रह जाये, पाकिस्तान के नेताओं के बावजूद, पाकिस्तान की आर्मी के बावजूद, तो माना जाना चाहिए कि पाकिस्तान चोर-डाकू प्रूफ मुल्क है। चोर-डाकू पाकिस्तान टेंशन प्रूफ हैं, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन में पाकिस्तान की पब्लिक रहती है, वह लंदन न जा सकती।

भारत में नेता एक कम से कम रहम करते हैं भारत पर कि वो भारत में ही रहते हैं। कमाते हैं तो खर्च भारत में ही करते हैं। बड़े बंगले बनाते हैं, तो इंडिया में ही खर्च करते हैं, बड़ी कारें खरीदते हैं, तो भी भारत में ही खरीदते हैं। भारत की इकोनोमी को ही फायदा होता है। भारतीय नेता कितने देशप्रेमी हैं, यह बात हम समझ सकते हैं पाकिस्तान के नेताओं की हरकतें देखकर।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

एआइ पर नकेल

एक ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के बहुआयामी लाभों को लेकर भारत समेत दुनियाभर में उत्साह है और हर दिन इस क्षेत्र में नये-नये प्रयोग हो रहे हैं. वहीं इस तकनीक के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग की आशंकाएं और चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं. वैश्विक स्तर पर एआइ के विस्तार और उपयोग से संबंधित नियमन के लिए मंथन चल रहा है, जिसमें भारत भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. इस क्रम में बड़ा कदम उठाते हुए भारत सरकार ने सभी एआइ प्लेटफॉर्मों को निर्देश दिया है कि वे अपने उत्पादों को लोगों के सामने लाने से पहले सरकारी अनुमति लें. केंद्रीय सूचना तकनीक मंत्रालय ने अपने निर्देश में यह भी कहा है कि एआइ तकनीक से कौन क्या बना रहा है, उस संबंध में डाटा रखा जाए, ताकि फेक सामग्री बनाने वाले की पहचान की जा सके. सूचना तकनीक राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि जब कोई कार या माइक्रोप्रोसेसर जैसी वस्तु बाजार में लायी जाती है, उससे पहले उसका पूरा परीक्षण किया जाता है, लेकिन एआइ के क्षेत्र में ऐसा नहीं हो रही है. चाहे बड़ी तकनीकी कंपनियां हों या स्टार्टअप, वे अपने एआइ उत्पाद को बिना गहन जांच के उपलब्ध करा दे रहे हैं. इससे उनके दुरुपयोग की आशंका बढ़ जाती है. चूंकि इस क्षेत्र में ढेरों प्लेटफॉर्म सक्रिय हैं और उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है, ऐसे में उनका इस्तेमाल कर रहे लोगों की डाटा सुरक्षा में सेंधमारी को रोकने के लिए भी अनुमति की व्यवस्था जरूरी है. हाल के दिनों में भारत और कई देशों में एआइ से डीपफेक और भ्रामक सामग्री बनाने के कई मामले सामने आये हैं. भारत सरकार ने जो निर्देश जारी किया है, उसमें एआइ प्लेटफॉर्मों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि वे किसी पूर्वाग्रह या भेदभाव को बढ़ावा न दें तथा चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों की अनुमति न दें. एक मार्च को जारी यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है तथा एआइ प्लेटफॉर्मों से यह अपेक्षा की जा रही है कि वे प्रावधानों के अमल के बारे में 15 दिनों के भीतर सरकार को सूचित करेंगे. उल्लेखनीय है कि पिछले साल नवंबर और दिसंबर में राजीव चंद्रशेखर और तकनीक उद्योग के प्रतिनिधियों के बीच चर्चा हुई थी. उसमें प्रस्तावित कानून और परस्पर तालमेल के साथ-साथ इस पर भी सहमति बनी थी कि एआइ प्लेटफॉर्म अपने उपयोगकर्ताओं को यह स्पष्ट हिदायत देंगे कि गैरकानूनी सूचना के साथ प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है, उन पर पाबंदी लगायी जा सकती है और कुछ मामलों में कानूनी व्यवस्था के तहत दंडित भी किया जा सकता है. आशा है कि नये निर्देशों से एआई तकनीक को सुरक्षित एवं प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी.

भारत सरकार ने सभी एआई प्लेटफॉर्मों को निर्देश दिया है कि वे अपने उत्पादों को लोगों के सामने लाने से पहले सरकारी अनुमति लें.

पारदर्शी और न्यायसंगत बने विश्व व्यापार संगठन

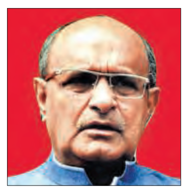

केसी त्यागी
पूर्व सांसद
kctyagimprs@gmail.com

बिशन नेहवाल
आर्थिक चिंतक

निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिक समानता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए डब्ल्यूटीओ की शासन संरचना में सुधार और पुनर्संतुलन के प्रयास किये जाएं.

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) को राष्ट्रों के बीच निष्पक्ष और खुले व्यापार को बढ़ावा देने के लिए गठित किया गया है. डब्ल्यूटीओ टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते (जीएटीटी) से उभरा, जिसे 1948 में एक बहुपक्षीय समझौते के जरिये स्थापित किया गया था, जिसमें अमेरिका समेत 23 देश शामिल थे. इसका उद्देश्य टैरिफ और अन्य व्यापार बाधाओं को धीरे-धीरे कम कर व्यापार को उदार बनाना था. पर तटस्थता के मुखौटे के नीचे शक्ति की गतिशीलता का एक जटिल जाल छिपा हुआ है, जहां दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका समेत विकसित देशों के हित अक्सर सर्वोच्च होते हैं. समानता और सहयोग के अपने कथित लोकाचार के विपरीत डब्ल्यूटीओ एक उपकरण बन गया है, जिसके माध्यम से पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका, के आधिपत्य को कायम रखा जाता है. दुनिया के अधिकांश हिस्सों में डब्ल्यूटीओ को अमेरिका की रचना माना जाता है, जिसे भारत जैसे विकासशील देशों पर थोपा गया है. उसके नियम मुख्य रूप से विकसित देशों के नियम हैं, भले ही बहुपक्षीय व्यापार वार्ता के क्रमिक दौर में सभी सदस्यों द्वारा उन पर सहमति व्यक्त की गयी हो. यह धारणा निराधार नहीं है. अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने वाले नियम और विनियम अक्सर पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका, की प्राथमिकताओं और प्रतिबद्धताओं को दर्शाते हैं. बौद्धिक संपदा अधिकारों से लेकर कृषि सब्सिडी तक वैश्विक व्यापार का ढांचा विकसित देशों के मानदंडों और मानकों से काफी प्रभावित है.

इसका प्रमाण ढूंढने के लिए दूर तक देखने की जरूरत नहीं है. मसलन, डब्ल्यूटीओ समझौतों की आधारशिला बौद्धिक संपदा अधिकार (ट्रिप्स) के व्यापार-संबंधी पहलुओं पर समझौते को लें. हालांकि जाहिर तौर पर इसका उद्देश्य बौद्धिक संपदा की रक्षा करना है, लेकिन ट्रिप्स विकसित देशों, विशेषकर अमेरिका, को उनकी तकनीकी प्रगति और नवाचारों की सुरक्षा कर असंगत रूप से लाभ पहुंचाता है. इससे विकसित देशों और निगमों को आवश्यक दवाओं और प्रौद्योगिकियों तक पहुंच के लिए संघर्ष कर रहे विकासशील देशों की कीमत पर वैश्विक बाजार में एक महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलता है. विकसित देश अक्सर अपने कृषि क्षेत्रों को सब्सिडी देते हैं, लेकिन भारत जैसे कृषि प्रधान विकासशील देश में किसानों को मिलने वाली सब्सिडी पर ऐतराज जताते हैं, जबकि यह सब्सिडी पश्चिमी देशों की तुलना में काफी कम है. डब्ल्यूटीए के नियमों के मुताबिक 10 प्रतिशत से ज्यादा सब्सिडी नहीं दी जा सकती है. भारत का कहना है वह इस सीमा को पार नहीं करता है. भारत में अभी हर किसान को प्रति साल सिर्फ 227 डॉलर (18,160 रुपये) की सब्सिडी मिलती है. यह बिजली, पानी, खाद, बीज, न्यूनतम समर्थन मूल्य आदि के तौर पर दी जाती है. प्रति किसान सालाना सब्सिडी ब्राजील में 25,900, चीन में 59,605, यूरोपीय संघ 4.67 लाख, जापान सात लाख, कनाडा 11.44 लाख और अमेरिका 48.46 लाख रुपये है. सब्सिडी देने के मामले में अमेरिका सबसे आगे है. यह भारत में किसानों को मिलने वाली सब्सिडी का 267 गुना है.

डब्ल्यूटीओ समझौते अक्सर विकासशील देशों को टैरिफ कम करने पर जोर देते हैं, जिससे सस्ता आयात होने से बाजार में विदेशी उत्पादों की बाढ़ सी आ जाती है. इससे स्थानीय व्यवसाय बंद हो सकते हैं, नौकरियां खत्म हो सकती हैं और घरेलू औद्योगिक विकास में बाधा आ सकती है. इसके कारण भारत समेत अन्य विकासशील देशों के किसानों को अस्थिर बाजारों का सामना करना पड़ता है. इस अस्थिरता को संबोधित करने के लिए ही भारतीय किसान पूर्व-निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे है. आयात पर शुल्क (टैरिफ) विकासशील देशों के लिए आय का साधन होते हैं और उनकी कमी होने से सरकारी राजस्व की हानि होती है, जिससे कल्याणकारी योजनाओं के लिए बजट कम हो सकता है. घरेलू समर्थन और निर्यात सब्सिडी जैसे तंत्रों से धनी देश कृषि व्यापार में अपना प्रभुत्व बनाये रखते हैं, जबकि वैश्विक दक्षिण में छोटे उत्पादकों को अनुचित प्रतिस्पर्धा और बाजार विकृतियों से जूझने के लिए छोड़ दिया जाता है. इससे न केवल वैश्विक असमानता बढ़ती है, बल्कि गरीबी और खाद्य असुरक्षा का चक्र भी कायम रहता है. डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान तंत्र के साथ भी ऐसा ही है. कानूनी संसाधनों और विशेषज्ञता की असंगत हिस्सेदारी के साथ अमेरिका अपने आर्थिक हितों की रक्षा करने और अपनी पसंदीदा व्यापार नीतियों के अनुपालन के लिए डब्ल्यूटीओ की न्यायिक प्रक्रिया का लाभ उठाता है. डब्ल्यूटीओ केवल अमीर देशों के हितों को आगे बढ़ाने का माध्यम नहीं है. यह एक बहुपक्षीय संस्था है, जिसके सदस्य अपने-अपने एजेंडे और प्राथमिकताओं पर काम करते हैं. इन वास्तविकताओं के आलोक में यह जरूरी है कि निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिक समानता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए डब्ल्यूटीओ की शासन संरचना में सुधार और पुनर्संतुलन के प्रयास किये जाएं. इसमें सदस्य देशों के बीच सत्ता के असमान वितरण को संबोधित करना, विकासशील देशों की आवाज और प्रतिनिधित्व को मजबूत करना और संगठन के संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना शामिल है. केवल ऐसे सुधारों के माध्यम से ही डब्ल्यूटीओ केवल कुछ चुनिंदा सदस्यों के बजाय अपने सभी सदस्यों के हितों की सेवा करने वाली एक वास्तविक बहुपक्षीय संस्था के रूप में अपने जनादेश को पूरा कर सकता है.

आज भारत समेत कई देशों के किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं. डब्ल्यूटीओ के साथ समझौतों की समीक्षा उनकी प्रमुख मांगों में से एक है. भारतीय किसान तो भारत पर डब्ल्यूटीओ से बाहर आने तक का दबाव बना रहे हैं. इसलिए भारत समेत सभी सदस्य देशों का दायित्व है कि वे एक अधिक न्यायसंगत और समावेशी वैश्विक व्यापार प्रणाली की दिशा में काम करें, जो विशेषाधिकार प्राप्त कुछ लोगों की तुलना में कई लोगों के हितों को प्राथमिकता दे. तभी विश्व व्यापार संगठन वास्तव में आपसी सम्मान और साझा लाभ के आधार पर राष्ट्रों के बीच समृद्धि और सहयोग को बढ़ावा देने के अपने वादे को पूरा कर सकता है. कृषि संबंधी समझौतों पर भारत सरकार के कड़े रुख के बाद किसानों ने राहत की सांस ली है.

(ये लेखकद्वय के निजी विचार हैं.)

'रेणु' : पहले उपन्यास से ही मच गयी थी धूम

कृष्ण प्रताप सिंह
वरिष्ठ पत्रकार
kp_faizabad@yahoo.com

जयंती विशेष

कहते हैं कि 'मैला आंचल' उपन्यास में रेणु उस अंचल के जनजीवन का बेहद सजीव व मर्मस्पर्शी चित्रण इसलिए कर पाये कि उनका उससे गुल से लिपटी हुई तितली जैसा कभी अलग न किया जा सकने वाला जुड़ाव था.

आंचलिक उपन्यासों की अप्रतिम सर्जना की बिना पर कथा सम्राट प्रेमचंद की परंपरा को नयी पहचान दिलाकर 'आजादी के बाद का प्रेमचंद' कहलाने वाले फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी के बिरले कथाकार हैं. आलोचकों द्वारा उन्हें उनके पहले उपन्यास 'मैला आंचल' के अलावा 'परती परिकथा' और 'तीसरी कसम उर्फ मारे गये गुलफाम' जैसी अनेक कृतियों के लिए सराहा जाता है, लेकिन सच यही है कि 1954 में पहली बार प्रकाशित 'मैला आंचल' ने उनको जैसी प्रतिष्ठा और ख्याति दिलायी, उनकी दूसरी कृतियों से वैसा कोई कारनामा संभव नहीं हुआ. उनकी महत्वाकांक्षी कहानी 'तीसरी कसम उर्फ मारे गये गुलफाम' पर सुप्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र ने बासु भट्टाचार्य द्वारा निर्देशित 'तीसरी कसम' जैसी फिल्म बनायी. अपने वक्त में मील के पत्थर सरीखी मानी गयी इस कालजयी फिल्म ने कहानी के पात्रों- हीरामन व हीराबाई- की अनूठी प्रेमकथा को अमर कर दिया. फिर भी रेणु का प्रतिनिधि उपन्यास 'मैला आंचल' को ही माना जाता है, जो उत्तर-पूर्वी बिहार के एक पिछड़े ग्रामीण इलाके की पृष्ठभूमि पर आधारित है.

वर्ष 1970 में इस उपन्यास की लोकप्रियता ने उन्हें 'पद्मश्री' दिलायी, पर सरकार विरोधी आंदोलनों के निर्मम दमन से चिढ़कर उन्होंने उसे 'पापश्री' करार देकर लौटा दिया. कहते हैं कि इस उपन्यास में रेणु उस अंचल के जनजीवन का बेहद सजीव व मर्मस्पर्शी चित्रण इसलिए कर पाये, क्योंकि उनका उससे गुल से लिपटी हुई तितली जैसा कभी अलग न किया जा सकने वाला जुड़ाव था. उन्हीं के शब्दों में कहें, तो मैला आंचल में फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है और कीचड़ भी है गरीबी, रोग, भुखमरी, जहालत, धर्म की आड़ में हो रहे व्याभिचार, शोषण, आडंबरों व अंधविश्वासों आदि का चित्रण भी है, क्योंकि 'मैं किसी से दामन बचाकर निकल ही नहीं पाया'. निकल भी कैसे पाते, उनका नाल जो गड़ा था वहां. वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश चौधरी ने कभी बिहार के अररिया जिले में फारबिसगंज के पास स्थित उनके गांव औराही हिंगना से लौटकर लिखा था- रेणु जी के बड़े बेटे पदम पराग राय 'वेणु' फारबिसगंज से विधायक हो गये उनकी जीवनसंगिनी लतिका रेणु नहीं रहीं औराही हिंगना में और भी बहुत कुछ बदल गया है लेकिन भले ही गांव बदल जाये, वक्त बदल जाये, हालात बदल जायें, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलने वाली-उस गांव और उस इलाके के परिवेश में फणीश्वरनाथ रेणु की मौजूदगी.

फणीश्वर नाथ 'रेणु'
(04 मार्च, 1921 – 11 अप्रैल, 1977)

चार मार्च, 1921 को औराही हिंगना में जन्म और 11 अप्रैल, 1977 को पटना में निधन के बीच के कोई 56 वर्षों के जीवन में स्वतंत्रता संग्राम, साहित्य, व राजनीति के क्षेत्र में उनकी सक्रियताओं के अनेक आयाम रहे हैं. साहित्य सेवा की ओर तो उनका गंभीर झुकाव 1952-53 में हुआ, जब वे बीमार होकर रुग्णशय्या पर थे. वर्ष

1942 में अभी उनकी इंटर की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी कि वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे और दो वर्ष जेल में काटने के बाद 1944 में रिहा हुए थे. साल 1950 में उन्होंने नेपाल में जनतंत्र की स्थापना के लिए चलाये जा रहे क्रांतिकारी आंदोलन में भी हिस्सा लिया था. बाद में पटना विश्वविद्यालय के छात्रों की संघर्ष समिति और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में भी सक्रिय रहे थे. साल 1941 में विवाह के बाद वे एक बेटी के बाप बने ही थे कि उनकी पत्नी रेखा देवी को लकवा मार गया और असहाय होकर वे अपने मायके में रहने लगीं. उन्होंने 1951 में पद्मा देवी से विवाह किया. जब वे गंभीर रूप से बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हुए, तो वहां काम कर रहीं लतिका राय चौधरी की सेवा से अभिभूत होकर उनसे प्यार कर बैठे. अगले ही बरस 1952 में उन्होंने लतिका को भी पत्नी बना लिया.

प्रसंगवश, रेणु हिंदी की उन गिनी-चुनी शख्सियतों में से भी एक हैं, जो स्वतंत्रता के बाद सक्रिय राजनीति का हिस्सा भी रहे. नामवर सिंह ने उत्तर प्रदेश में साठ के दशक में उत्तर प्रदेश की चकिया-चंदौली लोकसभा सीट से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था, तो रेणु ने 1972 में बिहार की फारबिसगंज विधानसभा सीट से नाव चुनाव चिह्न पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा, हालांकि वे सोशलिस्ट पार्टी की राजनीति भी करते रहे थे. विडंबना यह रही कि चुनावी राजनीति उन्हें कतई रास नहीं आयी. फारबिसगंज के मतदाताओं ने उन्हें तीसरे पायदान पर धकेल दिया, जिसके बाद वे सक्रिय राजनीति से अलग होने को मजबूर हो गये और आखिरी सांस तक साहित्य की साधना करते रहे.

देश दुनिया

नकद हस्तांतरण का सकारात्मक प्रभाव

दशकों से अंतरराष्ट्रीय समुदाय अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने की चुनौती से जूझ रहा है. कुछ प्रगति के बावजूद, हम अभी भी इस लक्ष्य से बहुत दूर हैं. अनुमानित 70 करोड़ लोग अभी भी प्रतिदिन 2.15 डॉलर से कम पर जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. हालांकि, पिछले दशकों के उलट, अब हमारे पास एक समाधान है जिससे हम अत्यधिक गरीबी के अंत में तेजी ला सकते हैं. और वह है सबसे गरीब परिवारों को सीधे नकद हस्तांतरण. यद्यपि यह अवधारणा नयी नहीं है. विशेषकर आपात स्थिति में, नकद सहायता प्रभावी साबित हुई है. कोविड-19 महामारी के दौरान, दुनिया में हर छह लोगों में से एक को कुछ नकद सहायता प्राप्त हुई. प्रत्यक्ष हस्तांतरण व्यक्ति को अपने जीवन पर नियंत्रण रखने और अपने परिवार की भलाई के लिए निवेश करने में सहायता करने का शक्तिशाली उपकरण है. यही कारण है कि उच्च और मध्यम आय वाले देश अपने सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क के केंद्र में नकद सहायता को तेजी से शामिल कर रहे हैं. नकद हस्तांतरण के सकारात्मक प्रभाव को लेकर कई लिखित प्रमाण मौजूद हैं और यह निर्विवाद है. तीन सौ से अधिक परीक्षणों से पता चलता है कि हस्तांतरण आय को दोगुने से अधिक बढ़ा सकता है, स्कूल नामांकन और उद्यमिता में वृद्धि कर सकता है, भूखे पेट रहने, बीमारी और अवसाद में कमी ला सकता है तथा घरेलू हिंसा को कम कर सकता है. यह भी महत्वपूर्ण है कि इससे न तो काम के घंटे कम होते हैं और न ही तंबाकू व शराब जैसी वस्तुओं पर खर्च बढ़ता है. इससे भी बढ़कर, प्रत्येक एक डॉलर के नकद हस्तांतरण का स्थानीय अर्थव्यवस्था में लगभग 2.50 डॉलर का प्रभाव पड़ता है. पहली बार, दुनिया के पास सफल होने के लिए पैसा और तरीका दोनों है. हमें किसकी प्रतीक्षा है?

-सिना लावसन व रोरी स्टेवार्ट

बोधि वृक्ष

सभी के लिए अच्छा बनें

हमें बचपन से सीख दी जाती है कि अपना चरित्र और व्यवहार ऐसा रखो कि सभी का सम्मान एवं प्यार मिले. इसलिए, जब कोई बच्चा शरारत करता है, तो अमूमन लोगों से यही सुनने को मिलता है कि इसके मां-बाप ने शिष्टाचार नहीं सिखाया होगा, तभी ऐसा कर रहा है. इससे इतना तो सिद्ध होता है कि हमारे आचरण या व्यवहार से हमारे संस्कारों का दर्शन होता है. इसलिए, यदि हम अपेक्षा रखते हैं कि हमारे साथ हमेशा सभी अच्छाई से पेश आएं, तो हमें भी सभी के साथ अच्छाई से पेश आने का संस्कार धारण करना होगा. कई लोग अक्सर दूसरों के मन में अपनी छवि बनाने के ख्याल से सतही स्तर पर ही अच्छा बनने का ढोंग करते हैं और अपनी इस चतुराई या जालसाजी में कुछ हद तक सफल भी हो जाते हैं. उन्हें इस बात का जरा भी ज्ञान नहीं होता कि कर्म का सार्वभौमिक कानून सबसे सूक्ष्म स्तर पर संचालित होता है. अतः आज नहीं तो कल उन्हें अपनी जालसाजी का फल उसी रूप में वापस मिलेगा. इसलिए समझदारी इसी में है कि हम वास्तविक रूप से सभी के प्रति अपने मन में अच्छी भावनाएं रखें. याद रखें, झूठ का मुखौटा आज नहीं तो कल सत्यता और शुद्धता के सामने फीका पड़ जायेगा. इसलिए आप जो हैं, जैसे भी हैं, अंदर-बाहर समान ही रहें. सामान्यतः हमारे अंदर अपने करीबी एवं मित्रों के प्रति प्यार एवं शुद्ध भावना रखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है. परंतु उन लोगों का क्या जो हमारे परिवार और दोस्तों के इस वृत्त के बाहर हैं? बहुधा उन लोगों के प्रति हमारी भावनाएं व व्यवहार हमें उनसे हुए अनुभव के आधार पर बदलती रहती है. नैतिक रूप से यह गलत है, किंतु हमारी अपनी व्यक्तिगत धारणा के वशीभूत हम दोहरा मापदंड अपने अंदर बना लेते हैं. हम एक ही गलती के लिए किसी एक के प्रति सहानुभूति और दूसरे के प्रति क्रोध व घृणा दिखाते हैं. यदि हम एक छोटे से सकारात्मक प्रयास के साथ, गलती करने वाले उस व्यक्ति की तरफ भी सहानुभूति दिखाकर उसे क्षमा कर दें, तो कितना अच्छा होगा?

-ब्रह्माकुमार निकुंज जी

कुछ अलग

आवाज दो हम एक हैं

आलोक पुराणिक
व्यंग्यकार
puranika@gmail.com

पुरानी फिल्मों में पिता परेशान रहता था कि उसकी बेटी को लुच्चे बहका कर कहीं ले न जायें. पिताजी बेटी को दूर मामा के यहां भेज देते थे. अब सीनियर नेता परेशान रहते हैं कि उनके विधायकों को विरोधी पार्टी वाले बहका कर न ले जायें. तो सीनियर नेता अपने विधायकों को किसी गेस्ट हाउस में भेज देते हैं. बच्चियों को मेच्योर्ड बनायें कि बहकें नहीं, लुच्चे तो अपने काम पर लगे ही रहेंगे. क्या यह बात विधायकों और उनके नेताओं से भी कही जा सकती है? कर्नाटक के कांग्रेस नेता डी शिव कुमार हिमाचल आये संकट सुलझाने के लिए. पर क्या संकट सुलझ गया! वो ही संकट रोजगार देता है, जो सुलझता नहीं है. राजनीति में संतुष्ट बंदा तलाशना मुश्किल है. जो सड़क पर है, उसे विधायक बनना है. जो विधायक है, उसे मंत्री बनना है. जो मंत्री है, उसे और अच्छे डिपार्टमेंट का मंत्री बनना है. जो अच्छे डिपार्टमेंट का मंत्री है, उसे मुख्यमंत्री बनना है. कई मुख्यमंत्री इसलिए भी परेशान हैं कि वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं हैं.

आफत यह है कि कितना असंतोष कोई किसी का निपटा सकता है! डी शिव कुमार पहले अपने राज्य कर्नाटक के असंतोष को देखें, फिर हिमाचल के असंतोष को देखें. असंतोष को ना देखो, तो कुरसी चली जाती है, यह बात महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे से बेहतर कौन जान सकता है! उनसे बेहतर हर बात संजय राउत जानते हैं. पर चिंता की बात उस दिन होगी, जब वो भी ठाकरे को छोड़कर उधर से इधर आ जायेंगे. इधर से उधर और उधर से इधर इस कदर नार्मल हो गया है कि अब तो समझना मुश्किल होता है कि कोई दरअसल हैं कहां. राज्य सभा चुनाव में हिमाचल में उधर वाले इधर वालों के ले गये. कर्नाटक में उधर वाले इधर वालों को ले गये. आवाज दो हम एक हैं.

पाकिस्तान में नवाज शरीफ ने अपनी बेटी मरियम नवाज को पंजाब का सीएम बनाया. हिंद-पाक एकता का विकट माहौल है. सब तरफ एक से ही हैं. हम एक से ही हैं, आवाज दें या नहीं. क्रिकेटर गौतम गंभीर ने कह दिया कि पालिटिक्स नहीं करनी, क्रिकेट पर ध्यान देना है. क्रिकेट में आईपीएल में इधर से उधर और उधर से इधर जाने पर बेइज्जती खराब नहीं होती, वहां खुला बाजार है. कोई इस साल गुजरात की टीम में खेल सकता है और अगले साल कोलकाता की टीम में. इधर से उधर बाजार के जरिये हो, मामला पारदर्शी रहता है. आइपीएल टाइप नीलामी की खुली व्यवस्था पालिटिक्स में भी आनी चाहिए. आ जायेगी, जल्दी आ जायेगी. फिर पालिटिक्स को भी उतना ही सीरियसली लिया जायेगा, जितना सीरियसली आईपीएल मैचों को लिया जाता है, जिसके रिकार्डों की गिनती आफिशियल क्रिकेट में होती ही नहीं है.

आपके पत्र

गगनयान से उम्मीद

गगनयान मानव सहित अंतरिक्ष मिशन है, जिसके अंतर्गत चार अंतरिक्ष यात्रियों को तीन दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजने की योजना है. इस मिशन के सफल होते ही भारत अंतरिक्ष में मानव को भेजने वाला चौथा देश बन जायेगा. अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत नित नये कीर्तिमान स्थापित कर रहा है. पूर्व में भी मंगलयान, चंद्रयान, आदित्य एल1 जैसे अंतरिक्ष मिशनों ने भारतीय प्रतिभा का लोहा दुनिया को मनवाया है, गगनयान भी सीधे तौर पर भारत और उसके विकास को बल मिलेगा.

निखिल रस्तोगी, लखनऊ

पेट्रोलियम वाहनों का विकल्प

वाहनों एवं औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण को बढ़ाने का प्रमुख कारण बन चुका है. प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए डीजल और पेट्रोल वाहन के स्थान पर सरकार को हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन एवं हाइड्रोजन ऊर्जा को प्रोत्साहित करना होगा. इन वाहनों के प्रयोग से प्रदूषण के स्तर में कमी आयेगी. अब समय आ चुका है कि डीजल और पेट्रोल के वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए और केवल हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक वाहन एवं हाइड्रोजन ऊर्जा से चलने वाले वाहनों को अनुमति प्रदान की जाए.

हिमांशु शेखर, गया

https://t.me/AllNewsPaperPaid

• अनंत ऊर्जा | स्वामी मुकुंदानंद, आध्यात्मिक गुरु और लेखक

मनुष्य की चेतना का स्तर बढ़ने से ही मानवता बदलेगी

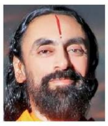

भारत के पवित्र ग्रंथों और प्राचीन संस्कृति ने हमेशा अपने नागरिकों को मानव गतिविधियों के हर क्षेत्र में 'सेवा परमो धर्म' को आत्मसात और लागू करने के लिए प्रेरित किया है। जब हम उच्च चेतना की ऐसी अवस्था में जीवन जीते हैं तो हमारे इरादे पवित्रता और हमारे कार्य उत्कृष्टता से भर जाते हैं, जिससे हमारे दैनिक अस्तित्व में शुभता आती है। तभी हमारे पास संगठनों को बदलने, समुदायों का उत्थान करने, देशों का विकास करने और दुनिया में क्रांति लाने की वास्तविक शक्ति होगी! मानवों का नेतृत्व करने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर मानवता का होना जरूरी है।

लगातार बदलते हुए इस विश्व में गंभीर मुद्दे हमेशा समाधान की मांग करते रहते हैं। शासन के प्रमुख निकाय और विश्व मंच समाधान के लिए बहुत अच्छी तरह से चर्चा और बहस कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से, हर कोई सबसे महत्वपूर्ण पहलू को नजरअंदाज कर देता है, जिसका स्थायी और दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है। यह पहलू है- इस ग्रह पर रहने वाले 8.1 अरब लोगों की मानवीय चेतना के स्तर को बढ़ाना। यही वह चीज है, जो वास्तव में मानवता को बदलेगी और एक सामंजस्यपूर्ण विश्व का निर्माण करेगी।

उच्चतर चेतना की ओर बढ़ने का व्यावहारिक रूप से क्या मतलब है? इसका तात्पर्य है कि हम अपने इरादों और ध्यान को स्वार्थी रवैए से हटाकर एक उच्च उद्देश्य की पूर्ति की ओर ले जाएं। आइए हम भगवद्गीता से प्रेरणा लें, जिसमें श्रीकृष्ण ने अर्जुन को क्या करें और क्या न करें, इस बारे में निर्देश नहीं दिया, बल्कि अर्जुन को उच्च मनोस्थिति की ओर प्रेरित किया। गीता का उपदेश सुनने से पहले अर्जुन के लिए कौरवों के खिलाफ युद्ध अपने राज्य, आत्म-गौरव और प्रतिष्ठा को वापस पाने का माध्यम था। बाद में इन्ही स्वार्थी विचारों के कारण अर्जुन को युद्ध में अपने रिश्तेदारों की मृत्यु और पारिवारिक-सामाजिक संबंधों से अलगाव की आशंका उत्पन्न हुई। इस विलाप ने उनकी विवेकशक्ति को धूमिल कर दिया। किंतु श्रीकृष्ण ने कुशलतापूर्वक अर्जुन को सर्वोच्च ज्ञान प्रदान करके इस विकट स्थिति को बदल दिया। परिणामतः, अर्जुन ने वीरता से युद्ध किया। अर्जुन की मानसिकता 'मैं', 'मुझे' या 'मेरे लिए' पर आधारित नहीं रह गई थी, बल्कि कर्तव्यपालन, धर्मपरायणता और उच्च उद्देश्य की सेवा की भावना से परिपक्व हो गई थी।

वास्तविक जीवन की एक उल्लेखनीय कहानी है, जो इस सच्चाई की गवाही देती है। यह घटना 26 नवंबर 2008 की है, जब राक्षसी आतंकवादी मुंबई की ताज पैलेस होटल में घुस गए और देखते ही देखते निर्दोष अतिथियों को मारना शुरू कर दिया। उस समय उस प्रतिष्ठित भव्य होटल में लगभग 1100 अतिथिगण और होटल के 600 कर्मचारी मौजूद थे। आपदा अभूतपूर्व थी। किसी भी कर्मचारी को ऐसी जानलेवा आपात-स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया था। फिर भी पूरे घटनाक्रम के दौरान वे सभी स्वेच्छा से होटल के अंदर रहे एवं मेहमानों को सुरक्षा प्रदान करने के प्रयासों में अपनी जान जोखिम में डाल दी। होटल परिसर के बारे में अपने ज्ञान और इंटरकॉम आदि जैसे संसाधनों के साथ उन्होंने अधिक से अधिक मेहमानों को सुरक्षित बाहर निकलने में सहायता की। उस अग्निपरीक्षा के अंत में लगभग 100 लोगों की मृत्यु हो गई, जिनमें से 69 कर्मचारी थे। ये वे कर्मचारी थे जिन पर उनके परिजन आश्रित थे। इतने बड़े संकट के समय भी अप्रशिक्षित कर्मचारियों ने ऐसे वीरतापूर्ण गुणों का प्रदर्शन किया, जिसने लग्जरी होटल के मालिक रतन टाटा को भी चकित कर दिया। यह इन सरल और विनयी मनुष्यों के चरित्र की असाधारण ताकत के बारे में बहुत कुछ बताता है, जिनका अंतःकरण निःस्वार्थ सेवा और बलिदान जैसे ऊंचे आदर्शों से सुसज्जित था।

यह दिल को छू लेने वाली वास्तविक गाथा दर्शाती है कि उच्च चेतना की स्थिति और उदाहरणीय नेतृत्व केवल सत्ता के पदों पर बैठे लोगों तक ही सीमित नहीं है। हममें से प्रत्येक के लिए जीवन में व्यक्तिगत या व्यावसायिक स्थितियों में एक सदाचारी जीवन जीने का विकल्प उपलब्ध है। हम एक बड़े भाई-बहन, मार्गदर्शक माता-पिता, अपने समुदाय में किसी सामाजिक उद्देश्य के लिए काम करने वाले व्यक्ति या किसी संगठन के प्रमुख आदि की भूमिका में हो सकते हैं। जीवन में किसी न किसी मोड़ पर, हमारी देखरेख में अन्य लोग होते हैं। दैनिक जीवन में उच्च चेतना के साथ काम करने का तात्पर्य यह है कि हम अपनी देखभाल में रहने वाले लोगों के लिए वास्तविक सरोकार रखें एवं उनके जीवन में मूल्य संवर्धित करें। आखिर, मानवों का नेतृत्व करने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर मानवता होना जरूरी है।

इस ग्रह पर रहने वाले 8.1 अरब लोगों की मानवीय चेतना के स्तर को बढ़ाने से ही मानवता बदलेगी और एक सामंजस्यपूर्ण विश्व का निर्माण हो सकेगा।

यूट्यूबः SwamiMukundanandaHindi/channels
फेसबुक : Hindi.Swami.Mukundananda
इंस्टाग्राम : swami.mukundananda.hindi

• बेस्ट सेलर से सबक | रॉबिन शर्मा

अगर दिन की शुरुआत भली तो सब भला...

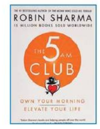

रॉबिन शर्मा की किताब 'द 5 एएम क्लब' उत्पादकता और रचनात्मकता बढ़ाने के लिए सुबह जल्दी उठने के महत्व पर प्रकाश डालती है। लेखक हमें सुबह की दिनचर्या बनाने के लिए एक रूपरेखा देते हैं, जो व्यक्तिगत विकास और सफलता के लिए कारगर है।

जाना-पहचाना है ना?

आप अलार्म की आवाज से उठते हैं, उसे बंद करते हैं, करवट लेकर फिर सो जाते हैं। अलार्म फिर बजता है, आप सुस्ती से उठते हैं और जल्दी से तैयार हो जाते हैं। जाना-पहचाना लगता है ना? क्योंकि एक औसत व्यक्ति यही करता है। सुबह जागो और पूरे दिन को अपने ऊपर हावी हो जाने दो।

टॉप 5% में आना है तो

लेकिन क्या आप औसत व्यक्ति बनना चाहते हैं? याद रखें कि अगर आप टॉप 5% लोगों की तरह बनना चाहते हैं तो आपको शेष 95% लोगों की तरह व्यवहार करना बंद करना होगा। अपने दिन की शुरुआत एक लक्ष्य और ऊर्जा के साथ करने का भी एक तरीका है, एक पैटर्न, जो आपको अधिक हासिल करने में मदद करेगा।

डिस्ट्रैक्शंस नहीं, फोकस

हमारे दिमाग में सीमित मात्रा में बैंडविड्थ होती है। जब हम अपने दिन को सोशल मीडिया, अपने आस-पास के लोगों के साथ बातचीत, टीवी आदि से लाद देते हैं, तो हम इस बैंडविड्थ को इस हद तक भर देते हैं कि दिन खत्म होने से पहले हम उसमें और कुछ नहीं ग्रहण कर सकते। लेकिन अगर आप सुबह 5 बजे उठते हैं, तो आप पाएंगे कि आप इन डिस्ट्रैक्शंस के बिना ही चीजों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।

एक प्रभावी मॉर्निंग रूटीन

अगर आप अपने जीवन को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत एक प्रभावी मॉर्निंग रूटीन से ही होगी। कहावत है कि अंत भला तो सब भला, जबकि सच्चाई यह है कि शुरुआत अच्छी हो तो ही सब अच्छा हो सकता है। जो मार्निंग-पर्सन नहीं है, वे भी कोशिश कर सकते हैं।

20/20/20 रूल का पालन

20/20/20 रूल का पालन करें, यानी तीन मूल्यवान गतिविधियों को नियमित 20-20 मिनट का समय दें। ये हैं कसरत- जिसका सरोकार शरीर की तंदुरुस्ती से है। ध्यान- जिसका सरोकार मन की शांति से है। और सीखना- जिसका सरोकार जीवन की बेहतरी से है। जो भी सफलतम व्यक्ति रहे हैं, उनमें सीखने की प्रबल भावना थी।

सुबह के समय की शांति

सुबह के समय हमारे मस्तिष्क की केमिस्ट्री थोड़ी अलग होती है। मस्तिष्क का प्री-फ्रंटल कॉर्टिक्स, या वह हिस्सा जो आपको बार-बार चिंता करने या चीजों का विश्लेषण करने पर मजबूर करता है, भोर के शांतिपूर्ण घंटों में कुछ समय के लिए बंद हो जाता है। यह भी देखा गया है कि सुबह के समय की शांति डोपामाइन और सेरोटोनिन को बढ़ाती है, जिससे आपको ऊर्जावान और शांत महसूस करने में मदद मिलती है।

मन के अलावा तीन और चीजें हैं...

सफलता के बारे में एक और मूल्यवान सबक यह है कि केवल मानसिकता पर ही ध्यान केंद्रित न करें। ये सच है कि आशावादी विचार मदद करते हैं, लेकिन संतुलन खोजने की कोशिश करें और जानें कि आपके पास तीन और आंतरिक साम्राज्य हैं। आपके पास मन के अलावा स्वास्थ्य, दिल और आत्मा भी हैं।

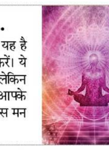

• रिसर्च आधारित पॉजिटिविटी- मेमोरी एडिटिंग का प्रयोग नई बहस को जन्म देगा

यादों की प्रयोगशाला : ध्यान करने वालों के मस्तिष्क अच्छी-बुरी यादों से तटस्थ रहते हैं

डॉ. रितु पांडेय शर्मा | लेखिका, माइंडफुलनेस विशेषज्ञ
reetupost@yahoo.com

हम सब कड़वीं यादें भुला देना चाहते हैं। क्योंकि ये दुखद स्मृतियां, बाहरी दुनिया से एक ट्रिगर मिलते ही हमें कई बार विचलित कर जाती हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि दिमाग में स्थित हिप्पोकैम्पस व कोर्टेक्स अनुभवों को याद रखने के लिए जिम्मेवार होता है। उधर अच्छी बुरी यादों को एमिग्डेला रजिस्टर करता है। मस्तिष्क में जब कोई मेमोरी रिकॉर्ड होती है तो इन्द्रियों से प्राप्त संवेदनाएं इसमें समाहित होती हैं। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने मेमोरी एनकोडिंग के समय हिप्पोकैम्पस के क्षेत्र में उच्च आवृति की रिपल्स की खोज की है। कोई घटना दोबारा याद करने पर इन रिपल्स की आवृत्ति बढ़ जाती है। यानी अच्छी याददश्त होने में रिपल्स की भूमिका महत्वपूर्ण है। किसी घटना विशेष की यादें किस जगह सीमित होती हैं ये कह पाना मुश्किल है। पर यादों की इस प्रयोगशाला में बराबर काम चलता रहता है। किसी विशेष समय में विशिष्ट स्मृति से जुड़े न्यूरॉन जब सक्रिय होते हैं तो न्यूरोसाइंटिस्ट उन्हें पहचानकर इस समय होने वाली मेमोरी हार्डेनिंग व बदलाव में रुकावट डालकर इस प्रक्रिया को स्थाई होने से रोक देते हैं। कई प्राणियों में इस तकनीक से बनी ताजा यादें मिटाई जा सकीं है लेकिन मानव के संदर्भ में मेमोरी एडिटिंग का प्रयोग नई बहस को जन्म दे सकता है। किसी को याद करने की घटना क्वांटम एंटेंगलमेंट से समझाई जा सकती है। वैसे प्रकृति इस जन्म की सभी यादों को मृत्यु के साथ ही मिटा देती है और दूसरी तरफ ध्यान की अवस्था का अनुभव जानने वालों के मस्तिष्क अच्छी-बुरी यादों को याद करने पर उससे जुड़ी संवेदना को महसूस नहीं करते बल्कि निष्क्रिय होकर एक फिल्म की तरह देखते हैं।

• देश-दुनिया की सकारात्मक परम्पराएं

कोस्टा-रिका की संस्कृति बना एक पॉजिटिव शब्द

• अगर आप मध्य अमेरिकी देश कोस्टा-रिका जाएं, तो मुमकिन है कि जगह-जगह पूरा-वीदा (pura vida) शब्द लिखा दिख जाए। यह वहां की संस्कृति में इतना रचा-बसा है कि साल 2023 में इसे ग्लोबल स्पेनिश डिक्शनरी में भी शामिल किया गया।

• पूरा वीदा का शाब्दिक अर्थ शुद्ध जीवन है। लेकिन कोस्टा-रिका में इसे सकारात्मकता के साथ जीवन जीने का एक तरीका माना गया है। अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ बेहतर रिश्तों के लिए भी यह शब्द इस्तेमाल होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोस्टा-रिका में भाषा विज्ञान के प्रोफेसर विक्टर सेंचेज के मुताबिक यह देश के पर्यटन ब्रांड का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। 1969 की फिल्म ईजी राइडर ने इस शब्द को नई लोकप्रियता दी थी।

सार्वजनिक जगहों के साथ-साथ एयरपोर्ट्स, पर्यटन स्थलों पर भी पूरा-वीदा लिखा हुआ मिल जाएगा।

© The New York Times

दैनिक भास्कर — अब आप NYT के सभी आर्टिकल DB एप पर हर सोमवार पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें डीबी एप।

दैनिक भास्कर से विशेष अनुबंध के तहत

टैक्नोलॉजी

माइक्रोसॉफ्ट की वर्ड फाइल के डिफाल्ट टाइप फेस में बदलाव

विक्टर माथेर

जब आप कोई किताब, ट्रैफिक साइन, होर्डिंग या यह खबर पढ़ते हैं तो आप अक्षरों पर कितना गौर करते हैं? यदि आप अधिकतर लोगों जैसे हैं तो आपका जवाब नहीं होगा। अगर आप वाकई ध्यान नहीं देते हैं तब भी आप महसूस करेंगे कि कोई बारीक बदलाव हुआ है। पिछले कुछ सप्ताहों में कई लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड प्रोग्राम्स पर काम करते हुए ऐसा महसूस किया है।

17 साल तक वर्ड फाइल का डिफाल्ट टाइप फेस केलिब्रि रहा है। अचानक कई यूजरों ने उन्हें एप्टॉस नामक नए टाइप फेस पर टाइपिंग करते हुए पाया है। यह परिवर्तन पावर पाइंट, आउटलुक और एक्सेल के लुक को भी प्रभावित कर रहा है। कंपनी के डिजाइन और रिसर्च वाइस प्रेसीडेंट जोन फ्रीडमैन कहते हैं, हम कुछ नया और फ्रेश पेश करना चाहते थे। यह आधुनिक दौर की कंप्यूटिंग को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। (तकनीकी तौर पर एप्टॉस और केलिब्रि टाइप फेस हैं जबकि फॉन्ट इटैलिक्स या बोल्डफेस जैसे किसी खास फेस या साइज के लिए उपयोग होता है। लेकिन, अक्सर फॉन्ट का उपयोग टाइपफेस के समानार्थी के बतौर होता है।)।

टाइपफेस की दुनिया में सेरिफ (अक्षरों के ऊपर और अंत में जुड़ी छोटी लाइन या नोक) और सेरिफ विहीन अक्षरों के बीच बड़ा अंतर है। सेरिफ विहीन अक्षर सहज और सामान्य लगते हैं। कैलिब्रि के समान एप्टॉस भी सेरिफ रहित टाइप फेस है। लेकिन, वह थोड़ा अलग है। फ्रीडमैन का कहना है, प्रिंटिंग प्रेसों के शुरुआती दौर में लगभग सभी टाइप फेस सेरिफ थे। बिना सेरिफ के अक्षर होर्डिंग, बिल बोर्ड के लिए रहते थे। वे बड़े और बोल्ड लेटर थे। उन्हें बेडौल, बेतुका (ग्रोटेस्क) कहा जाता था। उस समय सेरिफ रहित अक्षरों का इस्तेमाल बहुत कम एक या दो शब्दों या एक सेंटेंस में ही होता था। एप्टॉस का क्लासिफिकेशन निओ ग्रोटेस्क फॉन्ट के रूप में किया जाएगा। फ्रीडमैन बताते हैं, निओ ग्रोटेस्क की शुरुआत बीसवी संदी के मध्य में हुई थी। डिजाइनरों ने सेरिफ रहित फॉन्ट का उपयोग शुरू किया था। इस दौर में हेल्वेटिका और एरियल का जन्म हुआ।

© The New York Times

बिजनेस

बाजार में चीन के सस्ते वाहनों की बाढ़ रोकने के लिए सरकार कई जरूरी कदम उठाएगी

जिम टैंकरस्ले

अमेरिका ने चीनी इलेक्ट्रिक कारों को सुरक्षा के लिए खतरा बताया; बाइडेन ने टेक्नोलॉजी की जांच के आदेश दिए

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इंटरनेट से जुड़ी चीनी कारों को अमेरिका के ऑटो मार्केट में आने से रोकने के आदेश दिए हैं। इनमें इलेक्ट्रिक वाहन भी शामिल हैं। बाइडेन का कहना है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं क्योंकि उनके ऑपरेटिंग सिस्टम चीन को अहम जानकारी भेज सकते हैं। कॉमर्स विभाग ने सुरक्षा के खतरों की जांच शुरू कर दी है। इससे चीनी वाहनों पर नए नियम या प्रतिबंध लागू हो सकते हैं।

बाइडेन सरकार के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह पहला कदम है। अमेरिकी बाजारों में चीन निर्मित या चीनी कंपनियों द्वारा मेक्सिको जैसे देशों में असेम्बल सस्ते चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों की बाढ़ रोकने के लिए कुछ अन्य फैसले लिए जाएंगे। चीनी वाहनों के कारण घरेलू ऑटो निर्माता कंपनियां कारोबार से बाहर हो रही हैं। चीन ने पिछले कुछ वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ाया है। इससे अमेरिकी ऑटो कंपनियों को देश और विदेश में बढ़ावा देने की बाइडेन की औद्योगिक नीति से सीधा टकराव हो रहा है। चीन की कुछ छोटी कारों का मूल्य 9 लाख रु. है। यह अमेरिकी इलेक्ट्रिक कारों के मुकाबले बहुत कम है।

गुरुवार को बाइडेन ने एक बयान में कहा, चीन अवैध और अन्य तरीके अपनाकर ऑटो मार्केट पर दबदबा कायम करना चाहता है। चीन की नीतियों से हमारे मार्केट में उसके वाहनों की भीड़ हो जाएगी। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सरकार ने फैसला करने से पहले डेट्रॉयट में ऑटो कंपनियों, वर्करों की यूनियनों और ईवी बनाने वाली बड़ी कंपनी टेस्ला से चर्चा की थी। अभी हाल में टेस्ला को पीछे छोड़कर चीनी कंपनी बीवाईडी इलेक्ट्रिक कार बेचने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है।

नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन के संभावित प्रतिद्वंद्वी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हमेशा बाइडेन की आलोचना करते हुए कहते हैं कि राष्ट्रपति ने ऑटो कंपनियों को इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए मजबूर किया है। वैसे, बाइडेन और ट्रम्प स्वयं को चीन के खिलाफ सख्त रूख अपनाने वाला दिखाते हैं। गुरुवार के फैसले से चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर तत्काल रोक नहीं लग रही है। यों भी चीनी ईवी पर भारी टैक्स लगता है और वे अब तक अमेरिकी बाजार में घुसपैठ नहीं कर पाई हैं।

चीनी सॉफ्टवेयर से अमेरिकियों की निगरानी करने का खतरा

अमेरिकी अधिकारियों का कहना है, चीन निर्मित ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर पता लगा सकता है कि अमेरिकी कहां जाते हैं। अपने वाहनों की चार्जिंग कहां कराते हैं या वे सड़कों पर कौन सा म्यूजिक और पॉडकास्ट सुनते हैं। उन्होंने जिक्र किया है, चीनी अधिकारी चीन में वाहन बेचने वाली अमेरिकी ऑटो कंपनियों को अपने वाहनों में चीनी सॉफ्टवेयर लगाने के लिए विवश करते हैं। अमेरिकी कंपनियों ने बाइडेन प्रशासन को चीन में कारोबार के दौरान आने वाली दिक्कतों की जानकारी दी है। इनमें चीनी सॉफ्टवेयर लगाने का मामला भी शामिल है।

चीन के हेफेई प्रांत के नियो में एक फैक्टरी में इलेक्ट्रिक कारें तैयार हो रही हैं।

25% टैरिफ लगाने की संभावना

राष्ट्रपति की नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की प्रमुख लाएल ब्रेनार्ड का कहना है, चीन विदेशी बाजारों में अपनी कारों और अन्य वाहनों की जमकर सप्लाई कर रहा है। इनमें से कई वाहन अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में लगातार जानकारी जुटा सकते हैं। ड्राइवर के स्मार्टफोन या पास चल रही कारों के माध्यम से सूचनाएं हासिल की जा सकती हैं। अमेरिकी सरकार चीनी वाहनों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगा सकती है।

© The New York Times

दस साल, 82 हजार करोड़ रु. खर्च, फिर भी एपल की इलेक्ट्रिक कार स्टार्ट नहीं हो पाई

विश्लेषण

कार के स्वरूप पर अंदरूनी मतभेदों के कारण भी प्रोजेक्ट ठप हुआ

ब्रायन चेन, ट्रिप मिकल

पिछले दस साल से कंपनी के सीक्रेट कार प्रोजेक्ट पर काम कर रहे एपल के कई कर्मचारियों ने इसका नाम टाइटैनिक डिजास्टर रखा था। वैसे, प्रोजेक्ट का कोड नेम टाइटन था। वे जानते थे कि प्रोजेक्ट नाकाम हो जाएगा। कार प्रोजेक्ट में कई बार बदलाव हुए और इस बीच सैकड़ों कर्मचारी निकाले गए। कार के स्वरूप पर कंपनी के बड़े अधिकारियों की अलग-अलग राय थी। इसलिए टेस्ला से मुकाबला करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में शुरुआत के बाद उसे गूगल की वायमो सेल्फ ड्राइविंग कार जैसा बनाया गया।

प्रोजेक्ट पर काम कर चुके कुछ लोगों ने बताया, पिछले मंगलवार को कंपनी के बड़े अधिकारियों ने अंदरूनी तौर पर कार प्रोजेक्ट की मौत का ऐलान किया। टीम के कई सदस्यों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया काम सौंपा गया है। कार प्रोजेक्ट पर एपल ने 82 हजार करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। कार प्रोजेक्ट का अंत इस बात का प्रमाण है कि 2011 में स्टीव जॉब्स की मौत के बाद एपल को नए प्रोडक्ट बनाने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। दरअसल, ऑटोनोमस ड्राइविंग फीचर्स की कार के सॉफ्टवेयर और अल्गोरिदम को बनाना बहुत मुश्किल साबित हुआ। प्रोजेक्ट बंद होने के समय टेस्ला जैसी कार बनाने पर काम चल रहा था। एपल ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इंकार कर दिया है।

एपल ने जब 2014 में कार प्रोजेक्ट लॉन्च किया तब निवेशक, इंजीनियर और कंपनियां सेल्फ ड्राइविंग कारों के आइडिया के पीछे भाग रहे थे। एपल भी पीछे नहीं रहना चाहती थी। उस समय कंपनी ने एपल वॉच पर काम पूरा कर लिया था। कई इंजीनियर कुछ नया करने के लिए बेचैन थे। एपल के सीईओ टिम कुक ने इंजीनियरों को टेस्ला में जाने से रोकने के लिए प्रोजेक्ट मंजूर कर दिया। कंपनी ने टेस्ला खरीदने के संबंध में एलन मस्क से कुछ बातचीत की थी। लेकिन अंत में फैसला हुआ कि कोई अन्य कंपनी खरीदने की बजाय अपनी कार बनाना ज्यादा ठीक है। एपल की कार टीम में नासा में काम कर चुके और पोर्शे की रेसिंग कार डेवलप करने वाले इंजीनियर शामिल थे। कार प्रोजेक्ट की टीम ने कई नई टेक्नोलॉजी डेवलप की थी। इसमें मोड़ पर दिशा बताने वाली विंड शील्ड और सनरूफ शामिल है। सूर्य की गर्मी को कम करने के लिए सनरूफ को पॉलीमर से बनाया गया।

82 लाख रु.होता कार का मूल्य

प्रोजेक्ट से जुड़े छह कर्मचारियों के अनुसार प्रोजेक्ट की टीम के सदस्य जानते थे कि वे कठिन हालात से जूझ रहे हैं। अगर एपल की कार मार्केट में आती तो उसकी कीमत लगभग 82 लाख रुपए हो सकती थी। उसे स्मार्ट फोन और ईयरबड्स के मुकाबले बहुत कम मुनाफा होता। बाजार पर टेस्ला के दबदबा जमाने के कई साल बाद एपल कार आती।

© The New York Times

एपल सॉस में सीसे का लेवल ज्यादा होने से सैकड़ों बच्चे बीमार पड़े थे

हेल्थ

लेवल अधिक होने से शारीरिक और मानसिक विकास पर असर

क्रिस्टिना ज्यूएट

अमेरिका में एपल सॉस में दालचीनी से हुई लेड (सीसे) पॉइजनिंग ने बच्चों पर इस भारी धातु के जहरीले प्रभाव की ओर लोगों का ध्यान खींचा है। विश्वास किया जाता है कि एपल सॉस में दालचीनी (सिनामॉन) की मिलावट जानबूझकर की गई ताकि उसका वजन बढ़ाया जा सके। दालचीनी में सीसा बहुत ज्यादा होता है। डिसीज कंट्रोल और प्रिवेशन सेंटर्स का अनुमान है कि एपल सॉस में मिलावट से 400 से अधिक बच्चे बीमार पड़े थे। उनके खून में लेड का लेवल औसत से छह गुना अधिक पाया गया।

बच्चों में लेड पॉइजनिंग कई स्रोतों से हो सकती है। लेड का बेहद आम स्रोत पेंट है। सीसे के पुराने पाइपों से आने वाले पेयजल से भी बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। खाने से लेड पॉइजनिंग आम नहीं है लेकिन यह होती है। एक स्टडी में पाया गया कि स्वीट पोटैटो में सबसे अधिक लेड होता है। कई बार मसालों का वजन बढ़ाने या उनका रंग गहरा करने के लिए लेड की मिलावट होती है। अमेरिका में जिस एपल सॉस से बच्चे बीमार हुए वह इक्वेडोर से आया था। इक्वेडोर में हुई जांच से पता लगा कि दालचीनी में ग्राइंडर से लीड क्रोमेट पाउडर मिलाने के बाद उसे एपल सॉस में डाला गया।

डॉक्टरों का कहना है, शरीर में लंबे समय तक लेड का लेवल बढ़ने का पता नहीं चल पाता है। लेड ज्यादा होने से पेट में दर्द, उल्टी, थकान, पढ़ने और सीखने में कठिनाई, शारीरिक विकास में रूकावट और मिर्गी, बेहोशी जैसी स्थिति तक हो सकती है। अध्ययनों में पाया गया है कि बच्चों के खून में लेड का लेवल पांच या अधिक होने से उनके बौद्धिक स्तर पर फर्क पड़ता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में रिसर्च की प्रमुख डॉ. एना नेवेस एसियन का कहना है, बच्चों को कैल्शियम, आयरन और मिनरल्स से भरपूर आहार देने की जरूरत है। बच्चों को कई किस्म के फूड देने से किसी एक खराब प्रोडक्ट को बहुत अधिक खाने से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है।

© The New York Times

तेंदुओं की संख्या

स्वागत योग्य वृद्धि

भारत में तेंदुओं की संख्या मनुष्यों व प्रकृति से चुनौतियों के बावजूद बढ़ी है। बढ़ते पर्यावरणीय व मनुष्य-वन्यजीव टकराव के बावजूद भारत में तेंदुओं की संख्या में रिकार्ड बढ़ोत्तरी हुई है और यह 13,874 पहुंच गई है। यह वृद्धि इन शानदार वन्यजीवों की दृढ़ता तथा भारत में संरक्षण प्रयासों की सफलता का नतीजा है। भारत में तेंदुए विभिन्न भागों में पाए जाते हैं जिनमें घने जंगलों से लेकर शहरी क्षेत्र तक शामिल हैं। लेकिन मानव बस्तियों से निकटता अक्सर टकराव का कारण बनती है। भोजन या क्षेत्र की तलाश में तेंदुए अक्सर गांवों में पहुंच कर मवेशियों व कभी-कभी मनुष्यों पर हमले करते हैं। ऐसे टकराव से तेंदुओं और मनुष्यों, दोनों को काफी खतरा पैदा होता है। जलवायु परिवर्तन के कारण ये चुनौतियां बढ़ी हैं क्योंकि प्राकृतिक पर्यावास बदलने के साथ शिकार की उपलब्धता घटी है। जंगलों के विखंडित होने, जैव-विविधता के नुकसान तथा अन्य चुनौतियों के कारण तेंदुओं की संख्या पर दबाव बढ़ा है। इसके साथ ही उनका शिकार एक मुनाफे वाला बिजनेस बन गया है। बहुत से प्रभावशाली लोग पीछे छिप कर स्थानीय लोगों को उनके शिकार में लगाते हैं। ऐसे लोगों की पहचान कर उनको दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन इन विपरीत परिस्थितयों के बावजूद भारत में तेंदुओं की संख्या में वृद्धि अनेक कारणों से हुई है जिनमें संरक्षण की पहलें तथा कठोर वन्यजीव संरक्षण कानून शामिल हैं।

सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों-एनजीओ को पर्यावास संरक्षण, शिकार-विरोधी प्रयासों तथा स्थानीय समुदायों में तेंदुआ संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के काम में सक्रिय रूप से शामिल किया गया है।

'कैमरा ट्रैपिंग' तथा 'सेटेलाइट ट्रैकिंग' जैसी तकनीकों के प्रयोग से तेंदुओं के व्यवहार, पर्यावास प्रयोग तथा उनकी संख्या में परिवर्तन के बारे में गहन जानकारी मिली है जिसे संरक्षण रणनीतियों में शामिल किया गया है। समुदाय-आधारित संरक्षण दृष्टिकोण ने अच्छे नतीजे दिखाए हैं। स्थानीय समुदायों को संरक्षण प्रयासों में शामिल करने से उनके भीतर स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना पैदा होती है। तेंदुओं की संख्या में लगातार वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए निरंतर सरकारी प्रयासों की जरूरत है। हालांकि, तेंदुओं की संख्या में वृद्धि स्वागत योग्य है, पर इससे मानव जीवन को नुकसान नहीं होना चाहिए। तेंदुए वाले क्षेत्रों में उनके व्यवहार, संरक्षण महत्व तथा टकराव से बचने वाली रणनीतियों के बारे में जागरूकता अभियान चलाये जाने चाहिए। कम लागत वाले ऐसे तरीके खोजे जाने चाहिए जिनसे मानव जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उदाहरण के लिए, सुंदरबन में निवासी अपनी पीठ पर एक मास्क पहनते हैं ताकि रायल बंगाल टाइगर्स को भ्रमित किया जा सके। इसके साथ ही तत्काल पर्यावास संरक्षण प्रयास मजबूत करने की जरूरत है जिसमें पुनर्वनीकरण, वन्यजीव गलियारों की स्थापना तथा प्राकृतिक पर्यावासों में मानव घुसपैठ रोकना शामिल है। यह गलत धारणा भी दूर करने की जरूरत है कि ग्रामीण समुदाय जानवरों के प्रति शत्रुतापूर्ण भावना रखते हैं क्योंकि वे शताब्दियों से वन्यजीवों के बीच में रह रहे हैं। शिकार, अवैध वन्यजीव व्यापार तथा पर्यावास विनाश रोकने के लिए कानून-व्यवस्था एजेंसियों को वन्यजीव संरक्षण कानून कठोरता से लागू करने चाहिए। अंतरराष्ट्रीय संगठनों तथा पड़ोसी देशों से सहयोग कर सीमापार संरक्षण प्रयासों में भी सहायता करनी चाहिए। हमें नई वन्यजीव नीति बनाने की आवश्यकता है जिसमें वर्तमान स्थितियों का ध्यान रखते हुए मानव-वन्यजीव हितों में संतुलन बनाया गया हो।

भारतीय राजनय की भावनात्मक शक्ति

भारत विश्व मंच पर अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए भावनात्मक शक्ति के विभिन्न आयामों का प्रयोग कर रहा है। इससे राजनयिक संबंध गहरे होते हैं तथा क्षेत्रीय स्थायित्व बढ़ता है।

संतोष मैथ्यू
(लेखक, असोसियेट प्रोफेसर हैं)

भारत विश्व मंच पर अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए भावनात्मक शक्ति के विभिन्न आयामों का प्रयोग कर रहा है। इससे राजनयिक संबंध गहरे होते हैं तथा क्षेत्रीय स्थायित्व बढ़ता है। वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य में राष्ट्रीय शक्ति के परंपरागत आयामों में परिवर्तन हो रहा है। नीति-निर्माता और राजनयिक लगातार अंतरराष्ट्रीय संबंधों को परिभाषित करने तथा उनको स्वरूप प्रदान करने में भावनात्मक शक्ति के तत्वों की पहचान कर रहे हैं। इससे केवल सैनिक शक्ति के बजाय सांस्कृतिक प्रभावों तथा नैतिक अधिकारों को महत्व मिल रहा है। भारत अत्यन्त प्राचीन व विविधतापूर्ण सभ्यताओं व संस्कृतियों का देश रहा है। वर्तमान समय में विश्व मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए भारतीय राजनयिक अपनी सांस्कृतिक धरोहरों का बहुत अच्छा प्रयोग कर रहे हैं।

भावनात्मक शक्ति के संदर्भ में देखें तो धर्म भी राजनीति को परिभाषित करने तथा उसे स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नियाल फर्ग्यूसन ने कहा था, 'अक्सर विश्वास शक्ति का एक महत्वपूर्ण आयाम है और यह भौतिक संसाधनों जितना ही महत्वपूर्ण है। विश्वास से भले ही पहाड़ों को न खिसकाया जा सके, पर इससे लोगों में व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है।' भारत ने इस शक्ति का बहुत महत्वपूर्ण ढंग से उपयोग किया है। भारत की रणनीतिक सांस्कृतिक राजनय का हालिया उदाहरण संयुक्त अरब अमीरात-यूएई में पहले हिंदू मंदिर की स्थापना है। इसके स्थापना समारोह के आयोजन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रमुख भूमिका निभाई। यह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में मील का महत्वपूर्ण पत्थर है। भूक्षणवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण मंदिर-बीएपीएस के स्थापना समारोह के साथ भारत ने यूएई के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा किया है, जबकि उसने इस क्षेत्र के साथ सक्रिय रूप से गहन संबंध स्थापित किए हैं। इस आयोजन से भारत का राजनयिक दृष्टिकोण स्पष्ट होता है जो विश्वास, संस्कृति तथा धर्म पर आधारित है। इसका उद्देश्य अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है जिसमें सुरक्षा, ऊर्जा, समुद्री मामले तथा ढांचागत विकास शामिल हैं। मंदिर स्थापना आयोजन के अवसर पर हुई प्रधानमंत्री की यूएई यात्रा में दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया जिनमें व्यापार, निवेश तथा सुरक्षा शामिल हैं।

खाड़ी देशों और भारत के बीच बदलते राजनयिक परिदृश्य को मजबूत करने वाला यह एकमात्र आयोजन नहीं है। भारतीय राजनय की विजय इस तथ्य से भी स्पष्ट हुई है कि कतर ने हाल ही में आठ भारतीय नागरिकों को रिहा कर दिया जिनको वहां 2022 में गिरफ्तार किया गया था। कथित रूप से जासूसी के आरोपों में गिरफ्तार इन भारतीय नागरिकों की रिहाई के लिए भारत सरकार तथा कतर में भारतीय राजनयिकों ने व्यापक और गंभीर प्रयास किए थे। इससे भारतीय राजनयिक व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता स्पष्ट हुई जो विदेशों में फंसे अपने नागरिकों को बाहर निकालने में सक्षम है।

व्यापक वार्ताओं तथा रणनीतिक संवाद के माध्यम से हमारी सरकार ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि वह हर भारतीय के हितों का संरक्षण करने के मामले में प्रतिबद्ध है, भले ही वे दुनिया में चाहे जहां हों। दोहा यात्रा के पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कतर के साथ भारत के ऐतिहासिक और निकट संबंधों पर जोर दिया था। दोनों देशों के बीच मजबूत राजनयिक संबंधों ने परस्पर लाभदायक साझीदारी बढ़ाने तथा क्षेत्रीय संबंध मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इन राजनयिक पहलों का उद्देश्य केवल खाड़ी देशों के नेताओं के साथ निकट संबंध स्थापित करना ही नहीं है, बल्कि इनका उद्देश्य रणनीतिक योजनाओं के माध्यम से भारत की आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करना भी है। भारत ने मध्यपूर्व देशों के साथ दीर्घकालीन आर्थिक सहयोग विकसित किया है। इससे भारत की विकास योजनाओं में खाड़ी देशों के पूंजी निवेश के साथ ही रक्षा क्षेत्र में भी सहयोग लगातार बढ़ता जा रहा है।

भारत की सांस्कृतिक राजनय का विस्तार केवल 'हिंदूवाद' के क्षेत्र तक सीमित नहीं है। भारत ने 'बौद्ध सर्किट' का भी तेजी से व उल्लेखनीय विकास किया है जिसका उद्देश्य बौद्ध विरासती स्थलों को पुनर्जीवित व विस्तारित करने तथा इन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना है। 'स्वदेश दर्शन योजना' के अंतर्गत इस तीर्थयात्रा सर्किट में बौद्ध परंपराओं के अनुसार चार प्रमुख पवित्र स्थलों- बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और लुम्बिनी को शामिल किया गया है। यह भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय पर्यटन सर्किल है। नेपाल के लुंबिनी में भगवान बुद्ध के जन्मस्थल से लेकर यह सर्किट 'बौद्ध राजनय' की पहल रेखांकित करता है। इसका उद्देश्य बौद्ध धर्म के विचारों वाले देशों के साथ भावनात्मक शक्ति, पवित्र वस्तुओं तथा व्यापार संबंधों का विकास है। इस क्षेत्र तथा बौद्ध धर्म से प्रभावित क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक संबंधों के विस्तार से भारत इस क्षेत्र में दो देशों के बीच क्षेत्रीय टकरावों के कारण पैदा तनाव दूर करने के प्रयास कर रहा है। यह सीमापार के लोगों और भारतीय जनता के बीच व्यक्तियों के स्तर पर सकारात्मक संबंध विकसित करने का लक्ष्य भी सामने रखता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बौद्ध विरासती स्थलों का सांस्कृतिक संपत्तियों के रूप में प्रयोग कर रणनीतिक रूप से एशियान देशों के साथ संबंध मजबूत किए हैं। अप्रैल, 2023 में 'विश्व बौद्ध सम्मेलन' में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आधुनिक दुनिया की समस्याओं का समाधान भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को लागू कर हो सकता है। इस 'एक्ट ईस्ट' पालिसी के माध्यम से भारत ने एशिया-प्रशान्त क्षेत्र के प्रमुख देशों से अपने रणनीतिक संबंध मजबूत किए हैं। इसके लिए भारत और दक्षिणपूर्व एशियान देशों के साथ सांस्कृतिक संपर्क में बौद्धवाद का प्रयोग किया गया है। बौद्धवाद से ऐतिहासिक संबंधों की खोज कर भारत ने न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत मजबूत की, बल्कि इस भावनात्मक शक्ति से दुनिया भर से यात्रियों को भी आकर्षित किया। इन पहलों के माध्यम से भारत ने प्राचीन सभ्यताओं और परंपराओं के ध्वजवाहक के रूप में अपनी छवि मजबूत की है। इसके साथ ही पर्यटन के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देने वाले उद्यमों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत एशियान देशों के साथ ज्यादा गहन संपर्क विकसित करने के लिए स्वयं को धार्मिक सहिष्णुता, बहुलवाद तथा दुनिया के जिम्मेदार देश के रूप में प्रस्तुत कर रहा है।

दुनिया के जिम्मेदार देश के दृष्टिकोण के रूप में देखें तो मानवीय सहायता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता एक उल्लेखनीय उदाहरण है। अदन की खाड़ी में जब हौती विद्रोहियों ने एक व्यापारी जहाज पर हमला किया तो भारतीय नौसेना ने तेजी से कार्रवाई करते हुए मिसाइल डिस्ट्रायर आईएनएस विशाखपट्टनम को भेजा। इसके पहले भी भारत ने समुद्री डकैतों से निपटने और व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा देने के लिए भारतीय नौसेना का बार-बार प्रयोग किया है। इस हालिया घटना से दुनिया भर में एक जिम्मेदार समुद्री शक्ति के रूप में भारत की छवि मजबूत हुई। इस प्रकार भारतीय राजनय का विस्तार संस्कृति के क्षेत्र से बाहर जाकर रणनीतिक संबंधों और मानवीय प्रयासों तक होता है। संकट में फंसे देशों तथा भारतीय समेत अन्य देशों के नागरिकों की सहायता कर भारत ने शांति और स्थायित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता मजबूत की है।

भारत ने अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में संकटों के समय इन मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पूर्णत: स्पष्ट की है। राजनय के क्षेत्र में हर संकेत और हर संवाद का प्रयोग द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने तथा गठबंधन बनाने में किया जाता है। सांस्कृतिक व सार्वजनिक राजय का आक्रामक ढंग से प्रयोग कर भारत ने विश्व मंच पर अपना प्रभाव बढ़ाया है। सक्रिय सबंधों तथा रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से भारत ने अंतरराष्ट्रीय मामलों में प्रमुख शक्ति के रूप में अपनी स्थिति लगातार मजबूत की है। इस प्रकार उसने क्षेत्रीय स्थिरता तथा वैश्विक सहयोग में भी योगदान किया है।

दिल्ली में फूलों का वैभव

"दिल्ली ट्यूलिप फेस्टिवल लचीलेपन, सुंदरता और जीवन के शाश्वत नृत्य की स्थायी भावना का प्रमाण है।"

राजदीप पाठक
(लेखक, गांधी स्मृति एवं दर्शन संस्थान में कार्यरत हैं)

नई दिल्ली के कूटनीतिक क्षेत्र चाणक्यपुरी के केंद्र में स्थित, शांति पथ जीवंत रंगों से चित्रित एक मंत्रमुग्ध कर देने वाले कैनवास के रूप में उभरता है, जो लाल, सफेद, गुलाबी, पीले और बैंगनी रंग के ट्यूलिप की टेपेस्ट्री से सजा हुआ है। दिल्ली ट्यूलिप फेस्टिवल, जो अब लगातार दूसरे वर्ष है, 21 फरवरी, 2024 को समाप्त हो गया, जो 10 फरवरी को शुरू हुआ था। दूर-दराज से आए पर्यटक, प्रकृति की भव्यता के नजारे को देखकर आश्चर्यचकित रह गए, अमर की गूंज सुनाई दी पी. बी. शेली और जॉन कीट्स जैसे कवियों की कविताएँ। जैसे ही त्योहार शुरू हुआ, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए शहर के चौराहे और पार्क, वसंत के आगमन के साथ खिल उठे, और नई भव्यता के साथ सभी का स्वागत किया।

लेकिन इन ट्यूलिप के पीछे की कहानी क्या है? फारस की प्राचीन भूमि में सदियों पहले उत्पन्न हुए ट्यूलिप का प्रेम और समृद्धि के प्रतीक के रूप में महत्व है। रेशम मार्गों के साथ उनकी यात्रा इस्तांबुल से एम्स्टर्डम तक दिल को लुभाने वाली विदेशी भूमि और दूर क्षितिज की कहानियों को ले गई। डच स्वर्ण युग के दौरान नीदरलैंड के खेतों में ट्यूलिप एक सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में विकसित हुए थे। पश्चिमी यूरोप में इसके परिचय को लेकर अनिश्चितता के बावजूद, 16वीं सदी के अंत में वनस्पतिशास्त्री कैरोलस क्लूसियस जैसे व्यक्तियों के प्रयासों ने ट्यूलिप को लोकप्रिय बनाया, जिससे 17वीं सदी का प्रसिद्ध ट्यूलिप उन्माद पैदा हुआ।

19वीं और 20वीं शताब्दी तक, नीदरलैंड में ट्यूलिप की खेती फली-फूली, जिससे दुनिया के अग्रणी उत्पादक के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हो गई। ट्यूलिप और नीदरलैंड के बीच का संबंध 1950 के दशक

में प्रतिष्ठित गीत ट्यूलिप्स फ्रॉम एम्स्टर्डम के साथ और भी अमर हो गया। दिलचस्प बात यह है कि राजनयिक चैनलों के माध्यम से ही ट्यूलिप को नई दिल्ली के बगीचों में जगह मिली। एम्स्टर्डम ट्यूलिप फेस्टिवल और श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन जैसे त्योहारों से प्रेरित होकर, भारत-डच संबंधों ने इस वनस्पति राजदूत को जड़ें जमाने के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान की। नीदरलैंड से आयातित, इन ट्यूलिप को एनडीएमसी के बागवानी विभाग द्वारा प्रशिक्षित कुशल माली द्वारा प्यार से पाला गया है। जैसे ही सूरज शहर पर अपनी सुनहरी किरणें डालता है, ट्यूलिप खिल जाते हैं, हर कोने को प्रकृति की उत्कृष्ट कृति के कैनवास में बदल देते हैं। शांति पथ के सुरम्य रास्ते से लेकर जीवंत ट्यूलिप फेस्टिवल गार्डन तक, प्रत्येक स्थान जीवन और सुंदरता के स्थायी चक्र का प्रमाण बन जाता है। विभिन्न प्रतियोगिताओं और आयोजनों के माध्यम से नागरिकों को शामिल करते हुए, यह त्योहार प्रकृति की लय और समुदाय के बंधनों के साथ गहरे संबंध को बढ़ावा देता है।

एनडीएमसी के अध्यक्ष अमित यादव ने बताया कि सात प्रकार के ट्यूलिप लगाए गए थे, जिनमें से तीन लाख बल्ब नीदरलैंड से मंगवाए गए थे और अतिरिक्त 40,000 बल्ब डच दूतावास द्वारा दान किए गए थे। जल्दी खिलने से लेकर देर तक खिलने वाले प्रत्येक ट्यूलिप लचीलेपन और नवीकरण की कहानियाँ सुनाते हैं। यह त्यौहार न केवल सुंदरता का जश्न मनाता है बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए प्रकृति की देखभाल और सुरक्षा के महत्व को भी रेखांकित करता है।

दिल्ली ट्यूलिप फेस्टिवल शहरी सुंदरता और पारिस्थितिक चेतना के मिश्रण का प्रतीक है, जो आगंतुकों को मंत्रमुग्ध करता है और टिकाऊ पर्यटन के लिए एक प्रकाशस्तंभ के रूप में कार्य करता है। अपने सौंदर्य आकर्षण से परे, यह वैश्विक संबंधों को बढ़ावा देने और शहर के आकर्षण को बढ़ाने में सौंदर्य और कला की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है। जैसे ही दुनिया भर से पर्यटक ट्यूलिप की बहुरूपदर्शक सुंदरता की प्रशंसा करने के लिए इकट्ठा होते हैं, यह त्योहार वैश्विक विरासत का उत्सव बन जाता है, जो सांस्कृतिक बाधाओं को पार करता है और विविध पृष्ठभूमि के लोगों के बीच समझ और प्रशंसा को बढ़ावा देता है।

कई मायनों में, यह त्योहार शहरी जीवन की उथल-पुथल के बीच प्रकृति के लचीलेपन और सहनशक्ति का प्रतीक है। जैसे-जैसे ट्यूलिप महोत्सव ख़त्म होने वाला है, फूल अपने जीवंत रंगों से शहर के परिदृश्य को सजाना जारी रखते हैं। शहरी जीवन की हलचल भरी लय के बीच, ट्यूलिप आशा के मूक प्रहरी के रूप में खड़ा है, इसकी पंखुड़ियां जीवन के शाश्वत नृत्य की स्थायी भावना का प्रमाण हैं। आज, ट्यूलिप लचीलेपन और सहनशक्ति के प्रतीक के रूप में कार्य करता है, जो महासागरों और सदियों को पार करके दुनिया भर में सुंदरता का एक प्रतिष्ठित प्रतीक बन गया है। जबकि ट्यूलिप महोत्सव पर पर्दा डाला गया है, फूल अपने जीवंत रंगों के साथ शहर के परिदृश्य को सजाते हुए, ऊंचे खड़े हैं। यह त्यौहार सिर्फ एक स्थानीय कार्यक्रम से कहीं अधिक है; यह वैश्विक विरासत का एक हिस्सा है, एक उत्सव है जहां दुनिया भर से पर्यटक दूर-दूर तक फैले रंगों की बहुरूपदर्शक सुंदरता की प्रशंसा करने के लिए इकट्ठा होते हैं।

आप की बात

स्वास्थ्य पर संकट

स्वस्थ शरीर को सबसे बड़ा धन माना जाता रहा है। मगर एक नए अध्ध्यन से लगता है कि दुनिया भर की आबादी तेज़ी से बीमार होती जा रही है। दुनिया की 8 अरब की आबादी में से इस समय एक अरब से ज़्यादा लोग मोटापे का शिकार हैं। लांसेट में प्रकाशित पेपर के अनुसार मोटापे के शिकार लोगों में 88 करोड़ वयस्क तथा 16 करोड़ बच्चे हैं। अधिक वजन या मोटापा स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंताजनक है। सामान्य से अधिक वजन वाले लोगों को डायबिटीज और हृदय रोग जैसी क्रोनिक और जानलेवा समस्याओं का खतरा अधिक हो सकता है। इसके पीछे फ़ास्ट फ़ूड का बढ़ता चलन तथा आरामतलबी की आदत है। लेकिन इसके साथ ही अनेक विकासशील और गरीब देशों में लोग कुपोषण जनित बीमारियों का शिकार होकर अपनी शारीरिक व मानसिक क्षमताओं का विकास नहीं कर पाते हैं। विडंबना है कि खाते-पीते या तुलनात्मक रूप से समृद्ध लोगों की बीमारियों व उनके इलाज पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन गरीबों में होने वाली बीमारियों को अनदेखा किया जाता है क्योंकि उनसे दवा कंपनियों को मुनाफा होने की उम्मीद नहीं होती है। दुनिया में युद्ध, आर्थिक असमानता व बाजार की लूट ज्यादातर लोगों के स्वास्थ्य पर संकट पैदा करता है। इस विसंगति पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

– **जंग बहादुर सिंह,** जमशेदपुर

मोदी का अभियान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान को और धार दे दी है। झारखण्ड के धनबाद में उन्होंने कहा कि जेएमएम का अर्थ जमकर खाओ और कांग्रेस यानी परिवारवाद। दोनों घोटाले बाज, दोनों ने जनता को खूब लूटा, अब लूटा हुआ जनता को लौटाना पड़ेगा। आपने यह आशीर्वाद दिया है। यह मोदी की गारंटी है कि लूटा हुआ सब वापस आएगा, मतलब लूटने वाले नहीं बचेंगे। उनका इशारा जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर था। मोदी की बातों पर ध्यान दें तो वास्तव में जेएमएम का मतलब जमकर खाओ और मौज मनाओ ही होता है। कांग्रेस और जेएमएम की दिशा, दशा और कार्यशैली एक सरीखी है। दोनों परिवारवादी और तिजोरी भरने वाले हैं। विपक्षी भले ही ईडी और सीबीआई को भाजपा की शाखा बता दें, लेकिन अपने खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर सफाई देने की स्थिति में नहीं हैं। दूसरी ओर मोदी का भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान जनता की भावनाओं को स्वर दे रहा है जिन्होंने अनेक पार्टियों के छुटभैया नेताओं को करोड़पति बनते देखा है। ऐसे में जनता की हमदर्दी भ्रष्ट विपक्षी नेताओं के साथ होना लगातार असंभव होता जा रहा है। यह भावना भाजपा को 370 पार पहुंचा सकती है।

– **शकुंतला महेश नेनावा,** इंदौर

पक्षपाती डब्लूटीओ

विश्व व्यापार संगठन–डब्लूटीओ कहने को तो विश्व व्यापार व्यवस्थित रखने के लिए गठित संगठन है, मगर लंबे समय से यह बड़े देशों के पक्ष में ही काम कर रहा है। अमीर देश विकासशील देशों, छोटे देशों और गरीब देशों के लिए ऐसे नियम बना रहे हैं जो उन देशों के किसानों की सहायता में बाधक बन रहे हैं। इससे पश्चिमी देशों के किसान अपने उत्पादों पर भारी सब्सिडी प्राप्त कर उनको सस्ते दामों में विश्व बाजार में बेचते हैं। प्रदर्शनकारी भारतीय किसान तो चाहते हैं कि भारत इस संगठन से बाहर निकल जाए। लेकिन वर्तमान अंतरराष्ट्रीय स्थितियों को देखते हुए ऐसा कोई कदम असंभव, अतार्किक तथा आत्मघाती सिद्ध होगा। भारत आज आर्थिक रूप से विश्व की पांचवी शक्ति बन गया है और जल्द ही तीसरे नंबर की आर्थिक शक्ति बन जाएगा। भारत को दुनिया में अपनी बढ़ती शक्ति व लोकप्रियता का लाभ उठा कर डब्लूटीओ जैसी संस्थाओं के लोकतांत्रीकरण के लिए दबाव डालना चाहिए ताकि वे अमीर देशों के बजाय विकासशील व गरीब देशों के पक्ष में निर्णय ले सकें। इस उद्देश्य के लिए भारत अनेक देशों का समर्थन प्राप्त कर सकता है। पश्चिमी और अमीर देशों को अपनी वर्चस्ववादी व पक्षपाती नीतियां छोड़ने के लिए तैयार करना होगा।

– **विभूति बुपक्या,** खाचरोद

क्रिकेट से कमाई

बीसीसीआई, यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड टेस्ट और घरेलू क्रिकेट के लिए मैच फीस बढ़ाने पर विचार कर रहा है। यह बढ़ोतरी तीन गुना तक हो सकती है। क्रिकेट बोर्ड की इस पहल का लाभ खिलाड़ियों को भी मिलेगा और वे अधिक मनोयोग से खेलेंगे। लेकिन सेलिब्रिटी बन जाने के बाद क्रिकेटर विज्ञापनों से भी भरपूर धन प्राप्त करते हैं। लेकिन खेलों से बढ़ती कमाई के कारण अनेक लोग खेल भावना तथा खेलों के वाणिज्यीकरण पर सवाल उठाते हैं। हमारे देश में क्रिकेटरों को भरपूर दौलत और शोहरत मिलती है। लेकिन यही स्थिति अन्य खेलों से जुड़े खिलाडियों की नहीं है। हालांकि, क्रिकेट की तरह अब राज्य सरकारें और निजी क्षेत्र अन्य खेलों को भी बाजार या धंधा बनाने के प्रयास में लग गए हैं। क्रिकेट के साथ ही ऐसे खेलों को बढ़ावा मिलना चाहिए जिन पर ज्यादा खर्च की जरूरत न हो। क्रिकेट व संभावित कमाई वाले अन्य खेलों को कॅरियर बनाने का दुष्प्रभाव यह है कि खेल आम जनता, स्कूली बच्चों तथा ग्रामीण बच्चों के जीवन से दूर होते जा रहे हैं। खेल भावना को महत्व देना भी जरूरी है।

– **सुभाष बुड़ावन वाला,** रतलाम

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संपादकीय

समस्याओं और परेशानियों के बीच चलता जीवन

बेहतर जीवन जीने के लिए हर कोई परेशांहाल है। इस कलयुगी काल में, एक नहीं अनेक तरह की समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है। हर कोई अपनी परेशानियों से ही परेशान है। वर्तमान समय में हर कोई परेशानियों में जीवन जान चलाने को विवश है। हर किसी के सामने उलझनों का अंबार है। हर कोई इसके निदान में लगा हुआ है। पर समस्याएं हैं, उलझने है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। जिंदगी किसी तरह काटने में हर कोई लगा हुआ है और जिंदगी है कि कटती ही नहीं। समस्याओं के अंबार में उलझी पड़ी है, जिंदगी। जिंदगी के मायने ही समाप्त से हो चुके हैं ऐसी हालात पैदा हो? चुकी है कि हर कोई परेशान है। आज बहुतेरों के पास कमाई के साधन समाप्त हो चुके हैं, खाने के लाले पड़े हैं। जिंदगी ऑनलाइन चल रही है। अगर जिंदगी इस तरह चलेगी तो व्यवस्था को संभालने का ज्ञान ऑनलाइन ही लाना पड़ेगा। ऑनलाइन की जिंदगी कितनी कारगर और व्यवस्था परक बन पाएगी, कहना मुश्किल हो रहा है। हर कोई त्राहिमाम, त्राहिमाम कर रहा है बस जिंदगी सपाट चल रही है, आस लगाए कि दिन बेहतर होंगे। कब होंगे बेहतर कोई नहीं जानता यह तो सर्वविदित है, की यह देश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अधीन संचालित होता है और इस व्यवस्था में सरकार हर नागरिक के लिए सुख सुविधाओं की व्यवस्था करती है। लेकिन अगर इन व्यवस्थाओं में खामियां आ जाए और यह स्वार्थ परक बन जाए, तो व्यवस्था में गड़बड़ी तो दिखती ही दिखती है। हमारा देश इन दिनों बड़े ही परेशानियों से रूबरू हो रहा है। कई तरह की परेशानियां हैं, इस देश में और समाज के लोग इन परेशानियों में उलझ कर रह गए हैं। इसे हर हाल में सुलझाने में लगे लोग भी काफी परेशान हैं देश के लोग इन दिनों कई तरह की जाने अनजाने समस्याओं से लोग रूबरू होकर उलझे हुए है, देश के लोग परेशान हाल है। अपने अपने हित के लिए सभी संघर्षरत हैं। जनता नारे लगाने में व्यस्त है। सबकी अपनी अपनी चिंता है, व्यवहार है, व्यवस्था है। अब सरकार जो व्यवस्था करती है। वह कितना किसके लिए उपयोगी है? यह सब देख समझ कर ही सरकारी व्यवस्था की जाती है। लेकिन कई लोगों को यह व्यवस्था यानी सरकारी व्यवस्था। रास नहीं आती उन्हें लगता है कि सरकार गलत कर रही है और वह विरोध करने में जुट जाते हैं और सरकार जो गलत करती है, उसका विरोध होना लाजमी है। पर जो सही है उसका विरोध करके भी क्या फायदा? क्योंकि सरकार अपने हित के लिए नहीं, बल्कि देश हित को ध्यान में रखकर ही व्यवस्था करती है। विरोध भी होना चाहिए, विरोध नहीं होगा, तो सरकार मनमानी कर सकती है। इस देश प्रदेश के लोग अपनी अपनी चिंताएं जाहिर कर रहे हैं। किसी को लगता है, सरकार देश निकाला कर रही हैं, सरकार कहती है, कोई कहीं नहीं जायगा, यह तो सब नियमाकूल है और यह होना है। तब सवाल उठता है कि इस देश में जो व्यवस्थाएं हैं लोकतांत्रिक है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को अधिकार प्राप्त है। हर तरह की सुविधाएं हैं। हर तरह की बात को सुनने समझने की छूट है, करने की छूट है। लेकिन आदमी अपनी इसी छूट को जिस तरह से उपयोग करने में लगा है, वह सब कुछ देश के कुछ लोगो के लिए अच्छा नहीं लगता। लोग स्वतंत्र हैं, देश में आजादी है पर इसकी इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती कि वह इस व्यवस्था को तहस-नहस करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। समाज के लोग और सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाय यह, हम सभी मानते हुए चलते हैं। लेकिन इन दिनों हर तरह की व्यवस्था में कई तरह की खामियां भी देखने को मिल रही है। इन खामियों को दूर करना और कराना भी जरूरी है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर करके ही हर इन खामियों और इन कमियों को दूर करने में सक्षम हो पाएंगे सरकार जो कुछ भी करती है, वह निश्चित रूप से व्यवस्था के अधीन ही करती है। देश के सभी नागरिकों को जो सही नागरिक है। बाजीव में नागरिकों को हर तरह की व्यवस्था मिलनी चाहिए। लेकिन गैर वाजिब नागरिक भी इस देश में बड़ी संख्या में पैठ बनाए हुए हैं। यह ऐसे नागरिक हैं जो दूसरे देशों से यहां सरणार्थी आए और यहां बस गए उनका यह देश नहीं है। लेकिन वे इसी देश को अपना देश मानकर यहां की सुविधाओं को प्राप्त करने में लगे हैं। और सही नागरिको का हकमारी कर रहे हैं। कई ऐसे भी नागरिक हैं, जो इस देश में रह कर इस देश को बर्बाद करने के लिए ही अपना आशियां बनाए हुए हैं। यह भी है कि जो बाहर से देश के लोग आए हैं। सही नागरिकों का जो सुख सुविधा है, उसका उपयोग करते हैं। इस देश के नागरिकों का हक भी मार लेते हैं। देश की व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए यह जरूरी है। कि इस देश के जो नागरिक हैं, उनके लिए व्यवस्था हो ना कि यहां बाहर से आये सुख सुविधा उठाने वाले नागरिकों दी जाय। सही नागरिको को सुख सुविधाएं दिया जाए, जो बाहर से आए हैं, उन्हें सुख सुविधा लेने का कोई अधिकार नहीं है लेकिन वह अधिकार जमाते नजर आते हैं। और उन्हें सह देने के लिए इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत विरोधी दल जो सरकार में नहीं होते, वह हर कुछ जानते हुए भी चाहते हैं कि लोग उनके साथ हो और जहां वोट की राजनीति होती है, वहां यह तो होता ही है कि लोग गलत सलत तरीके से भी लोगों को अपनी ओर मिला कर रखते रहते हैं, उन्हें साथ लेकर अपनी ताकत को दर्शाने में लगते हैं। विरोध होना चाहिए, लेकिन सही विरोध होना चाहिए। उल जलूल विरोध के क्या मायने? इस देश में बढ़ती महंगाई बेरोजगारी की व्यवस्था कुछ ज्यादा ही लोगों को परेशान करती है और उलझाए रखती है। लेकिन इस ओर सरकार का ध्यान नहीं होता वह अपनी ओर से कुछ ऐसी व्यवस्था समाज और आमजन के बीच रखती है। जिसमें लोग उलझ कर रह जाते हैं और जो सही बात होनी चाहिए, वह मानस पटल से गायब हो जाती है। लोगों के मानसिक स्थिति को देखते हुए सरकार अपनी सोची-समझी चाल चलती रहती है। जनता उसी में उलझ कर नारे लगाती रहती है। विरोधी भी सरकार के विरोध में। उसी जनता के साथ हो जाते हैं जो नारे लगाने वाली होती है। अब ऐसे में इस देश में उलझनों को सुलझाने वाली व्यवस्था कब कारगर होगी, यह तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा? कई समस्याएं इतनी गहरी होती जा रही है। उससे निपटना आसान नहीं होता वर्तमान समय में कब कौन सा उलझन सामने उपस्थित हो जाए और आदमी लाचार हो जाए कहने का अर्थ यह कि जीवन में काफी उलझबढ़ गई है किसी के सामने घर चलाने की, उलझन काम तलाश की उलझन, बाजार से समान लाने से लेकर पहुंचाने और तमाम तरह की उलझने है उलझनों के सामने आदमी विवस हो गया है। आदमी करे तो क्या करें भला आज हर कोई जाल में फंस कर रह गया है निदान भी ढूंढते नहीं मिलता वेवस लाचार आदमी हाथ पर हाथ धरे, बस उलझनों के बीच अपने अपने को पाता है। कहां जाएं क्या करें, इसी सोच में दिन कट रहा है, रातें कट रही है। बेचारगी में जीवन कट रहा है। समय प्रवाह बस चलती जा रही है, चलती जा रही है। लोग कहते हैं कलयुग का जमाना चल रहा है कलयुग में हर किसी को कलयुगी ही बनकर ही जीवन जीना पड़ रहा है और जो इससे अलग होकर जीवन जीना चाहता है। उसे अनेक तरह की उलझन है और परेशानियां विकट समस्याएं झेलने पड़ते हैं। इसलिए हर किसी को अपने आपको इसी कलयुगी रूप में अपने आप को ढालकर जीवन जीने की विवशता है।

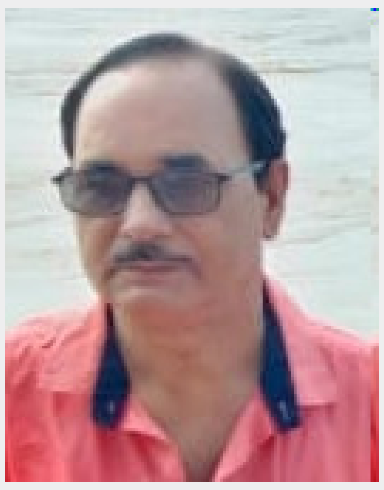

प्रभात वर्मा

राम : भारतीय मानस की सर्वोत्तम कल्पना

राम' शब्द जहन में आते ही मन- मस्तिष्क में सादगी से भरी हुई, धनुष धारण किए हुए श्याम वर्ण के एक दिव्य पुरुष की छवि उभर आती है। मन शुचिता से लबालब हो जाता है। हृदय भाव-विभोर हो जाता है! और शब्द चूने लगते हैं! साथ ही मन में कई अनुत्तरित प्रश्न भी उमड़ने लगते हैं कि आखिरकार 'राम' कौन थे?... क्या थे?... राम कहाँ उत्पन्न हुए?.... राम कब हुए?....राम मिथ है या यथार्थ?....राम पौराणिक हैं या ऐतिहासिक......? कुछ लोग तो यह भी कहने लगे हैं कि राम सर्वथा काल्पनिक हैं। इस नाम कि कोई व्यक्ति कभी हुआ ही नहीं। ऐसे में मामला और उलझ जाता है। चूँकि यह कथन राम के अस्तित्व को ही खारिज कर देता है! राम और रामकथा की प्रमाणिकता को सिद्ध करते हुए दिनकर जी ने कहा है- "राम -कथा के जिन पात्रों के नाम वेद में मिलते हैं, वे निश्चित रूप से, रामकथा के पात्र हैं या नहीं, इस विषय में संदेह रखते हुए भी यह मानने में कोई बड़ी बाधा नहीं दिखती कि रामकथा ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। अयोध्या, चित्रकूट, पंचवटी, रामेश्वरम् अनंत काल से रामकथा से संपृक्त माने जाते रहे हैं। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि दशरथी राम, सचमुच जनमें थे और उनके चरित्र पर ही आदिकवि वाल्मीकि ने 'रामायण' नामक महाकाव्य का सृजन किया?"(1) निस्संदेह राम एक ऐतिहासिक नायक हैं। इनकी ऐतिहासिकता को प्रमाणित करती हुई प्रसिद्ध इतिहास लेखिका रोमिला थापर कहती है- "कोसल के राजा के उत्तराधिकारी राम ने विदेह की राजकुमारी सीता से विवाह किया था। राम की सौतेली माता केकैयी अपने पुत्र को कोसल का राजा बनाना चाहती थी, और वे राम, सीता तथा लक्ष्मण को चौदह वर्षों के निर्वासित कराने में सफल हो गईं। इस निर्वासन में वे तीनों दक्षिण भारत के वनों में पहुँचे और वहाँ कुटिया बनाकर संन्यासी के रूप में रहने लगे। किन्तु लंका का राजा रावण सीता का अपहरण कर ले गया। राम ने वानरों के नेता हनुमान की सहायता से एक सेना का संगठन किया। रावण के विरुद्ध एक भयानक युद्ध हुआ, जिसमें रावण और उसकी सेना मारी गई। सीता को अग्नि-परीक्षा देकर अपनी पवित्रता सिद्ध करनी पड़ी, उसके बाद राम से उसका पुनर्मिलन हुआ। चौदह वर्ष पूरे हो गये थे। राम, लक्ष्मण और सीता कोसल लौटे। राम का राज्याभिषेक हुआ और 'रामराज्य' की स्थापना हुई।"(2) ऐतिहासिक चरित्र होने के कारण राम का समय निर्धारित किया गया। इतिहासकारों का मानना है कि राम का दक्षिण पार कर लंका पर विजय प्राप्त करने का वर्णन स्पष्ट रूप से दक्षिण में आर्यों के प्रवेश का संकेत करता है। चूँकि दक्षिण की ओर आर्यों के बढ़ने का समय साधारणतः सन् 800 ई.पूर्व माना जाता है। इसीलिए मूल रामायण की रचना इसके करीब पचास या सौ साल बाद हुई होगी। हालाँकि वाल्मीकि के जीवनकाल और रामायण के रचनाकाल के संबंध में पर्याप्त मतभेद है। 'डॉ. एच. याकोबी का मत है कि वाल्मीकि का समय भगवान बुद्ध से पहले का है और इसे वे ई.पू. 8 वीं सदी से पहले रखना चाहते हैं। डब्ल्यू स्केगेल इसको ई.पू. 11 वीं सदी तक ले जाते हैं। इसके विपरीत ए. बैबर तथा जी. टी. व्हीलर इसको ईसा के पश्चात के बताते हैं।'(3) मैं समझता हूँ कि 'रामायण' तथा 'महाभारत' की भाषा लौकिक संस्कृत है। भाषा-शास्त्रियों के मुताबिक लौकिक संस्कृत का समय ई. पू. 800 से ई.पू. 500 तक है। निश्चय ही रामायण तथा महाभारत की रचना इसी बीच हुई होगी। रामायण की रचना महाभारत से पहले हुई, इसके पीछे तर्क है कि रामायण की कथा महाभारत में 'रामाख्यान' के रूप में वर्णित है। स्वयं श्रीकृष्ण गीता का उपदेश देते हुए अर्जुन से कहते हैं- 'शस्त्र धारण करने वालों में मैं राम हूँ।' (रामः शस्त्रभृतामहम्) जबकि रामायण में महाभारत के किसी भी संदर्भ की चर्चा नहीं मिलती है। दूसरी बात यह है कि रामायण में जो उदारवादी मनुष्य हैं, महाभारत में उसमें बहुत गिरावट आयी है। जो लोग रामायण या वाल्मीकि को बुद्ध के बाद मानते हैं, उन्हें विचार करना चाहिए कि अगर बुद्ध वाल्मीकि से पहले हुए होते तो रामायण में उनकी चर्चा अवश्य की जाती। जिस तरह बौद्ध ग्रंथ- 'दशरथजातक', दशरथकथानकम्' तथा जैन- ग्रंथ- 'पउमचरिउ', 'महापुराण' आदि में राम का विस्मृत उल्लेख मिलता है। राम भारतीयता के पर्याय हैं। राम एक ऐसे नायक हैं, जिसने भारतीय समाज को विभिन्न स्तरों पर जोड़ने का कार्य किया है। राम, विषमता के विरुद्ध समता तथा टकराव के विरुद्ध सामंजस्य के प्रतीक हैं। राम ने न केवल सर्वोत्तम आदर्श हमारे सामने रखा, बल्कि विश्रृंखल भारत को जोड़ने का भी महनीय प्रयास किया। राम उत्तर, मध्य तथा दक्षिण भारत को जोड़ने की सफल कोशिश की। वे स्वयं उत्तर भारत में पैदा हुए। फिर उन्होंने बनवास के दौरान मध्य भारत के किष्किन्धा में पहुँच कर वन्य प्राणियों से मित्रता की तथा रावण -वध के क्रम में दक्षिण भारत के विभीषण से दोस्ती की। ये तमाम संबंध आर्य-अनार्य तथा सुर- असुर के संबंधों की भी व्यंजना है। केवट, जटायु और शबरी के प्रति राम का श्रद्धाभाव, उनके दलित-सवर्ण सामंजस्य का पर्याय है। इस संदर्भ में दिनकर जी का मत है- "भारत में संस्कृति- समन्वय की जो प्रक्रिया चल रही थी, रामायण में उसकी अभिव्यक्ति मिलती है। रामायण की रचना तीन कथाओं को लेकर पूर्ण हुई। पहली कथा तो अयोध्या के राजमहल की है, जो पूर्वी भारत में प्रचलित रही होगी; दूसरी रावण की जो दक्षिण में प्रचलित रही होगी; और तीसरी कथा किष्किंधा के वानरों की, जो वन्य जातियों में प्रचलित रही होगी। आदिकवि ने तीनों कथा को जोड़कर रामायण की रचना की।'(4) किन्तु उससे भी अधिक संभावना इस बात की है कि राम, वास्तव में ऐतिहासिक पुरुष थे। और सच में उन्होंने किसी वानर जाति की सहायता से लंका पर विजय प्राप्त की थी। रामायण में जो तीन प्रचलित कथाएँ हैं, उनके तीन अलग-अलग नायक भी हैं- राम, रावण और हनुमान। ये तीनों चरित्र तीन पृथक- पृथक संस्कृतियों के प्रतीक हैं, जिनका अद्भुत समन्वय वाल्मीकि ने दिखाया है। राम भारतीय मनीषा के एक ऐसे आदर्श नायक है, जिनका सर्वाधिक प्रभाव भारतीय समाज पर पड़ा है। वे एक आदर्श पुत्र, आदर्श शिष्य, आदर्श भाई, आदर्श पति तथा आदर्श राजा के रूप में सर्वविदित हैं। राम को लेकर ही गोस्वामी तुलसीदास ने 'रामराज्य' की परिकल्पना की है। तुलसी का यही रामराज्य गांधी को अतिप्रिय था। राम असत्य के खिलाफ जीवन भर लड़ाई लड़ते रहे। इसलिए वे अंधकार के विरुद्ध प्रकाश, अधर्म के विरुद्ध धर्म के प्रतीक हैं। राम में देवत्व का स्वरूप चाहे जितना भी प्रशंसनीय रहा हो, उसका मानव रूप निश्चित रूप से अनुकरणीय है। वे मनुष्य होने की तमाम मयार्दा से निष्पन्न पुरुष श्रेष्ठ है। तुलसीदास ने उसे मयार्दा पुरुषोत्तम कहकर उनका समुचित मूल्यांकन किया है। राम को कुछ लोग सामान्य मनुष्य मानते हैं तो कुछ लोग भगवान विष्णु के अवतार। रामायण में राम का वर्णन एक संघर्षशील मनुष्य के रूप में किया गया है। वहाँ एक ही जगह राम के बारे में नारद जी कहते हैं कि रूप, रंग, गुण, बल और वीर्य में राम विष्णु के समान हैं। राम का जीवन भारतीय मानस में संघर्ष की चेतना जगाने वाला है। राम अयोध्या के प्रशस्त सम्राट दशरथ के घर राजकुमार के रूप में उत्पन्न हुए, लेकिन उन्हें भी सामान्य बालकों की भाँति गुरु वशिष्ठ तथा विश्वामित्र के आश्रम में रहकर ज्ञान- साधना करनी पड़ी। जिस वक्त माता-पिता के सानिध्य में रहकर बाल जीवन का आनंद लिया जा सकता था, उसी समय उन्हें ताड़का, सुबाहु और मारीच जैसे दुर्दांत राक्षसों का समना करना पड़ा। राम विवाह करके दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किये ही थे कि चौदह वर्षों का कठोर वनवास मिला। वहाँ फिर सीता हरण की घटना घटी और रावण जैसे भयानक दानवों से पाला पड़ा। और तो और जब चौदह वर्षों का वनवास भोगकर घर लौटे और उनका ससम्मान राज्याभिषेक हुआ, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद उन्हें पत्नी सीता से अलग होना पड़ा। राम जो कुछ भी पाते हैं, वह अपने संघर्ष के कारण। राम यूँ ही राम नहीं बन गये। इसके केंद्र में उनका अपार धैर्य है। उनकी सादगी है। उनकी स्थित-प्रज्ञता है। जितनी घटनाएँ राम के साथ घटीं, उनमें से कोई एक घटना भी किसी सामान्य मनुष्य के जीवन में घट जाए, तो वह मिट जाएगा। परंतु राम परिस्थितियों से ठोकर खाकर और मजबूत होते गये। राम की सबसे बड़ी विशेषता है कि वे कभी विचलित नहीं होते.....जब उन्हें राज्याभिषेक की शुभ सूचना मिली, तब भी वे सामान्य बने रहे और जब वनवास का आदेश मिला, तब भी वे सामान्य ही बने रहे। यही चीज उन्हें मनुष्य से ऊपर उठाकर ईश्वरीय बनाता है। सबकुछ मिलने पर भी उनमें कोई अहंकार नहीं है और न ही सबकुछ खोकर वे क्रोधी, वाचाल या अव्यवहारिक होते हैं।

राम जितने पूजनीय और सम्माननीय हैं, उतने ही विवादास्पद भी। राम पर कुछ लोगों ने लांछन भी लगाने की चेष्टा की है। यथा - राम ने छिपकर बाली का वध किया! राम ने शंबूक की हत्या की! राम ने माता सीता को निर्वासित किया.....आदि-आदि! इन लांछनों की क्रमिक समीक्षा अनिवार्य है, ताकि राम के प्रति जो अपवाद फैला है, उसकी पड़ताल की जा सके। सबसे पहली बात यह है कि 'राम ने छिपकर बाली का वध किया!' इस संदर्भ मे यह विचारणीय है कि राम ने बाली का वध इसलिए किया, क्योंकि बाली ने अपने छोटे भाई की भार्या तारा का अपहरण किया था, जो घोर अपराध था। मानस में तुलसीदास ने स्पष्ट कर दिया है कि पराई स्त्री का शील-हरण करने वाला पुरुष घोर अपराधी है। ऐसे पुरुषों की हत्या करना पाप नहीं, पुण्य है! जहाँ तक शंबूक की हत्या तथा सीता - निर्वासित के प्रसंग हैं। इस संदर्भ में स्पष्ट कहा जा सकता है कि 'रामायण' के उपरोक्त दोनों प्रसंग प्रक्षिप्त हैं। हम सहज ही समझ सकते हैं कि जो राम, केवट का सम्मान कर सकता है, जो राम जटायु को अपनी गोद में लेकर पिता -सा सम्मान दे सकता है, जो राम शबरी के भक्तिभाव में निमग्न होकर जूठा बैर खा सकता है! वह क्या शंबूक जैसे ऋषि की हत्या कर सकता है......? वह भी इस अपराध के कारण कि उसने वेदों का पाठ किया है, मंत्रों का उच्चारण किया है। राम का व्यक्तित्व अत्यंत विराट है। उनसे ऐसे निकृष्ट कर्मों की कल्पना अनुचित और असंगत है। तीसरा प्रसंग है - सीता-निर्वासन का। विचारणीय है कि क्या राम ने उसी सीता का परित्याग किया, जिसके लिए वह समुद्र में पुल बांधा....जिसके लिए वह सैनिकों का संगठन किया.....जिसके लिए वह रावण समेत तमाम असुर कुलों का सर्वनाश किया। इस प्रसंग में यह भी दृष्टव्य है कि जिस राम ने पत्थर बनी माता अहिल्या का कायान्तरण किया, वह राम अपनी धर्मपत्नी का परित्याग क्या किसी धोबी के कहने पर कर सकता है। मैंने अहिल्या के लिए 'कायान्तरण' शब्द का प्रयोग इसलिए किया, क्योंकि वास्तव में अहिल्याबाई पत्थर न बनी होगी, बल्कि लोकलाज के कारण अथवा पति से परित्यक्त और समाज से बहिष्कृत होने के कारण पत्थर जैसी हो गई होगी! राम ने समाज से च्युत एक अबला स्त्री का सामाजिकरण किया। उसे खोया हुआ सम्मान दिलाया। ऐसे उदारमना राम से सीता-निर्वासन जैसा घृणित कार्य कैसे संभव है! इस तरह की तमाम धारणाएँ निराधार हैं। उपरोक्त संदर्भ में कहना न होगा कि रामायण के ये प्रसंग प्रक्षिप्त हैं। यह कैसे राम कथा में मिला दिया गया, इसके बारे में रामकथा पर मौलिक शोध करने वाले फादर कामिल बुल्के का कहना है कि, "वेद में राम कथा विषयक पात्रों के सारे उल्लेख स्फुट और स्वतंत्र हैं। रामकथा -संबंधी आख्यान-काव्यों की वास्तविक रचना वैदिक काल के बाद, इक्ष्वाकुवंश के राजाओं के सूतों ने आरंभ की। इस रामायण में अयोध्याकाण्ड से युद्धकांड तक की ही कथावस्तु का वर्णन था। कुशी -लव उसका गान करके और उसकी अभिनेता का अभिनय दिखाकर अपनी जीविकोपार्जन करते थे।"(6) इस प्रकार आदि रामायण की कथा विकसित होने लगी। कथा का कलेवर बढ़ने लगा। ज्यों-ज्यों राम कथा का यह मूल रूप लोकप्रिय होता गया, त्यों-त्यों जनता को यह जिज्ञासा होने लगी कि राम कैसे जनमे? सीता कैसे जनमीं? रावण कौन था?.... आदि-आदि। जनता की इन्हीं जिज्ञासाओं की शांति के लिए 'बालकांड' और 'उत्तरकांड' रचे गये। इस तरह राम की कथा रामायण (राम- अयन अर्थात राम का पर्यटन) न रहकर, पूर्ण रामचरित के रूप में विकसित हुई। 'राम जैसे-जैसे लोकप्रिय होते गये, वैसे-वैसे उनमें अलौकिकता भी आती गई। अतएव, राम मानव से परमेश्वर में तब्दील हो गये। राम की विराटता को शब्दों में बांधते हुए राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने उचित ही लिखा है- 'राम तुम्हारा जीवन ही काव्य है। कोई कवि बन जाय, सहज संभाव्य है।।'(7) कुल मिलाकर संपूर्ण भारतीय समाज 'राममय' है। राम अगर 'मिथ' ही है! अगर राम कल्पना ही है! तो भी, किसी ने कितना सुंदर मिथ रचा है। किसी ने कितनी सुंदर कल्पना की है! सच में अगर कोई मनुष्य या कोई भी समाज राम को अपने भीतर पचा ले, उनके तमाम आदर्शों को अपने जीवन में उतार ले। राम के रामत्व को आत्मसात कर ले, तो वह व्यक्ति या समाज कितना उदात्त, श्रेष्ठ और अनुकरणीय हो जाएगा।

संदर्भ- ग्रंथ- सूची : (1) संस्कृति के चार अध्याय- रामधारी सिंह दिनकर, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण -1956 ई., पृष्ठ- 77 (2) भारत का इतिहास- रोमिला थापर, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण -1975 ई., पृष्ठ- 27 (3) दलित साहित्य का समाजशास्त्र- हरिनारायण ठाकुर, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण-2009 ई., पृष्ठ- 173 (4) संस्कृति के चार अध्याय- रामधारी सिंह दिनकर, पृष्ठ -76 (5) हिन्दी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली- डॉ. अमरनाथ, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण-2012 ई., पृष्ठ- 299 (6) संस्कृति के चार अध्याय- रामधारी सिंह दिनकर, पृष्ठ- 78 (7) साकेत- मैथिलीशरण गुप्त, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण- 1932 ई., पृष्ठ- प्रथम।

दस्तक प्रभात
डॉ. उमेश कुमार शर्मा

सफाई का मुद्दा महत्वपूर्ण है भाई

जी हॉं दोस्तों, यह मेरा अनुभव कह रहा है कि देशवासियों को सफाई के प्रति जागरूक भले ही किया जा रहा है, पर, सफाई बहुत कम दिख रही है। पिछले वर्ष अहमदनगर के एक विद्यालय में मेरा जाना हुआ। वहॉं के महिला शौचालय में पहुॅंच कर बहुत दुःख हुआ। इतना गंदा शौचालय कि लग रहा था बरसों से साफ नहीं किया गया। इसी तरह जब अपने कुछ परिचित/रिश्तेदारों के यहां जाना हुआ तो वहां भी शौचालय बुरे हाल में मिला। मेरा यह अनुरोध है कि यदि हम सामान्य नागरिक हैं तो हमें भावी पीढ़ी की सुरक्षा के लिए बड़ी- बड़ी बातों के साथ शौचालय की सफाई पर भी चर्चा करनी चाहिए। हम बस खाने-कमाने में लगे हैं। अपना सुख, अपना घर, अपना रोना ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। शौचालयों की सफाई/पानी की टंकी की सफाई की सबसे अधिक आवश्यकता है। बड़े-बड़े सरकारी दफ्तरों/उनकी कॉलोनी में भी टॉयलेट/पीने के पानी से जुड़ी पानी की टंकी पीढ़ियों से साफ नहीं हुई हैं। इसपर किसी का ध्यान भी नहीं जाता है। यही हाल अस्पतालों में भी है। जनरल वार्ड का शौचालय तो इतना गन्दा मिलता है कि मत पूछो। जबकि वहॉं सफाई कर्मचारी की भी कोई कमी नहीं होती। दिल्ली की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में अचानक शौचालय जाना पड़ा, महिला शौचालय देखकर होश उड़ गये। छात्रों से पूछने पर पता चला कि बरसों से झगड़ा चल रहा पर प्रशासन की ऑंखें बन्द हैं। मुद्दा कामचोरी का नहीं है, मुद्दा यह है कि लोगों का ध्यान ही नहीं जाता है कि शौचालय को साफ रखना मानव जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सरकार कितने भी नियम बना दे, जबतक सोच नहीं बदलेगी, सफाई नहीं मिलेगी। एक बड़े सरकारी संस्थान के अधिकारी से जब इस विषय पर चर्चा की तो उन्होंने बड़े हल्के से कहा.."अरे! इस टंकी का पानी पिया थोड़े जाता है, मल-मूत्र की सफाई के काम आता है बस।" उनकी यह बात सुनकर बहुत दुःख हुआ। समझाने का प्रयास भी किया पर उनके व्यवस्थित दिमाग को छू पाना असंभव रहा। मित्रों, बच्चों को बचपन से साफ-सफाई के प्रति जागरूक करना पड़ता है। कोई बड़ी मंडी हो, दुकानदार बगल में पिच-पिच करके थूकता मिलता है। जरा सी दूरी पर मूत्र त्याग करके वह यह नहीं समझता कि अनजाने में वह कितने रोगों को बढ़ाता फिरता है। कई लोग पान मसाला खाकर जगह-जगह थूकते मिलते हैं। सड़क के किनारे मूत्र त्याग करना तो उनका अधिकार होता है। बड़े-बड़े होटलों में भी पानी की टंकी में बन्दर, कबूतर तक मरे मिले। बात यह नहीं है कि हम इतने लापरवाह क्यों हैं, बात यह है कि हमें गन्दगी से उत्पन्न बीमारियों की भयावहता का ज्ञान ही नही है। मेरे विचार से भोजन के साथ सफाई के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। भले उसके बदले हमें शाबासी न मिले, पर पीढ़ियों को निरोगी जीवन अवश्य मिल सकता है।

दस्तक प्रभात/रश्मि लहर

अभिभावक

बच्चो के बढ़ते दबाव हटाये खुशनुमा जीवनपयोगी घुंटी पिलाये वर्षों पूर्व बच्चों का जीवन आजकल के बच्चों से भिन्न होता था । खानपान, रहन सहन, पहनावा, मनोरंजन के तरीके, खेल का साधन बिल्कुल था साधारण । हालाँकि आजकल के बच्चों में कई गुणा भारी बदलाव का किस्सा अभिभावक से छुपा नहीं है । अभिभावकों से आम वर्ग में चर्चित रहता है बच्चों का किस्सा । अभिभावक से आम वर्ग में आजकल उनकी तमाम बदलती जीवन शैली पर अपनी टिप्पणी करते है । पहले बच्चों को साधारण निःशुल्क मनोरंजन से जुड़ने की उछलकूद रहती । वे खुद आगे आते जुटते खेलते । इनमें आजकल के बच्चों की जुड़ने में निःशुल्क का प्रश्न नहीं रह गया । बिन पैसे के अपनी अलग कल्पना विद्यमान रहती है । इनमें बच्चों की जीवन शैली घरपरिवार के बड़ेबुजुर्ग की सोच दृष्टिकोण से काफी हद तक विपरीत है । एक बात यह भी है कि घर परिवार में बच्चों के स्वभाव खर्चीले बन गए । भले ही खर्चीले हो बिना बच्चो के परिवार का माहौल भी सूना सूना सा लगता है । पहले बच्चों के पास घरेलू वस्तुओं का उपयोग खेलने में विचित्र होता हैरान कर देता । अभिभावकों को हैरानीयत भी होती । खेलने के साधन जुटाने का एक अलग माहौल उसपर शौक भी अलग होता खुद भी जुटाते घरवाले भी मुहैया कराते । घर की चहारदीवारी में बेकार पड़ी वस्तुओं को उपयोगी बनाते उन्ही से मस्त होकर खेलते । उनको उसी में असीमित आनंद का अनुभव होता । वे विद्यालय से लौटते घर में घुसते ही अपने खेलकूद के माहौल में बड़े चाव से खेलते, खुश होते खेलते । सभी बच्चो का आपस में मिलने जुलने और खेलने का चाव घना होता उसमें आनन्द बटोरने का एक जादू सा प्रतीत होता । घर दुकान गोदाम पड़ोसी के बरामदे या खुले स्थान खेल मैदान कहीं भी रमकर खेलते । इस आनंद का किस्सा समूचे मोहहले में गूंजता ।एक दूसरे में आनद का किस्सा साझा होता । अक्सर वे किसी भी परिवार के अभिन्न अंग बन जाते । किसी भी मित्र के घरपर ठहरना खाना खा लेना अपनापन मित्रता का व्यवहार गुण परिचय दशार्ते । खाने की वस्तु परोसने पर बड़े चाव से बेरोकटोक खाते । सभी घरों में लाड़ प्यार में कमी नहीं होती। अपने घर से ज्यादा पराये घर को आनंददायक स्थल बना लेते थे । बच्चों को रुपये पैसे से खुश होने की बजाय एक दूसरे साथी संगी के संग आपस में खेलने कूदने के सिवाय कुछ भी इच्छा नहीं होती । दिन या फिर रात खुशी से जीवन जीने की बात अजीब रहती । असली आनंद अजीबोगरीब खुशनुमा होता । आज हमें बच्चों की खशी हेतु खर्च करके वास्तविक खुशी मिल नही पाती । खुशी का अहसास तक नहीं होता । पहले जमाने के बच्चों में अपने आप खेलने कूदने के स्थान हँसी आनद में भर जाते ।पहले छुट्टियों का समय अलबेला कर लेते थे बच्चे । बच्चों को मात्र पांच दस पैसे मिलते उसी की चेहरे पर खुशी खिल उठती । उसका सदुपयोग करते बचत भी करते । खर्च करते पर जरूरत की वस्तु के वास्ते । ज्यादातर माता पिता के संग परिवार के संग समय बिताने घूमने फिरने किसी भी विवाह शादी समारोह आदि में संग जाने की खुशी रहती । बच्चो में खेलने कूदने की कसरत अनूठी लगती । एक दूसरे के पीठ पर चढ़कर या कुश्ती कब्बडी रुमाल कुर्सी आदि के खेल खेलते लट्टू घुमाते, कांच की गोटी से खेलते, काठ की लकड़ी को बेट बनाते, पुराने कपड़े लपेटकर गेंद बनाते, सड़क के पत्थर बटरोकर उनसे खेलते ऐसे खेलो की एक लंबी सूची है । अपनी पढ़ाई के पोथी पन्ने ढोकर खेल खेलने के आनंद ही नही लेते बल्कि शारीरिक अच्छी कसरत के खेल खो जाते । ये सभी निःशुल्क खेल बच्चो को एकाग्र करते खेल में लीन कर लेते । किसी किसी बच्चो के मन मे ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने एवं घरेलू खेलों में रमने, दादा दादी सह परिवारजनों के बुजुर्गों साथ बैठकर रौचक ज्ञानवर्धक कहानियों के सुनने, अपने आत्मीयजनों से परिवारजनो के बीच बैठकर बहुत ही ज्ञान के प्रेरक प्रसंग सुनना आदि का एक माहौल घरपरिवार में तो बनता ही कभी कभी पड़ोसियों के बच्चो के संग सामूहिक बैठकर बच्चो को शारीरिक मानसिक ज्ञान की कसरतें खूब कराई जाती । इसमें बच्चों की निष्ठा लगन खूब रहती । वे साधारण पौष्टिक खाद्य ही खाते । स्वस्थ्य बने रहने में खुद सतर्कता बरतते घरपरिवार में समय पर खाते ।उनका अपनापन का भाव जगाने का तालमेल बहुत ही शक्तिशाली होता । इसमें अभिभावक स्वयं जुटता । वे कदापि लापरवाही नहीं बरतते । परंतु आजकल ज्यादातर वैसे विचारों की कमी साफ झलकती है । समूचे कार्य करने के तरीके उसकी गति में हमारी कार्यव्यवस्था में कमी का परिणाम बच्चें पर ज्यादा फर्क पड़ता नजर आया । इसमें घोर लापरवाही सबसे बड़ा एक कारण है । आजकल बच्चो के खेलों पर खर्चा का हिसाब सोच से बाहर है। उनको खेलने की रुचि बनी है बहुत अच्छा है, मगर उसका आनद खुशी से ज्यादा तनावपूर्ण रवैया की झलक दिखती है ।इसका उदाहरण अभिभावकों का अपना बच्चा ही दे देता है । हम उनके मानसिक शारीरिक विकास में बाधक बने है । उनकी दिनचर्या की वास्तविकता को एक सिरे पर ले जाने से अक्सर दूर है । कहा जाता है कि बच्चे के दिमाग के द्वार को खोलने में उनको शारीरिक मानसिक रूप से मुक्त परिवेश में मुक्त खेलने कूदने हँसने मनोरंजन आदि से जुड़ने का खुशनुमा माहौल सबसे ज्यादा जरूरी है । वही हम जुटा नहीं पाते । हमारा दैनिक सफरनामा पहले भी समान था आज भी समान है । इसको असमान हम खुद बना दिये जो कि खुशी के माहौल से विपरीत है । हमें बच्चो के बढ़ते जीवन पर उपयोगी कदम उठाना है न कि दबाव के । हम आज दबाव के जीवन से बच्चो की जीवनपयोगी बातों को गहराई से नाप नही रहे । हरेक अभिभावक अपनी संतान की एक न एक समस्या के खतरे में उलझे हालात में प्रत्यक्ष किये जा रहे है । हमे आज फिर से खुशनुमा जीवन जीने के माहौल में बच्चों को एकत्रित करने की कड़ी चुनोतियाँ में उनको खुशी की जिंदगी में सर्वश्रेष्ठ बनाना है । अतीत और वर्तमान में बच्चो का जीवन आरामदायक के बजाय एक कठिन डगर संघर्ष में घिरा है । सबसे पहले इससे उबरना होगा । इसके लिए अभिभावकों को परिवार के नियम अनुशासन की कड़ी में लचीलापन लाना होगा । बच्चो को अपने भाव विचार में मुक्त होकर अपनी विकसित गति को सुचारू चलाने में सहयोगी बनना ही पहली जिम्मेवारी है । यह जिम्मेदारी निभती है तो बच्चों को खुलापन महसूस होगा वही खुले मन से उनकी योजनाओं को फलीभूत होने की गुंजाइश बढ़ेगी ।

दस्तक प्रभात/ललित शर्मा

https://t.me/AllNewsPaperPaid

केंद्र सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (प्रोसिजर एंड सेफगार्ड फॉर इंटरसेप्शन, मॉनिटरिंग एंड डिक्रिप्शन ऑफ इंफोर्मेशन) रूल्स में संशोधन किया है। अब न तो 'सुरक्षा एजेंसी' और न ही गृह सचिव इंटरसेप्शन रिकॉर्ड्स या डिक्रिप्टिड इंफोर्मेशन को हर छह माह के अंतराल पर नष्ट करने के आदेश नहीं दे सकेंगे।

— अरविन्द गुणाशेकर, पत्रकार@arvindgunasekar

'मदर इंडिया'

भारत डोगरा

न्याय की खातिर जो संघर्षरत रहीं

लगभग 65 वर्ष पहले महान फिल्मकार महबूब ने अपनी फिल्म 'मदर इंडिया' में ऐसी महिला की जीवन-कथा चित्रित की थी जो जीवन-भर गरीबी और अभाव से संघर्ष करने के बाद भी न्याय के लिए, जन-हित के लिए बड़ा बलिदान करने के लिए तैयार रही। हम ऐसे फिल्म-चरित्र की तो बहुत प्रशंसा करते हैं, पर कभी-कभी भूल जाते हैं कि ऐसी अनेक महान महिलाएं हमारे बीच सदा रही हैं-ऐसी 'मदर इंडिया' जिसे अपने गांव और आस-पड़ौस के गांव के बाहर चाहे लोग न जानते हों पर गांव के लोग जानते हैं कि उन्होंने बेहद प्रतिकूल परिस्थितियों में न्याय, जन-हित के लिए कितना कुछ किया है।

'मेथी मां' का जीवन इस विचार का सजीव उदाहरण है। उनके जीवन के शुरुआती दौर में दुखद घटनाओं का ऐसा सिलसिला रहा जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने साहस और धैर्य के बल पर न केवल अपने दुखों पर काबू पाया, बल्कि आगे बढ़कर गांव के कल्याण तथा विकास में असाधारण योगदान दिया सूचना का अधिकार, मनरेगा जैसे बड़े सामाजिक आंदोलनों में अहम भूमिका निभाई। राजस्थान के जिला अजमेर में किशनगढ़ प्रखंड के अंतर्गत खेड़ा गांव में रहने वाली 65 वर्षीय दलित महिला मेथी मां जब बहुत छोटी थीं तभी उनके माता-पिता का देहांत हो गया। वे प्रवासी मजदूर थे जिनकी चम्बल की बाढ़ में डूबने से मृत्यु हो गई। माता-पिता की मृत्यु के बाद वह एक शराबी रिश्तेदार के घर में रहीं जिसने मेथी मां को चंद रुपयों के लिए एक उम्रदराज व्यक्ति को सौंप दिया। मेथी का उम्रदराज पति एक दुर्घटना में इतनी बुरी तरह घायल हो गया कि उसके बाद कभी बिस्तर से उठ नहीं सका। मेथी ने इस विपत्ति की घड़ी में लंबे समय तक उसकी हर संभव देखभाल की।

इन सब परेशानियों के बावजूद मेथी जब सामाजिक कार्यकर्ताओं के संपर्क में आईं तो अपने गांव की सेवा के लिए बड़ी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार थीं। उन्होंने प्रसाविका (प्रसव में सहायिका दाई) का प्रशिक्षण लिया और जल्द ही इस काम में कुशलता हासिल कर ली। उन्होंने धुआंरहित चूल्हा बनाना भी सीख लिया और अपने गांव के रसोईघरों में अनेक धुआंरहित चूल्हे बिठाए। गांव में महिला-समूहों को संगठित करने में अग्रणी भूमिका निभाई। शीघ्र ही जात-पात के संकीर्ण दायरे को सफलता से पार करते हुए उन्होंने गांव के लोगों का इतना समर्थन पा लिया कि पंचायत में लोगों ने मेथी को वार्ड सदस्य चुन लिया। एक बार जब उनके गांव में दो परिवारों के बीच झगड़ा हुआ और लगा कि झगड़ा हिंसात्मक रूप ले लेगा, ठीक उसी समय मेथी मां अदम्य साहस दिखाते हुए बीच-बचाव करती हुई कूद पड़ीं और अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए विनती के स्वर में कहा, मार-पीट पर उतारू होने के पहले सिर्फ इतना सोच लेना कि नुकसान तुम्हारे सगे-संबंधियों का ही होगा। उनके इस आग्रह में इतनी गहराई थी कि झगड़े में शामिल दोनों परिवार पीछे हट गए और सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलह कर ली।

महान फिल्मकार महबूब ने अपनी फिल्म 'मदर इंडिया' में ऐसी महिला की जीवन-कथा चित्रित की थी जो जीवन-भर गरीबी और अभाव से संघर्ष करने के बाद भी न्याय के लिए, जन-हित के लिए बड़ा बलिदान करने के लिए तैयार रही। हम ऐसे फिल्म-चरित्र की तो बहुत प्रशंसा करते हैं, पर कभी-कभी भूल जाते हैं कि ऐसी अनेक महान महिलाएं हमारे बीच सदा रही हैं-ऐसी 'मदर इंडिया' जिसे अपने गांव और आस-पड़ौस के गांव के बाहर चाहे लोग न जानते हों पर गांव के लोग जानते हैं कि उन्होंने बेहद प्रतिकूल परिस्थितियों में न्याय, जन-हित के लिए कितना कुछ किया है। 'मेथी मां' का जीवन इस विचार का सजीव उदाहरण है। उनके जीवन के शुरुआती दौर में दुखद घटनाओं का ऐसा सिलसिला रहा जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने साहस और धैर्य के बल पर न केवल अपने दुखों पर काबू पाया

मेथी के गांव में शराब का एक ठेका था जिसकी वजह से गांव की महिलाएं तथा बच्चे बेहद परेशान थे। उन्होंने महिलाओं को एकजुट करके शराब के ठेके के खिलाफ ऐसी मुहिम छेड़ी कि शराब के ठेके को गांव से बाहर ही निकाल दिया। गरीब परिवार की एक महिला को गांव के एक दबंग परिवार ने डायन कहकर बहुत मारा-पीटा था। मेथी मां ने इस अन्याय के विरोध में गांव वालों को एकजुट किया। जल्द ही उस दबंग परिवार ने माफी मांगी और उस गरीब महिला को दोषमुक्त घोषित किया गया।

चाहे मामला आग लगने से पीड़ित अरामपुरा गांव के निवासियों की मदद का हो या कालीडुंगड़िया गांव में हुए हमले में पीड़ित व्यक्ति के लिए जयपुर फुट की व्यवस्था करने का, मेथी किसी भी तरह के अच्छे कामों में अपना योगदान देने के लिए स्वयंसेविका के रूप में हमेशा तैयार रहीं। यह लेखक उन्हें मिला तो उन्होंने कहा, 'वास्तव में सबसे महवपूर्ण बात यह है कि हर इंसान दूसरे इंसान के दुख को कम करने में अपना योगदान करे।'

अधिकांश गांव वालों के लिए गाल्कू मां की छवि और व्यक्तित्व मां की रही। करीब तीस साल पहले किशनगढ़ प्रखंड के पानेर गांव में महिला समूह के संगठन से जुड़ने के बाद उनके जीवन ने एक नया मोड़ ले लिया। कई स्थानों पर जहां महिला हिंसा तथा शोषण की घटनाएं होतीं तो गाल्कू मां जाकर विरोध प्रदर्शन में भाग लेतीं और यथासंभव मदद करती थीं। जयपुर में आरटीआई (सूचना के अधिकार) के एक धरने में वह लगातार 53 दिनों तक शामिल रहीं। उनके गांव में मजदूरों को जब मजदूरी नहीं मिली तो गाल्कू मां ने मजदूरों को इसका विरोध करने के लिए एकजुट किया। परिणाम यह हुआ कि पदाधिकारियों ने रात में ही मजदूरी बांटने के लिए विशेष प्रबंध किया। जब राजस्थान मजदूर-किसान मोर्चा प्रारंभ हुआ तो वह मोर्चे की सक्रिय सदस्य बनीं और मोर्चे के विरोध-प्रदर्शनों में बढ़-चढ़कर भाग लेती थीं। गाल्कू मां ने वार्ड पंचायत का चुनाव लड़ा तो आराम से जीत गईं। जरूरतमंद महिलाओं तथा बुजुर्गों की पेंशन तथा अन्य लाभप्रद योजनाओं के सही-सही लागू होने पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि रोजगार प्राप्ति में गरीबों को प्राथमिकता मिले और स्वयं नरेगा के कार्यस्थलों पर जाकर निरीक्षण करतीं और व्याप्त गड़बड़ियों का पता लगाती रहीं।

पिंगुन गांव, दुदु प्रखंड, जिला जयपुर की दलित महिला रुकमा मां अनेक संघर्षों से जुड़ी रहीं। एक बार रुकमा को दूरभाष से धौलप्रिया गांव में रेप की घटना की सूचना मिली। यह भी सूचना मिली कि बदमाशों ने गांव की घेराबंदी भी कर दी है ताकि कोई बाहर का व्यक्ति गांव में न घुस सके। ऐसे हालात में भी रुकमा ने एक ग्रामीण साथी को तैयार कर लिया जिसने उसे मोटरसाइकिल से घेराबंदी को तोड़ते हुए गांव के अंदर पंहुचा दिया। जब बदमाश और उनके साथियों ने रुकमा से उसका परिचय पूछा तो रुकमा ने जवाब दिया, 'मैं तुम्हारी मां हूं।' उन्होंने निडरता से न्याय के लिए लड़ाई की। रुकमा ने राजस्थान की रूपकंवर 'सती' घटना के विरोध में भी लोगों को संगठित किया। आरटीआई धरने के लिए लगातार 40 दिन ब्यावर और लगातार 53 दिन जयपुर में मौजूद रहीं।

साठ वर्षीय भंवरी देवी ने ग्रामीण महिलाओं को संगठित करने का काम तीस वर्षों से भी अधिक समय तक किया। अपनी युवावस्था में आजीविका के लिए सब्जी बेचने का कार्य किया। फिर उनका रुझान वृहत्तर सामाजिक मुद्दों की तरफ होने लगा जैसे सूखा-राहत का काम कैसे किया जाए जिससे जरूरतमंदों को समुचित लाभ मिल सके। उनके सामने सबसे चुनौतीपूर्ण समय तब था जब उन्होंने गांव के उन ताकतवर लोगों के विरोध में खड़े होने का निर्णय कर लिया जो एक अव्यस्क लड़की के रेप के आरोपियों का बचाव कर रहे थे। भंवरी ने बड़ी जोखिम भरी लड़ाई लड़ी। कई मुश्किलों का सामना करने के बाद दोषियों को सजा मिली। एक अन्य लड़की के अपहरण के मामले में भंवरी ओर उनकी साथियों ने उस जगह को ढूंढ निकाला जहां अपहरणकर्ता छिपे थे। भंवरी और उनके साथियों ने उस जगह पर पंहुच कर उस कमरे का दरवाजा तोड़ दिया और लड़की को सुरक्षित बरामद कर लिया गया तथा अपरहणकर्ताओं को पुलिस के हवाले कर दिया गया।

विज्ञापन और भाजपा

मीडिया

सुधीश पचौरी

भाजपा के राजनीतिक विचार पहले से ही पब्लिक के बड़े हिस्से में स्वीकृत होकर उसकी जुबान पर चढ़ चुके हैं। यही हमारे गली-मुहल्ले के 'जन विमर्श' में बाजाप्ता सुने जा सकते हैं। यही भाजपा का नेरेटिव है जो हर बाइट, हर खबर, हर विज्ञापन के जरिए पुख्ता होता रहता है

यह चुनाव का सीजन है, विज्ञापनों का सीजन है लेकिन खबर चैनलों में भाजपा को छोड़ किसी और दल के विज्ञापन नहीं नजर आते। ये सभी 'आम आदमी' को टारगेट करते हैं। मोदी सरकार की सारी योजनाओं को उनके जीवन को बेहतर बनाने वाला बताते हैं। सीधी सादी भाषा में मोदी की अनेक याजनाओं से हुए लाभों को गिनाते हैं। इनमें मोदी का चेहरा 'स्थायी भाव' की तरह होता है और कई में कैच लाइन 'अब की बार चार सौ पार' और कई में 'मोदी की गारंटी की गारंटी' होती है।

इनके मुकाबले, पंजाब में 'आप' पार्टी के सीएम भगवंत मान की योजनाओं के पंजाबी भाषा वाले विज्ञापन ही नजर आते हैं। जिस तरह भाजपा के विज्ञापनों में मोदी का चेहरा एक फीचर होता है उसी तरह पंजाबी विज्ञापनों में पंजाब के सीएम भगवंत मान का चेहरा होता है। बाकी किसी दल के विज्ञापन, खबर चैनलों में अभी तक नहीं देखे गए। यह अपने आप में अजीब सी बात है, जो चैनलों में विपक्ष की 'दयनीय उपस्थिति' के बारे में बताती है।

कुछ पहले तक जिन-जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उनकी सरकारों के विज्ञापन महीनों पहले से चैनलों में आने लगे थे। छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकारों के जनहित कार्यों को गिनाते चलते थे। राज्य-सीएम के चेहरे हुआ करते थे। झारखंड सरकार के विज्ञापन तो चैनलों में आते ही थे तेलंगाना के विज्ञापन तक दिखते थे, लेकिन लोक सभा के चुनावों में कुछ दिन रह गए हैं, पंजाब की 'आप' सरकार को छोड़ अन्य किसी 'इंडी दल' के विज्ञापन नहीं दिखते।

उधर,भाजपा सिर्फ विज्ञापनों के जरिए अपना संदेश नहीं देती, उसके सबसे बड़े नेता मोदी जी स्वयं हर दिन किसी न किसी जनसभा में किसी योजना की सौगात देते हुए जो भाषण देते हैं वो भी लाइव टेलीकास्ट होकर या खबर के रूप में आकर अप्रत्यक्ष किस्म के विज्ञापनों का रूप ले लेते हैं और विज्ञापनों से मिलकर उनके संदेश भाजपा के पक्ष में एक सघन वातावरण बनाते रहते हैं। विज्ञापन का तीसरा संस्करण चैनलों की बहसों में नजर आता है, जिनमें दलों के प्रवक्ता, पत्रकार/विश्लेषक विज्ञापन का काम करते हैं। ये सीधे विज्ञापन नहीं होते लेकिन ये हर दल की राजनीतिक लाइन को दर्शकों तक पहुंचाने वाले होते हैं। इसे हम चैनलों द्वारा आयोजित पब्लिक के बीच की जाती बहसों में देख सकते हैं जो सीधे 'पब्लिक के मूड' को कवर करते हैं। ये एक प्रकार की 'पब्लिक डिबेट' होते हैं जो जनता के तात्कालिक मूड मिजाज की जानकारी देते रहते हैं। ऐसे कार्यक्रम भी अंततः विज्ञापनों द्वारा बनाए जाते वातावरण को 'पुष्ट' या 'अपुष्ट' करते रहते हैं।

अगर अब तक के सीधे 'पेड विज्ञापनों' या बहसों में विशेषज्ञों के विचारों को, उनके बीच होते तर्क-वितर्क का जायजा लें तो कह सकते हैं कि भाजपा हर खबर, हर बहस में मोर्चा मारती नजर आती है। सारी बाइटें, खबरें और नारे पब्लिक के दिमाग में यही बिठाते हैं कि भाजपा ने बहुत कुछ किया है, बहुत करना है, मोदी ने बहुत कुछ किया है। दुनिया में देश की इज्जत बढ़ाई है। 370 हटाया है। मंदिर दिया है। उनका नारा है 'सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास'। उनका संकल्प भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। भारत को 'विश्वगुरु' बनाना है। इसे मोदी ही कर सकता है। इसके लिए चाहिए एक एकजुट बहुमत वाली ताकतवर सरकार। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी की गारंटी है। गारंटी की गारंटी है। मोदी किसी से नहीं डरता...मोदी मोदी मोदी मोदी...अबकी बार चार सौ पार, अबकी बार मोदी की सरकार। मोदी मोदी मोदी मोदी...ये कुछ ऐसी कैच लाइनें हैं, जो पब्लिक के एक बड़े हिस्से की जुबान में चढ़ चुकी हैं।

इसका अर्थ है कि भाजपा के राजनीतिक विचार पहले से ही पब्लिक के बड़े हिस्से में स्वीकृत होकर, उसकी जुबान पर चढ़ चुके हैं। यही हमारे गली-मुहल्ले के 'जन विमर्श' (पब्लिक डिस्कोर्स) में बाजाप्ता सुने जा सकते हैं। यही भाजपा का 'विकासवादी आख्यान' (नेरेटिव) है जो हर बाइट, हर खबर, हर विज्ञापन के जरिए पुख्ता होता रहता है। इसके मुकाबले विपक्ष की खबरों की सारी 'कैच लाइनें' भाजपा और मोदी की सरकार के प्रति सिर्फ 'शिकायतों' की हैं जो कोई आकर्षक और पॉजिटिव 'आख्यान' नहीं बनातीं। स्पष्ट है कि मौजूदा विज्ञापन युद्ध में भाजपा पहले पल से जीती हुई दिखती है।

जीडीपी की वृद्धि दर ने चौंकाया

आर्थिकी

प्रह्लाद सबनानी

वित्तीय वर्ष 2023-24 की तृतीय तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद के विशेष रूप से उद्योग क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर के आंकड़ों को देखकर विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि भारत आने वाले वर्षों में 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की विकास दर हासिल करने की ओर तेजी से बढ़ रहा है एवं अगले 4 साल के अंदर ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा

वित्तीय वर्ष 2023-24 की तृतीय तिमाही के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर ने भारत सहित विश्व के समस्त आर्थिक विश्लेशकों को चौंका दिया है। इस दौरान, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हासिल हुई है जबकि प्रथम तिमाही के दौरान वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत एवं द्वितीय तिमाही के दौरान 7.6 प्रतिशत की रही थी। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान वृद्धि दर 4.4 प्रतिशत रही थी। साथ ही, क्रेडिट रेटिंग संस्थान इकरा ने इस वर्ष तृतीय तिमाही में 6 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान एवं भारतीय स्टेट बैंक ने भी 6.9

प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान जताया था। कुल मिला कर, लगभग समस्त वित्तीय संस्थानों के अनुमानों को झुठलाते हुए सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर 8.4 प्रतिशत की रही है।

हम सभी के लिए हर्ष का विषय तो यह है कि विनिर्माण इकाइयों की वृद्धि दर 4.8 प्रतिशत से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 की तृतीय तिमाही में 11.6 प्रतिशत हो गई है तथा निर्माण के क्षेत्र में वृद्धि दर 9.5 प्रतिशत की रही है। साथ ही, खनन के क्षेत्र में वृद्धि दर 1.4 प्रतिशत से बढ़कर 7.5 प्रतिशत की रही है। ये तीनों ही क्षेत्र रोजगार सृजन के क्षेत्र माने जाते हैं। अतः देश में अब रोजगार के नये अवसर भी निर्मित हो रहे हैं। विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों में वृद्धि दर आकर्षक रही है। कृषि का क्षेत्र जरूर विपरीत मानसून एवं अल नीनो के प्रभाव के चलते, विपरीत रूप से प्रभावित हुआ है एवं कृषि के क्षेत्र में वृद्धि दर 0.2 प्रतिशत ऋणात्मक रही है। हालांकि वित्तीय वर्ष 2019-20 से लेकर 2022-23 तक कृषि के क्षेत्र में औसत वृद्धि दर 3 प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक की रही है। परंतु, प्रकृति के आगे तो किसी की चलती नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 की तृतीय तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद के विशेष रूप से उद्योग क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर के आंकड़ों को देखकर तो अब यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि भारत आगे आने वाले वर्षों में 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की विकास दर हासिल करने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है एवं अगले लगभग 4 साल के अंदर ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, वर्तमान में भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साथ ही, भारतीय शेयर बाजार भी बाजार पूंजीकरण के मामले में वर्तमान में विश्व में चौथे स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। क्योंकि, भारत में आर्थिक विकास की तीव्र गति को देखते हुए विदेशी निवेशक एवं विदेशी निवेश संस्थान, दोनों ही भारतीय पूंजी बाजार में अपने निवेश को निश्चित ही बढ़ाएंगे।

भारत में वित्तीय वर्ष 2023-24 की तृतीय तिमाही में अनुमानों से कहीं अधिक वृद्धि दर हासिल करने के पीछे दरअसल, हाल ही के समय में आर्थिक क्षेत्र के साथ साथ सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तन भी मुख्य भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं, इस ओर सामान्यतः विदेशी अर्थशास्त्रियों एवं वित्तीय संस्थानों का ध्यान शायद नहीं जा रहा है। हाल के समय में भारत में अब विभिन्न त्यौहार अत्यधिक उत्साह के साथ मनाए

अरावली पहाड़ी का बिगड़ रहा स्वरूप

पर्यावरण

देवेंद्रराज सुथार

राजस्थान के करीब 15 जिलों में आज भी अरावली की पहाड़ियां अवैध खनन का दंश झेल रही हैं। इन जिलों में अरावली पर्वतमाला का 80 प्रतिशत हिस्सा है। कुछ जगह लीज के नाम पर खनन हो रहा है, तो कुछ जगह बिना लीज अन्य जगहों से पहाड़ को खोखला किया जा रहा है। खरेखड़ी, बंदिया, नारेली के पास, किशनगढ़, मसूदा, पुष्कर, विजयनगर, टोंक, भीलवाड़ा आदि स्थानों पर अवैध खनन के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्र के पास अरावली की पहाड़ियों में अवैध खनन ज्यादा हो रहा है। यहां पंचायतों का रवैया तो अलग रहता ही है, ग्रामीण भी खामोश रहते हैं। अजमेर के निकट खरेखड़ी में भी अवैध खननकर्ता गोशाला में आर्थिक मदद एवं संचालन के नाम पर बेरोकटोक खनन करते हैं। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (सीईसी) की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, 1967-68 के बाद राजस्थान में अवैध खनन के कारण अरावली पर्वत श्रृंखला का 25 प्रतिशत हिस्सा समाप्त हो गया है। अरावली पर्वत क्षेत्र से लगे जंगलों में 371 तरह के औषधीय पेड़-पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से कई विलुप्त होने के कगार पर हैं।

उल्लेखनीय है कि प्री-क्रैम्बियन काल में बनी अरावली की पहाड़ियां एक वलित पर्वत श्रृंखला है। अरावली शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों- 'अरा' और 'वली' से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है- 'चोटियों की रेखा'। लेकिन कुछ संदर्भ कहते हैं कि अरावली दरअसल, आडावली का अपभ्रंश है और आडावली इसलिए क्योंकि यात्रा करते वक्त ये पहाड़ियां यात्रियों के आड़े आती थीं। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला मानी गई है और विश्व में भी प्राचीनतम है। यह पर्वत श्रृंखला राजस्थान को उत्तर से दक्षिण दो भागों में बांटती है। इसका सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में गुरुशिखर (1727 मीटर) है, जो माउंट आबू में है। इस पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई गुजरात से दिल्ली तक 692 किमी. है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 930 मीटर है तथा इसकी दक्षिण की ऊंचाई और चौड़ाई सर्वाधिक है। यह पर्वतमाला प्राकृतिक संसाधनों एवं खनिज से परिपूर्ण है, और पश्चिमी मरुस्थल के विस्तार को रोकने में मदद करती है। बाना, लूनी, साखी एवं साबरमती जैसी नदियों का उद्गम भी है।

अगर अरावली की पर्वतमाला नहीं बची तो इसके माध्यम से मिलने वाले ढेरों खनिजों सीसा, तांबा, जस्ता आदि के लाभ से हमें वंचित होना पड़ेगा। इससे निकलने वाली बाना, लूनी, साखी, साबरमती, केन, बेतवा, धसान, सिंध, पार्वती, काली सिंधु, बनास और सबसे अधिक पुरानी और अधिक महत्त्व की चर्मण्वती जैसी नदियां देखने को नहीं मिलेंगी। यही नहीं, इन पहाड़ियों के पश्चिम में विशाल थार मरुस्थल स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला का संरक्षण न सिर्फ राजस्थान, बल्कि पूरे देश के लिए अहम है। इस पर्वत श्रृंखला में बाघों से लेकर बघेरे, भालू, लकड़बग्घे, भेड़िये, सियार, लोमड़ी जैसे मांसाहारी, तो सांभर, नीलगाय, चीतल, चिंकारा, चौसिंगा, कृष्णमृग, जंगली सूअर जैसे शाकाहारी जीव भी पाए जाते हैं। ये पहाड़ियां भूजल को रिचार्ज में भी मदद करती हैं, जो हर वर्ष इस क्षेत्र में तपती गर्मी के महीनों के दौरान होने वाली पानी की कमी को देखते हुए महत्त्वपूर्ण है।

विशेषज्ञों के मुताबिक, ऐसा रास्ता निकालना होगा कि अरावली का संरक्षण किया जाए, खनन को कम नुकसानदायक बनाया जाए। अरावली की तबाही को अब खुली आंखों से न देखा जाए।

जीत पक्की कर रहा आंदोलन

बतंगड़ बेतुक

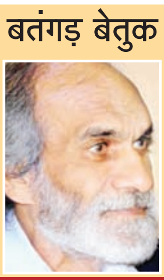

विभांशु दिव्याल

झल्लन बोला, 'ददाजू, अब चीजें हमें बिल्कुल रास नहीं आ रही हैं, हमारी बर्दाश्त के बाहर जा रही हैं।' हमने कहा, 'इसमें कौन सी नयी बात है। हर सुबह कोई न कोई चीज तेरी बर्दाश्त से बाहर जाती है और शाम होते न होते वापस अपने ठीये पर लौट आती है। वैसे अब कौन सी चीज तेरी बर्दाश्त से बाहर जा रही है, जो तुझे खिजा रही है?' वह बोला, 'अरे वही, हमारे किसान जो लगातार धरना दिये जा रहे हैं, जो उनसे करते बन रहा है वह किये जा रहे हैं, पर हमारी सरकार में बैठे लोग हैं जो किसानों की हर बात को हल्के में लिये जा रहे हैं, या तो उन्हें वादों की घुट्टी पिला रहे हैं या उन्हें गच्चे पर गच्चे दिये जा रहे हैं। अब तो हमारे इंडिया यानी बकौल मोदी घमंडिया गठबंधन ने भी अपना दिमाग झाड़ दिया है और किसानों के समर्थन में खूंटा गाड़ दिया है और हमारे भारत जोड़क यात्री नेता ने तो पूरे हिंदुस्तान को बता दिया है कि अगर वो खुदा ना खास्ता सत्ता में आ जाएगा तो सबसे पहला काम जो करेगा वो यही होगा कि किसानों की हर बात मानेगा और तुरंत एमएसपी कानून लागू करवाएगा। अब इस बात से तो हमारे मोदी जी को तुरंत डरना चाहिए और किसानों की मांगों को गंभीरता से लेकर तत्काल कुछ न कुछ करना चाहिए।'

हमने कहा, 'ये तो सबसे बढ़िया बात है कि इंडी गठबंधन का नेता बनकर बच्चा सत्ता में आ जाएगा तो पंजाब के किसानों की हर बात मानकर उनके मनमुताबिक एमएसपी कानून लागू करवाएगा। तो अब किसानों को कुछ ही दिनों में जाने वाली सरकार के दरवाजे पर काहे हल्ला मचाना चाहिए, काहे उसे रोज-रोज दिल्ली कूच का डर दिखाना चाहिए और काहे फालतू में बातचीत के एक राउंड के बाद दूसरा राउंड चलाना चाहिए। इन किसानों को इंडी गठबंधन के साथ जुट जाना चाहिए, इंडी गठबंधन के एक-एक नेता को अपने साथ ले आना चाहिए और पूरे देशभर में इस गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने के काम में जुट जाना चाहिए और बहुमत से जिताकर अपनी सरकार बनाने का रास्ता साफ करा लेना चाहिए और फिर अपनी मर्जी से जैसा चाहो वैसा कानून बनवा लेना चाहिए। इसलिए हमारी तो सलाह होगी कि पंजाब के आंदोलनिया किसान बबुआ की जोड़ो यात्रा से जुड़ जायें और जहां-जहां जायें वहां-वहां के किसानों को अपने साथ जोड़ते जायें और पूरे देश में ऐसी किसानी आंधी उठाएं कि मौजूदा सरकार के पांव उखड़ जायें, अपनी खुद की सरकार लायें, अपनी मनमर्जी के कानून बनाएं जिससे चारों तरफ किसानों की खुशहाली के नये रास्ते खुल जायें। और वैसे भी तेरा वो किसान नेता, क्या नाम है उसका अंधेर या पंधेर, जो कह रहा है कि देश के अस्सी प्रतिशत लोग किसानी से खाते-कमाते हैं, सो जाहिर है कि अगर इतने लोग चुनाव में साथ आ जाएंगे तो किसानों को अपनी सरकार बनाने से खुद भगवान भी नहीं रोक पाएंगे।'

हमने कहा, 'ये तो सबसे बढ़िया बात है कि इंडी गठबंधन का नेता बनकर बच्चा सत्ता में आ जाएगा तो पंजाब के किसानों की हर बात मान कर उनके मनमुताबिक एमएसपी कानून लागू करवाएगा। तो अब किसानों को कुछ ही दिनों में जाने वाली सरकार के दरवाजे पर काहे हल्ला मचाना चाहिए, काहे उसे रोज-रोज दिल्ली कूच का डर दिखाना चाहिए और काहे फालतू में बातचीत के एक राउंड के बाद दूसरा राउंड चलाना चाहिए। इन किसानों को इंडी गठबंधन के साथ जुट जाना चाहिए, इंडी गठबंधन के एक-एक नेता को अपने साथ ले आना चाहिए और पूरे देशभर में इस गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने के काम में जुट जाना चाहिए और बहुमत से जिताकर अपनी सरकार बनाने का रास्ता साफ करा लेना चाहिए और फिर अपनी मर्जी से जैसा चाहो वैसा कानून बनवा लेना चाहिए। इसलिए हमारी तो सलाह होगी कि पंजाब के आंदोलनिया किसान बबुआ की जोड़ो यात्रा से जुड़ जायें और जहां-जहां जायें वहां-वहां के किसानों को अपने साथ जोड़ते जायें

झल्लन बोला, 'आपके मुंह में घी शक्कर ददाजू, अब आप मुद्दे पर सही आ रहे हो और जो सूझा रहे हो सही सूझा रहे हो। हम भी यही चाहते हैं हरियाणा-दिल्ली के बार्डर पर वक्त जाया कर रहे किसान भाइयों को हर बार्डर तोड़ सारे देश में पसर जाना चाहिए और सारे देश के किसानों को अपने साथ ले आना चाहिए और पूरे देश में किसानों के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ना चाहिए। हमारी तो सलाह होगी कि इंडी गठबंधन के जितने भी बचे-खुचे सिपहसालार हैं सबको बाकी सारे कामधाम छोड़ किसान और एमएसपी को चुनाव का मुद्दा बनाना चाहिए मतलब इसी मुद्दे पर अगला चुनाव लड़ा जाना चाहिए और हमारे राहुल बबुआ की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नाम भी 'एमएसपी किसान यात्रा' हो जाना चाहिए। जब देश के चालीस करोड़ किसान और किसानी से जुड़े लोग एकजुट होकर चुनाव के मैदान में उतर आएंगे तो न तो मौजूदा सरकार बचेगी न सरकार चलाने वाले बच पाएंगे।'

हमें हंसी आयी, 'क्या बात है रे झल्लन, तूने तो हमारे मजाक को भी सीरियसली ले लिया और उस पर अपना प्रवचन भी दे दिया। अबे बेवकूफ, पंजाब के इन सिख किसानों का कोई भी नेता देश के किसी भी हिस्से में जाएगा तो समर्थन के नाम पर एक व्यक्ति इनके साथ नहीं आएगा। इस आंदोलन के बीच में से उग्रवादी, अलगाववादी, संप्रदायवादी आदि तत्वों की जैसी पुष्ट-अपुष्ट खबरें आ रही हैं, आंदोलनकारियों के जैसे-जैसे वीडियो सामने आ रहे हैं, वे डरा रहे हैं, इस आंदोलन की विश्वसनीयता को पलीता लगा रहे हैं। एक बात पक्की तौर पर दिखाई दे रही है कि देश के ज्यादातर मतदाता इस आंदोलन से चिढ़ रहे हैं और इस बात को इंडी गठबंधन के सभी नेता भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं इसीलिए न वे इन किसानों को अपने चुनाव का मुख्य मुद्दा बना रहे हैं और न इनके आंदोलन से जुड़ रहे हैं। तू हमारी बात लिख ले जैसे-जैसे यह जिद्दी आंदोलन चलता जाएगा वैसे-वैसे मोदी की जीत को पक्का करता जाएगा। अगर मोदी गुट चार सौ पार करेगा तो इसमें श्रेय इस कथित किसान आंदोलन का भी रहेगा।'

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन द्वारा हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड प्रेस, मौजा-दरियापुर, पुलिस स्टेशन-शाहपुर, दानापुर, पटना से मुद्रित तथा चतुर्थ तल, सहारा इण्डिया विहार, बोरिंग रोड क्रासिंग, पटना से प्रकाशित। ।समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - संजय त्रिपाठी *।

पटना कार्यालय- 3911448/417/454/422, फैक्स : 2535935,2520760 विज्ञापन-3911455/434, प्रसार- 3911451/428

वर्ष - 18, अंक 6232 आर.एन.आई. सं. -बीआईएचएचआईएन/2006/18082 Postal Reg. No. : R-10/NP-50/06-07

*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु उत्तरदायी

https://t.me/AllNewsPaperPaid

देश को नशे में डुबोने की साजिश

देश के विभिन्न भागों में नशीले पदार्थों की बरामदगी और तस्करों की गिरफ्तारी आम बात है। मगर जब कोई नशे की बड़ी खेप की बरामदगी होती है तो चिंताएं बढ़ जाती हैं। जहां घातक नशा हमारी युवा पीढ़ी को पथभ्रष्ट करके आत्मघात के रास्ते पर ले जा रहा है, वहीं नशे से उगाहे जाने वाले पैसे से अपराध व आतंकवाद की दुनिया ताकतवर हो रही है। खबर आई कि नौसेना, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनबीसी और गुजरात पुलिस के साझे ऑपरेशन में एक नाव से अब तक की सबसे बड़ी तीन हजार तीन सौ किलो ड्रग्स बरामद की है। इस नाव पर सवार पांच तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। आशंका है कि तस्कर पाकिस्तान के हो सकते हैं क्योंकि पैकेटों पर पाकिस्तानी कंपनी की मोहर लगी बतायी जाती है। बरामद नशीले पदार्थ की कीमत दो हजार करोड़ रुपये है। कल्पना कीजिये कि यह नशा यदि हमारे युवाओं की नसों में उतरता तो कितनी बड़ी हानि होती और भारत की दुर्लभ मुद्रा नशा तस्करों के हाथ में पहुंचती। बहुत संभव है कि आतंकवाद व अपराध की दुनिया को मजबूत करती। एनसीबी के अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है कि समुद्र में किसी बोट से यह अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है। इससे पहले गत बाईस फरवरी को पुणे से 700 किलो और दिल्ली से 400 किलो ड्रग्स मेफेड्रोन बरामद की गई थी, जिसकी कीमत ढाई हजार करोड़ रुपये थी। इस बरामदगी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में किस पैमाने पर नशीले पदार्थों का उपयोग बढ़ रहा है। नशीले पदार्थों की उस मात्रा की कल्पना करने से भी डर लगता है जो सुरक्षा एजेंसियों की नजर से बचकर निकल जाती होगी। निश्चित रूप से नशीले पदार्थों का सेवन अपराधों के लिये भी उर्वरा भूमि तैयार कर देता है। बहुत से युवा महंगे नशे की लत को पूरा करने के लिये अपराध की दुनिया में उतर जाते हैं। दुखद ही है कि हर साल देश में हजारों युवा नशे की ओवरडोज से मौत का शिकार हो जाते हैं। इस वजह से सरकारों का दायित्व बन जाता है कि देश के भविष्य को पतन के गर्त में गिरने से बचाने के लिये अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करें। लेकिन जिस पैमाने पर नशीले पदार्थों की बरामदगी हो रही है उससे तो डर लगता है कि लाखों युवा विभिन्न तरह के नशीले पदार्थों के आदी होते जा रहे हैं। फिल्मी सितारों व संभ्रांत लोगों की बिगड़ैल संतानों द्वारा आयोजित होने वाली रेव पार्टियां इसकी भयावहता को दर्शाती हैं। चिंता की बात यह है कि सीमाओं पर कड़ी सुरक्षा के चलते अब भारत-पाक सीमा पर ड्रोन के जरिये नशीले पदार्थों की तस्करी की जा रही है। पंजाब में पिछले दिनों सुरक्षा बलों ने कई ड्रोनों को मार गिराया और तस्करों से बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थ बरामद किये। चिंता की बात यह है कि कड़ी सुरक्षा के चलते अब समुद्री रास्ते से नशीले पदार्थों की तस्करी की जा रही है। कुछ समय पूर्व सोमनाथ के एक घाट पर बहकर आई साढ़े तीन सौ करोड़ की नशीले पदार्थों की खेप बरामद की गई थी। इससे पहले गुजरात बंदरगाह पर अचानक हुए निरीक्षण के दौरान एक पोत से पंद्रह हजार करोड़ की नशे की खेप की बरामदगी हुई थी। निश्चित रूप से नशे की खेप का एक बड़ा हिस्सा आज भी देश में खप रहा है, जिसको रोकने के लिये पुलिस, सुरक्षा बलों, एजेंसियों तथा समाज को बड़ी भूमिका निभानी चाहिए।

बिहारी क्रिकेटर कब खेलेंगे बिहार टीम से

आरके सिन्हा

(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं)

मौजूदा भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में बिहार के दो नव युवा खिलाड़ी झआकाशदीप और मुकेश कुमार ने शानदार प्रदर्शन करके अपनी प्रतिभा से क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। पर यह बिहार का दुर्भाग्य ही कहा जायेगा कि दोनों खिलाड़ी बिहार की टीम से नहीं खेलते। यह दोनों खेलते हैं बंगाल की टीम से रणजी ट्रॉफी में। इसकी वजह यह है कि बिहार में क्रिकेट मैनेजमेंट तार-तार हो चुका है। आकाशदीप का संबंध बिहार के रोहतास जिले से है।

अब आकाशदीप 7 मार्च से शुरू होने वाले पांचवें और आखिरी टेस्ट मैच के लिए हिमाचल प्रदेश जाएंगे और भारतीय क्रिकेट टेस्ट टीम का हिस्सा बनेंगे। उनकी तरह ही मुकेश कुमार भी हैं। बिहार के गोपालगंज जिले में स्थित काकड़कुंड गांव के रहने वाले मुकेश कुमार का चयन टीम इंडिया में वेस्टइंडीज टूर के लिए किया गया था। मुकेश कुमार भी तेज गेंदबाज हैं। मुकेश आईपीएल में भी धमाकेदार प्रदर्शन कर चुके हैं। वह आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स टीम का हिस्सा थे। मुकेश कुमार दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज हैं। इसके साथ ही, वह बायें हाथ के बल्लेबाज भी है। इस तरह दोनों ही खिलाड़ी भोजपुरिया हैं कमुकेश के पिता कोलकाता में टैक्सी चलाते थे। साल 2019 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तब मुकेश ने बंगाल में ही खेलते-खेलते कई लोगों से संपर्क बनाया और अपने मेहनत के बल पर नई पहचान बनाई। अफसोस कि बिहार में क्रिकेट का मैनेजमेंट बहुत बुरी स्थिति में है।

आकाशदीप ने रांची टेस्ट मैच में अपनी सधी हुई गेंदबाजी की बदौलत इंग्लैंड टीम के तीन खिलाड़ियों को आउट करके सनसनी मचा दी थी। उनके दादा निशान सिंह स्वाधीनता सेनानी थे। अब आकाशदीप 7 मार्च से शुरू होने वाले पांचवें और आखिरी टेस्ट मैच के लिए हिमाचल प्रदेश जाएंगे और भारतीय क्रिकेट टेस्ट टीम का हिस्सा बनेंगे। उनकी तरह ही मुकेश कुमार भी हैं। बिहार के गोपालगंज जिले में स्थित काकड़कुंड गांव के रहने वाले मुकेश कुमार का चयन टीम इंडिया में वेस्टइंडीज टूर के लिए किया गया था। मुकेश कुमार भी तेज गेंदबाज हैं। मुकेश आईपीएल में भी धमाकेदार प्रदर्शन कर चुके हैं। वह आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स टीम का हिस्सा थे। मुकेश कुमार दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज हैं। इसके साथ ही, वह बायें हाथ के बल्लेबाज भी है। इस तरह दोनों ही खिलाड़ी भोजपुरिया हैं कमुकेश के पिता कोलकाता में टैक्सी चलाते थे। साल 2019 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तब मुकेश ने बंगाल में ही खेलते-खेलते कई लोगों से संपर्क बनाया और अपने मेहनत के बल पर नई पहचान बनाई।

अफसोस कि बिहार में क्रिकेट का मैनेजमेंट बहुत बुरी स्थिति में है। इसलिए बिहार के प्रतिभाशाली खिलाड़ी अन्य टीमों का रुख करते हैं। पिछले महीने पटना में बिहार और मुंबई की टीमों के बीच रणजी ट्रॉफी का मैच हुआ तो बिहार की दो टीमें मैदान में आ गईं। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में खेले गए रणजी ट्रॉफी के एलिट ग्रुप बी मुकाबले में मुंबई की टीम ने बिहार को एक पारी और 51 रन से हराया। पर यह खबर नहीं थी। खबर यह थी कि मुंबई की टीम जिस स्टेडियम में मैच खेल रही थी उसकी हालत बेहद खराब थी। वहां पर दर्शकों के लिए बैठने तक की जगह नहीं थी। मैच को देखने के लिए रोज हजारों दर्शकों को भारी कठिनाई में मैच देखना पड़ा। जब देश में एक से बढ़कर एक बहुत सारे स्टेडियम बन चुके हैं, तब सारे बिहार में एक भी कायदे का स्टेडियम नहीं है। यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानी जा सकती।

इस बीच, ईशान किशन तो बीते कई सालों से भारतीय टीम में हैं। लेकिन वे भी झारखंड के लिए खेलतें है। उन्हें 2016 में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारत की टीम का कप्तान बनाया गया था। ईशान 2018 से इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा हैं। ईशान का जन्म बिहार के नवादा जिला में हुआ था। उनके जन्म के बाद उनका परिवार पटना शिफ्ट हो गया था। उन्हें भी झारखंड शिफ्ट होना पड़ा क्यों बिहार में क्रिकेट का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। क्रिकेट प्रेमियों को याद होगा कि संयुक्त बिहार के दौर में दिल्ली की टीम के कई बड़े खिलाड़ी बिहार से खेलने के लिए दिल्ली को छोड़ देते थे। इस लिहाज से रमेश सक्सेना का नाम सबसे पहले जेहन में आता है। उन्होंने एक टेस्ट मैच भी खेला। रमेश सक्सेना ने 1960-61 में अपना पहला प्रथम श्रेणी का मैच खेला था। उन्होंने 1966-67 में दिल्ली को अलविदा कह कर बिहार का रुख कर लिया था। रमेश सक्सेना के अलावा हरि गिडवाणी भी दिल्ली के बाद बिहार चले गए थे। उन्होंने लंबे समय तक बिहार की नुमाइंदगी की। यह दोनों क्लासिक बल्लेबाज थे। हरि गिडवाणी की पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में मिठाई की एक बहुत मशहूर दुकान भी है।

बिहार को क्रिकेट ही नहीं बल्कि सभी खेलों में अपने जौहर दिखाने होंगे। बिहार सरकार को भी राज्य में खेलों के विकास के लिए इन्वेस्ट करना होगा। सारे बिहार के समाज को सोचना होगा कि वे खेलों के संसार में किसी मुकाम पर क्यों नहीं पहुंच सके? आपको सारे बिहार में हॉकी के एक-दो एस्ट्रो टर्फ से ज्यादा हॉकी मैदान नहीं मिलेंगे। राष्ट्रीय नायक दादा ध्यानचंद के देश में इस तरह के राज्य भी हैं जहां पर एस्ट्रो टर्फ के मैदान ना के बराबर ही हैं। सारे बिहार में दो-तीन भी स्वीमिंग पूल मिल जाए तो बड़ी बात होगी। हां, सेना और अर्ध सैनिक बलों के कुछ स्वीमिंग पूल जरूर हैं। पर वे तो सबके लिए नहीं होते। अब बताएं कि बिहार से कैसे खिलाड़ी निकलेंगे। उन्हें न्यूनतम सुविधाएं तो मिलनी ही चाहिए।

बिहार में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने को लेकर कोई बात भी नहीं होती। बिहार को अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से ही कुछ प्रेरणा ले लेनी चाहिए। अब योगी सरकार के काल खंड में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी क्रिकेट और अन्य खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करने लगे हैं। वहां खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर उचित ध्यान दिया जा रहा है। सफल खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों के साथ-साथ अच्छे तरीके से पुरस्कृत भी किया जा रहा है। पिछले एशियाई में भाग लेने वाली भारत की टोली में उत्तर प्रदेश से 36 खिलाड़ी थे।एशि ?याई खेलों में उत्तर प्रदेश के एथलीटों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद सभी राज्य के खेलों से जुड़ी एसोसिएशन और कोच कसकर मेहनत करने लगे हैं। राज्य सरकार खेलों को गति देने को लेकर कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इस तथ्य से लग सकता है कि अब गांवों के स्कूलों में भी कोचिंग की व्यवस्था शुरू हो गई है। जिन खिलाड़ियों ने एशियाई खेलों में पदक जीते थे, उनकी झोलियां भर गईं हैं इनामों से।

बिहार ज्ञान का प्रदेश है। बिहारी सारे देश में अपने ज्ञान से सबको प्रभावित करते हैं। बिहार में पढ़ने-लिखने की बहुत समृद्ध परंपरा है। पर इतना ही काफी नहीं है। बिहार को खेलों में भी लंबी छलांग लगानी होगी। इसके लिए बिहार सरकार और बिहार के समाज को साथ एकजुट होकर प्रयास करने होंगे।

कैसे पूरा होगा भाजपा का मिशन 370 पार का लक्ष्य

शोभित सुमन

(भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद में डॉक्टोरल फेलो)

देश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर हलचल काफी तेज हो गई है। मार्च के दूसरे सप्ताह में चुनाव की तारीखों का ऐलान और पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है। भाजपा इस चुनावी समर में अपने मिशन 370 पार के लिए संकल्पित दिख रही है। इसकी बानगी भर यह है कि उसने लोकसभा चुनाव ऐलान से पहले ही प्रथम चरण के अपने 195 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। भाजपा का यह लक्ष्य है कि आगामी लोकसभा चुनाव में उसे 370 सीटों पर जीत मिले तो वहीं एनडीए 400 पार के आंकड़े को पार करे। अपने तीसरे कार्यकाल की ओर बढ़ने के लिए भाजपा ने काफी संयोजित तरीके से अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। कई वरिष्ठ नेताओं का टिकट भी काटा है तो कई दिग्गज नेताओं की सीटें भी बदली गई है। तो वहीं कई सीटों पर उसने अपने नए उम्मीदवार को चुनाव लड़वाने का ऐलान किया है। भाजपा के कार्यकताओं में भी यह जोश भरने वाला कदम है। भाजपा अभी जिस चुनावी अभियान में लगी हुई है उसके आसपास विपक्ष कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। भाजपा ने जहां अपने उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया है, तो वहीं इंडी गठबंधन एकजुटता दिखाने की राह पर ही अभी बढ़ रहा है। उसमें भी कई दरारें देखी जा रही है।

कांग्रेस जहां इंडिया गठबंधन के बूते भाजपा को मात देने का दम भर रही है। लेकिन ऐसा कहीं से मुमकिन होता नजर नहीं आ रहा है। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल के गठबंधन छोड़ने से उसे भी तगड़ा झटका लगा है। उसके बाद से इंडी गठबंधन की कोई सार्थक बैठक तक नहीं हो पाई है। रविवार को पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली में महागठबंधन ने अपनी ताकत दिखाई। इसमें विपक्ष के सभी नेताओं को एक मंच पर दिखाने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन चुनावी समर में उसे कितनी सफलता मिलती है यह देखने वाली बात होगी। गठबंधन के दलों में भी असंतोष की स्थिति साफ झलकती है।

भाजपा द्वारा जारी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट को अगर देखा जाए तो यह साफ दशार्ता है की सांगठनिक स्तर के उनके नेताओं को लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें दी गई है। भाजपा ने चुनाव में नए लोगों को भी मौका देने से परहेज नहीं किया है इस बार की पहली सूची में महिलाओं की भी संख्या भी काफी है। वहीं जो पार्टी लाइन से बाहर चल रहे थे उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है या उन पर अभी विचार चल रहा है। ऐसे भी उम्मीदवारों की संख्या इस लिस्ट में है जो पहले राज्य की राजनीति में सक्रिय थे। उन्हें वहां से शिफ्ट करके अब लोकसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। कई ऐसे केंद्रीय मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य थे उन्हें ऊपरी सदन राज्यसभा से हटाकर लोकसभा चुनाव लड़वाया जा रहा है। ऐसे में यह साफ है कि बीजेपी का फोकस बड़ी जीत की ओर है । भाजपा को इस बात की फिक्र कहीं से भी नहीं है कि नाराज हो रहे या टिकट नहीं पा रहे नेताओं में रोष व्याप्त हो सकता है या उनके विरोध के स्वर मुखर हो सकते हैं और ऐसे में उन्हें नुकसान हो सकता है। भाजपा का एक मात्र लक्ष्य है कि कैसे इस चुनाव में उसका प्रदर्शन अभूतपूर्व हो।

भाजपा जिस 400 पार के आंकड़े के साथ आगे बढ़ चली है उसमें वह सफल होती हुई दिखाई भी दे रही है। दक्षिण के राज्यों की सीटों पर भी भाजपा का फोकस है, जहां ऐसा माना जाता है कि दक्षिण के राज्यों में या तो क्षेत्रीय दलों का कब्जा है या फिर कांग्रेस वहां मजबूत स्थिति में है। भाजपा ने वहां भी कई प्रमुख सीटों पर मजबूत दावेदार पेश किए हैं।

ऐसी 161 सीटों पर भाजपा पिछले दो वर्षों से काम भी कर रही है, जहां या तो उसे हार मिली है या हार का आंकड़ा काफी कम वोटों का रहा है। इसके अलावा अलग-अलग क्लस्टर बनाकर उन सीटों की जिम्मेदारी वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री या क्षेत्रीय नेताओं को सौंपी गई है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में भाजपा का कोई भी लोकसभा सांसद नहीं है। ऐसे में दक्षिण के राज्यों में भी भाजपा कमजोर दिखाई देती है। 131 सीटों में बीजेपी के पास अभी केवल 29 सीटें हैं। इनमें से भी 25 सीटें भाजपा की केवल कर्नाटक से ही है। ऐसे में भाजपा दक्षिण में भी अपने पूरी ताकत को झोंकने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। इसलिए यह भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 के तर्ज पर ही दो सीटों से चुनाव लड़ाया जाए। दक्षिण के किसी सीट से मोदी को लोकसभा चुनाव में उतारा जाए। ऐसा करने से सांकेतिक रूप से भी भाजपा की स्थिति वहां मजबूत होगी और लोकसभा चुनाव में भाजपा को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल पाएगी।

मोदी ने भी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का जो लक्ष्य 370 तय किया है उसके लिए वह प्रतिबद्ध भी नजर आ रहे हैं। जाहिर है अगर बीजेपी को अपनी सीटें बढ़ानी है तो उसे मौजूदा स्थिति में जिन सीटों पर भाजपा का कब्जा है उसे बरकरार रखना होगा और उसके साथ नई सीटें भी जीतनी होगी। इसी क्रम में भाजपा उत्तर प्रदेश और बिहार में अपना पहले का प्रदर्शन बरकरार रखना चाहती है। इसी कारण से उसने बिहार में नीतीश कुमार को तो उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को अपने साथ लाकर अपनी स्थिति को मजबूत किया है। भाजपा एक-एक सीट की रणनीति बना कर दूसरी पार्टियों के नेताओं को भी अपने में शामिल करने के लिए प्रयासरत है जिनकी स्थिति उन सीटों पर मजबूत है। पीएम मोदी चाहते हैं कि 2024 के चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत हासिल हो ताकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस भाजपा की संकल्पना गढ़ी थी उसे वास्तव में साकार किया जा सके। 370 सीटों का आंकड़ा पार करने के बाद भाजपा उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देगी। इसके साथ भी मोदी के विकसित भारत की गारंटी को जन-जन तक पहुंचाने के लिए पूरी पार्टी अपनी ताकत से इस चुनाव को जीतने का दमखम भर रही है।

भाजपा के कार्यकताओं में भी यह जोश भरने वाला कदम है। भाजपा अभी जिस चुनावी अभियान में लगी हुई है उसके आसपास विपक्ष कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। भाजपा ने जहां अपने उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया है, तो वहीं इंडी गठबंधन एकजुटता दिखाने की राह पर ही अभी बढ़ रहा है। उसमें भी कई दरारें देखी जा रही है। कांग्रेस जहां इंडिया गठबंधन के बूते भाजपा को मात देने का दम भर रही है। लेकिन ऐसा कहीं से मुमकिन होता नजर नहीं आ रहा है। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल के गठबंधन छोड़ने से उसे भी तगड़ा झटका लगा है। उसके बाद से इंडी गठबंधन की कोई सार्थक बैठक तक नहीं हो पाई है। रविवार को पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली में महागठबंधन ने अपनी ताकत दिखाई। इसमें विपक्ष के सभी नेताओं को एक मंच पर दिखाने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन चुनावी समर में उसे कितनी सफलता मिलती है यह देखने वाली बात होगी। गठबंधन के दलों में भी असंतोष की स्थिति साफ झलकती है। भाजपा द्वारा जारी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट को अगर देखा जाए तो यह साफ दशार्ता है की सांगठनिक स्तर के उनके नेताओं को लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें दी गई है। भाजपा ने चुनाव में नए लोगों को भी मौका देने से परहेज नहीं किया है इस बार की पहली सूची में महिलाओं की भी संख्या भी काफी है। वहीं जो पार्टी लाइन से बाहर चल रहे थे उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है या उन पर अभी विचार चल रहा है। ऐसे भी उम्मीदवारों की संख्या इस लिस्ट में है जो पहले राज्य की राजनीति में सक्रिय थे। उन्हें वहां से शिफ्ट करके अब लोकसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। कई ऐसे केंद्रीय मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य थे उन्हें ऊपरी सदन राज्यसभा से हटाकर लोकसभा चुनाव लड़वाया जा रहा है। ऐसे में यह साफ है कि बीजेपी का फोकस बड़ी जीत की ओर है । भाजपा को इस बात की फिक्र कहीं से भी नहीं है कि नाराज हो रहे या टिकट नहीं पा रहे नेताओं में रोष व्याप्त हो सकता है या उनके विरोध के स्वर मुखर हो सकते हैं और ऐसे में उन्हें नुकसान हो सकता है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

विलम्बित न्यायकी चिंता

न्यायालयोंमें मुकदमोंको लम्बे समयतक लटकाये रखनेकी प्रवृत्ति न केवल गम्भीर चिंताका विषय है अपितु यह न्यायिक व्यवस्थाके समक्ष बड़ी चुनौती भी है। इसी प्रवृत्तिके चलते शीघ्र न्यायकी अवधारणापर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और विलम्बित न्यायको भी न्याय नहीं माना जा सकता है। इस सन्दर्भमें सर्वोच्च न्यायालयके मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चन्द्रचूड़ का यह कथन विशेष रूपसे महत्वपूर्ण है कि मुकदमोंकी सुनवाईमें तारीखपर तारीख वाली संस्कृति समाप्त होनी चाहिए। इसके साथ ही न्यायालयोंमें लम्बित मामलोंकी संख्या भी कम होनी चाहिए और सामान्य स्थिति होनी चाहिए। इसके लिए न्यायाधीशोंको महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी। गुजरातके कच्छमें जिला न्यायाधीशोंके सम्मेलनमें न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ने स्वीकार किया कि न्यायालयोंमें लम्बित मामलोंकी संख्या इस समय न्यायपालिकाके लिए बड़ी चुनौती है जबकि न्याय प्रशासनसे अपेक्षा होती है कि वह कानूनी विवादोंका उचित समय सीमामें निस्तारण करें। न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ने न्यायपालिकाकी वर्तमान कार्यप्रणालीपर भी सवाल खड़ाकर दिया और कहा कि न्यायकी अपेक्षा लेकर न्यायालय आने वाले आम आदमीकी सोच बन गयी है कि मामलोंको लम्बित रखना न्यायपालिकाकी कार्यप्रणालीका हिस्सा है। मुख्य न्यायाधीशने अपने सम्बोधनमें जो सवाल खड़े किये हैं, वह प्रासंगिक है। मुकदमोंके निस्तारणमें पीढ़ियां गुजर जाती हैं। यह बहुत बड़ी विसंगति है। इससे न्यायपालिकाके प्रति लोगोंका विश्वास प्रभावित होने लगता है। त्वरित न्याय समयकी मांग है और इसे मूर्तरूप देनेका दायित्व बार और बेंच दोनोंका है। अधिवक्ताओंको इस दिशामें अपनी सोच बदलनी होगी। मुकदमोंमें तारीखपर तारीख लेनेकी संस्कृतिको बढ़ावा देनेमें अधिवक्ताओंकी भी भूमिका रहती है, जो उचित नहीं है। मुकदमोंको लम्बे समयतक लटकानेके पीछे कुछ स्वार्थकी बातें भी शामिल हैं। इससे वादीको काफी परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसी स्थितिमें न्यायविदों, न्यायाधीशों और अधिवक्ताओंको मिलकर सोचना होगा कि त्वरित न्यायको कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। ऐसा करना न्यायपालिकाके प्रति विश्वासको और मजबूत करेगा। इस दृष्टिसे न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़की चिंता और सुझाव उचित और स्वागतयोग्य है।

मानवता शर्मसार

मानवताको शर्मसार करने वाली महिलाओंसे दुष्कर्मकी घटनाएं जघन्य अपराध है। इसपर प्रभावी अंकुश लगानेके लिए कड़े कानून भी हैं, इसके बावजूद भी इसके अपेक्षित परिणाम न मिलना गम्भीर चिन्ताका विषय है। इस तरहके घृणित अपराधकी घटना उस समय और असह्य हो जाती है जब कोई विदेशी महिला पर्यटक हैवानियतका शिकार बनती है। ऐसा ही भारतका अतिथि देवो भवकी सभ्यता और संस्कृतिको तार-तार करनेवाला एक मामला झारखण्डसे सामने आया है जिसने भारतीयोंका सिर शर्मसे झुका दिया। झारखण्डके दुमका जिलेमें शुक्रवारकी रात स्पेनकी एक महिला पर्यटकके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया जो अपने पतिके साथ दो बाइकसे विश्व भ्रमणपर निकली थी। दम्पती कोलकातासे नेपाल जानेके लिए बाइकसे निकले थे। रास्तेमें शाम हो जानेसे दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्रमें रात्रि गुजारनेके लिए उन्होंने मुख्य सड़कसे अन्दर अस्थायी शिविर लगाया और रात्रि विश्राम करने लगे। इसी दौरान नशेमें धुत सात युवक शिविरमें घुस गये और पतिकी पिटाईके बाद टेंटमें बांध दिया और महिलाको थोड़ी दूर लेजाकर उसके साथ दरिन्दगी की साथ ही उनके रुपये, घड़ी और आभूषण लूट लिये। शनिवारको महिला की मेडिकल जांचके बाद न्यायालयमें बयान दर्ज करा दिया गया है। इस सम्बन्धमें तीन युवकोंको हिरासतमें लिया गया है जिनमेंसे एक को पीड़िताने पहचान की है, शेषकी तलाश जारी है। जांचके लिए एसआईटी गठित की गयी है लेकिन इससे होगा क्या। जरूरत है प्रदेशकी कानून व्यवस्था दुरुस्त करनेकी जो पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। रात्रि लगभग ११ बजे पुलिस गश्ती दलको दम्पती इस सुनसान स्थानपर मिले थे तो उनकी सुरक्षाके व्यापक प्रबन्ध क्यों नहीं किय गये। यह प्रशासनिक व्यवस्थाको कटघरेमें खड़ा करता है। ऐसी घटनाओंसे विदेशोंमें भारतकी छवि खराब होती है। हर साल बड़ी संख्यामें विदेशी पर्यटक भारत आते हैं जिनकी सुरक्षाकी जिम्मेदारी सरकार की है। केन्द्र और राज्य सरकारोंको इसपर गम्भीरतासे विचार करनेकी आवश्यकता है।

लोक संवाद

एकांकी हो रही बसपा

महोदय,- आम चुनावसे पहले बसपा अपने अधिकांश सांसदोंको खोनेकी ओर अग्रसर दिख रही है। रविवारको उसके अंबेडकर नगर सांसद भाजपामें चले गये। कथित तौरपर तीन अन्य लोग उसका अनुसरण करनेके लिए तैयार हैं। बसपाके एक और सांसद समाजवादी पार्टी (सपा) में शामिल हो गये हैं, जबकि दो अन्य कांग्रेसकी ओर जा रहे हैं। बाहर निकलनेका कारण यह डर हो सकता है कि इस ध्रुवीकृत चुनावमें तीसरे विकल्पके लिए कोई गुंजाइश नहीं है, जहां समाजवादी पार्टी-कांग्रेस सीट शेयरिंग समझौतेके बाद, इंडिया ब्लॉकको भाजपाके लिए चुनौती देनेवालेके रूपमें देखा जा रहा है, जबकि बसपा अकेले जानेपर तैयार है। २०१९ के आम चुनावोंमें बसपाने उत्तर प्रदेशमें सपा और राष्ट्रीय लोकदलके साथ गठबंधनके हिस्सेके रूपमें अच्छा प्रदर्शन किया। उसने दस लोकसभा सीटें जीतीं। तीन साल बाद, बसपाने बिना सहयोगियोंके यूपी विधानसभा चुनाव लड़ा और केवल एक विधायकके साथ समाप्त हुई। पार्टी यह तर्क दे सकती है कि यह एक आंदोलन-कैडर आधारित पार्टी है जहां नेताओंकी तुलनामें प्रतीक, झंडा और विचारधारा अधिक मायने रखती है। सच तो यह है कि यूपीकी राजनीतिमें व्यापक बदलाव आया है और बसपाका वोट आधार सिकुड़ गया है। भाजपाने चतुर रणनीति और सोशल इंजीनियरिंगके साथ, बसपाके आधारमें सेंध लगा दी है, जिससे पार्टीका मूल वोट जाटव छिन गया है। विडंबना यह है कि २००० के दशककी शुरुआतमें, अपने विकास चरणके शीर्ष पर, बसपाने बहुजन (ओबीसी, दलित और आदिवासी) से व्यापक सर्वजन (समाजके सभी वर्गों) मंचपर स्थानांतरित होनेकी आवश्यकताको पहचाना। ध्रुवकी स्थितिमें उभरनेके लिए इस रणनीतिने पार्टीको २००७ के यूपी विधानसभा चुनाव जीतनेमें मदद की। सर्वजन समाजके विचारको भाजपाने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारेके साथ हथिया लिया है, हालांकि एक नये सामाजिक परिवेशमें जिसमें मुसलमानोंको शामिल नहीं किया गया है। द्रमुक जैसी विचारधारासे प्रेरित पार्टियां अपने सामाजिक आधारका विस्तार करनेके लिए सहयोगियोंकी आवश्यकताको पहचानती हैं। उदाहरणके लिए, इसने तमिलनाडुमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और प्रांतीय पार्टी कोंगुनाडु मुनेत्र कडगमके लिए एक-एक लोकसभा सीटकी पेशकश की है। **-चित्रा राय, वाया ईमेल।**

ड्रग्स तस्करोंके खिलाफ सख्त सरकार

महोदय,- सरकार ड्रग्स तस्करोंके खिलाफ सख्त है। गुजरातमें तटीय क्षेत्रकी वजहसे ड्रग्स कारोबारी सफल तो नहीं हो रहे हैं लेकिन नशीली ड्रग्स गुजरातके दरिया क्षेत्रोंमें घुसानेकी कई बार कोशिश की जाती है। पाकिस्तानसे वाया अफगानिस्तान होकर भारत भेजा जाता है। गुजरात राज्य पाकिस्तानके नदियोंके तटीय क्षेत्रसे जुड़ा हुआ है। इसलिए ड्रग्स घुसानेके लिए सबसे पहले गुजरात लाया जाता है। जहर बेचनेवाले इनसानियतके दुश्मन है। गुजरातके पोरबंदरके पास पकड़ा गया था तीन सौ किलो ड्रग्स। यदि यह ड्रग्स गुजरातमें घुसानेमें सफल हो जाते तो युवाओंकी जिन्दगी तबाह हो जाती थी। २०२२ में साढ़े चार सौ करोड़का ड्रग्स पुलिसने बरामद किया था। गुजरात सरकारने पिछले दो वर्षमें ५३३८ करोड़का ड्रग्स कब्जे किया। गत दिन वेरावल बंदरगाहसे ३५० करोड़की ड्रग्स गुजरात पुलिसने बरामद की थी। युवाओंको नशेके डोज देकर मानसिक संतुलन खोखला करनेकी नीति दुश्मन देशकी है। ड्रग्स कारोबारियोंपर सरकार सख्त रवैया अपना कर दोषियोंको सलाखोंके पीछे धकेलनेके लिए सख्त कदम उठाये। **-कांतिलाल मांडोत, सूरत।**

रसूखदारोंके लिए कानूनका मतलब

दो राय नहीं कि प्रभावशाली लोग कानूनको खिलौना समझकर खेलते हैं और व्यवस्था भी मददगार साबित होती है। बर्षोंसे देशमें ऐसा ही चलता आ रहा है। सख्त कानून और तमाम उपायोंके बाद भी रसूखदार कानूनका मजाक उड़ानेसे बाज नहीं आते। कानूनको बौना साबित करनेवाली इस जमातको राजनीतिक संरक्षण हासिल होता है।

❑ आशीष वशिष्ठ

धनबल और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त रसूखदार लोग व्यवस्थाकी कमियों और छिद्रोंके चलते नियम कानूनोंको आसानीसे गच्चा देते हैं। आम आदमीकी मामूली-सी गलतीपर उसे पकड़नेमें भरपूर तेजी दिखानेवाली पुलिसको प्रभावशाली और रसूखदार लोगोंतक पहुंचनेमें वक्त लग ही जाता है। पश्चिम बंगालमें इसकी अवधि कुछ ज्यादा ही लम्बी हो जाती है। संदेशखाली मामलेसे चौतरफा निन्दाका पात्र बना तृणमूल कांग्रेसका नेता शाहजहां शेख ५५ दिनोंसे फरार रहनेके बाद पुलिसकी गिरफ्तमें आया है! लेकिन तब, जब कलकत्ता उच्च न्यायालयने ममता सरकारको फटकार लगायी। यदि फटकार नहीं लगी होती तो उसे छुपाये रखा गया होता। वह जिस हनक और रूआबसे थाने और अदालतमें दाखिल हुआ, उससे यही लगा कि वह कोई शहंशाह है। पश्चिम बंगाल पुलिस उसके आगे दंडवत और सहमी-सी दिखी। उसे सत्ताका संरक्षण प्राप्त था, यह सचाई तृणमूल कांग्रेसके इस कथनसे छिपनेवाली नहीं कि हमने उसे निलंबित कर दिया। यह राजधर्म नहीं, बेशर्मी है कि उसे गिरफ्तार न करनेके लिए उच्च न्यायालयके आदेशकी गलत व्याख्यातक की गयी। यदि ईडीको शक है कि बंगाल पुलिस शाहजहां शेखकी मदद कर सकती है तो यह स्वाभाविक है। बड़ी निर्लज्जतासे तृणमूल कांग्रेसकी सरकार अपने नेताका बचाव करती रही। संदेशखालीकी महिलाओंने जिन शब्दोंमें अपनी पीड़ाका बयान किया है, उससे किसी पत्थर दिल व्यक्तिका भी दिल पिघल सकता है। लेकिन पश्चिम बंगालकी महिला मुख्य मंत्रीका दिल नहीं पसीजा। भारतीय जनता पार्टीके विरोध और हाईकोर्टकी सख्त टिप्पणियोंके बाद शाहजहांको गिरफ्तार किया गया।

किसी रसूखदारको जब जांच एजेंसी पकड़ती है तो वह विजय मुद्रा बनाकर हवामें हाथ लहराता है जैसे उसने कोई महान काम किया है। गिरफ्तारी या जांचके लिए जाते वक्त नेताओंके हाव-भाव ऐसे होते है मानो उनको तो राजनीतिके चलते फंसाया गया है। जांच एजेंसीके आफिसके बाहर नेताके समर्थकोंका धरना, प्रदर्शन अप्रत्यक्ष तौरपर प्रेशर डालनेका कृत्य है। वहीं किसी रसूखदारको सजा मिलनेपर जिस तरहकी प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, वे स्तब्ध करती हैं। उनमें अपने विशिष्ट होनेका अहंकार और न्यायालयकी अवमाननाके साथ संवेदनहीनताकी पराकाष्ठा दिखती है।

दिल्लीके मुख्य मंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवालसे प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी दिल्ली शराब घोटालेमें पूछताछके लिए अबतक आठ समन भेज चुका है। जांच एजेंसीके सामने पेश होनेकी बजाय केजरीवाल ईडीके समनको ही गैर-कानूनी बता रहे हैं। वह कानूनी दांव पेंचसे जांचसे बच रहे हैं और दिल्ली विधानसभामें खड़े होकर केन्द्रकी मोदी सरकारसे लेकर अपने राजनीतिक विरोधियोंपर जमकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। चूंकि विधानसभामें दिये बयानपर कोई कानूनी काररवाई नहीं हो सकती। इसीके चलते केजरीवालने विधानसभाको अपनी भड़ास निकालने और राजनीतिक विरोधियोंपर मनगढ़न्त आरोप लगानेका मंच बना रखा है। देशकी जनता उनका तमाशा देख रही है। जिस शराब घोटालेमें उनसे पूछताछ होनी है, उसी घोटालेमें उनके सबसे खास साथी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तिहाड़की रोटियां तोड़ रहे हैं। एक संवैधानिक पदपर बैठा व्यक्ति किस तरह कानून और संविधानका उपहास उड़ा रहा है, उससे समाजमें गलत उदाहण तो पेश हो ही रहा है। वहीं आम आदमीके मनमें यह सवाल भी उठता है कि क्यों कानून रसूखदारों सामने कमजोर और असहाय दिखाई देता है। केजरीवालकी तरह तेंलगानाके पूर्व मुख्य मंत्री हेमंत सोरेन भी ईडीके समनकी अवमानना करते रहे और खुदको बचानेके सारे यत्न उन्होने किये। बड़ी जदोजहदके बाद ईडीने उन्हें अपने शिकंजेमें लिया। फिलवक्त सोरेन जेलका भोजन पा रहे हैं।

पंजाब हरियाणा हाईकोर्टने हत्या और बलात्कारके मामलेमें जेलमें सजा काट रहे राम रहीमको बार-बार पैरोल दिये जानेपर सवाल उठाया। हाईकोर्टने कहा कि क्यों केवल राम रहीमको बार-बार पैरोल मिल रही है। बाकी कैदियोंको क्यों नहीं लाभ दिया जाता। रेपके दोषी राम रहीमको इस साल जनवरीमें ५० दिनकी पैरोल दी गयी थी। यह लगभग दस महीनेमें उसकी सातवीं और पिछले चार वर्षोंमें नौवीं पैरोल थी। हाईकोर्टने हरियाणा सरकारको आदेश दिया है कि अब अदालतकी अनुमतिके बिना राम रहीमको पैरोल नहीं दी जायगी। सत्ता, व्यवस्था, कानूनके रक्षक और संरक्षकके गठजोड़से ही राम रहीम जैसे रसूखदार कानूनको फुटबाल बनाकर खेलते हैं। जबतक सत्ताके गलियारोंसे आपराधिक लोगोंको संरक्षण मिलता रहेगा, तबतक ये निर्लज्जता बनी रहेगी। हरेक घटनामें किसी न किसी रसूखदारका, किसी न किसी सत्ताधारीका संरक्षण दिखता रहा है। हर बार सत्ताकी तरफसे कठोरसे कठोर काररवाई किये जानेकी बात कही जाती है, कुछ दोषियोंकी गिरफ्तारी भी हो जाती है, जांच करवाये जानेकी लीपापोती कर दी जाती है और उसके बाद सब कुछ भूल-भुला लिया जाता है। संदेशखाली जैसी घटनाएं कुछ दिन चर्चामें रहती हैं फिर जनमानसकी खोपड़ीसे गायब हो जाते हैं। निठारी कांड कितनोंको याद है। बिहार मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस कितनोंको याद है। कितनोंको उसके दोषीकी सजा याद है। कुछ दिन बाद ऐसा ही संदेशखालीमें को भी लेकर होगा।

प्रभावशाली किस मामलेमें फंस भी जाते हैं तो उनके चेहरे, बाडी लैग्वेंज, चेहरेसे टपकते घमंड और अहंकारको देखकर ऐसा नहीं लगता कि उनको कानूनका रत्तीभर भी भय है। पुलिस प्रशासनको तो वो अपना चाकर समझते हैं। कहीं न कहीं व्यवस्था भी उनकी चाकरी करती दिखाई देती है। न्याय-व्यवस्था भी ऐसी है कि प्रभावशाली लोगोंको जमानत देनेमें देर नहीं करती। आधी रातको भी उनके मामले सुन लिये जाते हैं। हालांकि देशकी अदालतोंमें करोड़ों मुकदमे लंबित हैं और आम व्यक्तिको न्याय पानेके लिए वर्षों प्रतीक्षा करनी पड़ती है। भ्रष्टाचार एवं अन्य गम्भीर मामलोंमें दर्जनों रसूखदार आसानीसे जमानत पाकर आरामकी जिन्दगी बिता रहे हैं। चारा घोटालेमें सजा पाये लालू प्रसाद यादव स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानियोंके चलते जमानतपर हैं। राजनीतिमें उनकी सक्रियता बताती है कि अब वह स्वस्थ हैं और यदि वह स्वस्थ हैं तो वह जमानतपर क्यों हैं। यदि रसूखदारोंको जेल जाना भी पड़ा तो वहां भी उनके मनमुताबिक ऐशोआराम जारी रहता है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। दिल्लीके मंत्री सत्येंद्र जैनके जेलकी कोठरीमें कथित तौरपर मालिश करानेका वीडियो देशने देखा है। यूपीके चर्चित नेता और माफिया मुख्तार अंसारीकी पंजाबकी जेलमें कांग्रेसकी सरकारने जो मेहमाननवाजीकी उसे कौन भूल पायगा। देशवासी भूले नहीं होंगे जब एक रसूखदार दामादने मैंगो पीपल कहकर आम आदमीका जिस तरह मजाक उड़ाया था, बॉलीवुडके एक गायकने फुटपाथपर सोनेवाले बेघर लोगोंको कुत्ते कहकर उसी अहंकारका परिचय दिया था। किसी नेता या रसूखदारको जब जांच एजेंसी पकड़ती है तो वह विजय मुद्रा बनाकर हवामें हाथ लहराता है। मानो उसने कोई महान काम किया है। गिरफ्तारीके समय या जांचके लिए जाते वक्त नेताओं और रसूखदारोंके हाव-भाव ऐसे होते है मानो वह अहसान करने जा रहे हैं और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, उनको तो राजनीतिके चलते फंसाया गया है। जांच एजेंसीके आफिसके बाहर नेताके समर्थकोंका धरना, प्रदर्शन अप्रत्यक्ष तौरपर जांच एजेंसीको डराने, धमकाने और प्रेशर डालनेका कृत्य है। वहीं किसी रसूखदारको सजा मिलनेपर जिस तरहकी प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, वे स्तब्ध करनेवाली होती हैं। उनमें अपने विशिष्ट होनेका अहंकार और न्यायालयकी अवमाननाके साथ-साथ संवेदनहीनताकी पराकाष्ठा भी सुनायी पड़ती है। खुदको कानूनसे ऊपर समझनेवाले किसी रसूखदारने यदि कोई गैर-कानूनी काम किया है तो देरसबेर कानून उनके कियेकी सजा देगा ही, लेकिन उस उच्चवर्गीय अहंकारपर अंकुश लगानेकी भी जरूरत है, जो अपने गलत कामोंको सही सिद्ध करनेके हठमें अमानवीय हो जाता है।

हिमाचलकी राजनीतिमें उथल-पुथल

वीरभद्र सिंहने अपने मुख्य मंत्रित्व कालमें मतान्तरण रोकनेके लिए हिमाचल प्रदेशमें कानून बना दिया था। तभीसे वे सोनिया गांधीको खटक रहे थे। सुक्खू सरकार स्वर्गीय वीरभद्रके प्रति निष्ठा रखनेवाले विधायकोंको किनारे करनेमें लगी थी।

❑ कुलदीप चंद अग्निहोत्री

हिमाचल प्रदेशमें राज्यसभाकी एकमात्र सीटके लिए २७ फरवरीको हुए चुनावके परिणामने प्रदेशकी राजनीतिमें भूकम्प ला दिया। ६८ सदस्यीय विधानसभामें भाजपाके पचीस सदस्य हैं और कांग्रेसके चालीस। सरकार चलाने, बचाने और राज्यसभाकी यह सीट जीतनेके लिए पैंतीस सदस्योंकी आवश्यकता थी। यानी कांग्रेसके पास ये तीनों काम निबटानेके लिए जरूरतसे ज्यादा पांच अतिरिक्त सदस्य हैं। इसी विश्वासके बलपर सोनिया गांधीने अपने परम भक्त अभिषेक मनु सिंघवीको हिमाचल प्रदेशसे राज्यसभा सदस्य बनानेका 'खतरनाक' निर्णय लिया था। राज्यके मुख्य मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खूने उनको इस लड़ाईमें जीतका अतिरिक्त विश्वास दिलाया ही होगा। खासकर तब जब उन्हें विश्वास था कि सरकारका समर्थन कर रहे तीन निर्दलीय भी अभिषेक मनु सिंघवीको राज्यसभामें हिमाचलका प्रतिनिधि माननेको तैयार हो जायंगे। वैसे इसे भी संयोग ही कहना चाहिए कि अभिषेक मनु सिंघवी राजस्थानके रहनेवाले हैं और वहांसे आसानीसे राज्यसभामें पहुंच सकते थे। लेकिन राजस्थानसे राज्यसभामें जानेका रास्ता सोनिया गांधीने अपने लिए सुरक्षित कर लिया और राजस्थानके सिंघवीको हिमाचलमें धकेल दिया, जबकि वे स्वयं हिमाचलसे लड़ सकती थीं और राजस्थानके सिंघवीको राजस्थानमें ही रहने दे सकती थीं।

क्या उन्होंने पहलेसे ही हिमाचलमें इस पराजयका खतरा सूंघ लिया था। फिलहाल इसपर राजनीतिक विश्लेषक अरसेतक माथापच्ची करते ही रहेंगे। लेकिन असली सवाल तो यह है कि कांग्रेस बहुमतसे ज्यादा सदस्य होते हुए भी भारतीय जनता पार्टीके हर्ष महाजनसे हारी कैसे। गणितका हिसाब किताब तो साफ-सुथरा है। कांग्रेसके छह विधायकोंने अपनी पार्टीके प्रत्याशीको वोट न देकर भाजपाके प्रत्याशीको वोट दे दिया। तीन निर्दलीय विधायकोंने भी इस चुनावमें भाजपाका साथ दिया। यानी कुल मिलाकर दोनों प्रत्याशी ३४-३४ वोटोंपर संतुलित हो गये। ऐसे मौकोंपर भाग्य यानी ईश्वर लीलापर विश्वास किया जाता है। भाजपा और कांग्रेस इस बातपर सहमत हो गये कि अब निर्णय ईश्वर यानी भाग्यपर छोड़ दिया जाय कि वह किसका साथ देता है। भाजपाको शायद विश्वास था कि ईश्वर उसीका साथ देगा, क्योंकि वे सब अभी-अभी अयोध्यामें राम मंदिरका निर्माण करके ही नहीं, बल्कि रामके विग्रहमें प्राण प्रतिष्ठा करके लौटे थे। अभिषेक मनु सिंघवीकी पार्टी निमंत्रण मिलनेके बावजूद अयोध्या नहीं गयी थी। वैसे एक बार तो कांग्रेस पार्टीने रामके अस्तित्वको ही नकार दिया था। परिणाम जाननेके लिए पर्ची डाली गयी तो वह भाजपाके पक्षमें निकली। इस ईश्वर लीलामें भाजपाकी जय-जय हुई और कांग्रेसकी पराजय। भाजपाके एक वरिष्ठ नेता जो दशकोंतक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघसे जुड़े रहे, कहते सुने गये कि हम तो पहले ही कहते थे कि संघ ईश्वरीय कार्य है। अभी कांग्रेस इस झटकेसे संभलती, तभी हिमाचलके पूर्व मुख्य मंत्री वीरभद्र सिंहके बेटे विक्रमादित्य सिंहने मंत्रिमंडलसे इस्तीफा दे दिया। वह सुक्खू मंत्रिमंडलमें लोकनिर्माण मंत्री थे। त्यागपत्रका कारण बताते हुए वह भावुक हो गये। उनका कहना था कि उनके पिताका अब भी इस सरकार द्वारा अपमान किया जा रहा है। उनकी प्रतिमा लगानेके लिए जमीनतक उपलब्ध नहीं करवायी गयी। जब सोनिया गांधीने अयोध्यामें रामके विग्रहकी प्राण-प्रतिष्ठाके अवसरपर आधिकारिक तौरपर पार्टीके शामिल होनेको सार्वजनिक तौरपर नकार दिया था तो विक्रमादित्य सिंह उसके बाद भी अयोध्या गये थे। वैसे वीरभद्र सिंहने अपने मुख्यमंत्रित्व कालमें मतान्तरण रोकनेके लिए हिमाचल प्रदेशमें कानून बना दिया था। तभीसे वह सोनिया गांधीकी आंखकी किरकिरी बन गये थे। सुक्खूकी कांग्रेस सरकार पहले दिनसे ही स्वर्गीय वीरभद्र सिंहके प्रति निष्ठा रखनेवाले विधायकोंको हाशियेपर धकेलनेके काममें लगी हुई थी।वीरभद्र सिंहकी पत्नी प्रतिभा सिंहको कांग्रेसका प्रदेश अध्यक्ष बनाकर सोनिया गांधीकी सन्तानने संतुलन साधनेकी कोशिश तो जरूर की, लेकिन सुक्खू उस संतुलनको धरातलपर नहीं उतार पाये। यह भी कहा जा रहा है कि सुक्खू विरोधी खेमेमें चौदह विधायक हैं, लेकिन रणनीतिके तहत अभी छह विधायकोंको ही सार्वजनिक रूपसे राज्यसभा चुनावके अवसरपर सामने लाया गया है। विक्रमादित्य सिंहका भले ही अब सुक्खू सरकारके साथ दिख रहे हैं लेकिन अंदरखानेमें बातें कुछ और ही चल रही हैं। इससे पहले जाते हुए विक्रमादित्य सिंह यह भी बता दिया कि विधानसभाका चुनाव प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्रीके नेतृत्वमें लड़ा गया था। शायद वह परोक्ष रूपसे सोनिया गांधी और उनके बच्चोंसे सवाल ही कर रहे थे कि फिर सुखविंदर सिंह सुक्खूको मुख्य मंत्री किस हिसाबसे बना दिया गया। हाईकमान तो पता नहीं इस सवालका उत्तर कब देता, लेकिन इस ग्रुपने राज्यसभाके चुनावको उचित अवसर जानकर स्वयं इसका उत्तर दे दिया। उत्तर इतना तीखा है कि शायद हिमाचल प्रदेशमें कांग्रेसकी सरकारको ही निगल जाय। बाकी राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रामें स्थान-स्थानपर मोहब्बतकी दुकानें सजानेमें पहलेकी तरह व्यस्त हैं। भले ही बादकी हकीकत यह है कि विक्रमादित्य सिंहको मना लिया गया है और उन्होंने इस्तीफा फिलहाल वापस ले लिया है। लेकिन उनके इस्तीफेसे कांग्रेसकी जो किरकिरी हुई, वह अब जगतके सामने हैं। देखना यह होगा कि कांग्रेस क्रॉस वोटिंग करनेवाले अन्य विधायकोंको कैसे मनाती है तथा सवाल यह भी है कि क्या विक्रमादित्य सिंहकी नाराजगी दूर हो गयी है। उधर सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकारको बचानेके लिए कांग्रेसने रणनीतिपर काम शुरू कर दिया है। उसने फिलहाल बजट भी पारित करवा दिया है। फिलहाल संकट टलता दिखता है, लेकिन ऐसी भी सूचनाएं हैं कि क्रॉस वोटिंग करनेवाले कुछ विधायक तो कांग्रेसका कहा मान भी सकते हैं, लेकिन दो विधायकोंको मनाना कठिन होगा।

आत्मबोध

विजया एकादशी

❑ सदानन्द शास्त्री

विजया एकादशी फाल्गुन मासके कृष्णपक्षकी एकादशीको कहा जाता है। यह एकादशी विजयकी प्राप्तिको सशक्त करनेमें सहायक बनती है। तभी तो प्रभु श्रीरामने भी इस व्रतको धारण करके अपनी विजयको पूर्ण रूपसे प्राप्त किया था। एकादशी व्रत करनेसे व्यक्तिके शुभ फलोंमें वृद्धि होती है तथा अशुभताका नाश होता है। विजया एकादशी व्रत करनेसे साधक व्रतसे संबंधित मनोवांछित फलकी प्राप्ति करता है। सभी एकादशी अपने नामके अनुरूप ही फल देती हैं। एक समय धर्मराज युधिष्ठिरने श्रीकृष्णसे कहाए हे जनार्दन! फाल्गुन मासके कृष्ण पक्षकी एकादशीका क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे बताइये। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मासके कृष्ण पक्षकी एकादशीका नाम विजया एकादशी है। इसके व्रतके प्रभावसे मनुष्यको विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतोंसे उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशीके महात्म्यके श्रवण एवं पठनसे समस्त पाप नाशको प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारदजीने जगत पिता ब्रह्मासे कहा महाराज! आप मुझसे फाल्गुन मासके कृष्ण पक्षकी एकादशीका विधान कहिये। ब्रह्माजी कहने लगे कि हे नारद! विजया एकादशीका व्रत पुराने तथा नये पापोंको नाश करने वाला है। इस विजया एकादशीकी विधि मैंने आजतक किसीसे भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्योंको विजय प्रदान करती है। विजया एकादशी व्रतके विषयमें यह मान्यता है कि एकादशी व्रत करनेसे स्वर्ण दान, भूमि दानए अन्न दान और गौ दानसे अधिक पुण्य फलोंकी प्राप्ति होती है। व्रत पूजनमें धूप, दीप, नैवेध, नारियलका प्रयोग किया जाता है। विजया एकादशी व्रतमें सात धान्य घट स्थापनाकी जाती है। इसके ऊपर विष्णु जीकी मूर्ति रखी जाती है। इस व्रतको करनेवाले व्यक्तिको पूरे दिन व्रत करनेके बाद रात्रिमें विष्णु पाठ करते हुए जागरण करना चाहिए। व्रतका समापन द्वादशी तिथिके प्रात:कालमें अन्नसे भरा घड़ा ब्राह्मणको दान करके किया जाता है। यह व्रत करनेसे दु:ख दूर होते हैं। अपने नामके अनुसार विजया एकादशी व्यक्तिको जीवनकी कठिन परिस्थितियोंमें विजय दिलाती है।

उच्च सदनमें भीतरघातकी राजनीति

❑ रोहित माहेश्वरी

हालिया राज्यसभा चुनावमें विधायकोंने खुलकर क्रॉस वोटिंग की। उत्तर प्रदेश, हिमाचल और कर्नाटकमें राज्यसभा चुनावके जो परिणाम आये उनमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेसको झटका लगा। उत्तर प्रदेशमें समाजवादी पार्टीके आधा दर्जन विधायकोंने भाजपाके आठवें प्रत्याशीको मत देकर अपने एक प्रत्याशीको हरवा दिया। इसी तरह हिमाचलमें कांग्रेसके छह विधायकों द्वारा भाजपा प्रत्याशीको मत देनेसे अभिषेक मनु सिंघवी हार गये। उत्तर प्रदेशमें भी सपा विधायकों द्वारा बगावतकी आशंका थी। वैसे बगावत कर्नाटकमें भी हुई जहां भाजपा विधायकने कांग्रेस प्रत्याशीको मत देकर सबको चौंका दिया। लेकिन उत्तर प्रदेशमें सपा और हिमाचलमें कांग्रेस का प्रत्याशी चूंकि हार गया इसलिए भाजपापर विधायकोंको लालच और भय दिखाकर तोड़नेका आरोप लगाया जा रहा है।

उत्तर प्रदेशमें जया बच्चनको उम्मीदवार बनाये जाते ही सपामें बगावतके सुर उठने लगे थे, जिन्हें अखिलेश यादवने अनसुना कर दिया। इसी तरह हिमाचलमें कांग्रेसको बगावतकी आशंका थी इसीलिए सोनिया गांधीको राजस्थानसे राज्यसभा भेजनेका फैसला लिया गया। कुछ मंत्री और विधायक खुलकर मुख्य मंत्रीके विरुद्ध थे। राम मंदिरके शुभारम्भपर विक्रमादित्य सिंह पार्टी लाइनसे अलग हटकर अयोध्या भी गये। उन्होंने मंत्री पदसे इस्तीफा दे दिया, लेकिन शाम होते-होते उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। इस घटनाक्रमके अगले दिन विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानियाने ह्विपकी अनदेखी करनेवाले सभी छह विधायकोंको अयोग्य करार दे दिया है। कुलदीप पठानियाने कहा कि सभी सदस्य अब सदनके सदस्य नहीं हैं। आदेश जारी होनेके बाद सभी छह सदस्य अबसे सदनके सदस्य नहीं रहे हैं। सभी विधायकोंको व्यक्तिगत तौरपर उपस्थित रहनेके लिए ह्वाट्सऐपपर सन्देश भेजा गया था। हिमाचल विधानसभा ई-विधानसे जुड़ी है। ऐसेमें विधायक सन्देश न मिलनेकी बात नहीं कर सकते हैं। सत्तापक्षने ह्विप जारी किया था और सभी छह सदस्य ह्विप जारी होनेके बावजूद सदनमें नहीं थे। उन्होंने कहा कि इसके बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्टमें होनेवाली न्यायिक प्रक्रियाको भी ध्यानमें रखा जायगा। छह विधायकोंको अयोग्य करार देनेके बाद हिमाचलकी राजनीतिमें फिर एक बार तूफान उठनेवाला है। उत्तर प्रदेशमें समाजवादी पार्टी चूंकि विपक्षमें है इसलिए उसे सरकार गिरनेकी चिन्ता तो है नहीं किन्तु लोकसभा चुनावके ठीक पहले पार्टीके विधायकोंकी बगावत अखिलेशके लिए चेतावनी है। निश्चित रूपसे भाजपाकी रणनीति विपक्षी दलोंमें सेंध लगानेकी है। सत्तामें होनेके कारण उसका प्रभाव और दबाव दोनों बढ़े हैं। लेकिन विपक्षको अपनी कमजोरी भी देखनी होगी। हिमाचलमें कांग्रेसकी अंतर्कलहका लाभ ही भाजपाने उठाया। उसी तरह कर्नाटकमें कांग्रेसके पास भारी बहुमत होनेके बाद भी उसने एक भाजपा विधायकको तोड़नेमें संकोच नहीं किया।

हिमाचलके मुख्य मंत्री कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्राकी पसंद थे जिन्हें पूर्व मुख्य मंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंहका परिवार पसन्द नहीं करता। विक्रमादित्य उन्हींके बेटे हैं और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह उनकी माता जी। इस प्रकार सिंघवी न हारते तब भी मुख्य मंत्रीकी कुर्सीको हिलानेका प्रयास जारी रहता। दरअसल ये कांग्रेसके शीर्ष नेतृत्वके लिए चेतावनी है कि उसके द्वारा थोपे गये नेताओंको आंख मूंदकर स्वीकार कर लेनेवाला दौर चला गया। वैसे भी पुरानी कहावत है कि जब केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है तो सूबे सिर उठाने लगते हैं। गांधी परिवार राज्योंमें अपनी मर्जीके नेताओंको लादनेकी जो गलती कर रहा है उसीके कारण अनेक राज्य उसके हाथसे खिसक गये।मध्य प्रदेशमें झटका खानेके बाद भी उसने राजस्थान और छत्तीसगढ़में पनपे असंतोषका समय रहते इलाज नहीं किया जिसका नतीजा सामने है। सपामें भी अखिलेश खुदको सर्वेसर्वा मानकर नेताओं और कार्यकर्ताओंके साथ ही गठबंधनके साथियोंसे दूरी बनाये रहते हैं। यही कारण है कि ओमप्रकाश राजभर और स्वामीप्रसाद मौर्यके बाद जयंत चौधरीने उनसे रिश्ता तोड़ लिया। रही-सही कसर पूरी कर दी राज्यसभा चुनावमें हुई क्रॉस वोटिंगने। इस प्रकार ये स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस और सपा जैसी पाटियोंके शीर्ष नेतृत्वका निचले स्तरतक संवाद टूट चुका है। इन पंक्तियोंके लिखे जानेतक खबर आ गयी कि असममें कांग्रेसके कार्यकारी अध्यक्षने भी पार्टी छोड़ दी। पश्चिम बंगालसे भी ऐसी ही जानकारी आयी है। बेहतर है भाजपाको कोसनेके बजाय कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियां अपने अंदरूनी हालात सुधारें। केवल आपसमें गठबंधन कर लेनेसे उनका बेड़ा पार नहीं होनेवाला। भाजपाकी रणनीति बेशक विपक्षका मनोबल तोड़नेकी है। इसके लिए वह कोई अवसर नहीं छोड़ना चाहती परन्तु जहां भाजपा कमजोर है वहां विपक्षको भी सफलता मिली। कर्नाटक और तेलंगाना इसके उदाहरण हैं। ऐसेमें विपक्षी दलोंको चाहिए वे अपने नेताओं और कार्यकर्ताओंका हौसला बढ़ाते हुए उन्हें पार्टीमें बने रहने प्रेरित करें। यदि वे इस काममें असफल रहते हैं तब फिर किसी औरको दोष देना कहांतक उचित है।

ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है, जब बिहारमें राष्ट्रीय जनता दलके नेता तेजस्वी यादवने खेला कर दिखानेका ऐलान किया था, हालांकि असल वक्त आनेपर खुद उनकी पार्टीके साथ खेला हो गया। फिलहाल जब कोई चलन इतना बेपर्दा रूप ले चुका हो तो यह जरूरी हो जाता है कि उसे संचालित करनेवाली परदेके पीछेकी परिघटनाको समझनेकी कोशिश की जाय तो यदि हम गौर करें तो यह साफ होनेमें देर नहीं लगती कि जिस लोकतंत्रपर हम गर्व करते हैं, वह धीरे-धीरे धनिकतंत्र या अभिजात्य-तंत्रमें तब्दील हो चुका है। जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वे असलमें देशके छोटेसे प्रभु वर्गके हितोंका प्रतिनिधित्व करने लगी हैं। दलबदल या क्रॉस वोटिंग नैतिकता या किसी ईमानका सवाल नहीं है और न ही जनताके साथ धोखा है। जनता अगले चुनावमें अपना जनादेश देकर उन्हें सही ठिकाने लगा सकती है, लेकिन इनसे सरकारें अस्थिर होती हैं और अंतत: प्रभाव जनतापर ही पड़ता है। अब अहम सवाल यह है कि क्या ऐसा कानून बनेगा कि एक दलसे जीतनेके बाद पाला न बदला जा सके।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

अंतरिक्ष में नई इबारत लिखने को हम हैं तैयार

हाल ही में उन अंतरिक्ष यात्रियों के नाम उजागर कर दिए गए, जिनमें से तीन को अंतरिक्ष में उड़ान भरने का अवसर मिलेगा। ये हैं- प्रशांत नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। ये सभी फाइटर पायलट हैं जो भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान अभियान के साक्षी बनने गगनयान से सैर करने वाले हैं। निःसंदेह, 40 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जा रहा है। परंतु इस बार वक्त भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। इन यात्रियों को 2025 में पृथ्वी से 400 किमी दूर स्थित कक्षा में भेजा जाएगा। ये केवल तीन दिन वहां रहेंगे। फिर भारतीय समुद्र में इन्हें उतारा जाएगा। ये चारों यात्री रूस के यूरी गागरिन अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण ले चुके हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अभियान गगनयान की चरणबद्ध तैयारी में क्रायोजेनिक इंजन सीई-20 को उड़ान भरने के लिए स्वदेशी तकनीक से विकसित कर लिया है। गगनयान भारत का पहला ऐसा अंतरिक्ष अभियान होगा, जो तीन भारतीयों को लेकर अंतरिक्ष की उड़ान भरेगा। इस दृष्टि से इंजन में सुधार में मानव सुरक्षा रेटिंग प्रक्रिया को सफल मान लिया गया है। इस इंजन को मानव मिशन के योग्य बनाने की दृष्टि से चार अलग-अलग स्थितियों में 39 हॉट फायरिंग टेस्ट से गुजरना पड़ा है। यह प्रक्रिया 8 हजार 810 सेकेंड तक चली। इस दौरान इन इंजनों को 6 हजार 350 सेकेंड तक जांच से गुजरना पड़ा। यह इंजन मानव रेटेड एलवीएम-3 प्रक्षेपण वाहन के ऊपरी चरण को शक्ति प्रदान करेगा। ये सब तैयारियां भेजे गए इंसान को सुरक्षित रूप में वापस लाने के लिए की जा रही हैं। यही इंजन अंतरिक्ष की उड़ानों से लेकर उपग्रहों के प्रक्षेपण एवं मिसाइल छोड़ने में काम आता है। निःसंदेह, हमारे वैज्ञानिकों ने अनेक विपरीत परिस्थितियों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद इस क्षेत्र में अद्वितीय उपलब्धियां हासिल की हैं। अन्यथा एक समय ऐसा भी था, जब अमेरिका के दबाव में रूस ने क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया था। अब वही रूस इस अभियान में हमारी सबसे ज्यादा मदद कर रहा है। असल में किसी भी प्रक्षेपण यान का यही इंजन वह अश्व-शक्ति है, जो भारी वजन वाले उपग्रहों व अन्य उपकरणों को अंतरिक्ष में पहुंचाने का काम करती है। दरअसल, भारत ने शुरूआत में रूस से इंजन खरीदने का अनुबंध किया था। लेकिन 1990 के दशक के आरंभ में अमेरिका ने मिसाइल तकनीक नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर) का हवाला देते हुए इसमें बाधा उत्पन्न कर दी थी। इसका असर यह हुआ कि रूस ने तकनीक तो नहीं दी लेकिन छह क्रायोजेनिक इंजन जरूर भारत को शुल्क लेकर भेज दिए। कालांतर में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की मदद से भारत को एमटीसीआर क्लब की सदस्यता भी मिल गई, लेकिन इसके पहले ही इसरो के वैज्ञानिकों के कठोर परिश्रम और दृढ़ इच्छाशक्ति के चलते स्वदेशी तकनीक के बूते चरणबद्ध रूपों में इंजन को विकसित कर लिया गया। मानव मिशन की इस उड़ान के पहले चरण का सफल प्रक्षेपण इसरो पहले ही कर चुका है। देश के महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान से जुड़े पैलोड के साथ उड़ान भरने वाले परीक्षण यान के असफल होने की स्थिति में क्रू मॉड्यूल अर्थात? जिसमें अंतरिक्ष यात्री सवार होंगे, को बाहरी अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के बाद वापस सुरक्षित लाने के लिए ह्यक्रू एस्केप सिस्टमह्व यानी चालक दल बचाव प्रणाली (सीईएस) का सफल परीक्षण कर इसरो विश्व कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। इस बचाव प्रणाली की जरूरत इसलिए थी, क्योंकि यान के असफल होने पर कई वैज्ञानिक प्राण गंवा चुके हैं। इस परीक्षण के अंतर्गत क्रू मॉड्यूल रॉकेट से अलग हो गया और बंगाल की खाड़ी में गिर गया। इसरो अध्यक्ष एस. सोमनाथ का कहना है कि इस मानव मिशन के लिए ह्यपर्यावरण नियंत्रण और जीवन समर्थन प्रणाली (ईसीएलएसएस) अन्य देशों से नहीं मिलने के कारण इसरो इसे स्वयं विकसित करेगा। गगनयान की उड़ान 2025 में भरी जाने की संभावना है।

क्या इंडिया गठबंधन भाजपा के लिये चुनौती बनेगा?

आरती कुमारी

राष्ट्र और राष्ट्रीयता के अस्तित्व पर ही प्रश्नचिन्ह लगने लगा है। कुछ अनहोनी होगी, ऐसा सब महसूस कर रहे हैं। प्रजातंत्र में टकराव होता है। विचार फर्क भी होता है। मन-मुटाव भी होता है पर मयार्दापूर्वक। लेकिन अब इस आधार को ताक पर रख दिया गया है। राजनीति में दुश्मन स्थाई नहीं होते। अवसरवादिता दुश्मन को दोस्त और दोस्त को दुश्मन बना देती है। यह भी बडे.रूप में देखने को मिल रहा है। राजनीति नफा-नुकसान का खेल बन रहा है, मूल्य बिखर रहे हैं। चारों ओर सत्ता की भूख बिखरी है। पिछले कुछ समय से इंडिया गठबंधन को एक के बाद एक कई झटके लगे। पहले तो कांग्रेस ने ही पिछले साल दिसंबर के विधानसभा चुनावों में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद में गठबंधन से जुड़ी बातचीत को ठंडे बस्ते में डाले रखा। बातचीत शुरू भी हुई तो नेताओं में न तो पहले जैसा जोश दिखा और न वैसी राजनीतिक जिजीविषा महसूस हुई। फिर गठबंधन के प्रस्ताव पर सबसे बढ़-चढ़कर काम करने वाले नीतीश कुमार ही उसे छोड़ गए। यूपी में रालोद के जयंत चौधरी भी इंडिया गठबंधन का हाथ थामते-थामते एनडीए में शामिल हो गए। इंडिया गठबंधन एवं कांग्रेस ने अनेक झटके झेले। छोटे-बड़े नेताओं के कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला भी तेज हुआ।

अंधेरों एवं निराशा के गर्त में जा चुके एवं लगभग बिखर चुके इंडिया गठबंधन के लिए कुछ अच्छी खबरों ने जहां उसमें नये उत्साह का संचार किया है वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिये चिन्ता के कारण उत्पन्न किये हैं। पहले उत्तर प्रदेश और फिर दिल्ली में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी से सीट बंटवारे पर बनी सहमति ने टूट की कगार पर पहुंचे इंडिया गठबंधन में वर्ष 2024 के आम चुनावों को लेकर संभावनाभरी तस्वीर को प्रस्तुत किया है। अब ये चुनाव दिलचस्प होने के साथ कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर वाले होंगे। इन नये बन रहे चुनावी समीकरणों के बावजूद भाजपा के लिये अभी कोई बड़ा संकट नहीं दिख रहा है। भले ही इंडिया गठबंधन ढ़ींगे हांके कि वह भाजपा एवं उसके गठबंधन के लिए कड़ी चुनौती पेश करने की स्थिति आ गयी है। भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों का जब गठबंधन बना तभी यह आशंका की गयी कि यह कितनी दूर चल पायेगा, टिक पायेगा भी या नहीं? कुछ हालात तो ऐसे भी बने कि इसके तार-तार होने की संभावनाएं बलवती हुई। भले ही अब कुछ सीटों पर दलों के बीच सहमति बनी हो लेकिन अभी कई महीने निकल जाने के बाद भी विधिवत रूप से इंडिया गठबंधन के संयोजक का नाम घोषित नहीं हो पाना अनेक सन्देहों एवं अटकलों का कारण बना हुआ है। सत्ता तक पहुंचने के लिए जिस प्रकार दल-टूटन व गठबंधन हो रहे हैं इससे सबके मन में अकल्पनीय सम्भावनाओं की सिहरन उठती है। राष्ट्र और राष्ट्रीयता के अस्तित्व पर ही प्रश्नचिन्ह लगने लगा है। कुछ अनहोनी होगी, ऐसा सब महसूस कर रहे हैं। प्रजातंत्र में टकराव होता है। विचार फर्क भी होता है। मन-मुटाव भी होता है पर मयार्दापूर्वक। लेकिन अब इस आधार को ताक पर रख दिया गया है। राजनीति में दुश्मन स्थाई नहीं होते। अवसरवादिता दुश्मन को दोस्त और दोस्त को दुश्मन बना देती है। यह भी बडे. रूप में देखने को मिल रहा है। राजनीति नफा-नुकसान का खेल बन रहा है, मूल्य बिखर रहे हैं। चारों ओर सत्ता की भूख बिखरी है। पिछले कुछ समय से इंडिया गठबंधन को एक के बाद एक कई झटके लगे। पहले तो कांग्रेस ने ही पिछले साल दिसंबर के विधानसभा चुनावों में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद में गठबंधन से जुड़ी बातचीत को ठंडे बस्ते में डाले रखा। बातचीत शुरू भी हुई तो नेताओं में न तो पहले जैसा जोश दिखा और न वैसी राजनीतिक जिजीविषा महसूस हुई। फिर गठबंधन के प्रस्ताव पर सबसे बढ़-चढ़कर काम करने वाले नीतीश कुमार ही उसे छोड़ गए। यूपी में रालोद के जयंत चौधरी भी इंडिया गठबंधन का हाथ थामते-थामते एनडीए में शामिल हो गए। इंडिया गठबंधन एवं कांग्रेस ने अनेक झटके झेले। छोटे-बड़े नेताओं के कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला भी तेज हुआ। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण का नाम खास तौर पर चर्चित रहा। इसे चाहे इन नेताओं का व्यक्तिगत अवसरवाद कहें या भाजपा और एनडीए नेतृत्व की सक्रियता एवं राजनीतिक कौशल इतना तय है कि इन नेताओं को कांग्रेस का भविष्य खास अच्छा नहीं दिख रहा। आम आदमी पार्टी एवं समाजवादी पार्टी जैसे दल अपनी साख बचाने एवं सत्ता के करीब बने रहने के लिये सीटों के बंटवारे पर सहमत हुए है, उसमें कांग्रेस का घूटने टेकना भी उसकी टूटती सांसों को बचाने की जद्दोजहद ही कहीं जायेगी। कांग्रेस एवं अन्य दलों के बीच सहमति के स्वर उभरने से आगामी लोकसभा चुनाव में अच्छा मुकाबला दिख सकता है। लेकिन अहम सवाल तो यही है कि क्या गठबंधन की गाड़ी आगे और हिचकोले नहीं खाएगी? क्या यह दावा पूरी दृढ़ता से किया जा सकता है? अरविन्द केजरीवाल ने कांग्रेस से सीटों पर सहमति बनाकर पलटूराम ही बने हैं। जी-भरकर एक-दूसरे को कोसने वाले जब हाथ मिलाए तो आश्चर्य होना स्वाभाविक है। देखा जाये तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच चुनावी गठबंधन होना मूल्यहीनता एवं सिद्धान्तहीनता की चरम पराकाष्ठा है क्योंकि कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ लड़ कर और आंदोलन खड़ा करके ही आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब की सत्ता से कांग्रेस को बाहर किया और अपनी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई। आम आदमी पार्टी के चमत्कारिक प्रदर्शन के चलते ही गुजरात में कांग्रेस ने अब तक का सबसे निराशाजनक प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने गोवा में भी कांग्रेस को काफी नुकसान पहुँचाया और हरियाणा में भी अपने संगठन का आधार बढ़ाया। ताजा कांग्रेस एवं आम आदमी पार्टी की सहमति से कांग्रेस को ही नुकसान होना है। केजरीवाल की बजाय ममता बनर्जी ने अलग छाप छोड़ी है। उसने बंगाल में कांग्रेस के लिए उनकी मौजूदा दो लोकसभा सीटों को ही छोड़ने की बात कह कर कांग्रेस के अधिक सीटों पर दावा करने के कारण स्वतंत्र चुनाव लड़ने की घोषणा कर गठबंधन को धराशायी किया। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल ही नहीं, बल्कि त्रिपुरा, असम और गोवा में भी स्वतंत्र चुनाव लड़ने की बात कह रही हैं, जिससे कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में निराशा ही हाथ लगेगी। इंडिया गठबंधन के नये बन रहे सकारात्मक परिदृश्यों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक सेहत पर कोई असर न झलकना उनकी राजनीतिक परिपक्वता की परिचायक है। 2024 के चुनावों में भाजपा के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 सीटों का लक्ष्य तय करने के मोदी के लक्ष्य के सामने अभी भी कोई बड़ी चुनौती दिख नहीं रही है। इन बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भाजपा एवं मोदी अपनी सीटें कहां से बढ़ा सकेंगे, इसके लिये भाजपा दोतरफा रणनीति पर काम कर रही है। पहली है, दक्षिणी राज्यों में पैठ बनाना। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि भाजपा पहले ही उत्तर-पश्चिम के कई राज्यों में चरम पर पहुंच चुकी है। दूसरी रणनीति है पुराने सहयोगियों को एनडीए में वापस लाने और नए सहयोगियों को जोड़ने की, जिसमें वह अब तक काफी हद तक सफल भी रही है। जदयू एनडीए के साथ फिर से आ गई है, रालोद भी एनडीए में लौट आई है, पंजाब में अकाली दल को वापस लाने के प्रयास जारी हैं और तेदेपा के साथ बातचीत अंतिम चरण में है। कुछ और पार्टियां एनडीए में शामिल हो सकती हैं। लेकिन एनडीए के विस्तार भर से भाजपा को 2024 में 370 सीटें नहीं मिलने वालीं। अभी उसे काफी जोड़-तोड़ करने होंगे। गौरतलब है कि अमित शाह ने तमिलनाडु की कमान संभाल ली है और पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख के. अन्नामलै को काम करने की खुली छूट दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तमिलनाडु का दौरा किया है, जिसे दक्षिण में भाजपा के चुनावी अभियान की शुरूआत के रूप में देखा जा रहा है। केन्द्रीय मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी के साथ सक्रिय किया गया है। भाजपा दक्षिण के राज्यों में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। राम मंदिर का उत्साह निश्चित रूप से उत्तर भारतीय हिंदी पट्टी के राज्यों में अधिक है, लेकिन दक्षिण भी भाजपा को कुछ चुनावी लाभ दे सकता है। याद रहे कि भाजपा ने पहले ही दक्षिण भारतीय राज्यों के लिए मतदाता-पहुंच कार्यक्रम शुरू कर दिया है। तेलंगाना और केरल आदि दक्षिण के राज्यों पर भाजपा विशेष बल दे रहा है, वहां भी इस बार अच्छा प्रदर्शन होने की संभावना है। भाजपा के राजनीतिक समीकरणों एवं रणनीतियों के चलते स्वतंत्र भारत का सबसे दिलचस्प चुनाव में अपने तय लक्ष्यों के अनुरूप ऐतिहासिक जीत को हासिल कर लें तो कोई आश्चर्य नहीं है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

भाजपा की पहली लिस्ट में फिल्मी कलाकारों के बल्ले-बल्ले, भोजपुरी सिनेमा से चार कलाकारों को मौका

अशोक भाटिया

भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इन उम्मीदवारों में कई नाम ऐसे हैं, जो फिल्म और टेलीविजन के जरिए पहले ही अपना एक खास मुकाम बना चुके हैं। भाजपा की टिकट पर कई अभिनेता और अभिनेत्रियां पहले भी संसद में पहुंचते रहे हैं। एक बार फिर पार्टी ने इनमें से कई पर विश्वास जताया है तो वहीं भोजपुरी और दक्षिण भारत की फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नामों को पहली बार चुनाव मैदान में उतारा है। भाजपा ने मथुरा से हेमा मालिनी पर एक बार फिर विश्वास जताया है। हेमा मालिनी मथुरा से सांसद हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने आरएलडी के कुंवर नरेंद्र सिंह को बड़े अंतर से शिकस्त दी थी। वहीं 2014 में उन्होंने आरएलडी के जयंत चौधरी को तीन लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। हेमा मालिनी हिंदी फिल्मों की बड़ी अभिनेत्री और बेहतरीन क्लासिकल डांसर हैं। देखा जाय तो बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी का एक सफल फिल्मी करियर तो रहा ही साथ ही उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में खूब नाम कमाया है । हेमा मालिनी ने साल 2004 में भाजपा ज्वाइन की थी। अमेठी से सांसद व मंत्री स्मृति ईरानी का नाम घोषित किया है । वह 2019 में कांग्रेस के युवा नेता राहुल गाँधी को हरा चुकी है ।दरअसल स्मृति ईरानी 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में तुलसी का किरदार निभाकर घर-घर में मशहूर हुई स्मृति ईरानी वर्तमान समय में मोदी सरकार में मंत्री हैं। राजनीति में आने के बाद स्मृति ने अभिनय के क्षेत्र से दूरी बना ली है। अभिनय से राजनीति तक पहुंचने का सफर स्मृति के लिए बेहद संघर्ष भरा रहा है। भाजपा ने भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया है। वह पहली बार चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। फिलहाल आसनसोल से फिल्म अभिनेता और तृणमूल कांग्रेस के नेता शत्रुघ्न सिन्हा सांसद हैं।

2019 में यहां से प्लेबैक सिंगर बाबुल सुप्रियो ने भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज की थी। हालांकि बाद में वह भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे, जिसके बाद उपचुनाव में इस सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा ने तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की थी। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो पवन सिंह की अनुमानित नेटवर्थ 6 से 8 मिलियन डॉलर के आस-पास है। भारतीय रुपये में ये 50 से 65 करोड़ रुपये के आस-पास होती है। पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा के बड़े नाम हैं और उनकी फैन फोलोइंग भी लाखों में है। पवन सिंह की कमाई का मुख्य जरिया फिल्में ही हैं। यही वजह है कि वह एक फिल्म के लिए लाखों रुपये चार्ज करते हैं। पवन सिंह एक फिल्म में काम करने के लिए 40 से 50 लाख रुपये फीस लेते हैं। सालभर में उनकी एक या दो फिल्में आ ही जाती हैं। भोजपुरी सुपरस्टार सिर्फ एक्टिंग में ही दमदार नहीं हैं, बल्कि सिंगिंग में भी उनका कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कई फेमस गाने गाए हैं। पवन सिंह एक गाने के लिए 2 से 3 लाख रुपये चार्ज करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पवन सिंह एक साल में 3 से 5 करोड़ रुपये की कमाई करते हैं। भोजपुरी एक्टर और गायक पवन सिंह ने 2014 में भाजपा ज्वाइन की थी। उसी समय से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा थी लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। दस साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उन्हें मौका मिला है। वहीं आसनसोल सीट के इतिहास को देखे तो अक्सर इस सीट पर सितारों को उतारा जाता है। इससे पहले 2019 में भाजपा की ओर से बाबुल सुप्रियो ने इस सीट पर कब्जा किया था। उन्होंने टीएमसी की मुनमुन सेन को परास्त किया था। पवन सिंह के साथ ही भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची में कई भोजपुरी स्टार दोबारा शामिल हैं। इनमें मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव निरहुआ शामिल हैं। भाजपा ने दिल्ली भोजपुरी स्टार और उत्तर-पूर्व दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी पर पार्टी ने एक बार फिर विश्वास जताया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मनोज तिवारी ने कांग्रेस उम्मीदवार और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को साढे तीन लाख से भी अधिक वोटों से हराया था। निर्वाचन क्षेत्र में पूर्वांचल के मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है और उनके बीच मनोज तिवारी लोकप्रिय चेहरा हैं। वह 2014 में भी इस सीट से सांसद रह चुके हैं। मनोज तिवारी बिहार के अटरवलिया गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई बनारस से की है। भाजपा ने गोरखपुर के मौजूदा सांसद और अभिनेता रवि किशन को एक बार फिर लोकसभा चुनाव का टिकट दिया है। रवि किशन गोरखपुर से सांसद हैं और पार्टी ने इसी सीट से उन पर एक बार फिर विश्वास जताया है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के रामभुआल निषाद को करीब तीन लाख वोटों के बड़े अंतर से हराया था। रवि किशन शुक्ल को रवि किशन के नाम से ही जाना जाता है। वह फिल्म अभिनेता के साथ टेलीविजन में भी काम कर चुके हैं। साल 2006 में वह भी बिग बॉस में भाग ले चुके हैं। इसके साथ ही भाजपा ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से एक और भोजपुरी स्टार को चुनाव मैदान में उतारा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ को आजमगढ़ से अखिलेश यादव ने करीब ढाई लाख वोटों से हराया था। हालांकि उपचुनाव में निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को हराकर इस सीट पर कब्जा जमाया था। एक बार फिर पार्टी ने उन्हें यहां से उम्मीदवार बनाया है। दिनेश लाल यादव गाजीपुर के छोटे से गांव टंडवा से ताल्लुक रखते हैं। दिनेश लाल यादव जिन्हे निरहुआ के नाम से भी जाना जाता है, एक भोजपुरी फिल्म गायक, अभिनेता और टेलीविजन प्रस्तोता हैं ।दिनेश लाल यादव भी बिग बॉस शो के कंटेस्टेंट रह चुके हैं। भोजपुरी अभिनेताओं के साथ भाजपा ने केरल की त्रिसूर सीट से फिल्म अभिनेता सुरेश गोपी को उम्मीदवार बनाया है। सुरेश गोपी एक अभिनेता होने के साथ ही पार्श्व गायक भी रह चुके हैं और साउथ इंडस्ट्री का बड़ा नाम हैं। इसके साथ ही भाजपा ने पश्चिम बंगाल की हुबली सीट से लॉकेट चटर्जी को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया है। लॉकेट चटर्जी ने 2019 का लोकसभा चुनाव भी हुबली लोकसभा सीट से लड़ा और जीता था। वह बांग्ला फिल्मों की अभिनेत्री और क्लासिकल डांसर हैं। अभी भाजपा की दूसरी लिस्ट भी आने वाली है । सूत्रों की माने तो गुरदासपुर से सन्नी देओल की जगह अक्षय कुमार चुनाव लड़ सकते है । वैसे पहले अक्षय कुमार की दिल्ली से चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही थी पर दिल्ली की सातों सीटों पर नाम घोषित हो चुके है । राजनीति सूत्रों की मानें तो इस बार कई सांसदों के टिकट रिपीट होने के चांस नहीं थे लेकिन कई उम्मीदवारों को रिपीट किया गया है। कई राज्यों में जाति जनगणना के आधार पर टिकट दिए गए हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि जिसके बारे में सोचा नहीं था, उसे इस बार टिकट मिला है।

सम्पादकीय

गगनयान दिखाएगा चांद पर भारतीयों के उतरने का रास्ता

लगभग 50 साल पहले अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ में चांद पर जाने की रेस शुरू हुई थी। अमेरिका पहला देश है, जो चांद पर इंसान को भेजने में सफल रहा। सोवियत संघ ने भी अपना लैंडर चांद पर उतरा। भारत इस क्षेत्र का अपेक्षाकृत नया खिलाड़ी है। चंद्रयान-तीन मिशन के जरिये वह अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखा चुका है। अब वह गगनयान के जरिये अपने चार अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में भेजेगा। उसका लक्ष्य अंतरिक्ष में एक स्टेशन बनाने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया और मिशन गगनयान की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मिशन पर जाने वाले चार यात्रियों को भी सम्मानित किया। इस समीक्षा बैठक में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के लिए एक दूरदर्शी रोडमैप तैयार किया गया। इसके लक्ष्यों में से एक है, भारत-निर्मित, स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना करना, जिसको भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के रूप में जाना जाएगा। यह भारत के अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे में एक 'एसेट' के रूप में कार्य करेगा। इस महत्वपूर्ण प्रयास के साल 2035 तक साकार होने की उम्मीद है। अनुमान है कि वर्ष 2030 तक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसे वर्तमान में अमेरिका, रूस, कनाडा, जापान और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है, बंद हो जाएगा।

गगनयान देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, जिसके तहत चार यात्रियों को अंतरिक्ष की सैर कराई जाएगी। इस मिशन को इस साल के आखिर या 2025 की शुरुआत में भेजा जा सकता है। इन चार यात्रियों में पहले हैं एस्ट्रोनॉट प्रशांत बालाकृष्णन नायर। प्रशांत केरल के केपलक्कड़ के नेनमारा के रहने वाले हैं। उनको रूस में मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए ट्रेनिंग दी गई है। दूसरे एस्ट्रोनॉट अजित कृष्णन वायुसेना के टेस्ट पायलट हैं। वह भी प्रशांत बालाकृष्णन की तरह ही एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन हैं। अजित कृष्णन का जन्म चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। तीसरे अंगद प्रताप भी वायुसेना में फाइटर और टेस्ट पायलट हैं। वह भी ग्रुप कैप्टन के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अंगद प्रताप का जन्म प्रयागराज में हुआ था। चौथे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला वायुसेना में विंग कमांडर हैं। लखनऊ में जन्मे शुभांशु की मिलिट्री ट्रेनिंग एनडीए में हुई है। गगनयान मिशन के लिए न जाने कितने पायलटों का टेस्ट हुआ, जिनमें से इन चारों को चुना गया। भारत और तब के सोवियन संघ के संयुक्त अंतरिक्ष अभियान में राकेश शर्मा आठ दिनों तक अंतरिक्ष में रहे थे। अंतरिक्ष में जाने वाले वह पहले भारतीय और विश्व के 138वें व्यक्ति थे। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक कल्पना चावला 19 नवंबर, 1997 को छह अंतरिक्ष यात्रियों के एक दल का हिस्सा थीं। अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की उड़ान से अंतरिक्ष की यात्रा करके कल्पना ने अपने नाम का डंका बजाया। कल्पना चावला ने इस मिशन में कुल 65 लाख मील का सफर तय किया। इस दौरान उन्होंने पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं कीं। लेकिन अपने दूसरे अभियान में 1 फरवरी, 2003 को पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने के बाद उनका अंतरिक्ष यान भीषण दुर्घटना का शिकार हो गया और कल्पना के साथ दल के सातों सदस्य धरती पर पहुंचने से पहले ही अवशेष में बदल गए।

कानून को अपना रसूख दिखाने वाले नेताओं पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी दिल्ली शराब घोटाले में पूछताछ के लिए अब तक आठ समन भेज चुका है। जांच एजेंसी के सामने पेश होने की बजाय केजरीवाल ईडी के समन को ही गैर कानूनी बता रहे हैं। वो कानूनी दांव पेंच से जांच से बच रहे हैं। और दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर केंद्र की मोदी सरकार से लेकर अपने राजनीतिक विरोधियों पर जमकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। चूंकि विधानसभा में दिए बयान पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। इसी के चलते केजरीवाल ने विधानसभा को अपनी भड़ास निकालने और राजनीतिक विरोधियों पर मनगंढ़त आरोप लगाने का मंच बना रखा है। देश की जनता उनका तमाशा देख रही है। जिस शराब घोटाले में उनसे पूछताछ होनी है, उसी घोटाले में उनके सबसे खास साथी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तिहाड़ की रोटियां तोड़ रहे हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति किस तरह कानून और संविधान का उपहास उड़ा रहा है, उससे समाज में गलत उदाहण तो पेश हो ही रहा है। वहीं आम आदमी के मन में यह सवाल भी उठता है कि क्यों कानून रसूखदारों सामने कमजोर और असहाय दिखाई देता है?

डॉ. आशीष वशिष्ठ।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रभावशाली लोग कानून को खिलौना समझ कर खेलते हैं और व्यवस्था भी उनके इस काम में खूब मददगार साबित होती है। बरसों बरस से देश में ऐसा ही चलता आ रहा है। सख्त से सख्त कानून बनाने और तमाम दूसरे उपायों के बाद भी रसूखदार कानून का आए दिन मजाक उड़ाने से बाज नहीं आते हैं। कानून को बौन साबित करने वाली इस जमात को राजनीतिक संरक्षण हासिल होता है। ऐसे में धनबल और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त ये लोग व्यवस्था की कमियों और छिद्रों के चलते नियम कानूनों को आसानी से गच्चा देते हैं। आम आदमी की मामूली-सी गलती पर उसे पकड़ने में भरपूर तेजी दिखाने वाली पुलिस को प्रभावशाली और रसूखदार लोगों तक पहुंचने में वक्त लग ही जाता है। पश्चिम बंगाल में इसकी अवधि कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाती है। संदेशखाली मामले से चौतरफा निंदा का पात्र बना तृणमूल कांग्रेस का नेता शाहजहां शेख 55 दिनों से फरार रहने के बाद पुलिस की गिरफ्त में आया है! लेकिन तब, जब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ममता सरकार को फटकार लगाई। यदि फटकार नहीं लगी होती तो उसे छुपाए रखा गया होता। वह जिस हनक और रूआब से थाने और अदालत में दाखिल हुआ, उससे यही लगा कि वह कोई शहंशाह है।

पश्चिम बंगाल पुलिस उसके आगे दंडवत और सहमी-सी दिखी। उसे सत्ता का संरक्षण प्राप्त था, यह सच्चाई तृणमूल कांग्रेस के इस कथन से छिपने वाली नहीं कि हमने उसे निलंबित कर दिया। यह राजधर्म नहीं, बेशर्मी है कि उसे गिरफ्तार न करने के लिए उच्च न्यायालय के आदेश की गलत व्याख्या तक की गई। यदि ईडी को शक है कि बंगाल पुलिस शाहजहां शेख की मदद कर सकती है तो यह स्वाभाविक है। बड़ी निर्लज्जता से तृणमूल कांग्रेस की सरकार अपने नेता का बचाव करती रही। संदेशखाली की महिलाओं ने जिन शब्दों में अपनी पीड़ा का बयान किया है, उससे किसी पत्थर दिल व्यक्ति का भी दिल पिघल सकता है। लेकिन पश्चिम बंगाल की महिला मुख्यमंत्री का दिल नहीं पसीजा। भारतीय जनता पार्टी के विरोध और हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद शाहजहां को गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल की तरह तेंलगाना के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ईडी के समन की अवमानना करते रहे और खुद को बचाने के सारे यत्न उन्होने किये। बड़ी जद्दोजहद के बाद ईडी ने उन्हें अपने शिकंजे में लिया। फिलवक्त सोरेन जेल का भोजन पा रहे हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या और बलात्कार के मामले में जेल में सजा काट रहे राम रहीम को बार-बार पैरोल दिये जाने पर सवाल उठाया। हाईकोर्ट ने कहा कि क्यों केवल राम रहीम को बार-बार पैरोल मिल रही है? बाकी कैदियों को क्यों नहीं लाभ दिया जाता? रेप के दोषी राम रहीम को इस साल जनवरी में 50 दिन की पैरोल दी गई थी। यह लगभग 10 महीने में उसकी 7वीं और पिछले चार वर्षों में 9वीं पैरोल थी। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि अब अदालत की अनुमति के बिना राम रहीम को पैरोल नहीं दी जाएगी। सत्ता, व्यवस्था, कानून के रक्षक और संरक्षक के गठजोड़ से ही राम रहीम जैसे रसूखदार कानून को फुटबाल बनाकर खेलते हैं। जब तक सत्ता के गलियारों से आपराधिक लोगों को संरक्षण मिलता रहेगा, तब तक ये निर्लज्जता बनी रहेगी। हरेक घटना में किसी न किसी रसूखदार का, किसी न किसी सत्ताधारी का संरक्षण दिखता रहा है। हर बार सत्ता की तरफ से कठोर से कठोर कार्यवाही किये जाने की बात कही जाती है, कुछ दोषियों की गिरफ्तारी भी हो जाती है, जांच करवाए जाने की लीपापोती कर दी जाती है और उसके बाद सब कुछ भूल-भुला लिया जाता है। संदेशखाली जैसी घटनाएं कुछ दिन चर्चा में रहती हैं फिर जनमानस की खोपड़ी से गायब हो जाते हैं. निठारी कांड कितनों को याद है? बिहार मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस कितनों को याद है? कितनों को उसके दोषी की सजा याद है? कुछ दिन बाद ऐसा ही संदेशखाली में को भी लेकर होगा। प्रभावशाली किस मामले में फंस भी जाते हैं तो उनके चेहरे, बॉडी लैग्वेंज, चेहरे से टपकते घमंड और अहंकार को देखकर ऐसा नहीं लगता कि उनको कानून का रत्ती भर भी भय है। पुलिस प्रशासन को तो वो अपना चाकर समझते हैं। कहीं न कहीं व्यवस्था भी उनकी चाकरी करती दिखाई देती है।

न्याय व्यवस्था भी ऐसी है कि प्रभावशाली लोगों को जमानत देने में देर नहीं करती। आधी रात को भी उनके मामले सुन लिए जाते हैं। हालांकि देश की अदालतों में करोड़ों मुकदमे लंबित हैं। और आम व्यक्ति को न्याय पाने के लिए वर्षों प्रतीक्षा करनी पड़ती है। भ्रष्टाचार व अन्य गंभीर मामलों में दर्जनों रसूखदार आसानी से जमानत पाकर आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। चारा घोटाले में सजा पाए लालू प्रसाद यादव स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के चलते जमानत पर हैं। राजनीति में उनकी सक्रियता बताती है कि अब वो स्वस्थ हैं। और अगर वो स्वस्थ हैं तो वो जमानत पर क्यों हैं? अगर रसूखदारों को जेल जाना भी पड़ा तो वहां भी उनके मनमुताबिक ऐशो आराम जारी रहता है। ऐसे सैंकड़ों उदाहरण है। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के जेल की कोठरी में कथित तौर पर मालिश कराने का वीडियो देश ने देखा है। यूपी के चर्चित नेता और माफिया मुख्तार अंसारी की पंजाब की जेल में कांग्रेस की सरकार ने जो मेहमाननवाजी की उसे कौन भूल पाएगा। देशवासी भूले नहीं होंगे जब एक रसूखदार दामाद ने मैंगो पीपल कहकर आम आदमी का जिस तरह मजाक उड़ाया था, बॉलीवुड के एक गायक ने फुटपाथ पर सोने वाले बेघर लोगों को कुत्ते कहकर उसी अहंकार का परिचय दिया था। किसी नेता या रसूखदार को जब जांच एजेंसी पकड़ती है तो वो विजय मुद्रा बनाकर हवा में हाथ लहराता है। मानो उसने कोई महान काम किया है। गिरफ्तारी के समय या जांच के लिए जाते वक्त नेताओं और रसूखदारों के हाव भाव ऐसे होते है मानो वो एहसान करने जा रहे हैं। और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, उनको तो राजनीति के चलते फंसाया गया है।

आज का इतिहास

4 मार्च की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- पश्चिम बंगाल में 1788 में कलकत्ता गजट का पहला प्रकाशन हुआ।
- सन 1930 में फ्रांस में आयी भयंकर बाढ़ से करीब 700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई।
- ब्रिटिश वायसराय, गवरनोर-जनरल एडवर्ड फ्रेदेरिक्क लिन्द्ले वुड और मोहनदास करमचंद गाँधी जी (महात्मा गाँधी) में सन 1931 में भेंट राजनीतिक कैदियों की रिहाई और नमक के सर्वजन उपयोग की छूट को लेकर मंत्रणा और इकरारनामे की घोषणा।
- नयी दिल्ली में सन 1951 में पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया गया।
- रोमानिया में 1977 में आये जबरदस्त भूकंप से लगभग 1541 लोगों की मौत हुई।
- संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों को अपनी परित्यक्ता पतनी एवं बच्चों को 1999 में जीवन निर्वाह भत्ता देने की घोषणा।
- तालिबान ने 2001 में मूर्तियों को ख़रीदने की ईरान की पेशकश ठुकराई।
- हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान् डॉ. मदन लाल मधु को 2008 में प्रतिष्ठित सम्मान मीडिया यूनियन ने स्वर्णाक्षर पुरस्कार से सम्मानित किया।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2008 में ईरान के ख़िलाफ़ नई पाबंदियाँ लागू की।
- राजस्थान के पोखरन से 2009 में ब्रह्मोस मिसाइल के नये संस्करण का परीक्षण किया गया।
- व्लादिमिर पुतिन ने 2012 में रूस के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता।

4 मार्च को जन्मे व्यक्ति

- 1856 में अंग्रेज़ी भाषा की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभासम्पन्न कवयित्री तोरु दत्त का जन्म।
- 1881 में प्राक्छायावादी युग के महत्त्वपूर्ण कवि रामनरेश त्रिपाठी का जन्म।
- 1886 में मद्रास के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी बलुसु संबमूर्ति का जन्म।
- हिंदी के लोकप्रिय साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु का 1921 में जन्म हुआ।
- 1922 में प्रसिद्ध गुजराती रंगमंच और फ़िल्म अभिनेत्री दीना पाठक का जन्म।
- 1980 में भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना का जन्म।
- 1980 में भारतीय फ़िल्म अभिनेत्री कामालिनी मुखर्जी का जन्म।

4 मार्च को हुए निधन

- मध्य प्रदेश स्थित विजयराघवगढ़ के राजकुमार और प्रसिद्ध साहित्यकार ठाकुर जगमोहन सिंह का 1899 में निधन।
- प्रसिद्ध भारतीय अधिवक्ता और राजनेता सत्येन्द्र प्रसन्न सिन्हा का 1928 में निधन।
- भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी और 'गदर पार्टी' के संस्थापक लाला हरदयाल का 1939 में निधन।
- भारतीय सांसद सुनील कुमार महतो का 2007 में निधन।
- भारत के राजनीतिज्ञों में से एक पी. ए. संगमा का 2016 में निधन।

रूढ़ियों को तोड़कर इतिहास गढ़ रहीं महिला खिलाड़ी

अपने देश में महिला प्रीमियर लीग, यानी डब्ल्यूपीएल का आगाज हो चुका है। दुनिया भर में महिला खेलों का विकास बदस्तूर जारी है। इसे पिछले साल एक नई ऊर्जा मिली थी। दरअसल, साल 2023 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लंबे अंतराल के बाद दो टेस्ट खेले। इंग्लैंड में द हंड्रेड वीमेंस कॉम्पिटिशन (क्रिकेट प्रतियोगिता) के दूसरे संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। टूर डी फ्रांस फेमिनिन (साइकिल प्रतियोगिता) एक रोमांचक श्रृंखला साबित हुई। फॉर्मूला वन ने महिला ड्राइवरों के लिए फीडर प्रोग्राम की घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने संयुक्त रूप से फीफा महिला विश्व कप का आयोजन किया। इंग्लैंड की महिला फुटबॉल टीम की गोलकीपर मैरी इयरप्स ने क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड और गोल्फर रोरी मैक्लरॉय जैसे खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का खिताब जीता, वहीं द गार्जियन के फुटबॉलर ऑफ द ईयर के लिए स्पेनिश खिलाड़ी जेनी हर्मोसो को नामित किया गया। जाहिर है, खेलों में महिलाओं की दुनिया लगातार निखर रही है, पर सुधार की गति उम्मीद से धीमी है। अब डब्ल्यूपीएल में ही 10 टीमें हैं, पर पांच टीमों के साथ इसे शुरू किया गया। बेशक, बीसीसीआई ने फिल्मी सितारों के प्रदर्शन से इसके उद्घाटन समारोह को आकर्षक बना दिया, पर कोलकाता नाइट राइडर्स (जिसके मालिक शाहरुख खान हैं) जैसी बड़ी आईपीएल फ्रेंचाइजी के पास अब भी डब्ल्यूपीएल टीम नहीं है। इसी तरह, महिला और पुरुष, दोनों क्रिकेट खिलाड़ियों को समान वेतन जरूर मिलता है, लेकिन महिलाएं शायद ही टेस्ट क्रिकेट खेलती हैं। फ्री हिट : द स्टोरी ऑफ वीमेंस क्रिकेट इन इंडिया की लेखिका सुप्रिता दास कहती हैं, इन सबके अलावा परदे के पीछे कई अन्य मसले भी हैं और टीम व बैकरूम स्टाफ के चयन-प्रक्रिया भी उलझी हुई है। आईपीएल और आईएसएल के साथ काम करने वाले मार्केटिंग प्रोफेशनल मानते हैं कि प्रायोजकों को महिलाओं के खेल में निवेश करने के लिए मनाना आज भी काफी मुश्किल होता है। उनमें यह पूर्वाग्रह भी है कि महिलाओं के खेल की गुणवत्ता कमजोर होती है, जो सच नहीं है।

हालांकि, सवाल सिर्फ प्रायोजकों का नहीं है, पेशेवर रूप से खेलने में सक्षम बनने के लिए महिला खिलाड़ियों को खुद कई चुनौतियों से टकराना पड़ता है। विकसित देशों से लेकर विकासशील दुनिया तक, जिम्नास्टिक से लेकर कुश्ती तक, बीच वॉलीबॉल से लेकर फुटबॉल तक, तमाम जगहों पर महिला खिलाड़ियों को जूझना पड़ता है। सरकारी निकायों व खेल संस्थाओं द्वारा उन्हें हतोत्साहित किया जाता है। और, यह सब तब हो रहा है, जब महिलाओं के खेल अविश्वसनीय रूप से मुख्यधारा में आने लगे हैं।

विशेष आलेख

अपनी भूलों के भंवर में कांग्रेस

कांग्रेस को ताजा झटका हिमाचल से लगा है। वहां न केवल राज्यसभा के लिए पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी को अप्रत्याशित पराजय का सामना करना पड़ा, बल्कि लंबे समय तक इस पर्वतीय प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा रहे वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया। फिलहाल उन्हें पार्टी ने रोक लिया है, पर क्रॉस वोटिंग करने वाले छह विधायकों को अपनी सदस्यता से हाथ धोना पड़ गया। शिमला में सियासी तापमान इस समय चरम पर है। कांग्रेस अगर इस झंझावात से उबरने में कामयाब हो जाए, तब भी उस तबके में कोई कमी नहीं आएगी, जो इस पार्टी को पुरा ऐतिहासिक साबित करने में जुटा है। ये लोग भूल जाते हैं कि राजनीति सांप-सीढ़ी का विषम खेल है, कोई परिकथा नहीं।

अपनी बात समझाने के लिए मैं आपको 40 साल पीछे ले चलता हूं। उस वर्ष के अंत में हुए आम चुनाव में कांग्रेस ने 414 और भारतीय जनता पार्टी ने महज दो सीटें जीती थीं। क्या तब किसी ने सोचा था कि हर ओर से निंदा के शिकार अटल बिहारी वाजपेयी कुलजमा 12 बरस में देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे और सूर्य की तरह चमकते राजीव महज चार साल में आभा खो बैठेंगे? इससे पहले जिन मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह को इंदिरा गांधी ने अलग पार्टी बनाने पर मजबूर कर दिया था, वे भी प्रधानमंत्री की कुरसी तक पहुंचे। इंदिरा गांधी के शुरुआती दौर में ही अपमानित महसूस करने वाले नीलम संजीव रेड्डी तो राष्ट्रपति बन गए थे। यही नहीं, राजीव ने जिन विश्वनाथ प्रताप सिंह को अपमानित कर पार्टी से निकाल दिया था, वह उनके तत्काल बाद प्रधानमंत्री चुने गए। पता नहीं, आपको याद है या नहीं? 1989 के चुनाव में विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रमुख चेहरा तो थे, पर उनका रास्ता हमवार न था। शपथ ग्रहण से पहले परदे के पीछे जबर्दस्त द्वंद्व चल रहा था कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा? चंद्रशेखर उन्हें नेता मानने को तैयार न थे। इस कठिन परिस्थिति से उबरने के लिए कुछ सयानों ने सुझाया कि क्यों न हरियाणा के वरिष्ठ नेता चौधरी देवीलाल को प्रधानमंत्री बना दिया जाए? दोनों खेमे इस पर सहमत भी हो गए थे, लेकिन हरियाणा के ताऊ ने ऐन समय पर अकल्पनीय चाल चल दी। अपने नाम की घोषणा होने के बाद उन्होंने माइक संभाला और जो कहा, उससे सभी अचंभित रह गए। उनके शब्द थे कि मैं ताऊ ही बना रहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री तो राजा साहब (वी.पी. सिंह) रहेंगे। वहां तत्काल जयघोष गूंजने लगा। यह फैसला जनभावना के अनुकूल था, मगर चंद्रशेखर और उनके साथियों ने इसे दिल पर ले लिया। वह पहले दिन से सरकार गिराने में जुट पड़े। महज 11 महीने के छोटे से अंतराल में अपना मनोरथ पूर्ण करने में वह सफल रहे और अब उनकी बारी थी।

है न गजब! जिस राजीव गांधी को बदनाम कर सत्ता से हटाने वालों के वह सरदार थे, उन्हें दर-बदर कर कुरसी हासिल करने में चंद्रशेखर को राजीव गांधी की मदद मिली। यह बात अलग है कि महज आठ महीनों में कांग्रेस ने उनके पैर के नीचे की कालीन सरका दी। अब कांग्रेस की बात। यह ठीक है कि 1989 से एक अपवाद को छोड़कर इस पार्टी का वोट बैंक छीजता चला गया है, पर भूलिए मत, आज भी तीन राज्यों में इसकी बहुमत संपन्न सरकार है। झारखंड की हुकूमत में यह हिस्सेदार है और जनवरी के अंत तक बिहार के सत्ता-सदन में भी इसका दखल होता था। 13 राज्यों में इसे प्रमुख विपक्षी पार्टी का दरजा हासिल है। देश के हर जिले में जर्जर ही सही, पर इसका संगठन मौजूद है और वह हमेशा के लिए गर्त में चला गया हो, ऐसा भी नहीं है। देश भर में पार्टी के पास 650 से अधिक विधायक हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में लगभग 12 करोड़ मतदाताओं ने इस पर भरोसा जताया था। कुलजमा 196 लोकसभा सीटों पर यह दूसरे नंबर पर थी।

क्या आपको अब भी लगता है कि कांग्रेस का खेल खत्म हो रहा है? रही बात राहुल गांधी की, तो यह तय जान लीजिए कि वह आज भी कांग्रेस के सबसे बड़े और लोकप्रिय नेता हैं। यह बात अलग है कि अगर हार का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा, तब या तो कांग्रेस बिखर जाएगी अथवा उसे नया झंडाबरदार चुनना होगा। इससे बचने के लिए नेहरू-गांधी परिवार को अपनी ऐतिहासिक कमजोरियों से छुटकारा पाना होगा। उन्हें अपने संदेश का तरीका और नए संदेश-वाहक चुनने होंगे। इंदिरा गांधी के शुरुआती वक्त तक कांग्रेस बड़े क्षत्रपों की पार्टी हुआ करती थी। उसके पास हर राज्य में इतने कद्दावर नेता थे कि वे सत्ता और संगठन, दोनों को संभालने का माद्दा रखते थे। इंदिरा गांधी ने जिस एक नायकवाद की शुरुआत की, उनके वंशज उसी का शिकार बन रहे हैं। उनके पुत्र राजीव गांधी ने भी इसे सुधारने के बजाय बढ़ाने का अनर्थ किया। राहुल भी राजनीति में अपने पिता की तरह हिचकते हुए आए थे। उनसे उम्मीद थी कि वह इस भूल को सुधारने का सार्थक प्रयास करेंगे। वह ऐसा न कर सके। इन चुनावों से पूर्व मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में पार्टी ने सत्ता हासिल कर ली थी। कायदे से ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विविध लक्ष्यों को पूरा करेंगे। क्या आप यह जानना चाहते है कि आपके जीवन के ऐसे कौनसे क्षेत्र है, जहां आपके सितारे बुलंद रहेंगे और दूसरी तरफ, अपको किस बातों से सावधान रहना चाहिए। हम न सिर्फ हमारे काम में और जटिल मुद्दों को सुलझाते वक्त सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे, बल्कि पारम्परिक संबंधों में भी, जहां यह स्थानान्तरण हमें संताए और बातचीत में लाभ प्रदान करेगा

मेष

मनपसंद भोजन का आनंद प्राप्त होगा। लेन-देन में सावधानी रखें। शत्रुओं का पराभव होगा। विवाद को बढ़ावा न दें। भय रहेगा। प्रमाद न करें। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा। व्यवसाय ठीक चलेगा।

वृष

भाइयों का सहयोग मिलेगा। पुराने किए गए प्रयासों का लाभ मिलना प्रारंभ होगा। मित्रों की सहायता कर पाएंगे। नौकरी में चैन रहेगा। निवेश शुभ रहेगा। किसी वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग प्राप्त होगा। पूजा-पाठ में मन लगेगा।

मिथुन

आय में निश्चितता रहेगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। प्रमाद न करें। लाभ बढ़ेगा। यात्रा में सावधानी रखें। जल्दबाजी से हानि होगी। अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे। चिंता तथा तनाव रहेंगे। दूसरों के कार्य में दखल न दें। पारिवारिक चिंता बनी रहेगी।

कर्क

जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा। कारोबार में वृद्धि होगी। नौकरी में अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। रुके हुए कार्यों में गति आएगी। घर-बाहर सभी अपेक्षित कार्य पूर्ण होंगे। दूसरों के कार्य की जवाबदारी न लें। वाणी पर नियंत्रण रखें। अपेक्षित कार्यों में विलंब होगा।

सिंह

वाणी पर नियंत्रण रखें। अपेक्षित कार्यों में विलंब हो सकता है। अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। नौकरी में उच्चाधिकारी की प्रसन्नता प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। शारीरिक कष्ट से बाधा संभव है।

कन्या

आय में निश्चितता रहेगी। मातहतों से अनबन हो सकती है। पारिवारिक समस्याओं में इजाफा होगा। चिंता तथा तनाव बने रहेंगे। भागदौड़ रहेगी। दूर से बुरी खबर मिल सकती है। विवाद को बढ़ावा न दें। बनते कामों में बाधा हो सकती है।

तुला

प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। निवेश शुभ रहेगा। पार्टनरों का सहयोग प्राप्त होगा। लेन-देन में जल्दबाजी न करें। व्यापार में अधिक लाभ होगा। यात्रा मनोरंजक रहेगी। किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा।

वृश्चिक

कोर्ट व कचहरी के काम बनेंगे। अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। बेचैनी रहेगी। चोट व रोग से बचें। विवेक से कार्य करें। लाभ में वृद्धि होगी। मान-सम्मान मिलेगा। प्रसन्नता रहेगी। कारोबार में वृद्धि होगी। नौकरी में अधिकार बढ़ सकते हैं।

धनु

छोटे भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा। संचित कोष में वृद्धि होगी। प्रतिद्वंद्विता में वृद्धि होगी। जीवनसाथी से अनबन हो सकती है। स्थायी संपत्ति खरीदने-बेचने की योजना बन सकती है। परीक्षा व साक्षात्कार आदि में सफलता प्राप्त होगी।

मकर

व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। किसी के व्यवहार से स्वाभिमान को चोट पहुंच सकती है। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। नौकरी में अनुकूलता रहेगी। व्यापार में वृद्धि होगी। कोई बड़ी बाधा आ सकती है। राजभय रहेगा।

कुंभ

दूसरों से अपेक्षा न करें। कुसंगति से हानि होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। नौकरी में अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। किसी बड़े काम करने की योजना बनेगी। व्यवसाय लाभप्रद रहेगा।

मीन

चिंता तथा तनाव रहेंगे। पार्टनरों से मतभेद संभव है। व्यवसाय ठीक चलेगा। समय नेष्ट है। वाहन व मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें। जरा सी लापरवाही से अधिक हानि हो सकती है। पुराना रोग बाधा का कारण बन सकता है। जल्दबाजी से काम बिगड़ेंगे।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

यशोदा मैया ने बनाया मंत्री और अब देवकी मैया बनाएगी सांसद

(उत्तरशक्ति)

महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्यमंत्री तथा वरिष्ठ भाजपा नेता कृपाशंकर सिंह हमेशा से अपनी कर्मभूमि मुंबई के साथ-साथ जन्मभूमि जौनपुर से भी जुड़े रहे। वे अपने वक्तव्यों में भी बराबर कहते रहे कि उत्तर प्रदेश उनकी मां है तो महाराष्ट्र उनकी मौसी। उत्तर प्रदेश को देवकी मैया और महाराष्ट्र को यशोदा मैया की संज्ञा देने वाले कृपाशंकर सिंह हमेशा अपनी जन्मभूमि के विकास और वहां की समस्याओं के निराकरण की दिशा में समर्पित निस्वार्थ भावना के साथ लगे रहे। प्रदेश और केंद्र के मंत्रियों से अच्छे संबंध होने के कारण उन्होंने समय-समय पर जनपद में पुल और सड़कों से लेकर विकास के अनेकों काम किए। केंद्रीय नेताओं के साथ-साथ आम जनता से भी जुड़े रहे। कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए सप्ताह में दो से तीन बार जौनपुर की यात्रा करते रहे। यही कारण है कि जब राजनीति की भविष्यवाणी करने वाले लोग उन्हें टिकट की रेस से बाहर मान रहे थे, उसी समय केंद्र ने उनकी जमीनी ताकत को समझते हुए तथा उन पर विश्वास करते हुए उन्हें टिकट पकड़ा दिया। कृपाशंकर सिंह ने लंबे समय तक महाराष्ट्र की राजनीति में सफलतापूर्वक काम किया। महाराष्ट्र के साथ-साथ हुए दिल्ली की राजनीति से भी जुड़े रहे। लंबे समय तक उन्होंने महाराष्ट्र और दिल्ली की राजनीति के बीच सेतु का काम किया। दिल्ली के बड़े-बड़े नेता जब मुंबई आते थे, तो कृपाशंकर सिंह ही उनकी सारी व्यवस्था देखते रहे। कृपाशंकर सिंह के साथ-साथ उत्तर भारतीय समाज का कद भी बढ़ता गया। उन्होंने हमेशा खुद को उत्तर भारतीय नेता के रूप में ही प्रस्तुत किया। परिश्रम संस्था के बैनर तले उनके नेतृत्व में वसई, विरार ,नालासोपारा, भायंदर, मीरा रोड में किए गए रोड शो में जिस तरह आम उत्तर भारतीयों की भीड़ दिखाई दी, उससे राजनीति के बड़े-बड़े जानकार भी हक्का-बक्का रह गए। रिक्शा चालक, फेरीवाला, टैक्सी चालक से लेकर सभी पार्टियों के उत्तर भारतीय नेता और कार्यकर्ता उनके रोड शो में शामिल हुए। बढ़ती उम्र के बावजूद कृपाशंकर सिंह आज भी किसी युवा की तरह पूरी तरह से सक्रिय हैं। आज भी वे 24 घंटे के अंदर देश के अलग-अलग दिशाओं में यात्रा कर सकते हैं।कृपाशंकर सिंह में सबसे बड़ा गुण उनकी विनम्रता, शालीनता ,सादगी और सहयोग की प्रवृत्ति है। यही विशेष गुण उनको आम लोगों से जोड़कर रखती है। इसका अंदाजा आप पिछले दिनों घटी एक घटना से लगा सकते हैं। पुणे की एक झोपड़पट्टी में रहने वाला रामधीरज यादव नामक एक रिक्शा चालक स्थानीय गुंडो से परेशान था। गुंडे उस पर घर छोड़ने का दबाव बना रहे थे। मीनाताई हुबलीकर नामक सामाजिक कार्यकर्ता ने उसे कृपाशंकर सिंह का नंबर देकर कहा कि तुम्हारी समस्या का वही समाधान कर सकते हैं। रामधीरज यादव ने कृपाशंकर के मोबाइल पर अपनी समस्या लिखकर व्हाट्सएप मैसेज किया। कृपाशंकर सिंह ने मैसेज पढ़कर तत्काल उस रिक्शा चालक से संपर्क किया। उन्होंने वहां के पुलिस अधीक्षक से बात की। उनके प्रयासों का नतीजा रहा कि आज रामधीरज यादव का परिवार पूरी तरह से सुरक्षित और शांतिपूर्वक रह रहा है। कृपाशंकर सिंह ने कभी जाति और धर्म की राजनीति नहीं की। जनता की सेवा करना उनका सबसे बड़ा धर्म रहा। देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान राहुल एजुकेशन के सचिव राहुल तिवारी के अनुसार कृपाशंकर जी अजातशत्रु है, अपनों पर तकलीफ पड़ने पर वे आधी रात को भी पहुंच जाते हैं। वे किसी को भी अपना दुश्मन नहीं मानते। उन्होंने कहा कि राजनीति में ऐसे लोगों की सख्त आवश्यकता है,जो आम लोगों की पीड़ा और तकलीफ को महसूस करता हो।

-शिवपूजन पांडे

आर्थिक वृद्धि दर ने साबित किया कि मुश्किल हालात में मोदी का नेतृत्व देश के काम आया

वित्तीय वर्ष 2023-24 की तृतीय तिमाही के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर ने भारत सहित विश्व के समस्त आर्थिक विश्लेषकों को चौंका दिया है। इस दौरान, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हासिल हुई है जबकि प्रथम तिमाही के दौरान वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत एवं द्वितीय तिमाही के दौरान 7.6 प्रतिशत की रही थी। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान वृद्धि दर 4.4 प्रतिशत रही थी। साथ ही, क्रेडिट रेटिंग संस्थान इकरा ने इस वर्ष तृतीय तिमाही में 6 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान एवं भारतीय स्टेट बैंक ने भी 6.9 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान जताया था। कुल मिलाकर, लगभग समस्त वित्तीय संस्थानों के अनुमानों को झुठलाते हुए सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर 8.4 प्रतिशत की रही है। हम सभी के लिए हर्ष का विषय तो यह है कि विनिर्माण इकाईयों की वृद्धि दर 4.8 प्रतिशत से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 की तृतीय तिमाही में 11.6 प्रतिशत हो गई है तथा निर्माण के क्षेत्र में वृद्धि दर 9.5 प्रतिशत की रही है। साथ ही, खनन के क्षेत्र में वृद्धि दर 1.4 प्रतिशत से बढ़कर 7.5 प्रतिशत की रही है। यह तीनों ही क्षेत्र रोजगार सृजन के क्षेत्र माने जाते हैं। अतः देश में अब रोजगार के नए अवसर भी निर्मित हो रहे हैं। विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाईयों में वृद्धि दर आकर्षक रही है। कृषि का क्षेत्र जरूर, विपरीत मानसून एवं अल नीनो के प्रभाव के चलते, विपरीत रूप से प्रभावित हुआ है एवं कृषि के क्षेत्र में वृद्धि दर 0.2 प्रतिशत ऋणात्मक रही है। हालांकि वित्तीय वर्ष 2019-20 से लेकर 2022-23 तक कृषि के क्षेत्र में औसत वृद्धि दर 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक की रही है। परंतु, प्रकृति के आगे तो किसी की चलती नहीं है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के तृतीय तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद के विशेष रूप से उद्योग क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर के आंकड़ों को देखकर तो अब यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि भारत आगे आने वाले वर्षों में 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की विकास दर हासिल करने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है एवं अगले लगभग 4 साल के अंदर ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, वर्तमान में भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साथ ही, भारतीय शेयर बाजार भी बाजार पूंजीकरण के मामले में वर्तमान में विश्व में चौथे स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। क्योंकि, भारत में आर्थिक विकास की तीव्र गति को देखते हुए विदेशी निवेशक एवं विदेशी निवेश संस्थान, दोनों ही भारतीय पूंजी बाजार में अपने निवेश को निश्चित ही बढ़ाएंगे। भारत में वित्तीय वर्ष 2023-24 की तृतीय तिमाही में अनुमानों से कहीं अधिक वृद्धि दर हासिल करने के पीछे दरअसल हाल ही के समय में आर्थिक क्षेत्र के साथ साथ सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तन भी मुख्य भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं, इस ओर सामान्यतः विदेशी अर्थशास्त्रियों एवं वित्तीय संस्थानों का ध्यान शायद नहीं जा रहा है। हाल ही के समय में भारत में अब विभिन्न त्यौहार अत्यधिक उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं। इन त्यौहारों के मौसम एवं शादियों के मौसम में भारतीय परिवारों, विशेष रूप से मध्यम वर्गीय एवं उच्च वर्गीय परिवारों के खर्च में अपार वृद्धि हो रही है। इस खर्च का पूरा पैसा भारतीय अर्थव्यवस्था में आ रहा है, जिससे आर्थिक वृद्धि दर में तेजी दिखाई देने लगी है। वर्ष 2023 में दीपावली त्यौहार के दौरान लगभग 4 लाख करोड़ रुपए की राशि भारतीय परिवारों द्वारा खर्च की गई थी। शादियों के दौरान भारतीय परिवारों द्वारा अतिरिक्त खर्च किया जाना भी केवल भारत की ही विशेषता है, अन्य देशों में शादियों के दौरान इस प्रकार के खर्च नहीं होते हैं। दूसरे, भारत में हाल ही के समय में धार्मिक पर्यटन में अपार वृद्धि देखने में आई है, क्योंकि इन क्षेत्रों की आधारभूत संरचना में आमूल चूल सुधार हुआ है। पर्यटन के बढ़ने से न केवल रोजगार के लाखों नए अवसर निर्मित हो रहे हैं बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी अपार बल मिल रहा है।

भाजपा की पहली लिस्ट में फिल्मी कलाकारों के बल बल्ले, भोजपुरी सिनेमा से चार कलाकारों को मौका

अशोक भाटिया

(उत्तरशक्ति)

भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इन उम्मीदवारों में कई नाम ऐसे हैं, जो फिल्म और टेलीविजन के जरिए पहले ही अपना एक खास मुकाम बना चुके हैं। भाजपा की टिकट पर कई अभिनेता और अभिनेत्रियां पहले भी संसद में पहुंचते रहे हैं। एक बार फिर पार्टी ने इनमें से कई पर विश्वास जताया है तो वहीं भोजपुरी और दक्षिण भारत की फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नामों को पहली बार चुनाव मैदान में उतारा है। भाजपा ने मथुरा से हेमा मालिनी पर एक बार फिर विश्वास जताया है। हेमा मालिनी मथुरा से सांसद हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने आरएलडी के कुंवर नरेंद्र सिंह को बड़े अंतर से शिकस्त दी थी। वहीं 2014 में उन्होंने आरएलडी के जयंत चौधरी को तीन लाख से ज?यादा वोटों से हराया था। हेमा मालिनी हिंदी फिल्मों की बड़ी अभिनेत्री और बेहतरीन क्लासिकल डांसर हैं। देखा जाय तो बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी का एक सफल फिल्मी करियर तो रहा ही साथ ही उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में खूब नाम कमाया है। हेमा मालिनी ने साल 2004 में भाजपा ज्वाइन की थी।

अमेठी से सांसद व मंत्री स्मृति ईरानी का नाम घोषित किया है ।वह 2019 में कांग्रेस के युवा नेता राहुल गाँधी को हरा चुकी है। दरअसल स्मृति ईरानी 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में तुलसी का किरदार निभाकर घर-घर में मशहूर हुई स्मृति ईरानी वर्तमान समय में मोदी सरकार में मंत्री हैं। राजनीति में आने के बाद स्मृति ने अभिनय के क्षेत्र से दूरी बना ली है। अभिनय से राजनीति तक पहुंचने का सफर स्मृति के लिए बेहद संघर्ष भरा रहा है। भाजपा ने भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया है। वह पहली बार चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। फिलहाल आसनसोल से फिल्म अभिनेता और तृणमूल कांग्रेस के नेता शत्रुघ्न सिन्हा सांसद हैं। 2019 में यहां से प्लेबैक सिंगर बाबुल सुप्रियो ने भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज की थी। हालांकि बाद में वह भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे, जिसके बाद उपचुनाव में इस सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा ने तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की थी। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो पवन सिंह की अनुमानित नेटवर्थ 6 से 8 मिलियन डॉलर के आस-पास है। भारतीय रुपये में ये 50 से 65 करोड़ रुपये के आस-पास होती है। पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा के बड़े नाम हैं और

उनकी फैन फोलोइंग भी लाखों में है। पवन सिंह की कमाई का मुख्य जरिया फिल्में ही हैं। यही वजह है कि वह एक फिल्म के लिए लाखों रुपये चार्ज करते हैं। पवन सिंह एक फिल्म में काम करने के लिए 40 से 50 लाख रुपये फीस लेते हैं। सालभर में उनकी एक या दो फिल्में आ ही जाती हैं। भोजपुरी सुपरस्टार सिर्फ एक्टिंग में ही दमदार नहीं हैं, बल्कि सिंगिंग में भी उनका कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कई फेमस गाने गाए हैं। पवन सिंह एक गाने के लिए 2 से 3 लाख रुपये चार्ज करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पवन सिंह एक साल में 3 से 5 करोड़ रुपये की कमाई करते हैं।

भोजपुरी एक्टर और गायक पवन सिंह ने 2014 में भाजपा ज्वाइन की थी। उसी समय से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा थी लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। दस साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उन्हें मौका मिला है। वहीं आसनसोल सीट के इतिहास को देखे तो अक्सर इस सीट पर सितारों को उतारा जाता है। इससे पहले 2019 में भाजपा की ओर से बाबुल सुप्रियो ने इस सीट पर कब्जा किया था। उन्होंने टीएमसी की मुनमुन सेन को परास्त किया था। पवन सिंह के साथ ही भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची में कई भोजपुरी स्टार दोबारा शामिल हैं। इनमें मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव निरहुआ शामिल हैं। भाजपा ने दिल्ली भोजपुरी स्टार और उत्तर-पूर्व दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी पर पार्टी ने एक बार फिर विश्वास जताया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मनोज तिवारी ने कांग्रेस उम्मीदवार और दिल?ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को साढे तीन लाख से भी अधिक वोटों से हराया था। निर्वाचन क्षेत्र में पूर्वांचल के मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है और उनके बीच मनोज तिवारी लोकप्रिय चेहरा हैं। वह 2014 में भी इस सीट से सांसद रह चुके हैं। मनोज तिवारी बिहार के अटरवलिया गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई बनारस से की है। भाजपा ने गोरखपुर के मौजूदा सांसद और अभिनेता रवि किशन को एक बार फिर लोकसभा चुनाव का टिकट दिया है। रवि किशन गोरखपुर से सांसद हैं और पार्टी ने इसी सीट से उन पर एक बार फिर विश्वास जताया है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के रामभुआल निषाद को करीब तीन लाख वोटों के बड़े अंतर से हराया था। रवि किशन शुक्ल को रवि किशन के नाम से ही जाना जाता है। वह फिल्म अभिनेता के साथ टेलीविजन में भी काम कर चुके हैं। साल 2006 में वह भी बिग बॉस में भाग ले चुके हैं। इसके साथ ही भाजपा ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से एक और भोजपुरी स्टार को चुनाव मैदान में उतारा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ को आजमगढ़ से अखिलेश यादव ने करीब ढाई लाख वोटों से हराया था। हालांकि उपचुनाव में निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को हराकर इस सीट पर कब्जा जमाया था। एक बार फिर पार्टी ने उन्हें यहां से उम्मीदवार बनाया है। दिनेश लाल यादव गाजीपुर के छोटे से गांव टंडवा से ताल्लुक रखते हैं। दिनेश लाल यादव जिन्हे निरहुआ के नाम से भी जाना जाता है, एक भोजपुरी फिल्म गायक, अभिनेता और टेलीविजन प्रस्तोता हैं। दिनेश लाल यादव भी बिग बॉस शो के कंटेस्टेंट रह चुके हैं। भोजपुरी अभिनेताओं के साथ भाजपा ने केरल की त्रिसूर सीट से फिल्म अभिनेता सुरेश गोपी को उम्मीदवार बनाया है। सुरेश गोपी एक अभिनेता होने के साथ ही पार्श्व गायक भी रह चुके हैं और साउथ इंडस्ट्री का बड़ा नाम हैं। इसके साथ ही भाजपा ने पश्चिम बंगाल की हुबली सीट से लॉकेट चटर्जी को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया है। लॉकेट चटर्जी ने 2019 का लोकसभा चुनाव भी हुबली लोकसभा सीट से लड़ा और जीता था। वह बांग्ला फिल्मों की अभिनेत्री और क्लासिकल डांसर हैं।

अभी भाजपा की दूसरी लिस्ट भी आने वाली है। सूत्रों की माने तो गुरदासपुर से सन्नी देओल की जगह अक्षय कुमार चुनाव लड़ सकते है । वैसे पहले अक्षय कुमार की दिल्ली से चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही थी पर दिल्ली की सातों सीटों पर नाम घोषित हो चुके है। राजनीति सूत्रों की मानें तो इस बार कई सांसदों के टिकट रिपीट होने के चांस नहीं थे लेकिन कई उम्मीदवारों को रिपीट किया गया है। कई राज्यों में जाति जनगणना के आधार पर टिकट दिए गए हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि जिसके बारे में सोचा नहीं था, उसे इस बार टिकट मिला है।

गोबर की आत्मकथा : गोबर दोबारा मानव जाति का अन्नदाता और प्राणदाता बन सकेगा?

-आत्माराम यादव

मैं गोबर हूँ, आज अपनी आत्मकथा सुनाना चाहता हूँ। मुझ गोबर के पिता का नाम जठरानलानन्द है और श्रीमती सुरभी अर्थात गाय मेरी माता हैं। मेरे जन्मस्थान का नाम लेने से दिन-भर अन्न-जल के दर्शन न होंगे, इसलिए नहीं बताऊँगा। हाँ, मैं इस बात से पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि मेरे जन्म स्थान का पता आप सभी जानते है। मैं अपना परिचय देने से पहले गाय का परिचय देना चाहूंगा जिससे मैं पैदा होता हूँ। हिन्दू-शास्त्रों में महादेव जी को वृष और भगवती को गौ-रूप से वर्णन किया गया हैं :-ह्ज्ञानशक्तिः क्रिया-धेनु देंवीरूपा प्रकीर्तिता ह्र ह्रनीलग्रोवो महादेवः शरण्यो गोपति चिंराट्।ह्र ह्रशास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्माजी गाय का शरीर बनाने लगे तब उन्होंने सब देवताओं को गाय के शरीर में निवास करने हेतु आमंत्रित किया।सभी देवता खुशी-खुशी आए और सबको गाय के शरीर में अपनी अपनी जगह मिल गयी। इस तरह गाय के रोएँ-रोएँ में देवताओं का निवास हो गया। परन्तु इस दौड़ में लक्ष्मी जी एवं गंगाजी पिछड़ गयी और लेट पहुँची वे अपना श्रृंगार करने के कारण विलम्ब से आयी तब तक गाय का शरीर बन चुका था। अब क्या होगा, दोनों बोली, हम गाय के शरीर में जरूर रहेंगी, हमें स्थान मिलना ही चाहिए। तब ब्रह्माजी ने लक्ष्मीजी को गाय के गोबर में अर्थात मुझमें स्थान दिया और गंगाजी को गोमूत्र में स्थान मिला।

मुझ गोबर की सृष्टि से आप सभी भली भांति परिचित ही है फिर भी आप सभी अपने-अपने ज्ञान-विवेक से मुझ गोबर को गाय का मल कहकर हीन भावना से भर जाते है पर आपके पूर्वजों से मुझे बहुत सम्मान मिला है वे जानते थे कि मैं अस्पृश्यों की योनिम में जन्म लेकर भी गंगाजल की तरह पूज्य और पवित्र हूँ इसलिए वे किसी भी मांगलिक कार्य करने से पहले यज्ञ-मण्डप में सबसे पहले मेरा प्रवेश कराकर मुझसे आच्छादित कराकर पूजा पाठ की शुरूआत करते थे। हिन्दू घराने की बात हो या किसी भी ऋषि-मुनि आश्रम की, सभी जगह मेरी उपस्थिति अनिवार्य एवं आवश्यक रही है, वेद पुराणों-शास्त्रों में या किसी भी शुभ अवसर, शादी विवाह में गोरी-गणेश के रूप में मैं ही तो पूजनीय रहा हूँ। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि: यावद् गो-ब्राह्मणाः सन्ति तावत पृथ्वी च सुस्थिरा, तस्मात पृथ्वी-रक्षणार्थ पूजयेत द्विज-गो-सतीः ह्र अर्थात- ह्रजबतक गौ और ब्राह्मण अवस्थित हैं, तब तक ही पृथ्वी थिर भाव से अवस्थित रह सकती है। इसलिये पृथ्वी के रक्षणार्थ द्विज, गौ और सती स्त्री पूज्य है। यानी जब तक धरा है, गाय है मुझ गोबर में लक्ष्मी का वास होने के कारण मैं सदैव पूजनीय रहने वाला हूँ।

गोबर गनेश की पूजा मुझे वैसे ही नहीं मिली जब मुझ गोबर में लक्ष्मी का वास हुआ तब से मैं इस धरा पर उत्पन्न होने वाली सभी प्रकार की औषधियों का सार बन गया हूँ एवं मेरा रस पाकर वनस्पतियों लहराने लगती है, सच मायने में मानव जाति को अन्न एवं औषधियों का प्रदाता मैं गोबर ही हूँ जो उनका प्राणदाता भी हूँ किन्तु जिन्होंने मुझे सम्मान दिया वे लोग आज नहीं है, उनकी पीढ़ी के ये लोग मुझ गोबर को विस्मरण कर हेय समझकर अपने प्रारब्ध पर ताला लगा चुके है, पर मैं आज भी उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि वे अगर मझ गोबर को पूर्ववत अपना ले तो मैं इनके भाग्योदय को चरमा पर पहुँचा सकता हूँ। यही नहीं जो लोग मुझे दुर्गन्धयुक्त समझते है उन्हें बता दूँ कि पतंजलि संस्थान चलाने वाले दुर्गन्धों को दूर करने के लिए मुझ गोबर का प्रयोग कर साबुन,क्रीम, आदि बनाकर आप सभी की मलिनता एवं चर्म रोगों का नाश कर रहे है। वे जानते है कि संसार के सभी भयंकर कीटाणुओं को, मनुष्यों की महामारी को चुटकी में समाप्त करने के लिए मेरा किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, वे प्रयोग कर अपनी विलासिता के किले तैयार कर रहे है। धर्मशास्त्र और आयुर्वेद मुझ गोबर की महिमा से भरे है। महात्मा गांधी ने मेरी महिमा का वर्णन इस प्रकार किया कि- ह्रगोबर का उपयोग अधिकतर उपल्लो (कण्डों) के लिए किया जाता है। इसमें जरा भी शक नहीं कि गोबर का यह दुरुपयोग नहीं, तो कम-से-कम उपयोग अवश्य है। यह तो ताँत के लिए भैंस मारने के समान है। अगर एक उपले की कीमत एक पाई होती, तो गोबर का पूरा उपयोग करने से एक उपले के बराबर गोबर की कीमत कम-से-कम दस- गुनी अधिक होती है। आज अगर हम इससे होनेवाली अप्रत्यक्ष हानि का ही अन्दाज लगाव तो वह इतनी अधिक होगी कि उसकी कीमत आँकना ही मुश्किल होगा। गोबर का पूरा-पूरा सदुपयोग तो उसकी खाद बनाने में ही है। कृषिशास्त्र के जानकारों का मत है कि गोबर के जला डालने से ही हमारे खेतों की ताकत घटी है। बिना खाद के खेत और बिना घी के लड्डू में कोई फर्क नहीं होता, दोनों शुष्क होते हैं। गोबर की खाद के मुकाबले रासायनिक खाद कहीं घटिया होती है। मुझ गोबर का विवाह पृथ्वी की पुत्री उर्वरा से हुआ है, जब तक मेरी पत्नी के साथ मुझे लोक खुलकर न मिलने देंगे तब तक मेरे श्राप से दरिद्रता में ही रहेंगे। धरती समझती है और जानती है कि मै। रसीला, हूँ और रससे भरा होने पर अपना रस केवल धरा की उर्वरा को ही समर्पित कर सकता हूँ । मुझ गोबर का प्रयोग कर आप मेरी एक बून्द रस के लिए तरस जाओंगे और मैं तुम्हारे कितने भी प्रयास से बून्द नहीं टपकाऊँगा। हॉ आप मुझ ताजे गरमागरम गोबर के शरीर पर बारीक कपड़ा रखकर मुझे निचोड सकते हो। पहले के आयुवेर्दाचार्य मेरे रस से रतोंधी की दवा बनाकर दृष्टिमान्य गोमय तैल बनाने में मेरा उपयोग करते थे और चर्म रोग का मरिचादितैल बिना मुझ गोबर के रस से नहीं बनता था। यही नहीं मुझ गोबर से अशुद्ध रहने पर शरीर में होने वाले खाज खुजलियॉ , भगन्दर, बबासीर आदि की औषधि भी मुझसे बनाकर मेरे सारे गुणों का इस्तेमाल कर कई वैध मुझ गोबर की बदौलत ही नाम और शौहरत पा चुके है। मुझ गोबर पर आयुर्वेद में, अर्थववेद आदि अनेक स्थानों पर बहुत कुछ लिखा गया है जिसमें मेरे गुणों को पढ़कर आप आश्चर्यचकित रह जाएगे,और अगर आप मुझ गोबर पर शोधपूर्वक प्रायोगिक उपचार की शुरूआत कर दें तों देश के अधिकांश अस्पताल मरीजों को तरस जाएगें।

मैं आपको अपनी आत्मकथा में वे सारे तथ्य नहीं रख सकता जिसे आप जानते नहीं। हो इतना अवश्य है कि जैसा कि मैंने कहा मेरी पत्नी पृथ्वी की पुत्री उर्वरा है, तो मैं उर्वरा की उचित देखभाल कर सकता हूँ। उर्वरा हर खेत की मिट्टी में है, मैं चाहता हूँ कि हर खेत की मिट्टी में मुझ गोबर का प्रयोग कर मेरे प्रभाव का और मेरे औषधीय रसों का रसास्वादन कराया जाए। जिस प्रकार मिट्टी पर मेरा प्रभाव है उसी प्रकार धातुओं पर भी मेरा प्रभाव है जिसमें स्वर्ण पर्पटी संग्रहणी रोग की सर्वोत्तम औषधि है वह मेरी ही बेदी पर बनाई जाती है इसके अलावा पंचामृत पर्पटी भी बिना मुझ गोबर के नहीं करती है। जब मैं शुष्क हो जाता हूँ तब भी मेरा उपयोग कम नहीं होता और लोकपचार में लगा मुझ सूखे गोबर को लोग कंडे या उपले नाम लेकर स्वयं के लिए स्वादिष्ट दाल-बाटी बनाने के काम में लेते है।

मुझ गोबर से बने कण्डों का बड़ा महत्व है। कण्डों का प्रयोग हर पूजापाठ में, हवनवेदी में, हवनकुण्ड में आहूति देने के लिए किया जाता है। देश के अधिकांश गॉवो-शहरों में आज भी मुझसे बने कण्डों-उपलों के बिना चूल्हा ठण्डा पड़ा रहता है। धातुओं को गर्म कर उपयोगी बनाए जाने के लिए कण्डे ही काम आते है बिजली की आग अथवा अन्य रासायनिक मेरे सामने चित्त पड़े रहते है। मुझ कण्डों का प्रयोग सदियों से आज भी बुजुर्ग लोग थकान होने पर अपने तलुओं में रगड़वाकर थकानमुक्त होते है। जब प्राणान्त हो जाता है तब मुझ कण्डों को मृतक के परिजन अपने घर पर हांडी में सुलगाकर मृतक के सिरहाने रखकर श्मशान घाट तक की यात्रा के पश्चात मृतक देह के साथ जलाया जाता है। मुझ गोबर तक को अपने गुणगान को सुनाने में झिझक आने लगी, कहीं तुम इंसान ये न समझ बैठे की मैं भी यश प्राप्ति की पंक्ति में हूँ, नहीं ऐसा नहीं मेरी उपयोगिता को आप सभी जानते समझते है, और समय पर मुझ गोबर का उपयोग करने से नहीं चूकते हो। अंत में मैं गोबर स्वयं अपनी बात समाप्त करने से पहले हर भारतवासी को मुझ गोबर गणेश की शपथ देना चाहूंगा कि कि आप सभी मेरी जननी माँ सुरभि गाय की महादशा से परिचित हो, किस प्रकार आप अपनी खुली आंखों से गोवंश को कत्लखाने में मिटते देख रहे है, यदि गोमाता की रक्षा नहीं की गयी तब सोचिए आप अपने घर के मांगलिक कार्यो, पूजा अनुष्ठानों में गाय का गोबर न मिलने पर क्या करेंगे ? जरूरत जागने की है, जागिए गोमाता की रक्षा और गोधन के सदुपयोग के लिए खड़े हो जाईए और भारत को पुनः गोधन से समृद्ध कर अपनी पूजनीया गोमाता से प्राप्त होने वाले मुझ गोबर को अपनी पत्नी पृथ्वीपुत्री उर्वराभूमि से मिलन कराईए ताकि मैं मानवजाति के सच्चे अन्नदाता और प्राणदाता होने के अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहनकर कर देश में स्वास्थ्य, संपदा से परिपूर्ण कर सकूँ। (उत्तरशक्ति)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

जीवन में आशाओं के अनंत आकाश

संजीव ठाकुर

जिंदगी का कैनवास जन्म से लेकर क1 तक समुद्र की तरह विराट और गहराई लिए हुए होता है। जीवन में वयक्तिक, पारिवारिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक विकास की संभावनाओं के साथ मनुष्य अपना जीवन प्रारंभ कर विकास प्रगति तथा ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है,बशर्ते उसके व्यक्तित्व में जीवन के प्रति जीजिविषा, संघर्ष करने की क्षमता, अनंत आत्म विश्वास और संयम के घटक मौजूद हो। ऐतिहासिक तौर पर भारतीय विकास सांस्कृतिक संरचना एवं संस्कार के मूलभूत तत्वों को लेकर दुनिया में अभूतपूर्व रहा है। वैसे भी भारतवर्ष सभ्यता से लेकर संस्कृति की प्रकृति के मामले में वैभवशाली इतिहास को समेटे हुए हैं। विकास और प्रगति के सोपान को कोई एक दिन वर्ष अथवा दशक में रेखांकित नहीं किया जा सकता, यह एक निरंतर, सतत एवं समय के साथ चलने वाली क्रिया की प्रतिक्रिया है। और प्रकृति सभ्यता तथा मानव जीवन में परिवर्तन एक अकाट्य सत्य और शाश्वत अभिक्रिया है। व्यक्ति के जीवन तथा समाज या देश में विकास के संदर्भ में एवं घटकों को प्रारंभ से आदमी का धन उपार्जन, गरीबी भुखमरी से लड़ाई भूतकाल की कुरीतियों की विडंबना से संघर्ष का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन सब से समाज की प्रगति और विकास में राजाओं, सम्राटों की कूटनीति ,राजनीति सर्वोपरि रही है इतिहास से लेकर अब तक मनुष्य देश और विश्व के विकास में राजनैतिक नीति निर्देशक तत्व ही देश को बलवान,शक्तिहीन,भौगोलिक रूप से बड़ा या छोटा बनाते आए हैं। किसी भी राष्ट्र के राजा, सम्राट या राष्ट्र प्रमुख की अपनी क्षमता ,शक्ति, ऊर्जा और उसके विवेक से उस राष्ट्र की प्रगति विशाल या न्यूनतम होती देखी गई है। भूतकाल में कई संघर्षशील एवं उत्साह से लबरेज यात्रियों के वृतांत हमारी नजरों में आए हैं यथा कोलंबस और वास्कोडिगामा जैसे अत्यंत ऊजार्वान संघर्षशील और साहसिक यात्रियों द्वारा लगभग नामुमकिन रास्तों की खोज कर एक मिसाल कायम की है। नेपोलियन का एक बड़ा सूत्र वाक्य था कुछ भी असंभव नहीं है।

> **अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से भी किसी भी राष्ट्र में सदैव विकास वैभव और आर्थिक तंत्र को मजबूत करने की संभावनाएं अवस्थित रहती हैं। भारत की विशाल जनसंख्या को देखते हुए भारत में गरीबी, भुखमरी ,बाढ़ तथा अन्य विभीषिका सदैव आती जाती रहती हैं। विशाल जनसंख्या के होने के कारण भारत में ही भारत की बड़ी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है और केवल भारत के कुछ नागरिकों को ही सारी जीवन की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं,**

बिस्मार्क जर्मनी के एक ऐसे सम्राट रहे हैं जिनके बारे में कहा जाता है की उनके हाथों में दो गेंद तथा 3 गेंदें हवा में होती थी, यूरोप का जादूगर भी कहलाता था, पूर्व से ही समुद्रगुप्त ,कनिष्क, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, शेरशाह सूरी जैसे शासकों का अदम्य आत्मविश्वास एवं संघर्ष करने की क्षमता के फल स्वरुप भी भारत आज इस स्वरूप में विद्यमान है। अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से भी किसी भी राष्ट्र में सदैव विकास वैभव और आर्थिक तंत्र को मजबूत करने की संभावनाएं अवस्थित रहती हैं। भारत की विशाल जनसंख्या को देखते हुए भारत में गरीबी, भुखमरी ,बाढ़ तथा अन्य विभीषिका सदैव आती जाती रहती हैं। विशाल जनसंख्या के होने के कारण भारत में ही भारत की बड़ी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है और केवल भारत के कुछ नागरिकों को ही सारी जीवन की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, बाकी लोग इन सुविधाओं से वंचित भी हैं। हमारा देश स्वतंत्रता के बाद से ही आवाज की कमी भूख गरीबी भ्रष्टाचार काला धन हवाला कुपोषण बेरोजगारी की बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है। भारत की विशाल जनसंख्या के बावजूद ऐतिहासिक तौर पर देश सांस्कृतिक वैचारिक और संस्कारी ग्रुप से सदैव समृद्ध रहा है और धार्मिक रूप से भी देश में ज्ञान की जड़े बहुत गहराई तक हैं। भारत को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करने के लिए वेद, पुराण, उपनिषद, गीता ,रामायण ,महाभारत महा ग्रंथों की पृष्ठभूमि बड़ी ही शक्तिशाली है। देश में अनेक साधु संत ज्ञानी जिनमें मोहम्मद मूसा कबीर, रैदास, नामदेव, तुकाराम चैतन्य, तुलसीदास शंकरदेव जैसे महापुरुषों ने देश के सांस्कृतिक आध्यात्मिक विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया है। भारत में अनेक विदेशी आक्रमणों को झेल कर उन्हें आत्मसात किया है किंतु हमारी संस्कृत पाली एवं प्राकृत भाषा अन्य भाषाओं के साथ आज भी समृद्ध है। भारत में अनेक भाषा क्षेत्र एवं बोलियां हैं किंतु हिंदी, पंजाबी, गुजराती, बांग्ला, मराठी ,असमिया भाषाएं उसी तरह पल्लवित पुष्पित हो रही हैं जैसे की संस्कृत और प्राकृत पाली भाषा होती रही है। भारत में स्वाधीनता के बाद विकास के प्रगति के पथ पर वैज्ञानिक क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया और पृथ्वी से लेकर नभ तक हर क्षेत्र में मानव की अतीव उत्कंठा ,जीजिविषा के कारण हमने चांद पर भी अपने वायुयान भेजें हैं। देश के नागरिकों की भौतिकवादी सुविधा के लिए भी हमने वतानुकुलित यंत्र ,वायुयान तेज चलने वाली ट्रेनें और वायुमंडल में अनेक ऐसे तथ्यों को जो आज तक छुपे हुए थे उजागर कर अपने महत्व के लिए इसका उपयोग करना शुरू किया है। यह कहावत आशाओं पर आकाश टिका हुआ है और आकाश का कोई अंत नहीं यानी मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है मनुष्य पर सही प्रतीत होती है।इसी तरह प्रगति और विकास का भी कोई अंत या अनंत नहीं है। भारत देश में वैश्विक स्तर पर राजनैतिक सामाजिक वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक स्तर पर काफी प्रगति की एवं विश्व में योग अध्यात्म दर्शन का लोहा भी मनवाया है। मनुष्य की अभिलाषा का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है, मनुष्य मूल रूप से अत्यंत महत्वकांक्षी,लोलुप एवं इच्छाओं का दास हुआ करता है, ऐसे में पूर्व में किए गए कार्यों को निरंतर सुधार कर उसे नए रूप में प्राप्त करना मनुष्य की अभिलाषा हो सकती है,पर इसके लिए अथक मेहनत संघर्ष आत्मविश्वास एवं संयम की आवश्यकता होगी तभी जाकर हम अपने नए-नए लक्ष्यों को विकास तथा प्रगति के पैमाने पर टटोलकर आगे बढ़ा सकते हैं। पर लक्ष्य की प्राप्ति के साधन जरूर सच्चे ,पवित्र और मानव कल्याण की ओर अग्रेषित होने चाहिए, तब ही विकास प्रगति चाहे वह आध्यात्मिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक अथवा वैज्ञानिक ही क्यों ना हो सफल हो सकती है। (उत्तरशक्ति)

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 15

डब्ल्यूटीओ में मामूली प्रगति

विश्व व्यापार संगठन की 13वीं मंत्रिस्तरीय बैठक या एमसी13 जैसा कि आमतौर पर इसे जाना जाता है- अबूधाबी शहर में मामूली आम सहमति के साथ संपन्न हुई।

डिजिटल व्यापार पर शुल्क लगाने की देशों पर लगी रोक दो साल के लिए बढ़ाने पर अंतिम समय में हुए समझौते को ही प्रतिनिधि एक छोटी-सी जीत बता सकते हैं। लेकिन सच तो यह है कि यही एकमात्र अच्छी खबर है। शनिवार तड़के तक चली बैठक के बाद जारी घोषणापत्र में यह संकेत दिया गया कि सदस्य देश डब्ल्यूटीओ के कामकाज के लिए आवश्यक सुधारों पर काम करना जारी रखेंगे। यह भारत की सबसे बुनियादी मांगों में से एक है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बिल्कुल सही तरीके से यह बात रखी कि जब तक डब्ल्यूटीओ के बुनियादी कार्यों में सुधार नहीं किया जाता-जैसे कि विवाद समाधान प्रणाली- डब्ल्यूटीओ के दायरे का विस्तार करने के प्रयासों की गुंजाइश बहुत कम है।

केंद्रीय तंत्र जिसके द्वारा डब्ल्यूटीओ आगे बढ़ सकता है वह यह है कि अमेरिकी प्रशासन-किसी भी पक्ष का-राष्ट्रों के बीच व्यापार विवादों पर फैसला करने वाले अपील निकाय में नए न्यायाधीशों के नामांकन पर अपनी अभूतपूर्व आपत्ति छोड़ दे। इस निकाय में 2024 तक सुधार करने का लक्ष्य था, लेकिन इस समयसीमा का पालन नहीं हो पाया। इस गतिरोध के जारी रहने की बड़ी जिम्मेदारी वॉशिंगटन में जो बाइडन प्रशासन की ही है।

यहां तक कि बुनियादी जुड़ाव की भी कमी सबसे अधिक तब दिखाई दी जब अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने शुक्रवार को मंत्रिस्तरीय वार्ता छोड़कर जाने का फैसला किया, जबकि अन्य लोग समझौता करने की कोशिश करने के लिए रुके रहे। भारत के लिए सरकार की मुख्य प्राथमिकता यही थी कि भारत की अनाज खरीद प्रणाली का बचाव किया जाए, जिसे कि फिलहाल वह घरेलू स्तर पर सुधारने की कोशिश कर रही है। इसने पश्चिमी देशों को उतना परेशान नहीं किया जितना कि कुछ साथी विकासशील देशों को।

ब्राजील ने भारत के खिलाफ आरोप का नेतृत्व किया, जबकि थाईलैंड के प्रतिनिधि ने अनाज भंडारण पर हमला करते हुए इसे वैश्विक खाद्य कीमतों को प्रभावित करने वाला बताया। भारत के विरोध के बाद थाईलैंड को डब्ल्यूटीओ में अपने राजदूत को वापस बुलाना पड़ा।अनाज खरीद को महत्त्व देने के पुराने तरीके पर भारत की कुछ मांगें वस्तुनिष्ठ तरीके की हैं और उनमें सुधार की जरूरत है। इसी तरह मत्स्यपालन के मामले में, जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ने पर रोक लगाना भारत के हित में है, खासकर चीन जनवादी गणतंत्र के विशाल बेड़ों द्वारा।

ऐसा करने के लिए, भारत के समान छोटे पैमाने के मछली पकड़ने के लिए बेड़े रखने वाले विकासशील देशों के साथ एक गठजोड़ करना चाहिए, और पश्चिमी देशों द्वारा सब्सिडी पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास का जवाबी प्रस्ताव पेश करना चाहिए।इसे आसानी से किया जा सकता था क्योंकि पिछले साल आयोजित एमसी12 मत्स्यपालन पर एक समझौते तक पहुंचने में विफल रहा था।

इस तरह के दृष्टिकोण का खतरा दोहरा है। सबसे पहले, इसका मतलब यह है कि चीन के व्यवहार को अनुशासित करने के लिए डब्ल्यूटीओ का उपयोग करने की क्षमता का भारत लाभ नहीं उठा पा रहा। और दूसरा, यह भारत के महत्त्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों सहित अन्य देशों के लिए बहुल समूह (प्लूरीलैटरल ग्रुप) बनाने के लिए प्रोत्साहन बढ़ाता है जिससे वे बहुपक्षीय समझौते (मल्टीलैटरल एग्रीमेंट) की आवश्यकता से बचते हैं। ये बहुल समूह भारत को शामिल किए बिना भविष्य के व्यापार नियमों को प्रभावी ढंग से निर्धारित करेंगे।

इस प्रकार, मत्स्यपालन से लेकर कृषि तक के महत्त्व के मुद्दों को उठाने की भारत की इच्छा की सराहना की जा सकती है, लेकिन बहुपक्षीय प्रणाली में बहुत लंबे समय तक गतिरोध बने रहने देना भारतीय व्यापारियों और उत्पादकों के लिए खतरनाक है।

विकासशील देशों के नेता के रूप में भारत को दक्षिण अफ्रीका और छोटे द्वीपीय देशों सहित समान विचारधारा वाले देशों का गठबंधन बनाने की पहल करनी चाहिए, जो पश्चिमी प्रस्तावों के लिए समझदार और दूरदर्शी विकल्प पेश कर सकें।

दल बदलने के लिए क्यों उतारू हैं राजनेता

अगर भारतीय राजनीति किसी भी स्पष्ट विचार या 'निस्संदेह' जैसे उत्तर को चुनौती न देती तो यह उतनी दिलचस्प नहीं होती

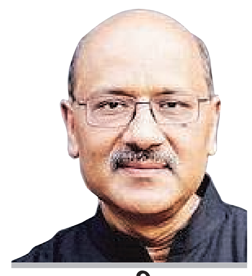

राष्ट्र की बात
शेखर गुप्ता

हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में राज्य सभा चुनावों में हुई क्रॉस-वोटिंग और दलबदल के घटनाक्रम ने कई महत्त्वपूर्ण सियासी सवाल खड़े कर दिए हैं। जैसे कि नेताओं को पार्टी के प्रति वफादार रहने या उसे छोड़ने का मुख्य प्रेरणास्रोत क्या है? किन वजहों से कुछ दल एक साथ रहते हैं जबकि कुछ विभाजित हो जाते हैं? पार्टियों को एकजुट रखने का मूल आधार क्या है और किन वजहों से यह आधार कमजोर हो जाता है?

पहली वजह, निश्चित रूप से सत्ता और पूंजी की ताकत है जो लोगों को पार्टी में रहने या छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। ये वजहें इन दलों को एक साथ बनाए रखने वाले गोंद या दूर करने वाले चुंबक की तरह ही होनी चाहिए। लेकिन यह सच नहीं है। अगर ऐसा होता, तब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 1984 में कांग्रेस की 414 सीट की तुलना में सिर्फ दो सीट पर सिमट जाने के बाद भी सबसे अधिक एकजुटता बनाए रखने वाली राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनी रहती?

भाजपा, वर्ष 1980 में मूल भारतीय जनसंघ (बीजेएस) के नए अवतार के रूप में उभरी थी। लेकिन भारतीय जनसंघ राजनीतिक वनवास के दौर में भी दशकों तक अपना अस्तित्व मजबूती से बनाए रखने में कामयाब रही थी। वर्ष 1947 और 1989 के बीच न तो इस पार्टी और न ही इसके उत्तराधिकारी दल को केंद्र की सत्ता का स्वाद चखने को मिला। हालांकि जनता पार्टी के घटक के रूप में वर्ष 1977-79 के 28 महीने के दौरान इसे जरूर सत्ता से जुड़ने का मौका मिला था।

जनसंघ ने खुद को जनता पार्टी में मिला लिया और इसके सभी सदस्यों ने भी कर्तव्यपरायणता दिखाते हुए बिना किसी विरोध के अपनी सहमति व्यक्त की। इसका स्पष्ट तर्क यह हो सकता है, 'बेशक, उन्होंने सत्ता के लिए ऐसा किया।' लेकिन इस तर्क में भी खामियां हैं। ऐसा इसलिए कि सत्ता जाने के बाद, जनसंघ के सभी लोग भाजपा के रूप में फिर से संगठित हो गए। कोई भी कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ या अपना खुद का कोई दल नहीं बनाया। इससे यह निष्कर्ष निकालने में सहूलियत मिल सकती है कि विचारधारा के चलते दल एकजुट हो सकते हैं। मैं यहां कुछ और तर्क की चुनौती देने के लिए तैयार हूं।

क्या लोग भाजपा/जनसंघ को नहीं छोड़ते रहे हैं? बिल्कुल, बलराज मधोक और कुछ अन्य लोगों ने 1970 के दशक की शुरुआत में पार्टी में एक शख्सियत के बढ़ते प्रभाव को लेकर विरोध किया था और पार्टी छोड़ दी थी। लेकिन वे दल बदल कर कांग्रेस में नहीं गए, चाहे इंदिरा गांधी उन्हें कितना भी लुभाने की कोशिश करतीं। समसामयिक स्तर पर देखा जाए तो शंकरसिंह वाघेला, कल्याण सिंह, उमा भारती और बीएस येदियुरप्पा ने पार्टी छोड़ दी और अपने छोटे राजनीतिक दल बना लिए। केवल वाघेला ने मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया और यह बात वर्ष 1996 की है। वह उस वक्त से पार्टी छोड़ चुके हैं और अब नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं। बाकी तीनों नेताओं की भाजपा में घर वापसी हो चुकी है। भाजपा अकेली ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिसकी कोई राजनीतिक उप शाखा नहीं है।

भारतीय राजनीति उतनी दिलचस्प नहीं होती अगर वह किसी भी स्पष्ट लगने वाले विचार या 'निस्संदेह' से शुरू होने वाले उत्तर का खंडन नहीं करती। लेकिन एक सवाल यह भी है कि अगर विचारधारा दलों को एक साथ रखती है, तब समाजवादी पार्टी में सबसे अधिक विभाजन क्यों देखा गया और प्रारंभिक दौर में व्यक्तिगत संस्थापकों के अधीन अलग सियासी दल बनाने के रास्ते क्यों अपनाए गए?

समाजवादियों के पास एक विचारधारा भी थी और इसके भीतर एक और भी स्पष्ट रूप से परिभाषित विचारधारा थी, लोहियावाद। अब उन धड़ों को गिनें जिनमें लोहियावादी विभाजित हो गए हैं और उन्होंने अलग-अलग रास्ते चुने। इनमें नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, मुलायम/अखिलेश, लालू/तेजस्वी शामिल हैं। यह गिनती जारी रखी जा सकती है।

हमारे पास एक और विकल्प है जो बहुत स्पष्ट लगता है। भाजपा का मुख्य नेतृत्व कभी संसाधन विहीन नहीं था बल्कि इनमें से ज्यादातर का तालुल्क संपन्न परिवारों से था। इन्हें संघ की तरफ से प्रशिक्षण मिला था और इसलिए वे पूरी गहराई से उस विचारधारा से जुड़े थे।

जो चीज राजनीतिक दलों को एक साथ जोड़े रखती है वह है आर्थिक रूप से आरामदायक व्यक्तिगत जीवन और वैचारिक प्रतिबद्धता का होना। इसके साथ ही, सत्ता का स्वाद भी जो भाजपा को 1989 से ही मिला है। लेकिन भारत के वामपंथियों के बारे में क्या कहा जा सकता है?

ऐसी मिसाल शायद ही मिले जब वामपंथी दलों के सदस्य ने दल बदला हो। अगर विचारधारा की बात छोड़ दे तों उनकी वफादारी कैसे बनी रहती है, खासतौर पर इस तथ्य पर विचार करते हुए कि उन्हें शायद ही कभी सत्ता मिलती है और उनके पास निजी तौर पर खूब संपत्ति भी नहीं है? इस संदर्भ में 'स्पष्ट रूप से और निस्संदेह' वाला उत्तर भी नहीं कारगर होगा। इसकी वजह यह है कि वामपंथी दल नहीं बदलते बल्कि वे विभाजित हो जाते हैं। लेकिन वे सत्ता या पैसे के लिए ऐसा नहीं करते हैं। वे वैचारिक शुद्धता की तलाश में विभाजित होते हैं और उनका गहन तर्क इस बात पर होता है कि किसका अनुसरण करना है: लेनिन, माओ, त्रोत्सकी, रूस या फिर चीन?

सवाल फिर भी है कि क्या कोई ताकतवर शख्सियत या कोई राजनीतिक वंशवादी परंपरा ही राजनीतिक दलों को एकजुट रख सकती है और नई प्रतिभा को अपनी ओर आकर्षित भी कर सकती है। आप नरेंद्र मोदी की भाजपा, स्तालिन की द्रमुक (जिसकी एक खास विचारधारा है, हालांकि यह एक राज्य तक ही सीमित है) और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को बाहरी स्तर पर देखें क्योंकि इन्हें भी कुछ लोगों ने छोड़ा है। लेकिन अन्य सभी व्यक्तित्व/वंशवादी परंपरा वाले राजनीतिक दलों पर भी गौर करें तब आपको मालूम पड़ेगा कि मायावती की बसपा, शिवसेना, शरद पवार की राकांपा या बादल परिवार के शिरोमणि अकाली दल को छोड़कर जाने वाले लोग भी मिलेंगे। हम आज के संदर्भ के लिहाज से सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर वापस आते हैं जो कांग्रेस की अपने संगठन को एकजुट रखने में विफलता से जुड़ी है। पार्टी यह दावा करती है कि इसकी एक विचारधारा हैं और शीर्ष स्तर पर एक नेता/वंशवादी परंपरा भी है। जब हिमंत विश्व शर्मा से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता इस पार्टी छोड़ देते हैं तब उन्हें पार्टी की विचारधारा के प्रति सच्चा न रहने के लिए खारिज कर दिया जाता है। पार्टी में देने के लिए शक्ति और संरक्षण का दायरा भी है लेकिन यह कम हो रहा है। शीर्ष स्तर पर एक मजबूत शख्सियत/वंशवादी नेतृत्व होने के चलते यह शत-प्रतिशत उपयुक्त भी लगता है। हालांकि पार्टी से प्रतिभाशाली लोगों का पलायन हो रहा है। हालात यहां तक बिगड़े कि इसके एक मुख्यमंत्री (पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश) को पूरे विधायक दल के साथ भाजपा में शामिल होते देखा गया है।

इसकी वैचारिक प्रतिबद्धता विश्वसनीय नहीं है और यह इस बात से स्पष्ट है कि इसके कई प्रमुख नेता आसानी से भाजपा से जुड़ जाते हैं। क्या इसके लिए पैसा, सत्ता और 'एजेंसियों से सुरक्षा' के साथ-साथ मोदी-शाह भाजपा के अनूठे 'आकर्षण' को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है?

हालांकि 1969 के बाद से ही पार्टी हर कुछ वर्षों में विभाजित हो रही है। आखिरी बड़ा विभाजन तब हुआ जब जनवरी 1978 में पार्टी के वरिष्ठतम नेता सत्ता से कुछ महीने बाहर रहने का दुख नहीं सह सके। इनमें शामिल थे 'इंदिरा इज इंडिया' वाले डी के बरुआ, वसंतदादा पाटिल, वाई बी चव्हाण और स्वर्ण सिंह। बाद में, पार्टी के हमेशा वफादार रहे ए के एंटनी कांग्रेस (अर्स) में शामिल हुए और फिर अपनी खुद की पार्टी कांग्रेस (ए) बना ली। चौधरी चरण सिंह, शरद पवार, वाईएस जगनमोहन रेड्डी, ममता बनर्जी और हिमंत विश्व शर्मा सभी ने मुख्य पार्टी के कमजोर होने के साथ ही अपनी खुद की राजनीतिक ताकत बनाने की कोशिश की।

इसका निष्कर्ष क्या है? पहली बात यह है कि विचारधारा एक मजबूत बंधन हो सकती है, लेकिन इसके लिए यह स्पष्ट और धारदार विचारधारा होनी चाहिए और इसे कम उम्र से ही लोगों के दिमाग में बिठाया जाना चाहिए, जैसा कि भाजपा/संघ, वामपंथियों और द्रविड़ दलों ने किया है। एक मजबूत व्यक्तित्व या वंशवादी परंपरा पार्टी को एकजुट रख सकती है, लेकिन ऐसा तभी संभव है जब वे अपने समर्थकों को वोट दिलवाने की गारंटी दे सकें। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन और बंगाल में ममता की ताकत यही है। पैसे और सत्ता का लोभ भी पार्टी में शामिल होने वालों की संख्या बढ़ा सकता है, जैसा कि आज भाजपा ने दिखाया है।

कांग्रेस इन सभी परीक्षाओं में विफल हो गई। इसकी विचारधारा अस्पष्ट है। यह खुद को जेएनयू-वामपंथी विचारधारा की तर्ज पर धर्मनिरपेक्ष होने की बात करती है, लेकिन इसके साथ ही यह अपने 'शिवभक्त' नेता की 'जनेऊधारी' (पवित्र धागा पहनने वाले) दत्तात्रेय ब्राह्मण पहचान को भी प्रदर्शित करने से परहेज नहीं करती है। वहीं दूसरी ओर यह अयोध्या में मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण ठुकरा देती है।

कांग्रेस का आर्थिक मुद्दों पर वामपंथी रुख और अदाणी, अंबानी और 'भारत के मुट्ठी भर अमीरों' के खिलाफ तीखी बयानबाजी खोखली लगती है क्योंकि उसी जमात के साथ इसके अपने पुराने रिश्ते रहे हैं। पार्टी के सदस्यों को भी यह पता नहीं है कि वह किस चीज के लिए संघर्ष करें और उन्हें पैसे या सत्ता का कोई रास्ता नहीं दिखता, उन्हें एक राजनीतिक घराने के नियंत्रण में रहना पड़ता है जो भले ही पार्टी के अंदर कितनी भी ताकतवर हो, उन्हें वोट दिलाने में सक्षम नहीं है, ऐसे में उनके विकल्प तलाशने की संभावना ही दिखती है।

यही बात पिछले हफ्ते शिमला में कांग्रेस के साथ और उसके सहयोगी दल समाजवादी पार्टी के साथ लखनऊ में हुई।

दूसरी ओर, भाजपा एक मजबूत पैकेज की तरह है और यह पार्टी से जुड़ने वालों को वैचारिक फेविकोल, दल-बदल कर आने वाले लोगों के लिए शक्ति और सुरक्षा के साथ 'मोदी की तरफ से वोटों की गारंटी' भी देती है। आम चुनाव की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय राजनीति की तस्वीर कुछ ऐसी ही है।

स्वचालित कार की सवारी बन रही हकीकत

वंदना गोम्बर

भविष्य की कार संभवतः इलेक्ट्रिक, साझा कार और स्वचालित कार होगी। आपने इस तरह के बयान पहले भी सुने होंगे लेकिन सच यह है कि यह भविष्य की कार नहीं बल्कि आज मौजूद है। पिछले महीने की शुरुआत में, मैंने सैन फ्रांसिस्को में एक वेमो कैब की सवारी की। यह स्वचालित कैब शहर की सड़कों से होते हुए कुछ गलियों से गुजरने के साथ ही कई मुश्किल मोड़ पर भी घूमी लेकिन हम बिना किसी परेशानी अपनी मंजिल तक पहुंच गए।

ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य हाथों ने स्टीयरिंग व्हील घुमाई हो जो मशीन शायद लंबे समय तक स्वचालित कारों का हिस्सा नहीं रहेगी। वेमो गाड़ी इलेक्ट्रिक जगुआर आई-पेस मॉडल से बनी हैं और इनकी सेवाएं अन्य शहरों में भी जल्द उपलब्ध होंगी। इनका किराया उबर और लिफ्ट जैसी टैक्सी सेवाओं के समान ही है।

ब्लूमबर्ग एनईएफ इन स्वचालित वाहनों को अब भी एक ऐसे कारक के तौर पर देखता है जो हमारे आवागमन के तरीके पूरी तरह से बदल सकता है या कुछ शहरों के चुनिंदा क्षेत्रों तक ही सीमित रह सकता है। इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य अधिक स्पष्ट है, हालांकि इसमें भी बदलाव हो रहा है। इस साल दुनिया भर में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री 20 फीसदी तक बढ़ सकती है, जिनमें से लगभग 1.67 करोड़ वाहन निर्यात किए जा रहे हैं। बैटरी और धातु क्षेत्र में भी तेज गतिविधियां देखी जा रही हैं।

बीएनईएफ के धातु और खनन विश्लेषक एलन रे रेस्टॉरो का कहना है, 'लंबी अवधि में मांग में वृद्धि निश्चित है।' हालांकि, अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के कारण अधिशेष मात्रा के चलते कीमतों पर भी दबाव पड़ा है। वर्ष 2023 में निकल की कीमतों में लगभग 47 प्रतिशत की गिरावट आई। लीथियम की कीमतों में गिरावट के बावजूद एक्सॉन मोबिल कॉर्प ने हाल में कहा कि वह अर्कांसस में अपनी परियोजना को आगे बढ़ाएगी।

बीएनईएफ ने 30 देशों की वैश्विक लीथियम-आयन बैटरी आपूर्ति श्रृंखला की रैंकिंग में कनाडा को शीर्ष स्थान दिया है जो रैंकिंग एक सुरक्षित, विश्वसनीय और टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला बनाने की क्षमता पर आधारित है। कनाडा के बाद चीन, अमेरिका, जर्मनी, फिनलैंड और दक्षिण कोरिया का स्थान है। भारत इस साल पांच स्थान ऊपर चढ़कर 13वें स्थान पर पहुंच गया है। विकासशील देशों के लिए जलवायु से जुड़े लक्ष्यों के लिए राशि आवंटित करने में अग्रणी माने जाने वाले विश्व बैंक समूह ने अगले साल वार्षिक फंडिंग बढ़ाकर 40 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा है यानी विश्व बैंक जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए विकासशील देशों को अधिक सहायता प्रदान करेगा। उत्सर्जन कम करने या रोकने के लिए की जाने वाली कार्रवाई और जलवायु परिवर्तन से समायोजन के लिए यह राशि समान रूप से विभाजित की जाएगी। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने बीएनईएफ को दिए गए एक साक्षात्कार में कहा, 'इस राशि के लिए कोई ठोस वैज्ञानिक आधार नहीं है और मुझे यह नहीं पता है कि यह सही है या नहीं।' पूंजी का समान विभाजन दरअसल विकसित और विकासशील देश दोनों की चिंताओं को दूर करने के लिए किया गया है। यह विश्व बैंक के धरती को एक रहने लायक ग्रह और गरीबी मुक्त दुनिया बनाने के नए दृष्टिकोण के अनुरूप है। इसके लिए जलवायु परिवर्तन से जुड़े निवेशों में वृद्धि की आवश्यकता होगी। पिछले साल जलवायु परियोजनाओं को 38.5 अरब डॉलर की फंडिंग मिली थी।

बंगा की प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में अफ्रीका में 10 करोड़ लोगों को अक्षय ऊर्जा देने वाली 15 अरब डॉलर की योजना शामिल है। इसमें कई देशों के सहयोग से कार्बन क्रेडिट को अधिक मूल्य पर बेचने के प्रयास के साथ मीथेन उत्सर्जन को सीमित करने की योजना और भारत में हरित हाइड्रोजन से जुड़े बुनियादी ढांचे को समर्थन देना शामिल है।

सौर ऊर्जा 2024 में एक और रिकॉर्ड बनाएगी और इस साल 520 गीगावॉट से अधिक क्षमता स्थापित किए जाने की उम्मीद है और यह पिछले साल की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि है। करीब 37 से अधिक बाजार एक गीगावॉट से अधिक क्षमता जोड़ेंगे। बाजार की मौजूदा स्थिति के बारे में बीएनईएफ ने कुछ इस तरह बयां किया, 'सौर मॉड्यूल की कीमतें रिकॉर्ड निचले स्तर पर हैं और सभी घटकों की आपूर्ति भी भरपूर है। अंतिम उपयोगकर्ता वाले बाजार फल-फूल रहे हैं जबकि निर्माता लाभ कमाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।'

भारत सौर ऊर्जा स्थापित करने के मामले में विश्व में तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनने की ओर अग्रसर है और इससे आगे अमेरिका और चीन है जबकि ब्राजील और जर्मनी इसके पीछे हैं। हालांकि, सौर ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला के स्थानीयकरण की महत्त्वाकांक्षा, कम कीमतों और कम या न के बराबर लाभ मार्जिन की वास्तविकता से टकराएगी। इसका मतलब यह हो सकता है कि यूरोप, अमेरिका और अन्य देशों में प्रस्तावित कई कारखाने कभी नहीं बन पाएंगे। भारत ने पिछले साल लगभग 23 गीगावॉट सौर ऊर्जा की नीलामी की थी जो ग्रिड कनेक्शन क्षमता को दर्शाता है। यह पिछले दो वर्षों में नीलाम की गई कुल क्षमता से भी अधिक है और यह एक नया रिकॉर्ड है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

आपका पक्ष

वन्य जीवों का संरक्षण जरूरी

3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 20 दिसंबर, 2013 को वन्य जीवों के संरक्षण और इनकी सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से भी इसे मनाने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी, 2024 के रेडियो प्रोग्राम में इस दिवस पर भी बात की थी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष डिजिटल नवाचार को ध्यान में रखा जाएगा। आज दुनिया नई तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और अब वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भी डिजिटल नवाचार की जरूरत है। माना जाता है कि धरती पर लगभग 3,00,000 वनस्पति और जीव-जंतु हैं, लेकिन इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए पर्यावरण को इस कदर बिगाड़ दिया की इनमें से बहुत से जीव-जंतु लुप्त हो गए और कुछ लुप्त होने की कगार पर हैं। यह जैव विविधता के लिए खतरे का संकेत है। प्रकृति की शान पशु, पक्षियों और सभी प्राणियों से है। अपनी सुख-सुविधाओं की खातिर आज इंसान प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। साथ ही प्रकृति के सौंदर्य को चार चांद लगाने वाले वन्य जीव, पशु-पक्षियों की रक्षा करना ही भूल गया है। उनमें से कुछ प्रजातियां विलुप्त हो गई है। कुदरत ने प्राणी जाति के लिए एक चक्कर-सा बनाया है। इसमें हर जीव-जंतु, पक्षियों का होना जरूरी है। सरकार वन्य जीवों के संरक्षण और उनके अवैध शिकार को रोकने के लिए कई योजनाएं चलाती हैं। करोड़ों रुपये इस पर खर्च किए जाते हैं मगर नतीजा सिफर है। केंद्र और राज्यों की सरकार को जंगलों के संरक्षण की तरफ भी गंभीरता से ध्यान देना होगा, ताकि बाघ और अन्य जंगली जीव-जंतु जंगलों में ही विचरण करें। ये रिहायशी इलाकों का रुख करके लोगों के लिए परेशानी और किसी की जान की दुश्मन न बनें और न ही इनकी प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा बढ़े।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

केंद्र सरकार वन्य जीव संरक्षण पर कई योजनाएं चलाकर करोड़ों रुपये खर्च करती है मगर योजनाएं सफल होती नहीं दिखती हैं

नौसेना: आत्मनिर्भरता के राष्ट्रीय कदम

हाल ही में भारतीय नौसेना प्रमुख ने कहा कि दूसरे देशों से हासिल की गई सभी पुरानी मिसाइल प्रणालियों को नौसेना से हटा दिया जाएगा। अब हम भारतीय नौसेना के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को एक मुख्य या प्रधान हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इन मिसाइलों में आवश्यकतानुसार रेंज, क्षमता व घातकता के आधार पर बदलाव किए गए हैं, इसलिए यह स्वदेशी हथियार प्रणाली भारतीय नौसेना का प्रमुख हथियार रहेगी। दरअसल, भारत रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित तथा निर्मित करने की अपनी क्षमता का लगातार विस्तार कर रहा है। 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत रक्षा क्षेत्र में उन्नत अत्याधुनिक तकनीकों और प्रणालियों को शामिल कर सेना को मजबूती दी जा रही है। बीते कुछ वर्षों से भारत रक्षा के क्षेत्र में अव्वल दर्जे के हथियार तैयार कर रहा है। इन सब हथियारों की एक विश्वसनीय धमक विदेशों में भी बन चुकी है। सरकार का संकल्प देश को न सिर्फ वैश्विक पटल पर और मजबूत कर रहा है, बल्कि भारत निर्मित स्वदेशी उपकरणों के प्रति विदेशी सेनाओं के भरोसे को भी दर्शा रहा है।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो – पीटीआई

नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार नौसेना अधिकारी मेस में वसंत ऋतु के आगमन पर आयोजित जश्न में शामिल हुए। भारतीय नौसेना ने अपने मेस के लिए पोशाक के रूप में कुर्ता-पायजामा को अपनाया है। इसे नौसेना ने परंपरा और आधुनिकता के संगम की तरह देखा जा रहा है।

हिन्दुस्तान
1936 सत्य • सार्थक • सदैव

इंसान की पूंछ

यह सवाल पुराना है कि इंसानों की पूंछ कहां गई? अमेरिकी शोधकर्ताओं ने मनुष्यों और अन्य वानरों द्वारा साझा किए जाने वाले आनुवंशिक परिवर्तनों की पड़ताल की है। अनुमान है कि लगभग 2.5 करोड़ वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने अपनी पूंछ गंवा दी थी। वास्तव में पूंछ संबंधी यह खोज ढाई वर्ष पहले हो गई थी, किंतु व्यावहारिक रूप से चूहों पर कुछ परीक्षण कार्य चल रहा था। जीन-संपादित चूहों के कई उपभेदों को विकसित करने और अतिरिक्त परीक्षण करने की जरूरत थी, ताकि आनुवंशिक परिवर्तनों का प्रभाव स्पष्ट रूप से सामने आए। इस कार्य में शोधकर्ताओं को सफलता मिली है और उसके बाद ही शोध का *नेचर* पत्रिका में प्रकाशन हुआ है। जीनोम में इंसानों के समान ही बदलाव करके चूहों की पूंछ को छोटा या खत्म करना संभव है। इस नई शोध का सर्वाधिक श्रेय आनुवंशिकीविद बो जिया को दिया जा रहा है। पूंछ का सवाल उन्हें बचपन से परेशान करता आ रहा था और कुछ साल पहले इस विषय पर शोध की जरूरत उन्हें इसलिए महसूस हुई, क्योंकि वह खुद टेलबोन की चोट से उबर रहे थे। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में पीएचडी के दौरान ही उन्होंने इस पर गंभीरता से काम शुरू कर दिया था और अब उनकी टीम की मेहनत रंग लाई है। अधिकांश बंदरों के विपरीत, वानरों - जिनमें मनुष्य भी शामिल हैं - और उनके करीबी विलुप्त रिश्तेदारों की पूंछ नहीं होती है। उनका कोक्सीक्स या टेलबोन कशेरुकाओं का एक अवशेष है, जो अन्य जानवरों में अभी भी पूंछ का निर्माण करता है। इस विशेषता या बदलाव का आनुवंशिक आधार डॉक्टर जिया और उनकी टीम ने ढूंढ़ लिया है। अब डॉक्टर जिया कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स में एमआईटी और हार्वर्ड के ब्रॉड इंस्टीट्यूट में शोधरत हैं। यह स्पष्ट है कि जीन के प्रभाव में ही इंसानों की पूंछ गायब हुई है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए जीनोम ब्राउजर से पता चला है कि मनुष्य और अन्य वानरों में टीबीएक्सटी डीएनए सम्मिलन होता है, जो बंदरों जैसी पूंछ वाले अन्य जीवों के पास नहीं होता है। टीबीएक्सटी के माउस संस्करण की प्रतिलिपि वाले जीन-संपादित चूहों में पूंछ दोषों की एक श्रृंखला थी। शोध या परीक्षण के दौरान कुछ चूहों की पूंछ छोटी हो गई थी या पूरी तरह गायब हो गई थी या कुछ दूसरे प्रकार के भी प्रभाव हुए थे। जब टीबीएक्सटी के चूहा या माउस संस्करण में वानर आनुवंशिक को मिलाया जाए, तो पूंछ का नुकसान हो सकता है। यह भी एक रोचक खोज है कि पूंछ के विकास के लिए करीब 140 जीन जिम्मेदार हो सकते हैं। मतलब, मानव का विकास ही ऐसे हो रहा था कि पूंछ का अंत होना ही था। शोधकर्ताओं ने पता किया है कि बीती सदियों में वानरों या मनुष्यों में हजारों आनुवंशिक परिवर्तन हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं। आनुवंशिक तंत्र की वजह से ही पूंछ इंसानों के शरीर से विदा हो चुकी है, लेकिन इंसान अपनी पूंछ को भूल नहीं पा रहा है। जब पूंछ विदा हुई होगी, तो इंसानों को सीधे चलने में सुविधा हुई होगी और उनका पेड़ों पर चढ़ना कम हुआ होगा। बहरहाल, जीवाश्मों से भी पता चलता है कि प्रारंभिक वानर पेड़ों पर रहने वाले बंदरों की तरह चार पैरों पर चलते थे और लाखों साल बाद दो पैरों पर चलने की क्षमता विकसित हुई। वैसे, वानर ही ऐसे एकमात्र प्राइमेट नहीं हैं, जिनके पास पूंछ नहीं है : मैंड्रिल, कुछ मकाउ और बड़ी आंखों वाले लोरिस की भी पूंछ नहीं होती है, जिससे पता चलता है कि पूंछ न होने का गुण अनेक जीवों में विकसित हुआ है।

आनुवंशिक तंत्र की वजह से पूंछ इंसानों के शरीर से विदा हो चुकी है, पर इंसान पूंछ को भूल नहीं पा रहा है। हालांकि, पूंछ न होने से इंसान को सीधे चलने में सुविधा हुई।

हिन्दुस्तान Hindustan | **75 साल पहले** 04 मार्च, 1949

नया डच प्रस्ताव

हिन्देशिया की समस्या को सुलझाने के लिए नीदरलैण्ड सरकार ने हालैण्ड की राजधानी हेग में आगामी १२ मार्च को एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया है। हिन्देशिया के सभी राजनीतिक दलों और पार्टियों तथा अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों को भी इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए निमंत्रित किया गया है। हिन्देशिया के लिए अन्तरिम संघ सरकार की स्थापना करने और उसके साथ ही नीदरलैण्ड और हिन्देशिया की एक यूनियन कायम करने के प्रश्न पर सम्मेलन में विचार किया जायेगा। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए संयुक्त राष्ट्रीय संघ के कमीशन को भी बुलावा भेजा गया है। नीदरलैण्ड की सरकार की ओर से कहा गया है कि सुरक्षा कौंसिल ने हिन्देशिया को सत्ता हस्तान्तरित करने की अन्तिम तिथि १ जुलाई, १९५० निर्धारित की है उसके बहुत पहले ही वह सत्ता सौंप देना चाहती है। नीदरलैण्ड सरकार ने दूसरा महत्वपूर्ण कदम यह उठाया है कि उसने हिन्देशिया के प्रजातंत्री नेताओं को रिहा करने का आदेश दे दिया है, जिन्हें हिन्देशिया में गत दिसम्बर मास में फौजी कार्रवाई प्रारम्भ करते समय डचों ने गिरफ्तार कर लिया था। कुछ प्रजातंत्री नेताओं को रिहा कर दिया गया है और शेष भी निकट भविष्य में रिहा कर दिये जायेंगे।

जहां तक प्रजातंत्री नेताओं को रिहा करने का ताल्लुक है, नीदरलैण्ड सरकार ने उचित कदम उठाया है। उसे बहुत पहले ही उन्हें रिहा कर देना चाहिए था। सुरक्षा कौंसिल और एशियाई देशों की कान्फ्रेंस दोनों ने प्रजातंत्री नेताओं की तात्कालिक रिहाई की मांग की थी। उस न्यायोचित मांग को पूरा करने में नीदरलैण्ड सरकार ने काफी टालमटोल से काम लिया। आखिर सुबह का भूला शाम को घर आ जाये तो यह सन्तोष का ही विषय हो सकता है। किन्तु नीदरलैण्ड सरकार ने प्रजातंत्री नेताओं को रिहा करके अधूरा कदम उठाया है। उसने प्रजातंत्री इलाके पर फौजी ताकत के जरिये जो अधिकार जमा लिया है, उसे समाप्त करने का साहस उसने नहीं दिखाया है। उसने यह कार्रवाई प्रजातंत्री सरकार के साथ किये गये पूर्व समझौतों को भंग करके की थी। जब तक हिन्देशिया में यथापूर्व स्थिति नहीं कायम कर दी जाती, तब तक प्रजातंत्री नेताओं का समाधान नहीं हो सकता। उस दशा में वे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने को रजामन्द होंगे या नहीं, इसमें भारी सन्देह है।

प्रत्याशी घोषणा में बढ़त के मायने

सत्तारूढ़ भाजपा ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही एक तिहाई से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम स्पष्ट कर दिए हैं। अब दूसरी पार्टियों में भी प्रत्याशी चयन में तेजी आ जाएगी।

यहां स्कैन करें

राहुल वर्मा | फेलो, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च

किसी भी जंग में समय रहते बड़ी सेना उतारने के अपने फायदे हैं। चुनावी मैदान में भी पहले आई सेना की ताकत स्वतः ही कुछ ज्यादा हो जाती है। इस लिहाज से देखें, तो भारतीय जनता पार्टी के 195 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची सबसे जल्दी आ गई है और उसके बाद चुनावी सरगर्मी भी बहुत बढ़ती जा रही है। ज्यादातर लोगों का चुनावी विश्लेषण इसी आधार पर रहता है कि कितने ओबीसी को टिकट दिए, कितने एसटी को टिकट दिए। विश्लेषण में सामाजिक समीकरणों पर ध्यान देने की कोशिश होती है। अभी जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे, उसमें भी यही देखा जा रहा था कि कैसे भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए अलग-अलग तरह से कोशिशें कर रही है।

सूची देखकर लगता है, भाजपा ने टिकट देते समय विभिन्न वर्गों का ध्यान रखा है। युवाओं को भी तरजीह मिली है। भाजपा के 47 प्रतिशत प्रत्याशी ऐसे हैं, जिनकी उम्र 50 से भी कम है। युवा नेताओं पर ज्यादा भरोसा करना वाकई कारगर साबित हो सकता है। बहरहाल, किसको टिकट मिला से ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि किसका टिकट कट गया। भाजपा ने ढेर सारे सांसदों और मंत्रियों के टिकट काट दिए हैं। दिल्ली को अगर देखें, तो 7 सीटों में चार सीटों पर पिछली बार जीते प्रत्याशी को मौका नहीं दिया है।

खैर, अगर हम यह देखने की कोशिश करें कि किस आधार पर टिकट कटा है या किस आधार पर बंटा है, तो इसका कोई तय ढर्रा या पैटर्न नजर नहीं आता है। कई ऐसे नाम चल रहे थे, जिनके बारे में लग रहा था कि इनका टिकट कट जाएगा, पर उनका टिकट नहीं कटा, जैसे मथुरा से हेमा मालिनी का टिकट। कोई भी पार्टी कितनी भी ताकतवर हो जाए, टिकट देने की प्रक्रिया अलग ही होती है, इसका कोई तय फॉर्मूला नहीं होता है। टिकट वितरण के बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता है। सर्वोच्च नेताओं के अलावा किसी को मालूम नहीं होता है कि निर्णय क्या और कैसे लिया जा रहा है। लगभग हर पार्टी के हाईकमान के साथ ऐसा ही है, किसी भी पार्टी में चंद लोग ही जानते हैं कि किसको टिकट मिलेगा और किसका कटेगा। यह बात नई नहीं है, जो नेता टिकट देने का फैसला कर रहे होते हैं, उन्हें अनेक पैमानों पर विचार करना पड़ता है। युवाओं को भी उतारना है, महिलाओं को भी टिकट देना है, टिकट ऐसे नहीं बांटना है कि अन्य सीटों पर भी उसका नकारात्मक असर हो। कुल मिलाकर, भारतीय लोकतंत्र में टिकट बंटने की प्रक्रिया सहज नहीं, बल्कि बहुत जटिल होती है और इसे पुरस्कार या दंड के लेंस से नहीं देखा जा सकता।

बहरहाल, इस आधार पर भी विवेचना हो रही है कि फलां ने अच्छा काम किया था, पर टिकट कट गया या फलां ने खराब काम किया था, फिर भी टिकट मिल गया। जाहिर है, बार-बार चर्चा होगी कि किस आधार पर टिकट कटा होगा? यह माना जाता है कि जिनका टिकट कटा है, उनका जनता से जुड़ाव अच्छा नहीं था। उनका अपनी पार्टी या संगठन से तालमेल सही नहीं था। कुछ लोग ऐसे भी थे, जो अक्खड़ किस्म के थे, अपनी दुनिया में मस्त रहते थे, उन पर अब पार्टी दांव लगाकर खतरा उठाना नहीं चाहती है।

हालांकि, किसी भी पार्टी में ऐसे लोग भी होते हैं, जो अच्छा काम कर रहे होते हैं, पर आलाकमान में कोई उनकी पैरवी करने वाला नहीं होता है, तो टिकट कट जाता है। ऐसा भी लगता है कि भाजपा अब ऐसे लोगों को टिकट देना नहीं चाहती है, जो समुदाय विशेष के खिलाफ तीखी टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं। यहां आप रमेश बिधूड़ी का नाम ले सकते हैं, जिनका टिकट कट गया है। हालांकि, ऐसे प्रत्याशी भी हैं, जिन्होंने गलत बातें कही हैं, पर उन्हें दूसरे कारणों से टिकट दे दिया गया है। दरअसल, मूल रूप से कोई भी पार्टी टिकट बांटते हुए जीत को अधिक महत्व देती है।

एक और बात, भाजपा अक्सर परिवारवाद पर हमले बोलती है, पर यहां भी कुछ नेताओं के बेटे-बेटियों को टिकट दिया गया है। परिवारवाद का आरोप शायद उन्हीं पार्टियों के लिए है, जिनका संचालन कोई एक परिवार कर रहा है। भाजपा नेताओं के बीच परिवारवाद में भी जीत की गारंटी को महत्व दिया गया लगता है। बहुत से नेता हैं, जो अपनी संतानों के लिए टिकट मांग रहे हैं, पर उन्हें निराशा हाथ लगी है।

बहरहाल, इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा ने 2024 के लिए बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है और वह न केवल चुनाव जीतना चाहती है, बल्कि साल 2019 के प्रदर्शन में भी सुधार करना चाहती है। पिछली बार 303 सीटें मिली थीं और इस बार 370 से ज्यादा सीटें जीतने की योजना है। ऐसे में, जाहिर है, भाजपा ऐसे नेताओं को ही मैदान में उतारेगी, जो जीतने में सक्षम होंगे। भाजपा बहुत मजबूती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने रखकर चुनाव लड़ रही है, पर अच्छा चुनाव लड़ने वाली पार्टी यह भी जानती है कि प्रत्याशियों का भी अपना महत्व है। आज लोगों को अच्छे उम्मीदवारों की उम्मीद रहती है, अतः भाजपा कहीं भी यह गलती नहीं करेगी कि किसी को भी मैदान में उतारकर पार्टी के प्रदर्शन को खराब किया जाए।

यह एक बड़ी बढ़त की बात है कि भाजपा ने चुनाव की घोषणा से पहले ही एक तिहाई से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम स्पष्ट कर दिए हैं। ऐसा अभी तक किसी भी पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर नहीं किया है। हां, कुछ पार्टियों ने क्षेत्रीय आधार पर अपने उम्मीदवारों के नाम उजागर किए हैं, जैसे समाजवादी पार्टी। प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के मोर्चे पर भाजपा सबका नेतृत्व करती दिख रही है। जल्दी उम्मीदवार उतारने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि किसी के बागी होने पर स्थिति संभालने के लिए समय मिल जाता है।

जहां तक मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की बात है, अभी तो विपक्षी 'इंडिया' के अंदर ही अनेक राज्यों में सीटों का बंटवारा स्पष्ट नहीं हुआ है। कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा में बहुत पीछे चल रही है। जब विपक्ष सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ मजबूती से उम्मीदवार उतारेगा, तभी बेहतर चुनावी विश्लेषण की स्थिति बनेगी। हम उम्मीद कर सकते हैं कि भाजपा की घोषणा के बाद अन्य पार्टियों में भी प्रत्याशी चयन में तेजी आएगी। जब टिकट कटने का दुख और मिलने का सुख हर पार्टी में होगा, तब देखने वाली बात केवल यही होगी कि जीत का सेहरा किसके माथे बंधता है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज आर्थिक तरक्की का राज

यहां स्कैन करें

आलोक जोशी | वरिष्ठ पत्रकार

चुनाव का मौसम आ रहा है, बल्कि आ चुका है। ऐसे में, महंगाई का नाम आना स्वाभाविक है और आर्थिक तरक्की, यानी 'ग्रोथ' का भी। यह बात प्रश्न है कि महंगाई या ग्रोथ जैसे विषयों की अब चुनावी राजनीति में कोई भूमिका बची भी है या नहीं? मगर हर खास-ओ-आम को यह जानने में दिलचस्पी जरूर है कि महंगाई घटी या नहीं, और भारत की तरक्की का क्या हाल है? पिछले दिनों एक के बाद एक ऐसे कई आंकड़े आए हैं, जिनसे इस तरह के सवालों के जवाब भी मिलते हैं और उम्मीद भी बंधती है कि लंबे समय के बाद एक बार फिर भारत तेज रफ्तार विकास का न सिर्फ सपना देख सकता है, बल्कि उसके जल्दी ही साकार होने की उम्मीद भी कर सकता है।

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) देश की आर्थिक तरक्की का सबसे बड़ा पैमाना है। ताजा आंकड़ा अक्तूबर से दिसंबर 2023 का आया है। यह वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही है। इस दौरान भारत की जीडीपी में पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 8.4 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। यह जबर्दस्त खुशखबरी है, क्योंकि अच्छे से अच्छा सोचने वाले अर्थशास्त्री भी इतनी वृद्धि का अंदाजा नहीं लगा पाए थे। उन्हें उम्मीद थी कि जीडीपी करीब 6.6 प्रतिशत की बढ़त दिखाएगी। अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि कृषि क्षेत्र के उत्पादन में 0.8 प्रतिशत की मामूली गिरावट दर्ज हुई है। ऐसा पिछले पांच साल में पहली बार हुआ और गिरावट भी मामूली है। कृषि क्षेत्र भारत की जीडीपी में 15 प्रतिशत का हिस्सेदार है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि कृषि में मंदी के बावजूद इतनी जबर्दस्त ग्रोथ आई कहां से?

भारत की जीडीपी में पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 8.4 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। यह एक बड़ी खुशखबरी है।

सबसे अधिक तेजी दिखाई पड़ी है मैन्युफैक्चरिंग, यानी फैक्टरियों में होने वाले उत्पादन में। यहां 11.6 प्रतिशत का जोरदार उछाल है और निर्माण-क्षेत्र में भी 9.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद खनिज और खनन में 7.5 प्रतिशत की बढ़त दिखाई पड़ी है। हालांकि, सेवा क्षेत्र की बढ़त 6.7 प्रतिशत ही रही है। उधर एक और आंकड़ा है, जो बाजार में मांग का हाल बताता है। यह है रोजमर्रा की चीजों पर खर्च। इसमें 3.5 फीसदी की बढ़त है, जबकि सरकार के ऐसे ही खर्च में लगभग तीन प्रतिशत की गिरावट दिख रही है। मगर निवेश का हाल बताने वाले मानक जीएफसीएफ (ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन) में पिछले साल के मुकाबले 10.6 प्रतिशत की बढ़त दिख रही है, यानी इस वर्ष ऐसा खर्च बढ़ा है, जिससे किसी तरह की संपत्ति खड़ी हुई है। अब जनवरी से मार्च के बीच की ग्रोथ कमजोर भी रही, तब भी भारत सालाना 7.6 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़त दिखा सकता है।

दूसरी ओर, महंगाई का हाल क्या है? खुदरा महंगाई का आंकड़ा भी दिसंबर के 5.69 प्रतिशत से घटकर जनवरी में 5.1 फीसदी पर आ चुका है। यह रिजर्व बैंक के चार प्रतिशत के लक्ष्य पर तो नहीं है, मगर बर्दाश्त की हद, यानी दो से छह फीसदी के बीच ही है और ऊपरी हद से दूर भी। रिजर्व बैंक ने अगले वित्त वर्ष की चार तिमाहियों के लिए महंगाई दर का अनुमान क्रमशः पांच प्रतिशत, चार प्रतिशत, 4.6 प्रतिशत और 4.7 फीसदी बताया हुआ है। साथ ही उसने चालू वित्त वर्ष के लिए तरक्की का अनुमान 6.5 और अगले वित्त वर्ष के लिए सात फीसदी बताया है।

ऐसे में, यह तर्क दिया जा सकता है कि अब महंगाई अनुमान के करीब दिख रही है और आर्थिक तरक्की की रफ्तार तो उम्मीद से तेज हो चुकी है, फिर रिजर्व बैंक को भी कारोबारियों को राहत और विकास को सहारा देने के लिए ब्याज दरें घटाने पर विचार करना चाहिए। उत्साहजनक संकेतों के बीच चुनाव के ऐन पहले यह उम्मीद बेवजह भी नहीं है।

लगभग दस साल बाद घर खर्च का हिसाब देने वाले सरकारी सर्वे के नतीजे भी हाल ही में आए हैं। पहली बार ग्रामीण इलाकों में भी घर खर्च में खाने-पीने की चीजों का हिस्सा आधे से कम रह गया है, मतलब संपन्नता बढ़ी है।

बहरहाल, जिस वक्त लगभग पूरी पश्चिमी दुनिया और विकासशील देशों का भी एक बड़ा हिस्सा आर्थिक मंदी की आशंका से जूझ रहा है; ब्रिटेन और जापान जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी की चपेट में आ गई हैं, तब भारतीय अर्थव्यवस्था अगर ऐसी तेज रफ्तार तरक्की दिखा रही है, तो भारतीय रिजर्व बैंक से भी इस काम में हाथ लगाने की उम्मीद करना बेमानी नहीं है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

ताकि निरर्थक परंपरा न बने

झेन परंपरा में बिल्लियों को बहुत मानते हैं। झेन की पूरी सिखावन और अभ्यास है- शांत व सजग रहना। अतः उनके लिए बिल्ली एक आदर्श है, क्योंकि उसका शरीर विरोधाभासों से बना है। जितना मुलायम, उतना ही फुर्तीला। बिल्ली को पकड़ने की कोशिश करें, तो पता चलेगा। वह सोती है, तो बहुत शिथिल और उतनी ही सतर्क रहती है। इसलिए उसे स्वाभाविक झेन गुरु कहा जाता है। झेन मठों में आमतौर पर बिल्लियां पाई जाती हैं।

एक झेन गुरु अपने प्रवचन के दौरान मठ की बिल्ली को बांधने के लिए कहते थे, क्योंकि वह निरंतर आस-पास घूमती रहती और बीच में म्यांऊ-म्यांऊ भी करती। स्वाभाविक ही इससे लोगों का ध्यान भटक जाता था। आखिरकार यह एक प्रथा बन गई कि जब भी प्रवचन की तैयारियां होतीं, पहले बिल्ली को खोजकर एक खंभे से बांध दिया जाता। कुछ सालों बाद, जब गुरु की मृत्यु हो गई, तो जो शिष्य उनके सान्निध्य में रहते थे और जिन्हें खंभे से बिल्ली को बांधने की आदत सी पड़ गई थी, वे अपने गुरु की याद में एक नई बिल्ली लाकर खंभे से बांधने लगे। इतनी जल्दी वे उस लगाव से मुक्त होना नहीं चाहते थे। फिर वह पीढ़ी भी गुजर गई। नए शिष्य आए, तो उन्होंने सोचा कि रोज बिल्ली को लाकर बांधने के बजाय क्यों न उसकी एक मूर्ति बनाकर गुरु जी के चित्र के पास रख दी जाए। अब गुरु के चित्र के साथ-साथ बिल्ली की मूर्ति की भी पूजा होने लगी। आगंतुक पूछते, यह बिल्ली की मूर्ति किसलिए? उत्तर तो कोई नहीं जानता था, वे यही कहते, ऐसी यहां की परंपरा है।

इस कहानी को याद करने की वजह है, कोई भी रस्म या रिवाज आसानी से परंपरा बन सकता है, यदि उसे होशपूर्वक न किया जाए। वह रिवाज किसलिए शुरू किया गया था, उसे कब तक जारी रखना है और कब बंद कर देना है, यह समझ के साथ करना होता है।

उदाहरण के लिए, ओशो जब भारत के शहरों में घूम-घूमकर ध्यान शिविर लगाया करते थे, तब उनके बैठने के लिए वहां जो भी कुरसी उपलब्ध होती, उसे लाकर रख दिया जाता। उसे छिपाने के लिए उस पर सफेद चादर डाल दी जाती। धीरे-धीरे वह एक प्रथा बन गई। जहां भी ओशो के व्याख्यान होते, कितनी ही अच्छी कुरसी क्यों न हो, उस पर सफेद चादर जरूर डाल दी जाती। और तो और, बाद में भी जो शिविर हुए, उनमें लंबे समय तक सफेद चादर वाली कुरसी ही रखी जाने लगी। इससे पहले कि यह परंपरा बने, सावधान होना जरूरी है। परंपरा वह काई है, जो ठहरे हुए पानी पर जमती है। उसे बार-बार हटाना जरूरी है। धार्मिकता धर्म न बने, इसके लिए सतर्कता बरतनी पड़ती है।

कोई भी रस्म या रिवाज आसानी से परंपरा बन सकता है, यदि उसे होशपूर्वक न किया जाए। परंपरा वह काई है, जो ठहरे हुए पानी पर जमती है। उसे बार-बार हटाना जरूरी है।

अमृत साधना

मलाला यूसुफजई | नोबेल विजेता

यह देखना दर्दनाक है कि जो बच्चों की तालीम की जगह थी, वह आज इजरायली हमलों से बचकर भाग रहे हजारों लोगों की पनाहगाह है। गाजा का हर बच्चा शांति व अपने स्कूल का हकदार है। युद्ध विराम का हम और इंतजार नहीं कर सकते।

अनुलोम-विलोम

इंटरनेट चैटिंग

एकाकीपन मिटा रही इंटरनेट चैटिंग

सूचना और संचार क्रांति से जब जीवन का हर कोना प्रभावित हो रहा है, तो भला रोमांस और डेटिंग की दुनिया इससे कैसे अछूती रह सकती है? इंटरनेट की दोस्ती अपेक्षाकृत आसान होती है और इसमें व्यक्ति की पहचान उसके चेहरे या जाति से नहीं होती। वास्तव में, इंटरनेट चैटिंग (बातचीत का ऑनलाइन माध्यम) ऐसे लोगों के लिए मिलने-जुलने, दोस्ती करने, वार्तालाप करने, रोमांस या डेटिंग का बेहतरीन माध्यम है, जो बेहद शर्मीले होते हैं या अकेलेपन से ग्रस्त हैं। वे यहां नए दोस्तों से मिल सकते हैं, उनसे अपनी भावनाएं साझा कर सकते हैं और खुद को कहीं अधिक सुरक्षित व ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। इसमें सामने वाले की हैसियत या प्रतिष्ठा की परवाह नहीं की जाती। चूंकि सारा काम वर्चुअल, यानी आभासी होता है, इसलिए इसमें कई तरह के खर्च भी बच जाते हैं।

ऐसा नहीं है कि यहां कोई सावधानी नहीं बरतनी पड़ती। यहां भी 'फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन' का फॉर्मूला काम करता है। यदि किसी दोस्त पर आप पहली मुलाकात में प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे, तो वह आपसे संबंध जारी रखने में शायद ही दिलचस्पी लेगा। इंटरनेट पर एक-दूसरे को प्रभावित करने के लिए चंद सेकंडों का अवसर मिलता है। इसी में आपको अपने शब्दों का जादू चलाना पड़ता है। देखा जाए, तो यही वह बड़ी चुनौती है, जो वास्तविक दुनिया की दोस्ती में नहीं झेलनी पड़ती। घर-मुहल्ले का कोई इंसान अगर किसी दिन आपकी अनदेखी करता है, तो दूसरे या तीसरे दिन आपके पास भी आता है। मगर इंटरनेट पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहां हर कोई हड़बड़ी में रहता है। समय सबके पास सीमित है। इसीलिए, चंद लम्हों में वह भा जाए, तो ठीक, वरना किसी के पास आपका इंतजार करने का वक्त नहीं है। एक तरह से यह ठीक भी है कि यहां कोई आपसे जबरिया चिपकता नहीं। चिपकने पर उसे ब्लॉक करने का विकल्प आपके पास है।

ऐसे में, कुछ सामान्य सावधानियां बरतकर इंटरनेट पर अच्छे दोस्त बनाए जा सकते हैं। मसलन, चैटिंग रूम या ऑनलाइन पत्र-व्यवहार के दौरान किसी अभद्र संवाद से बचें। इंटरनेट प्रोफाइल बनाने में भी सावधानी बरतें और उसमें सच लिखें। ई-मेल असली हो और उसका आप नियमित उपयोग करते हों। यहां भी दूसरों की उपस्थिति में सहज रहने वाला व्यक्ति दोस्ती को काफी आगे तक ले जा सकता है। एक-दूसरे से गिले-शिकवे करने से बचें। याद रखें, आपकी व्यावहारिक कुशलता पसंदीदा दोस्त और अच्छे इंसान की तलाश में बहुत मददगार साबित हो सकती है।

पूजा गुप्ता, टिप्पणीकार

ज्यादातर मामलों में धोखा देने का मंच

आज के तेज-तर्रार युग में लगातार ऑनलाइन रहना एक आदर्श बन गया है। यह सच है कि इंटरनेट ने हमारे जीवन को काफी बदल दिया है और तमाम तरह की सुविधाएं भी इसने हमें दी हैं, मगर इसकी अपनी चुनौतियां भी हैं। इंटरनेट चैटिंग भी कोई अपवाद नहीं है। इसकी लत हमारे लिए कई तरह से नुकसानदेह है। सोशल मीडिया मंचों का ज्यादा उपयोग करने से हम सामाजिक अलगाव के शिकार बन सकते हैं। इससे हमारा वास्तविक जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। हमारे भीतर अकेलापन व वैराग्य की भावनाएं पैदा हो सकती हैं और हमारा स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हो सकता है।

यह समझने की बात है कि इंटरनेट ने हमें सूचनाओं के ऐसे सागर में डुबो दिया है, जहां फर्जी सूचनाएं ही ज्यादा तैरती रहती हैं। चूंकि तमाम कोनों से हम तक असत्यापित सामग्रियां पहुंचती हैं, हम उन पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं। इंटरनेट चैटिंग में इसी विश्वास का फायदा उठाया जाता है। वहां ईमानदारी और भोलापन जैसे गुण आपके खिलाफ जा सकते हैं और दुनिया भर में आपको बदनाम कर सकते हैं। वास्तविक जीवन में किसी एक दोस्त से मिला धोखा आपको कुछ समय तक परेशान करता है, लेकिन आभासी दुनिया में किया गया विश्वासघात ताउम्र पीछा नहीं छोड़ेगा। विशेष तौर पर मासूम लड़कियां इसकी शिकार बनाई जाती हैं, जिससे उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। असल में, इंटरनेट की दुनिया इतनी विशाल है कि आप यहां आसानी से सच और झूठ को नहीं बांट सकते। हो सकता है कि इंटरनेट पर जो आपका सबसे अच्छा दोस्त हो, वह असली जीवन में ऐसा इंसान हो, जिसे आप पसंद नहीं कर सकेंगे। यह भी मुमकिन है कि वह खुद को इंटरनेट पर काफी होनहार और योग्य बता रहा हो, लेकिन वास्तविक जीवन में उतना ही निकम्मा और नालायक हो। चूंकि इंटरनेट चैटिंग में सामने वाली की पहचान जाहिर नहीं होती, इसलिए उसके लिए धोखा देना सबसे आसान होता है। इसी कारण इससे बचना ही बेहतर है।

सच यही है कि सोशल मीडिया ने हमें सबसे ज्यादा 'अनसोशल', यानी असामाजिक बना दिया है। इंटरनेट चैटिंग इसलिए भी भरोसे के लायक नहीं, क्योंकि जिस दोस्ती की बुनियाद ही झूठ पर टिकी हो, उस पर कैसा विश्वास? इससे कैसे एक-दूसरे को जान सकेंगे? इसलिए, इस तरह की चैटिंग से दूरी ही अच्छी। बेहतर यही है कि हम अपने आस-पास में दोस्त बनाएं, जो वक्त-बेवक्त हमारे काम आ सकें। असल दोस्ती का मतलब भी तो यही है।

अपर्णा कुमारी, टिप्पणीकार

https://t.me/AllNewsPaperPaid

कल्पमेधा

समस्त प्रगति का श्रेय उन लोगों को जाता है, जिन्होंने प्रचलित विचारधाराओं के विरुद्ध कदम उठाए।

– अडलाई स्टीवेन्सन

धमाके की जगहें

बंगलुरु के कैफे में हुए बम विस्फोट से एक बार फिर सुरक्षा इंतजामों में अधिक कड़ाई की जरूरत रेखांकित हुई है। हालांकि घटना के बाद प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया और उसने दोषी को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। गनीमत थी कि विस्फोटक हल्की तीव्रता का था और उसमें ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ। उसमें दस लोग घायल हो गए। पता चला है कि शुक्रवार की दोपहर एक युवक बैग लेकर कैफे में घुसा और कुछ भोजन का आदेश देने के बाद बैग वहीं छोड़ कर चला गया। उसके कुछ देर बाद ही धमाका हो गया। सीसीटीवी कैमरे में उस युवक की तस्वीर कैद हो गई है। पुलिस अभी इस घटना को आतंकवादी साजिश मानने से इनकार कर रही है। गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। हालांकि पुलिस इस विस्फोट का अध्ययन करीब चौदह महीने पहले मंगलुरु में इसी तरह एक प्रेशर कुकर में हुए विस्फोट से जोड़ कर करने का प्रयास कर रही है। मगर यह सवाल अभी तक अनुत्तरित है कि अगर इस विस्फोट के पीछे किसी आतंकवादी संगठन का हाथ नहीं है, तो आखिर वहां किस तरह के अपराधी संगठन सक्रिय हैं, जो बंगलुरु में दहशत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।

बंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है और वहां अनेक देशी-विदेशी साफ्वेटयर कंपनियों के मुख्यालय और शैक्षणिक संस्थान भी हैं। किसी व्यावसायिक शहर में इस तरह विस्फोट की घटनाओं से वहां के कारोबारियों के मनोबल पर बुरा असर पड़ता है। खासकर विदेशी कंपनियां ऐसी असुरक्षित जगहों पर अपना कारोबार चलाना ठीक नहीं मानतीं। इसलिए भी कर्नाटक सरकार के लिए यह विस्फोट एक चुनौती की तरह हुआ है। स्वाभाविक ही इस घटना के बाद बंगलुरु की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि ज्यादातर सार्वजनिक स्थानों पर अब सुरक्षा की दृष्टि से जांच के कड़े इंतजाम किए जाते हैं। थैले आदि की विशेष रूप से जांच की जाती है। इस तरह ऐसी जगहों पर बैग वगैरह में विस्फोटक छिपा कर ले जाना और अपनी साजिशों को अंजाम देना अपराधियों के लिए आसान नहीं होता है। मगर जिस कैफे में विस्फोट हुआ, वह एक छोटी-सी जगह है, इसलिए वहां जांच के ऐसे उपकरण इस्तेमाल नहीं होते रहे होंगे। शहरों में ऐसी अनेक छोटी-छोटी जगहें होती हैं, जिनमें बीस-पचास लोगों के बैठने और नाश्ता-भोजन आदि की व्यवस्था होती है। ऐसी जगहों पर प्रायः मशीनों से लोगों और चीजों की जांच के इंतजाम नहीं किए जाते। उसी का फायदा बंगलुरु विस्फोट के अपराधी ने उठाया।

आतंकवादी गतिविधियों से सबसे अधिक खतरा ऐसी ही जगहों पर होता है, जहां भीड़भाड़ अधिक रहती है और बाजार में जांच आदि के पुख्ता इंतजाम नहीं होते। आतंकवादियों और शरारती तत्त्वों के लिए ऐसी जगहों पर अपनी साजिशों को अंजाम देना और कम विस्फोटक के जरिए अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाना आसान होता है। यह ठीक है कि हर छोटी-छोटी दुकान का मालिक ग्राहकों और उनकी वस्तुओं की जांच की व्यवस्था नहीं कर सकता, मगर ऐसे इलाकों के प्रवेश द्वारों पर सरकार की तरफ से जांच के इंतजाम तो किए ही जा सकते हैं। हालांकि अक्सर देखा गया है कि जिन जगहों पर ऐसे इंतजाम हैं भी वहां जांच उपकरण ठीक ढंग से काम नहीं करते। बंगलुरु की घटना एक तरह से देश के सभी संवेदनशील शहरों में सुरक्षा इंतजाम को लेकर चेतावनी की घंटी है।

मानवीयता के विरुद्ध

दुनिया में कहीं भी युद्ध चल रहा होता है तो उसमें शामिल दोनों पक्ष एक-दूसरे को कठघरे में खड़ा करते हैं। इजराइली सीमा के भीतर घुस कर जब हमास ने हमला किया था, तब तमाम देशों ने हमास की आलोचना की थी और इजराइल ने अपने जवाबी हमले को बचाव की कोशिश बताया था। मगर उसके बाद से युद्ध जिस शक्ल में जारी है, इजराइली हमलों में गाजा पट्टी में करीब तीस हजार लोग मारे जा चुके हैं, उसे देखते हुए अब इजराइल की गतिविधियों की अनदेखी कर पाना खुद उसके पक्ष में खड़े देशों के लिए भी संभव नहीं जान पड़ रहा है। यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि घोषित तौर पर युद्ध जारी रहने के बावजूद किसी देश के सैनिक ऐसे लोगों पर हमला कर देंगे, बहुतों को मार डालेंगे, जो भूखे और लाचार खड़े कहीं से मानवीय मदद और भोजन मिल जाने की आस में थे। गुरुवार को उत्तरी गाजा में भूख का सामना कर रहे लोग मानवीय मदद पहुंचने और भोजन का इंतजार कर रहे थे, तभी इजराइली टैंकों के जरिए उन पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई, जिसमें एक सौ बारह लोग मारे गए।

इजराइली सैनिकों की इस कार्रवाई के बाद जहां अमेरिका और फ्रांस जैसे सहयोगी देश भी नाराज और दुखी हैं, ब्राजील, जर्मनी आदि कई देशों सहित संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी निंदा करते हुए इसकी जांच की मांग की है, मगर इजराइल के रुख में कोई नरमी नहीं दिख रही। भारत ने भी कहा है कि इस तरह से इतने लोगों का मारा जाना और गाजा में स्थिति 'अत्यंत चिंता' का विषय है। सवाल है कि आज क्या तमाम देशों की सहमति से तय किए गए अंतरराष्ट्रीय नियम-कानूनों पर अमल की अनिवार्यता समाप्त हो गई है कि युद्ध के दौरान किन हालात में और किन पर हमला करना है और कहां नहीं? आम लोगों, अस्पतालों, स्कूलों, शरणस्थलों जैसी कई जगहें तय की गई हैं, जिनमें विकट स्थितियों में भी हमला करने की मनाही होती है। मगर जो इजराइल अब तक फिलिस्तीन पर हमले को अपनी जवाबी कार्रवाई बताता रहा है, क्या वह भूख से लाचार लोगों पर इस तरह हुई गोलीबारी को सही ठहरा सकता है?

अर्थव्यवस्था का मानवीय चेहरा

मानवीय अर्थव्यवस्था में गरीब कल्याण, श्रमिकों के साथ बेहतर व्यवहार, सामाजिक रूप से जागरूक निवेश, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, आदि तत्त्व शामिल होते हैं।

अजय जोशी

अर्थव्यवस्था में मानवीय दृष्टिकोण की अवधारणा कार्ल मार्क्स के समय से ही अस्तित्व में है। आर्थिक विज्ञान और बाजार गतिविधियों के नैतिक आयामों का विश्लेषण करने वाले विद्वानों का मानना है कि अब भी हम अर्थव्यवस्था के मानवीय चेहरे की तलाश में हैं। मानवीय अर्थव्यवस्था में गरीब कल्याण, श्रमिकों के साथ बेहतर व्यवहार, सामाजिक रूप से जागरूक निवेश, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा आदि तत्त्व शामिल होते हैं। दिखने में यह पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का तीसरा रास्ता लग सकता है, लेकिन आज के परिवेश में यह उपयुक्त नहीं लगता, क्योंकि वास्तविक समाजवाद का पतन हो चुका है। इसलिए इसको पूंजीवाद के मानवीय चेहरे के रूप में ही देखना उपयुक्त होगा। इस दृष्टि से मानवीय गरिमा को मान्यता देना, लोगों को गरीबी से बाहर निकालना, पारिवारिक जीवन यापन के लिए एक ठोस आधार प्रदान करना और मानवीय जरूरतों के अनुरूप आवश्यक सामग्री के उत्पादन की क्षमता विकसित करने जैसी क्रियाएं जरूरी होती हैं।

देश की सरकारों ने अर्थव्यवस्था में मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (मनरेगा), बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शहरों में गरीबों और बेघरों को आवास प्रदान करने वाली योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 सहित अनेक योजनाओं के जरिए नागरिकों को विभिन्न रूपों में सुविधाएं उपलब्ध कराई। योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जीएसटी, आयकर जैसे कराधान के प्रावधान भी किए। करों के मामले में अधिकतर करदाताओं की शिकायत रहती है कि उन पर कर का बोझ अधिक है, जिससे उनको अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन में कठिनाई आती है और उनके द्वारा उत्पादित माल और सेवाओं पर लगे करों के कारण उनके महंगा होने से उपभोक्ताओं को अधिक खर्च का बोझ उठाना पड़ता है।

कराधान के मामले में कौटिल्य ने कहा था कि जनता पर कर का बोझ कम पड़े, इसलिए मधु सिद्धांत के अनुसार कर लेना चाहिए। यानी मधुमक्खी जिस तरह फूलों से रस लेकर शहद बनाती है, फूलों को नुकसान नहीं होने देती और शहद से लोगों को फायदा मिलता है, उसी प्रकार की कर व्यवस्था होनी चाहिए। आम जनता को आवश्यक सुविधाएं करदाताओं पर अनावश्यक कर का बोझ डाले बिना दी जानी चाहिए।

अर्थव्यवस्था के मानवीय चेहरे की दृष्टि से विगत वर्षों में हुए दो बड़े आंदोलनों का संदर्भ लेना समीचीन होगा। पहला, किसान आंदोलन और दूसरा, कर्मचारियों द्वारा नई पेंशन योजना की जगह पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू करने की मांग का आंदोलन। किसानों का कहना है कि खेती अब उनके लिए लाभदायक नहीं रह गई है। उनको उनकी फसलों का पर्याप्त मूल्य न मिलने से वे कर्ज में डूबते जा रहे हैं और आत्महत्या करने जैसी नौबत आ रही है, इसलिए उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी मिलनी चाहिए। वे अपनी सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी चाहते हैं। सरकार वर्तमान में 22 खरीफ और रबी फसलों पर एमएसपी दे रही है।

इनमें धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, तूर (अरहर), मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन (पीली), तिल, नाइजर-बीज और कपास शामिल हैं। इसमें आवश्यकता के अनुसार वृद्धि भी करती है।

आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि देश का कुल वार्षिक बजट

> **दोनों ही मामलों में मानवीय पहलू महत्त्वपूर्ण है। एक वर्ग जो किसान है और जिसे अन्नदाता माना जाता है और दूसरा वर्ग सरकारी कर्मचारी है, जो सारे सरकारी तंत्र की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। अगर इन दोनों वर्गों की मांगें पूरी तरह से नहीं मानी जा सकतीं, तो कुछ ऐसे उपाय तो किए ही जा सकते हैं, जिनसे अर्थतंत्र पर बुरा प्रभाव पड़े बिना इनको संतुष्ट किया जा सके। सरकार द्वारा किसानों को सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी देना संभव नहीं है, तो बातचीत से बीच का रास्ता निकाल कर अन्य तरीकों से उनकी आय बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए।**

सामान्यतया लगभग चालीस लाख करोड़ रुपए का होता है, अगर सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी दे दी जाए तो अकेले इस मद में ही सरकार को लगभग दस लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जिससे विकास के लिए अन्य मदों में खर्च के लिए बहुत कम राशि रह पाएगी। समय-समय पर एमएसपी में बढ़ोतरी से खर्च बढ़ेगा और महंगाई भी बढ़ेगी, जिसका अंततः भार करदाताओं और उपभोक्ताओं को वहन करना पड़ेगा।

केंद्र और राज्य सरकारों में जहां पर नई पेंशन योजना (एनपीएस) लागू है, वहां के लाखों कर्मचारी लंबे समय से इस योजना की जगह पुरानी पेंशन लागू करने की मांग कर रहे हैं। कई बार धरना-प्रदर्शन कर चुके हैं। कुछ राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू भी कर दिया है। पुरानी पेंशन के संबंध में भी सरकार का यही तर्क है कि सरकार पर पेंशन का बोझ बहुत बढ़ जाएगा और विकास के अन्य कार्यों हेतु धन की व्यवस्था करना कठिन हो जाएगा। आरबीआइ ने राज्यों की वित्त संबंधी रपट 2023-24 में कहा है कि आंतरिक अनुमानों के मुताबिक अगर सभी राज्य ओपीएस बहाल करते हैं, तो सरकार का वित्तीय बोझ एनपीएस की तुलना में 4.5 गुना बढ़ सकता है। ओपीएस से 2060 तक वार्षिक अतिरिक्त बोझ जीडीपी का 0.9 फीसद पहुंच जाएगा।

अनुमान है कि ओपीएस का अंतिम बैच 2040 के दशक के शुरू में सेवानिवृत्त हो जाएगा और 2060 के दशक तक लोगों को ओपीएस के तहत पेंशन मिलती रहेगी। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ओपीएस से पिछले तीन दशक में केंद्र और राज्य सरकारों की पेंशन देनदारियां कई गुना बढ़ गई हैं। वर्ष 1990-91 में केंद्र सरकार का पेंशन बिल 3,272 करोड़ रुपए था और सभी राज्यों के लिए कुल व्यय 3,131 करोड़ रुपए था। वर्ष 2020-21 तक केंद्र का बिल 58 गुना बढ़कर 1,90,886 करोड़ रुपए हो गया और राज्यों के लिए यह 125 गुना बढ़कर 3,86,001 करोड़ रुपए हो गया है और यह लगातार बढ़ रहा है। दूसरी तरफ, कर्मचारियों का तर्क है कि एनपीएस में नाममात्र की पेंशन मिलती है, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद जीवन यापन बहुत कठिन हो जाता है। ऐसे कई उदाहरण है, जिनमें कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन मात्र तीन चार सौ रुपए प्रति माह है। इसमें किसी भी तरह की बढ़ोतरी भी नहीं होती।

दोनों ही मामलों में मानवीय पहलू महत्त्वपूर्ण है। एक वर्ग जो किसान है और जिसे अन्नदाता माना जाता है, और दूसरा वर्ग सरकारी कर्मचारी है, जो सारे सरकारी तंत्र की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। अगर इन दोनों वर्गों की मांगें पूरी तरह से नहीं मानी जा सकतीं, तो कुछ ऐसे उपाय तो किए ही जा सकते हैं, जिनसे अर्थतंत्र पर बुरा प्रभाव पड़े बिना इनको संतुष्ट किया जा सके। सरकार द्वारा किसानों को सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी देना संभव नहीं है, तो बातचीत से बीच का रास्ता निकाल कर अन्य तरीकों से उनकी आय बढ़ने के प्रयास करने चाहिए। इसी प्रकार कर्मचारियों को भी पूरी तरह ओपीएस देना संभव न हो तो एनपीएस को आकर्षक बनाते हुए न्यूनतम पेंशन की गारंटी और समय-समय पर उसमें वृद्धि की व्यवस्था की जा सकती है।

सरकार ने एनपीएस में सुधार के लिए समिति गठित कर रखी है, उसे इन बातों को दृष्टिगत रखते हुए अपनी रपट देनी चाहिए। किसानों और कर्मचारियों के अलावा समाज के विभिन्न वर्गों के गरीबों और पिछड़ों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु भी प्रभावी कदम उठाए जाने जरूरी हैं, तभी अर्थव्यवस्था के मानवीय पहलू और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सार्थक हो सकती है।

दुनिया मेरे आगे

यही है सूरत-ए-हाल

सुरेश सेठ

देश में शिक्षा क्रांति के नए माडल आ गए हैं। आजकल चुनावी एजंडे में भी नई शिक्षा नीति के साथ नौजवानों की जिंदगी बदल देने के वादे किए जाते हैं। ग्रामीण अंचलों में मोबाइल टावर नहीं, लेकिन वहां इंटरनेट क्रांति का सपना दिखाया जाता है। नई शिक्षा नीति में कृत्रिम मेधा से लेकर चैट-जीपीटी और डीपफेक की बातें धड़ल्ले से की जाती हैं, लेकिन अध्यापक अपने पुराने बिंदुओं को कक्षाओं में व्यर्थ होता देखकर इस नई उपलब्धि से आंख बचाने की कोशिश करते नजर आते हैं। इसीलिए आज भी इन विद्यालय परिसरों में कला संकायों और विज्ञान की शिक्षा लेने वाले अधिक हैं। कंप्यूटर साफ्टवेयर से उन्हें परहेज है, क्योंकि अध्यापक भी इस नई विद्या पर अज्ञानता से सिर खुजाते नजर आते हैं। पुराना सूत्र है 'बिन विद्या नर पशु समान'। अब बताइए, कौन-सी विद्या?

यह साफ्टवेयर डिजिटल विद्या या वही कला, विज्ञान या पाठ्यक्रम वाली तोता-रटंत शिक्षा। बेशक देश आजाद हुआ तो शिक्षा क्रांति की घोषणा कर दी गई थी। कहा गया था कि देश में कोई पढ़े-लिखे बिना नहीं रहेगा। पढ़ाई का प्रमाण-पत्र और डिग्रियां हर बच्चे के हाथ में होंगी। वे नौकरी के लिए कतार लगा कर बरसों इंतजार नहीं करेंगे। मगर वास्तविकता यह है कि शिक्षा बदले माहौल में फिसड्डी साबित हो रही है और रोजगार दफ्तरों के बाहर धूल फांकता यौवन अब रियायती दुकानों के बाहर खड़ा है। हालात कुछ इस कदर बदले हैं कि नौजवान पढ़-लिख कर इनके नौकरी दिलाऊ दफ्तरों के चक्कर लगाने के बजाय ठेके पर विदेश भिजवाने के संदिग्ध दफ्तरों के बाहर मोर्चा जमाए हैं। नई शिक्षा नीति रोजगारपरक है, मगर लाखों लोगों ने भारतीयता छोड़ने की अर्जी दी है। केवल विशिष्ट सेवा से ही लोग एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं। शेष लोग यहां अनुकंपा की आशा में नशे की अंधी गलियों में चक्कर लगाते हैं। उधर कोई नहीं पूछता कि इतने लोग रोजी-रोटी की तलाश में अपना देश छोड़ कर दूसरे देश कैसे पहुंच गए! अवैध रूप से वहां पहुंचे लोग दोयम दर्जे के असामान्य प्रवासियों के रूप में जीवन जीने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने देश में अव्वल दर्जे का नागरिक बन जाने के लिए प्रस्तुत नहीं।

दरअसल, यहां अव्वल दर्जे का नागरिक बन कर जीने का अर्थ है रोजगार मेलों में नौकरी मांगने के लिए भटकते रहना, फिर हास्यास्पद वेतन पर काम करने के लिए हामी भरना। मनरेगा के नाम पर ऐसी दिहाड़ियों को सिर-माथे पर लेना जो नौकरी करते हुए भी भुखमरी की सौगात दे सकें। नई शिक्षा नीति से देश को रोजगारपरक तरक्की देने के निरंतर दावों के बीच यह देश भुखमरी सूचकांक में कुछ पायदान नीचे क्यों उतर गया? जो भूख से मरे, उनमें पढ़े-लिखे कितने थे और अनपढ़ कितने? भूख से आई मौत तो शिक्षित-अशिक्षित का अंतर नहीं करती। पढ़ा-लिखा काम करने के लिए न जाने कब से तैयार बैठा है और उसे कैसी सलाह दी जा रही है?

जिन शिक्षालयों में सरस्वती की पूजा होनी चाहिए, वहां पूजक नदारद होते जा रहे हैं। उनके इर्द-गिर्द 'आईलैट्स' अकादमियां कुकरमुत्तों की तरह उग आई हैं। वहां पढ़ने वालों की नहीं, विदेश भाग सकने वालों की भीड़ लगी है। ऐसे विशेषज्ञ मिल जाते हैं, जो बताते हैं कि मान्य पलायन के लिए अपेक्षित 'बैंड' न भी मिले तो भी उन्हें परदेस भिजवा दिया जाएगा। यह दीगर बात है कि अमेरिका या विलायत जाने के बजाय अरब और अफ्रीकी देशों में पहुंचा दिया जाए। चांद-सितारों को छूती अटारियां पाने की तमन्ना के साथ विदेश पलायन की होड़ लगी है, जबकि वहां पहुंचे तो छिप-छिप कर जीना पड़ता है। आखिर वहां भी सेना सहायकों के नाम पर जरूरत पड़ती रहती है। जनसंपर्क से लेकर 'ग्रीन कार्ड' की जरूरत है, लेकिन जो अपना आधार कार्ड न बचा सके, वे 'ग्रीन कार्ड' कैसे पाएं? इधर युवाशक्ति के देश के पास किंकर्त्तव्यविमूढ़ अपने नौजवान हैं। नेता कहते हैं, 'राज्यों की विलक्षणता बदली है कि अब यहां नौकरी पाने के लिए रिश्वत नहीं देनी पड़ती' और विश्व का भ्रष्टाचार सूचकांक बताता है कि भ्रष्टाचार उन्मूलन के ऊंचे नारों के बावजूद आज भी देश चिंताजनक स्तर पर खड़ा है। अब तो यह हालत हो गई है कि महंगाई बहुत हो गई है, और केवल वेतन में किसी का गुजारा नहीं होता।

> **चांद-सितारों को छूती अटारियां पाने की तमन्ना के साथ विदेश पलायन की होड़ लगी है, जबकि वहां पहुंचे तो छिप-छिप कर भी जीना पड़ता है। आखिर वहां भी सेना सहायकों के नाम पर जरूरत पड़ती रहती है। जनसंपर्क से लेकर 'ग्रीन कार्ड' की जरूरत है, लेकिन जो अपना आधार कार्ड न बचा सके, वे 'ग्रीन कार्ड' कैसे पाएं?**

नौनिहालों को इंसान बना सकने वाली शिक्षा क्रांति मुंह बिसूर कर निराश बैठी है। महामारियों ने निजी शिक्षा संस्थानों के बखिये उधेड़ दिए। भरोसा करके भारत का भविष्य छात्र-छात्राएं सस्ते सरकारी स्कूलों की ओर भागे। यहां अधिकांश प्राथमिक स्कूल आज भी वृक्षों के साये तले नामालूम इमारतों में लगते हैं। या ऐसी रंग-बदली इमारतें कि जहां विद्यार्थियों को लगे कि यह छत हमारे सिर पर अब गिरी कि तब गिरी।

चुनावी ज्वार में भिड़ते हुए राजनीतिक दल शिक्षा को लेकर 'तेरी कमीज से मेरी कमीज ज्यादा उजली है' के नारे बुलंद करते, लेकिन पढ़ाने वाले अध्यापक बरसों से ठेके पर हैं या कच्चे और अस्थायी रह कर निम्नतम वेतन पर जीते हैं। विपक्षी नेता इन्हें धीरज बंधाते हैं और शिक्षा की बदहाली को बेनकाब करते हैं। विद्यार्थियों की कुछ पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां सिर फूटने की खबरें आने लगती हैं और शिक्षा परिसर खाली होते जा रहे हैं। युवा शक्ति पारपत्रों के दफ्तरों के बाहर कतार बनाकर खड़ी है।

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

चौपाल

परीक्षा की पद्धति

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने हाल ही में कक्षा नौ से बारह के लिए 'खुली पुस्तक परीक्षा' की व्यावहारिकता की जांच करने के लिए एक पायलट अध्ययन का प्रस्ताव दिया है। यह दरअसल एक परीक्षा पैटर्न या तरीका है, जहां विद्यार्थियों को प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अपनी पुस्तकों और नोट्स का संदर्भ लेने की अनुमति होती है। कई बार कहा जाता है कि 'खुली पुस्तक परीक्षा' शुरू करने की क्या जरूरत है! रटकर याद करने से योग्यता आधारित शिक्षा की ओर परिवर्तन सुनिश्चित करता। जहां तक इस परीक्षा पद्धति की अहमियत का सवाल है, यह 'महत्त्वपूर्ण क्षमताओं' को विकसित करने में मदद कर सकता है। उन्हें कम तनावपूर्ण होने का लाभ मिलता है। यह विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों को समायोजित कर सकता है, रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान कर सकता है और सीखने के परिणामों का समर्थन कर सकता है। दूसरी ओर, इसके कुछ नुकसान भी हैं। इसमें इंटरनेट के नेटवर्क संपर्क से संबंधित मुद्दे हैं।

– रवि रंजन, नई दिल्ली

हादसों का सिलसिला

कुछ दिन पहले गंगा स्नान करने गए श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली कासगंज में तालाब में गिर गई और तेईस लोगों की मौत हो गई। अक्तूबर, 2022 में भी कानपुर जिले के घाटमपुर क्षेत्र में देवी दर्शन कर उन्नाव से लौट रहे 26 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। ट्राली पर 50 से ज्यादा लोग सवार थे। इन दुर्घटनाओं के बाद सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि आखिर जिम्मेदार कौन है? ट्रैक्टर ट्रालियों के संचालन में नियमों की कमी, अप्रशिक्षित चालकों का होना और असुरक्षित डिजाइन के कारण ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। वाहनों के पंजीकरण में कमी और निर्माण की गुणवत्ता की लापरवाही ने इस समस्या को और भी बढ़ावा दिया है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम, जैसे कि ट्रालियों का पंजीकरण केवल कृषि कार्य के लिए होना और उपज के अनुसार भारवहन क्षमता के संचालन, सुरक्षा उपायों में सुधार लाने के लिए अहम हैं। यातायात प्रशासन और पुलिस को भी योगदान करना आवश्यक है। सड़क सुरक्षा मानकों का पालन करने, चालकों को प्रशिक्षित करने और असुरक्षित वाहनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने में उन्हें सहायता करनी चाहिए।

– सुधीर कुमार, याकूबपुर, औरैया

चुनाव का समय

हाल ही में विधि आयोग ने कहा है कि वह 'एक राष्ट्र एक चुनाव' को लेकर संविधान में संशोधन करने की सिफारिश कर सकता है। हमारे देश में समय-समय पर एक साथ चुनाव करवाने को लेकर चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन इसके कई नकारात्मक पहलुओं को लेकर इस पर ठोस विचार विमर्श नहीं हो पाता था। इस बार विधि आयोग इस पर ठोस कदम उठाते हुए संविधान में संशोधन कर एक नया अध्याय जोड़ने की सिफारिश कर सकता है। भारत में 1952 से लेकर 1967 तक सभी चुनाव एक साथ हुआ करते थे, लेकिन इंदिरा गांधी के शासनकाल में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव पहली बार अलग अलग समय पर होने लगे थे।

– शाहिद हाशमी, नई दिल्ली

एकाकीपन की मुश्किल

एक समय था जब बुजुर्ग लोग ही एकाकीपन के शिकार होते थे। अब इस समस्या ने युवाओं को भी अपनी पकड़ में लेना शुरू कर दिया है। कई लोगों को मनोचिकित्सा केंद्रों पर जाना पड़ रहा है। इंसान अपनी भावनाओं को शब्दों के जरिए अभिव्यक्त करता है। परिवार में उसकी ये जरूरतें पूरी हो जाती हैं। अकेलेपन से तनाव होता है। अवसाद जैसी समस्याएं पनपने लगती हैं। विद्यालय और महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के बीच ऐसे समूह बनने चाहिए, जिनमें वे अपने मन की बात बता सकें। एकाकीपन को दूर करने के लिए अपनी दिनचर्या को ठीक रखें। अपने सोने और उठने का समय निर्धारित करें। हर व्यक्ति को स्वयं को सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ना चाहिए। अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ समय बिताने की जरूरत है। मन की बात भी बतानी चाहिए।

– राजेंद्र कुमावत, जयपुर

https://t.me/AllNewsPaperPaid

www.readwhere.com

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । मुंबई । सोमवार, 4 मार्च 2024

कांग्रेस की मुश्किल

हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनावों के दौरान हुई क्रॉसवोटिंग से उठा राजनीतिक तूफान शांत होने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस आलाकमान के भेजे विशेष प्रतिनिधियों ने तो मेल-मिलाप कराने का प्रयास किया ही, स्पीकर ने बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई भी कर दी। फिर भी कुछ है कि प्रदेश कांग्रेस में असंतोष की आग बुझ नहीं रही।

झटका झेल गई सरकार | दिलचस्प है कि सिर्फ एक राज्यसभा सीट वाले इस राज्य में ही राज्यसभा चुनावों ने सबसे ज्यादा अप्रत्याशित फैसला। कांग्रेस विधायकों की क्रॉसवोटिंग की खबर आने के बाद इसकी वजहों के रूप में गिनाए जाने वाले मुद्दों में कोई कमी नहीं रही। लेकिन सारे मुद्दे तब हल हुए मान लिए गए जब हाईकमान के विशेष प्रतिनिधि - डीके शिवकुमार और भूपिंदर सिंह हुड्डा- ने सभी पक्षों से बातचीत करके मामला सुलझाने का दावा किया। क्रॉसवोटिंग करने वाले छह कांग्रेसी विधायकों को विधानसभा सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित करने का मतलब यही था कि अब इनके वापस लौटने के कोई आसार नहीं रह गए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने यह भी कह दिया कि इन लोगों को हटा दें तब भी विधानसभा में उनकी सरकार का बहुमत कायम रहता है।

असंतुष्टों ने नहीं मानी हार

नहीं डाले हथियार | इससे साफ था कि राज्य की सुक्खू सरकार ने यह झटका बर्दाश्त कर लिया। माना गया कि बागी गुट के लिए अब एक तिहाई संख्या जुटाना मुश्किल होगा। चूंकि विधानसभा का तीन साल से ज्यादा का कार्यकाल बाकी है, इसलिए विधायक अपनी सदस्यता को खतरे में डालना पसंद नहीं करेंगे। इसके बाद स्वाभाविक ही यही अपेक्षा की जा रही थी कि अब यह मसला धीरे-धीरे शांत पड़ जाएगा। लेकिन बाद की घटनाएं बता रही हैं कि बागी गुट ने अभी तक हथियार नहीं डाले हैं।

परोक्ष धमकी | अयोग्य ठहराए जा चुके विधायकों के बयान छोड़ भी दिए जाएं तो मंत्रियों का व्यवहार भी सवाल उठा रहा है। शनिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में भी दो मंत्री शामिल नहीं हुए। उनके अलावा दो मंत्री बैठक के बीच से निकल कर आ गए। हालांकि इसकी भी अलग-अलग व्याख्याएं की जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि असंतुष्ट गुट अब भी अपने तेवर कड़े ही किए हुए है। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मीडिया में साफ कह रही हैं कि अभी तक उनका BJP से संपर्क नहीं है, लेकिन कल क्या होगा इस बारे में कुछ नहीं कह सकतीं।

लोकसभा चुनाव का एंगल | साफ है कि लोकसभा चुनाव का एंगल इस पूरे मामले को उलझाए हुए है। जहां BJP इस आग के और भड़कने में अपना फायदा देख रही है, वहीं कांग्रेस नेतृत्व दोनों पक्षों को साथ बनाए रखने की भरसक कोशिश कर रहा है। उधर, असंतुष्ट गुट को भी जोर देकर अपनी मांगें मनवाने का यही उपयुक्त मौका लग रहा है। बहरहाल, इस दिलचस्प कशमकश का आखिर नतीजा क्या निकलता है, यह देखने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा।

चक्र-व्यू

पसंद का पनवाड़ी

राहुल पाण्डेय

जिस तरह से पसंद का नाई जल्दी नहीं मिलता, वैसे ही पसंद का पनवाड़ी भी जल्दी नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि इस संसार में नाइयों की कमी है या पनवाड़ियों का टोटा है। मसलन, हमारे फैजाबाद का हनुमानगढ़ी चौराहा ही ले लीजिए। यहां और नहीं तो कम से कम आठ पान की दुकानें हैं, और लगभग इतनी ही हजामत की दुकानें भी। मगर सबकी दुकान नहीं चलती। अच्छे पान के मुरीद चूने-कत्थे की मालिश से ही समझ जाते हैं कि इसकी गिलौरी कैसी बनेगी। अच्छा पान वही है, जो मुंह में जाते ही गिलौरी बनकर सेट हो जाए। पान की गिलौरी गाल में बाईं ओर रखी है, धीमे-धीमे उससे रस निकल रहा है। कभी गिलौरी में एक डली टक से टूटती है तो कभी इलायची के दाने टूटी डली के बीच में आकर उसे खुशबू का तिलक लगाते हैं। मगर यह सब वही जान सकता है, जो पान खाता हो। आजकल पान खाने वाले तो दूर, पान खाने वाले को पहचानने वाले भी मुश्किल से मिलते हैं।

जिस तरह से अच्छे नाई की कैंची कभी खामोश नहीं होती, वैसे ही अच्छे पनवाड़ी की दुकान कभी सूनी नहीं होती। कुछेक दुकानों पर तो मैंने देखा है कि शौकीन लोग खुलने से पहले ही पहुंचे रहते हैं। और जब पान लगना शुरू हो रहा होता है, तो एकटक उसे यूं देखते हैं मानो पान नहीं, कोई अप्सरा सज रही हो। एक अच्छा पनवाड़ी बहुत अच्छे से जानता है कि शौकीन की मेनका चूना-कत्था-डली से ही नहीं सजेगी, बल्कि कुछ किवाम, कुछ ब्रास या ठंडी मीठी चटनी का भी श्रृंगार लगेगा। जिस तरह से एक अच्छा नाई अच्छे से जानता है कि आपको मशरूम कट ही पसंद है, उसी तरह एक अच्छा पनवाड़ी भी आपकी पसंद अच्छे से जानता है। वह पनवाड़ी बिलकुल अच्छा नहीं माना जाता, जो न पान के शौकीन को जानता है, और न ही उसके शौक के पान को।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली-NCR हो या मुंबई ही क्यों न हो, मैंने देखा है कि यहां लोग पान और गुटखे में भी फर्क नहीं कर पाते। किसी ने पान खा रखा है, दूर से किवाम की भीनी-भीनी खुशबू आ रही है। मुंह लाल हो रखा है। मगर यहां के लोग पूछते हैं, ये कौन सा गुटखा खा रखा है? पान खाने वाले से यह पूछना कि कौन सा गुटखा खा रखा है, उसे परम दुख देना होता है। गुटखा तो कोई भी खा सकता है। दस रुपये का पैकेट लिया, फाड़ा और मुंह में डाल लिया। हर जगह मिलता भी है। मगर पान हर जगह नहीं मिलता। इसके लिए तलाश भी करनी पड़ती है और इंतजार भी। जरूरी नहीं कि तलाश घर के पास ही पूरी हो जाए। शौकीन लोग इसके लिए कई-कई किलोमीटर चले जाते हैं। मुझे लगता है कि यही शौक हमारी संस्कृति है, जिसका ऊपर बताए लोगों से नाता कट रहा है। इन लोगों ने पान खाना नहीं सीखा। और कभी सीखा भी तो उस पर गुटखा चढ़ा दिया। यह एक सांस्कृतिक अतिक्रमण है। इसीलिए, यहां लोगों को पान खाकर संस्कृति की रक्षा करने वाले भी दस रुपल्ली के गुटखेबाज लगते हैं।

एकदा

राजकाज में स्त्री शक्ति

एक दिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से राज्य के बारे में चर्चा करते हुए कहा, 'हमें महिलाओं की दशा पर विचार करना चाहिए।' 'क्यों आचार्य? क्या समस्या है? हमारे यहां तो महिलाएं सुरक्षित हैं।', चंद्रगुप्त मौर्य बोले। आचार्य बोले, 'इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे यहां महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है, पर मैं इसे और अच्छा बनाना चाहता हूं।' 'वह कैसे?', चंद्रगुप्त ने हैरानी से पूछा। 'मैं चाहता हूं कि हर विवाहित स्त्री को यह अहसास होना चाहिए कि उसका भी अपना अलग अस्तित्व है और उसके अंदर निर्णय लेने की शक्ति है। इसलिए उन्हें हर तरह के कार्यों में शामिल करना चाहिए। समय-समय पर उनसे राजकाज की बातें भी करनी चाहिए और उनकी सलाह और शिकायतें ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। उनमें कई बार गहन मर्म रहता है।' आचार्य की बात सुनकर चंद्रगुप्त हैरत से बोले, 'आचार्य, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। भला महिलाओं को राज-काज में लाने की क्या आवश्यकता है?' चाणक्य बोले, 'महाराज! यह समझने के लिए आपको स्त्रियों से बात करनी होगी।' चंद्रगुप्त मौर्य ने उस दिन राजमाता और पत्नी से राजकाज की कुछ गंभीर बातों पर मंत्रणा की तो वे दोनों पूरी गंभीरता से इसमें शामिल हुईं और सम्राट को जरूरी सुझाव दिए। बाद में चंद्रगुप्त चाणक्य से बोले, 'आचार्य, मैंने राजमाता और पत्नी से राजकाज के कुछ गंभीर मसलों पर बातचीत की। उनकी सलाह बड़ी उपयोगी लगी मुझे।' चाणक्य बोले, 'महिलाओं की शक्ति असीमित है। उनकी दृष्टि बेहद महीन होती है और उनके अंदर एक अलग समझ होती है जो खतरे के संकेत पर जागृत हो जाती है। याद रखो अपने साम्राज्य को, इसकी पूरी जनता को प्रगति की ओर ले जाने का सबसे सरल मार्ग स्त्री है।' चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की इस बात की गंभीरता को समझा और स्त्री शक्ति के जागृत करने के लिए राजकाज में स्त्रियों का सहयोग लेना शुरू किया।

Subrata Dhar

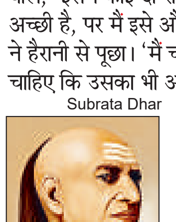

संकलन : रेनू सैनी

पांच राज्यों में विपक्षी दल मज़बूत दिख रहे हैं, लेकिन मोमेंटम BJP और सहयोगी दलों के साथ

आम चुनाव में विपक्ष के पास क्या है रास्ता

चंद्रभूषण

राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' में अब एक पखवाड़ा और बचा है। इस यात्रा के समय और इसके पीछे मौजूद राजनीतिक समझ को लेकर सवाल उठते रहे हैं। जब सारी राजनीतिक पार्टियां चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार तय करने में जुटी हैं, महीन ढंग से एक-एक संसदीय सीट के लिए रणनीति तय कर रही हैं, तब बिना किसी बड़ी अनुगूंज वाली यात्रा में जुटे रहने का क्या मतलब है?

मुद्दों की राजनीति | लेकिन इसे दूसरी तरह भी देखा जा सकता है। आज जब पूरा विपक्ष रक्षात्मक हुआ पड़ा है, हर विपक्षी नेता अपना गढ़, अपनी निजी छवि बचाने में जुटा है, तब कोई तो है जो जरूरी मुद्दों पर सरकार को कठघरे में लाने की राष्ट्रीय राजनीति कर रहा है। वैसे भी राहुल गांधी की इस यात्रा का पिछले साल की शुरुआत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली उनकी यात्रा से अलग होना तय था। इसकी शुरुआत मणिपुर से होनी थी, जहां लंबे समय से सामुदायिक हिंसा जारी है।

निर्णायक बदलाव | बीच में परिस्थितियों का एक निर्णायक बदलाव नीतीश कुमार के पाला बदलकर UPA से NDA में चले जाने के रूप में देखने को मिला। छह महीने से राहुल गांधी राज्य मशीनरी में पिछड़े तबकों की कम भागीदारी को मुद्दा बनाते आ रहे हैं। यात्रा के नाम में 'न्याय' शब्द का जुड़ना कांग्रेस पार्टी की इस बदली हुई समझ को ही जाहिर करता है।

जाति जनगणना | बहरहाल, इस प्रस्थापना की बुनियाद में नीतीश कुमार द्वारा बिहार में कराई गई जाति जनगणना थी, जिसका मोमेंटम संभालना नीतीश के दूसरी तरफ चले जाने के बाद विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ज्यादातर राजनीतिक पर्यवेक्षकों को इससे राहुल गांधी पर हंसने का एक और मौका मिल गया।

अभी भी विपक्ष के पास मौका
- BJP ने 370 सीटों का लक्ष्य रखा है
- कई राज्यों में है बराबरी का मुकाबला
- नीतीश के जाने से कमजोर हुआ विपक्ष

कांग्रेस की गलती | पिछड़ा आरक्षण के सक्रिय समर्थक दल के रूप में कांग्रेस पार्टी की पहचान कभी नहीं रही। दूसरे का उभारा मुद्दा पकड़कर लंबी छलांग लगाने की यह कोशिश किसी दिन मुंह के बल गिरेगी, इसका अंदाजा कांग्रेस के रणनीतिकारों को पहले ही हो जाना चाहिए था। खासकर तब, जब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पिछड़ा पृष्ठभूमि के मुख्यमंत्री होने के बावजूद इनके विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी हो।

सत्ता पक्ष मजबूत | यह सही है कि 2024 के आम चुनाव में जाने से ठीक पहले सत्तापक्ष ऊपरी तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। BJP ने अपने दम पर 370 सीट और सहयोगियों के साथ मिलकर 400 के पार जाने का दावा किया है। लेकिन आक्रामकता बता रही है कि जमीनी स्थिति को लेकर सरकारी खेमे में उतनी आश्वस्ति नहीं है।

युवाओं में बेरोजगारी | 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने को सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रचारित कर रही है, लेकिन यह हकीकत अपनी जगह है कि काम-धंधे के नाम पर बहुत सारे लोगों के पास आज कुछ भी नहीं है। नौजवानों में बेरोजगारी 25 फीसदी होने की बात चर्चा में नहीं आ पा रही है। मध्यवर्ग को एक अर्से से नई पीढ़ी के सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की अच्छी पगार का भरोसा रहा है, लेकिन यह सेक्टर भी सुस्ती के दौर से गुजर रहा है।

AI Image

विपक्ष कहां मजबूत | चुनावी माहौल के हिसाब से देखें तो भारत के आधे हिस्से में, यानी पांचों दक्षिण भारतीय राज्यों के अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आम चुनाव से ठीक पहले विपक्ष का पलड़ा या तो भारी है या मामला बराबरी का जान पड़ता है।

मोमेंटम सत्ता पक्ष के पास | बाकी राज्यों में सत्तापक्ष यकीनन मजबूत है और सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकल मोमेंटम उसके साथ है। यह मतदान के दिन तक ऐसा ही बना रहा तो विपक्ष के मजबूत राज्यों में भी बहुत सारी सीटें उसके हाथ से निकल जाएंगी। लेकिन अगले एक महीने के अंदर विपक्ष अपने साझा राजनीतिक अभियान से कुछ जमीनी मुद्दे उठा सका तो ऐन मौके पर चुनाव में ठीकठाक जान पड़ सकती है।

पाला बदलने का खेल | सत्तापक्ष की खासियत यह है कि पिछले छह महीने में उसने विपक्षी नेताओं को एक दिन भी चैन की सांस नहीं लेने दी है। कांग्रेस पार्टी और क्षेत्रीय विपक्षी दलों की असुरक्षित, महत्वाकांक्षी दूसरी-तीसरी कतारों की ओर से उसे इसके लिए भरपूर मौका भी मिला है। आरोप लगते रहे हैं कि विपक्ष के इस भुरभुरेपन के लिए इन पार्टियों की अति केंद्रित परिवारवादी राजनीति जिम्मेदार है। लेकिन किसी सांसद, विधायक या पूर्व मंत्री को अगर अपना आगे का रास्ता अवरुद्ध दिखा, तो उसकी पार्टी और आइडियॉलजी कितनी भी अच्छी क्यों न हो, इतने लंबे इंतजार के बाद पहला बुलावा मिलते ही वह दूसरे पाले में चला जाएगा।

अवसरवादी राजनीति | इस स्थिति के लिए कुछ हद तक भारतीय राजनीति में व्याप्त वैचारिक अवसरवाद भी जिम्मेदार है। धर्मनिरपेक्षता और अपनी शक्ति भर कमजोर तबकों के साथ खड़े रहना मुख्यधारा के ज्यादातर राजनेताओं के लिए जुबानी जमाखर्च तक ही सीमित रहा है। पूरी जिंदगी जिसने राजनीति से कुछ पाना ही सीखा हो, इसके लिए कुछ खोना, कोई कष्ट बर्दाश्त करना जिसकी कल्पना से भी परे हो, वह सत्ताधारी राजनीति के सामने दस साल टिक गया, यह बहुत बड़ी बात है। आगे टिकट लेकर भी वह पाला बदल सकता है।

आंकड़े भरोसेमंद नहीं | भारत जैसे उभरते हुए लोकतंत्र के लिए निश्चित रूप से यह परीक्षा की घड़ी है। विपक्ष की अनुपस्थिति में लोग एक सम्मोहन जैसी स्थिति में जी रहे हैं। एक समय था जब सांख्यिकी के मामले में भारत इतना मजबूत था कि सारे नव-स्वतंत्र देश इसके गुर सीखने के लिए यहां अपने विशेषज्ञ भेजते थे। चीनी प्रधानमंत्री चाओ एनलाई ने 1955 के आसपास 'ऐक्शनेबल स्टैटिस्टिक्स' जुटाने के तरीके समझने के लिए कोलकाता में एक हफ्ता लगाया था। लेकिन आज हालत यह है कि भारत का कोई सरकारी आंकड़ा भरोसेमंद नहीं है।

नीति आयोग को उसके गठन के समय योजना आयोग से इस मामले में अलग बताया गया था कि गरीबी के आंकड़े जुटाना और गरीबी रेखा तय करना उसका काम नहीं है। पर 'भारत में गरीबी लगभग समाप्त हो चुकी है', यह ज्ञान दुनिया को उसी से प्राप्त हुआ।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

बहुत हसीन हैं पांव, ज़मीन पर ज़रूर रखिए

एक टापू पर दो जूता कंपनियों के सेल्समैन उतरे। टापू दुनिया की नजर से दूर था और वहां के लोग आधुनिकता से अनजान। जो सेल्समैन पहले पहुंचा, वह देखकर निराश हो गया कि लोग तो नंगे पांव रहते हैं। उसने अपनी कंपनी में संदेश भिजवाया कि यहां कोई जूता नहीं पहनता, हमारे लिए कोई स्कोप नहीं है। वहीं, जब दूसरे सेल्समैन का सामना होता है स्थानीय लोगों से, तो वह अपनी कंपनी से अति उत्साह में कहता है, 'किसी के पास जूता नहीं है यहां। तुरंत जहाज भरकर माल भेजो।'

इस कहानी को अभी तक मार्केटिंग के नजरिये से ही सुनाया गया है और दूसरे वाले सेल्समैन को प्रस्तुत किया गया एक उदाहरण के रूप में। उसकी ओर इशारा करके सीख दी गई कि देखो, मौके तो हर जगह होते हैं, बस पहचान करना आना चाहिए। चलिए, मान लेते हैं इसे। लेकिन, अगर उस टापू के लोग वाकई नंगे पैर ही रहना चाहते हों तो? आखिर नंगे पांव घूमने में क्या बुराई है?

मार्केटिंग का ही कमाल है कि उसने जूते-चप्पलों के बीच भी फूट डाल दी है। ऑफिस का जूता पार्टी में नहीं जा सकता, बाहर की स्लिपर घर के अंदर नहीं आ सकती और बाथरूम की चप्पलों ने अगर कमरे में कदम रखा तो खैर नहीं। लेकिन कभी पांवों से पूछा नहीं गया गया कि उनकी हसरत क्या है, कहीं वो आजाद तो नहीं रहना चाहते?

आजादी सभी को चाहिए और जब बात पैरों की हो, तो उसका मतलब होता है वातावरण के साथ गहरा नाता जोड़ना। नंगे पैर अहसास कराते हैं मिट्टी का, रेत का, घास की हरी-हरी चादर का और उस पर पड़ी ओस का। जूतों के लिए तो हर रास्ता एक होता है, ये पैर महसूस करते हैं कि जमीन समतल है या खुरदुरी, और रास्ता कितना मुश्किल या आसान होने वाला है। पैर नंगे हों, तो

AI Image

जीवन आनंद

ही अनुभव करते हैं ठंडी और गर्म हवाओं को, गड्ढों में भरे बारिश के पानी को और पतझड़ से टूटे पत्तों की चरमराहट को। वे संवाद करते हैं प्रकृति के साथ। महसूस करते हैं धरती को और संदेश पहुंचाते हैं हम तक। यूं इन्हें कैद करना अपना एक जरिया बंद कर देना है।

बड़े-बुजुर्ग कह गए हैं कि पांव हमेशा जमीन पर रहने चाहिए। बात ठीक भी है। पैरों के बंधन नजरिया बदल देते हैं सोचने और समझने का। लेकिन, अगर बंधन टूट जाएं तो दुनिया उसी तरह से दिखती है, जैसी वह है। मेडिटेशन का एक प्रकार है माइंडफुलनेस। इसका मतलब होता है कि आसपास जो जैसा है, जो जैसा घट रहा है, उसे बिल्कुल उसी तरह महसूस करना, उसके बारे में जागरूक होना और ध्यान केंद्रित करना। नंगे पैर इसी माइंडफुलनेस की ओर ले जाते हैं। चैतन्य बनाते हैं। भावनाओं को काबू में करना सिखाते हैं। दिमाग शांत होता है, तो दिल में सुकून रहता है। नींद चैन भरी और गहरी आती है।

इस तरह चहलकदमी के कुछ फायदे स्वास्थ्य से भी जुड़े हैं। कुछ स्टडी का कहना है कि इससे ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, नेगेटिविटी कम होती है, थकान घटती है। बॉडी का बैलेंस सुधरता है। पैरों की मांसपेशियां मजबूत और चुस्त बनती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि धरती के इलेक्ट्रिकल चार्ज हमारे शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रल कर देते हैं। इससे स्वास्थ्य बेहतर रहता है। लेकिन, धरती की इस खासियत का फायदा उठाने के लिए शरीर का सीधा संपर्क होना चाहिए जमीन से और ऐसा तब आसानी से हो जाता है जब पांव नंगे हों।

जूते पहनकर समाज से मिला जाता है और नंगे पांव ईश्वर से। इसीलिए शायद महान लेखक खलील जिब्रान याद दिला गए हैं कि, 'पृथ्वी तुम्हारे नंगे पैरों को महसूस करके प्रसन्न होती है और हवाएं तुम्हारे बालों से खेलने के लिए उत्सुक रहती हैं।' और उनके कई बरस बाद फिल्म 'पाकीजा' में राजकुमार कहते हैं कि पांव बहुत हसीन हैं, जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। वह मीना कुमारी को सलाह दे सकते थे कि इन हसीन पांवों में जूती डालकर ही नीचे उतरिएगा। आखिर तब तो मैले होने का खतरा नहीं रहता। लेकिन, उन्होंने ऐसी कोई सलाह नहीं दी क्योंकि तब पांवों की खूबसूरती कहां दिखती।

शेयर करें अपने अनुभव

जीवन की दिनचर्या के अनुभवों में आप कैसे आनंद महसूस करते हैं, हमें बताएं nbtreader@timesgroup.com पर, और सब्जेक्ट में लिखें- **'जीवन आनंद'**

महिलाओं से यहां भी होता है भेदभाव

मृत्युंजय राय

मां को जब बुखार होता तो उसका असर परिवार के किसी अन्य सदस्य के रूटीन पर नहीं पड़ने देतीं। तय समय पर परिवार के सभी सदस्यों को नाश्ता, स्कूल के लिए टिफिन और पिता का ऑफिस के लिए लंच पैक करतीं। पिता अगर कहते कि डॉक्टर के पास चलो, तो कहतीं- बुखार ही तो है, ठीक हो जाएगा। क्रोसिन की गोली ले लेती हूं।

अक्सर घरों में मां, बहन और पत्नियां यही करती हैं। वे इस बात को लेकर कुछ ज्यादा ही सचेत रहती हैं कि उनकी बीमारी से परिवार के रूटीन पर फर्क न पड़े। अपनी बीमारी को लेकर उनके अंदर मानो शर्मिंदगी हो। अमेरिकी डॉक्टर एलिजाबेथ कॉमेन (Elizabeth Comen) ने **'All in Her Head: The Truth and Lies Early Medicine Taught Us About Women's Bodies and Why It Matters Today'** नाम की किताब में इसी विषय को उठाया है। वह ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और करीब दो दशक का तजुर्बा रखती हैं। डॉ. कॉमेन लिखती हैं कि इलाज के लिए आने वाली महिलाएं उनसे बेवजह माफी मांगती हैं। कई बार ऐसी वजहों को लेकर, जिनका कोई तुक नहीं बनता। मसलन, अगर उन्हें पसीना अधिक हो रहा हो तो माफी मांगती हैं। डॉक्टर से अपनी बीमारी से जुड़े सवाल करने को लेकर माफी मांगती हैं। वे इस बात पर भी डॉक्टर की माफी चाहती हैं कि क्यों वे खुद ही कैंसर का पता पहले नहीं लगा पाईं।

AI Image

विचार विंडो

किताब में डॉ. कॉमेन ने इस सवाल का जवाब दिया है कि औरतें ऐसा करती क्यों हैं? वह इसके लिए मेडिकल बिरादरी को कसूरवार मानती हैं। वह लिखती हैं कि अतीत में औरतों को उनके शरीर पर शर्मिंदा किया गया। डॉ. कॉमेन का कहना है कि महिला मरीजों की लाइफ आज भी इससे प्रभावित हो रही है। वह लिखती हैं कि अव्वल तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में हार्ट और कुछ तरह के कैंसर का पता लगाने में अधिक वक्त लगता है।

दूसरी बात यह है कि महिलाओं के मामले में गलत डायग्नोसिस की आशंका भी अधिक होती है क्योंकि इसके लिए पुरुष मरीजों वाले मानतंड अपनाए जाते हैं। वह बताती हैं कि कई बार औरतों को पेनकिलर तक लिखने से डॉक्टर हिचकते हैं। वे दर्द या बीमारी को उनकी एंग्जाइटी बता देते हैं या कहते हैं कि यह सब उनके दिमाग का वहम है। डॉ. कॉमेन लिखती हैं कि यह औरतों का 'डिफॉल्ट डायग्नोसिस' है।

अतीत में औरतों पर जो अन्याय हुए हैं, इसी वजह से आज कई महिलाएं जब इलाज कराने डॉक्टर के पास जाती हैं तो वहां उसके बारे में बात करने में वे शर्मिंदगी महसूस करती हैं। मेडिकल सिस्टम एक तरह के स्त्री-द्वेष से ग्रस्त रहा है और डॉ. कॉमेन के मुताबिक, यह अपने आप में बड़ी बीमारी है।

'All in Her Head,' में डॉ. कॉमेन बताती हैं कि सदियों तक इलाज करने वालों का यही मानना था- 'औरतें असल में छोटे कद के पुरुष हैं। जिनके पास बस मर्दों की तरह एक्सटर्नल जेनाइटल्स और दिमाग नहीं है।' कई बीमारियों को तो वह हार्मोन का असर बताकर इग्नोर कर देते थे।

अमेरिका के संदर्भ में डॉ. कॉमेन लिखती हैं कि ऐसा सलूक तो वहां की श्वेत महिलाओं के साथ हो रहा था, फिर अश्वेत और गरीब औरतों को तो डॉक्टर्स और भी नीची नजरों से देखा करते थे। शुक्र है कि वक्त के साथ औरतों के डायग्नोसिस को लेकर हालात बेहतर हुए हैं। वह बताती हैं कि अपने शरीर को मरीज कहीं बेहतर समझता है। इसलिए महिलाएं जब इलाज कराने जाएं तो अपनी बात अधिकार के साथ डॉक्टर के सामने रखें। डॉ. कॉमेन सलाह देती हैं- डॉक्टर के पास जाने से पहले खुद से सवाल करें कि शरीर का कौन सा हिस्सा आपको परेशान कर रहा है। अगर लगता है कि डॉक्टर आपकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है तो किसी दोस्त या परिवार के किसी सदस्य को लेकर अगली बार उसके पास जाएं। उसकी मदद से महिलाएं अपनी समस्या के बारे में डॉक्टर को साधिकार बता सकती हैं। आखिर में डॉ. कॉमेन की सलाह है कि इतना सब करने के बाद भी अगर डॉक्टर पसंद न आए तो उसे बदलने में ही भलाई है। आखिर, भरोसेमंद डॉक्टर से इलाज कराना हर पेशंट का अधिकार है।

आगे बढ़ें लड़कियां

प्रणव प्रियदर्शी

शालिनी अरोड़ा बैंकिंग और बीमा होल्डिंग कंपनी नैटवेस्ट में एवरीडे बैंकिंग टेक्नॉलजी विंग (इंडिया) की हेड हैं। उनकी अपनी ग्रोथ स्टोरी भी खासी इंस्पायरिंग है, लेकिन बात उनकी सोच की करें तो उसमें ज्यादा जोर इस बात पर दिखता है कि लड़कियां आगे बढ़ें। उनके मुताबिक इसके लिए न सिर्फ लड़कियों को अपने स्तर पर निरंतर प्रयास करना होगा बल्कि खुद इंडस्ट्री को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि उसमें लड़कियों के आने और आगे बढ़ने लायक स्पेस और माहौल बना रहे। वह मानती हैं कि पर्सनल अचीवमेंट और उससे उपजा संतुष्टि का अहसास उनके लिए भी अहम है, लेकिन जब बात पूरी इंडस्ट्री की हो, आधी दुनिया की हो तो किसी एक शख्स के पर्सनल अचीवमेंट पर ज्यादा जोर देने से सही संदेश नहीं जाता। मिसाल के तौर पर, वह ध्यान दिलाती हैं कि मौजूदा दौर में टेक्नॉलजी लगातार विकसित हो रही है जिससे नई-नई फील्ड और एप्लिकेशंस सामने आ रहे हैं। जाहिर है, ऐसे में अलग-अलग तरह के पर्सपेक्टिव और स्किलसेट इंडस्ट्री के विकास की शर्त बन जाते हैं। महिलाओं का इंडस्ट्री में होना, बल्कि अग्रणी भूमिकाओं में होना इसी बिंदु पर अहम साबित होता है। एंपैथी और ऐसी ही अन्य पर्सनल क्वॉलिटीज की बदौलत महिलाएं कंपनी में दूसरी टीमों के साथ सहयोग कर प्रक्रिया को आसान और सहज बनाती हैं। इसका फायदा उस कंपनी को ही नहीं, पूरी इंडस्ट्री को इस रूप में मिलता है कि नए-नए आइडियाज जेनरेट होते रहते हैं और उन पर सही ढंग से अमल भी होता रहता है। गड़बड़ यह है कि STEM (साइंस, टेक्नॉलजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स) वर्कफोर्स में महिलाओं की मौजूदगी वैसे ही कम है और जो थोड़ी-बहुत कसर रह जाती है, पैट्रिआर्की से जुड़े पूर्वाग्रह उसे भी पूरा कर देते हैं। इसीलिए बकौल शालिनी यह जरूरी हो जाता है कि महिलाओं की क्षमता पर सवाल उठाने वाले पूर्वाग्रहों से लड़ा जाए। वह कहती हैं कि सभी महिलाओं को मेरा सुझाव यही है कि स्टीरियोटाइप्स को चुनौती देती रहें, अपनी व्यक्तिगत क्षमता को बढ़ाती रहें और इस बात को समझती रहें कि ऐसा करना सिर्फ उनकी अपनी ग्रोथ के लिए नहीं बल्कि इंडस्ट्री और समाज के ओवरऑल ग्रोथ को सुनिश्चित करने के लिए भी जरूरी है।

शालिनी अरोड़ा

आधी दुनिया

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ जन साक्षरता अभियान

महोदय, 29 फरवरी को प्रकाशित 'साक्षरता का मतलब सिर्फ दस्तखत करना नहीं' लेख पढ़ा। साक्षरता एक मौलिक मानव अधिकार है। यह साक्षरता कार्यक्रम हमारी तत्कालिक सरकार द्वारा चलाया गया एक महत्वकांक्षी और दूरदर्शी योजना है। यह एक ऐसी मुहिम है जो सीखने के पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देती है। इसमें बुनियादी शिक्षा के साथ-साथ वृक्षारोपण अभियान, पर्यावरण संबंधी जागरूकता और स्वच्छता अभियान को भी शामिल किया गया है। देश के नागरिकों के उज्ज्वल भविष्य के साथ ही उन्हें सशक्त नागरिक बनाने की दिशा में साक्षरता अभियान जरूरी तो है, उससे कहीं अधिक यह एक जन आंदोलन भी है। साक्षरता पहल को मजबूत करने के लिए सरकार अब संचार साधनों का सहयोग भी ले रही है, समाज के लोगों को भी इस अभियान को सफल बनाने में योगदान देना होगा।

- दीपा सिन्हा (मुंबई), ईमेल से

■ विपक्ष मौन क्यों है

संदेशखाली के अपराधी को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन जो पुलिस इतने मामले दर्ज होने के बाद भी उस अपराधी को पकड़ नहीं कर पाई, हिन्दू पीड़ित महिलाओं द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के बावजूद भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका, उस आरोपी से अब वही पुलिस सख्ती से राज कैसे उगलवा सकती है। महिलाओं के यौन शोषण पर मुख्यमंत्री ममता के साथ विपक्ष की चुप्पी भी अपराधियों के हौसले बढ़ानेवाली है। राज्य सरकार की जगह केंद्रीय जांच एजेंसी ही आरोपी को सजा व पीड़ितों को न्याय दिलवा सकती है।

- सुधा चौबे (मुंबई), ईमेल से

■ कड़ा मैकेनिज्म करें तैयार

देश के राजनीतिक दल खुद में सुधार लाने को तैयार नहीं हैं, विपक्ष ने भी जनता को निराश ही किया है। देश की राजनीति में नेताओं के दोहरे कैरेक्टर नजर आते हैं, जो सुविधा और सत्ता से अपने को दूर नहीं कर पा रहे हैं। चुनाव आयोग की सिफारिशों व अदालतों के निर्देशों का दागी-बागी और भ्रष्टाचारी नेताओं पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। दागी नेताओं और दलबदल कानून को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन है, लेकिन इन मामलों में केंद्रीय चुनाव आयोग की भूमिका लचर नजर आती है। ऐसे में निष्पक्ष चुनाव और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के साथ ही जनादेश का मान रखने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग और देश की सर्वोच्च अदालत को कड़ा मैकेनिज्म तैयार करने की सख्त जरूरत है। राजनीतिक शूचिता को बरकरार रखने के लिए लोगों की नजरें केंद्रीय चुनाव आयोग और सर्वोच्च अदालत पर ही टिकी हुई हैं।

-अंजनी कुमार दाधीच (मुंबई), ईमेल से

nbtedit@timesgroup.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

खबर: मोदी के सामने नीतीश ने कहा, हम आपके साथ ही हैं।

टिप्पणी: अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे।

- सुधीर अग्रवाल, ईमेल से

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

hindi.speakingtree.in

राधिका ने अनंत कृष्ण को प्रबल वेग से नृत्य करके पाया

सुरक्षित गोस्वामी

हमारे सबसे निकटतम कोई है तो वह परमात्मा है और अगर सबसे दूर कोई है, तो वह भी परमात्मा ही है। जब परमात्मा को पाने का प्रबल भाव प्रकट हो जाए, तब परमात्मा अंग-संग प्रकट हो जाते हैं, अन्यथा परम तत्व कभी भी हमारी अनुभूति में नहीं आ पाता। हम परमात्मा की चर्चा कर सकते हैं लेकिन चर्चा से उन्हें आत्मसात नहीं कर सकते। परमात्मा को पाने के अहंकार में कोई धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं, पर उससे परमात्मा नहीं मिल सकेंगे। परमात्मा को तो अहंकार के नाश से ही पाया जा सकता है। उन्हें भीतर अनुभव करने के लिए समर्पित साधना चाहिए। साधना भी कोई ऐसी-वैसी नहीं, बल्कि प्रबल वेग से भरी साधना! परमात्मा को पाने के लिए इस प्रबल वेग को अपने अंदर जगाना होता है। इसके लिए अलग-अलग साधकों ने अनेक मार्ग खोजे।

नृत्य भी परमात्मा को पाने का एक अनूठा मार्ग है। परमात्मा को पाने के लिए जब अपनी सुध-बुध खोकर नृत्य किया जाता है तो इस अवस्था में मैं, मेरा और मेरे वालों की आसक्ति का भाव टूट जाता है, जिससे साधक का चित्त शुद्ध हो जाता है। अब साधक उस दिव्यता के साथ एक हो जाना चाहता है! उसका यह नृत्य ब्रह्मांडीय नृत्य के साथ एकाकार होने लगता है। साधक के शरीर की ऊर्जा, प्रकृति की ऊर्जा से एक हो जाती है। उसकी आत्मा का योग परम आत्मा से हो जाता है। तब साधक परमसत्ता के साथ एक होकर उस परमात्मा को अपने भीतर ही पा लेता है। महारास में भी कृष्ण को केंद्र मानकर सभी गोपियां जब नृत्य करती हैं तब प्रत्येक गोपी कृष्ण को अपने अंग-संग अनुभव करने लगती है। इसलिए महारास प्रकृति और पुरुष के एक हो जाने का नृत्य है।

भक्ति योग में भगवान को पाने का नृत्य एक सरल उपाय है, जहां प्रियतम परमात्मा हो जाते हैं और साधक सखी बन जाता है। राधिका ने भी अनंत कृष्ण को नृत्य से ही पाया है। मीरा ने अपना आप भुलाकर घुंघरू बांधकर गली-गली नाच-गाकर कृष्ण को पाया है। चैतन्य महाप्रभु ने प्रभु का संकीर्तन भरा नृत्य कर प्रभु के साथ एकाकार होकर परमात्मा को पाया। ज्ञानियों ने परमतत्व ईशा को ज्ञान से पाया तो सूफियों ने whirling करके पाया। बुद्ध ने ध्यान से पाया। Christ वालों ने कष्ट सहने की सहनशक्ति बढ़ाकर परमात्मा को पाया। राम भक्तों ने मर्यादित होकर राम को पाया तो कबीर ने निर्गुण भक्ति से निराकार को पाया। गुरु ग्रंथ साहिब वालों ने अनेक पैगंबरों की वाणी के रस को निचोड़ कर पिया और एक ओंकार को पाया! ऐसे ही अर्जुन ने रसहीन संघर्ष को साधकर और संघर्ष से ऊपर उठकर रस से परिपूर्ण पुरुषार्थ करके कृष्ण को पाया। जनक ने राजपाट करते हुए गुरु के चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त कर परमात्मा को पाया। जैनियों ने तप से, नचिकेता ने तीव्र इच्छा से, निष्कामियों ने ज्ञान देकर, योगियों ने योग रमा कर परमात्मा को पाया है।

परमात्मा को पाना कठिन नहीं है, बल्कि उसको पाने के लिए हमारे अंतरतम में प्रबल वेग का होना कठिन होता है, क्योंकि चंचल मन हमारे भीतर प्रबल वेग को लाने नहीं देता। साधना में इसी चंचल मन को साधा जाता है। साधना का तरीका अलग-अलग हो सकता है, पर जिस पल वह प्रबल वेग हमारे भीतर जाग गया, उसी पल परमात्मा हमारे सबसे नजदीक हो जाते हैं।

आर.एन.आई. पंजीयन नंबर 1613/1957 स्वत्वाधिकारी बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के लिए आर. कृष्णमूर्ति द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 से प्रकाशित और उनके द्वारा (1) टाइम्स ऑफ इंडिया सबर्बन प्रेस, आकुर्ली रोड, निकट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, कांदिवली (पू.) मुंबई 400101 एवं (2) टाइम्स ऑफ इंडिया प्रिंट सिटी, प्लॉट नं. 4, टी.टी.सी. इंडस्ट्रियल एरिया, ठाणे बेलापुर रोड, ऐरोली, नवी मुंबई-400708. फोन नं. (022) 2760 9999 ; फैक्सः (022) 2760 5275। फोन मुंबईः (022) 66353535, 22733535 रेस्पांसः (022) 66353636, 22733636 फैक्सः (022) 22731889, 22731144, कांदिवली (022) 28872324 से मुद्रित। स्थानीय संपादक (मुंबई) : सुंदर चंद ठाकुर (पी. आर. बी. अधिनियम के अंतर्गत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी) सर्वाधिकार सुरक्षित। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। सड़क व रेल परिवहन सेवा शुल्कः मुंबई, ठाणे व रायगड जिलों के बाहर 1.00 रुपया। विमान सेवा शुल्कः रायपुर, नागपुर, गोवा एवं वाया 2.00 रुपये, इंदौर, चेन्नै एवं वाया 3.00 रुपये, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोचीन, कोयम्बतूर, एरनाकुलम, हैदराबाद, कोझीकोड, मंगलूर, त्रिवेंद्रम, उदयपुर, वाइजग एवं वाया 4.00 रुपये, दिल्ली, कोलकाता, एवं वाया 5.00 रुपये।

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

संस्थापक: शहीद शिरोमणि लाला जगतनारायण जी, अमर शहीद रमेश चन्द्र जी एवं कलम के योद्धा अश्विनी कुमार जी

फिर शर्मसार हुआ भारत

विदेश से भारत घूमने आई स्पेन की महिला के साथ गैंगरेप की घटना ने एक बार फिर भारत को शर्मसार किया है। महिला अपने पति के साथ झारखंड के दुमका पहुंची थी कि हैवानियत की हदें पार करते हुए 8-10 लोगों ने उसके साथ दरिन्दगी की। पीड़ित महिला अपने पति के साथ बाइक चलाते हुए दुमका अस्पताल पहुंची और खुद पुलिस को सूचित किया। यद्यपि पुलिस ने इस संबंध में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है लेकिन दुष्कर्म मामले ने भारत की छवि अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर खराब की है जो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत में विदेशी पर्यटक महिलाओं से दुष्कर्म की घटनाएं कोई नई नहीं हैं। भारत की छवि दुनियाभर में रेप कैपिटल की बन चुकी है और अब विदेश में रहने वाले लोग भारत को महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं मानते। भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव: यानि अतिथि को देव का दर्जा दिया गया है। अगर विदेशी महिला पर्यटकों से दुष्कर्म की घटनाएं होती रहीं तो इससे विदेशी पर्यटकों का भारत आना कम हो जाएगा और पर्यटन उद्योग को काफी नुक्सान होगा।

नैशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की 2023-24 की रिपोर्ट बताती है कि देश में बलात्कार के मामलों में इजाफा हुआ है। उदाहरण के लिए राजधानी दिल्ली को ही लेते हैं। ताजा आंकड़े दिल्ली को भारत के 19 बड़े शहरों में से सबसे असुरक्षित बता रहे हैं। निर्भया के साथ 16 दिसम्बर, 2012 को गुजरी वो खौफनाक रात आज भी इस तारीख के नाम से सिहरन पैदा करती है। सिर्फ 16 दिसम्बर ही क्यों? बेटियों के साथ रेप के बाद निर्भय हत्याओं का अंतहीन सिलसिला पहले की तरह जारी है। विदेशी पर्यटक महिलाएं तो साहसी हैं जो न्याय के लिए लड़ना जानती हैं। गोवा में 2008 में स्कॉरलैट रेप और किलिंग की घटना के बाद उसके परिजनों ने दोषियों को दंडित कराने के लिए भारत आकर कानून का सहारा लिया। कई मामलों में दोषियों को सजाएं भी हुई हैं। रेप मामलों में जमीनी हकीकत सरकारी आंकड़ों से अलग होती है क्योंकि हालात ऐसे हैं कि रेप के बाद परिजन अगर एफआईआर दर्ज कराना भी चाहते हैं तो उन्हें धमकियां दी जाती हैं। गांव और छोटे शहरों के मामलों को लोकलाज की वजह से छुपाया जाता है। केस दर्ज ही नहीं होता। जब मामलों का ऑफिशियल कोई रिकार्ड ही नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं कि अन्य देशों की तुलना में भारत में लड़कियां और महिलाएं सुरक्षित हैं। बेशक 8 मार्च को भारत में भी विश्व महिला दिवस मनाया जाएगा। लम्बे-चौड़े भाषण दिए जाएंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण का ढिंढोरा पीटा जाएगा। जब रोजाना हैवानियत की हदें लांघी जाएंगी और महिलाओं की अस्मिता का जनाजा निकाला जाएगा तो ऐसे दिवस मनाने की कोई सार्थकता नहीं होगी।

आज बाबुल की गलियां ही नरक बन गई हैं। अपने रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। बहू-बेटियां घर में ही असुरक्षित हैं, समय- समय पर ऐसे घिनौने कर्म होते हैं कि कायनात कांप उठती है कि आदमी इतने नीच काम क्यों कर रहा है। महिलाएं कहीं भी महफूज नहीं हैं। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। देश में प्रतिदिन घटित हो रही वारदातों से महिलाओं की सुरक्षा पर प्रश्नचिन्ह लगता जा रहा है कि महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। इन वारदातों से हर भारतीय उद्वेलित है। सुरक्षा के दावों की पोल खुल गई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इतंजाम करने होंगे तभी इन पर रोक लग सकती है। जघन्य व दिल दहला देने वाली दुष्कर्म की घटनाओं से जनमानस खौफजदा है।

आज बाबुल की गलियां ही नरक बन गई हैं। अपने रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। बहू-बेटियां घर में ही असुरक्षित हैं, समय- समय पर ऐसे घिनौने कर्म होते हैं कि कायनात कांप उठती है कि आदमी इतने नीच काम क्यों कर रहा है। महिलाएं कहीं भी महफूज नहीं हैं। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। देश में प्रतिदिन घटित हो रही वारदातों से महिलाओं की सुरक्षा पर प्रश्नचिन्ह लगता जा रहा है कि महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। इन वारदातों से हर भारतीय उद्वेलित है। सुरक्षा के दावों की पोल खुल गई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इतंजाम करने होंगे तभी इन पर रोक लग सकती है। जघन्य व दिल दहला देने वाली दुष्कर्म की घटनाओं से जनमानस खौफजदा है। आखिर कब तक बेटियां दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी। ऐसी वारदातें बहुत ही चिंतनीय हैं। बेखौफ दरिंदें अराजकता फैला रहे हैं। दरिंदों की दरिंदगी की वारदातें कब रुकेंगी, अपराध की तारीख बदल जाती है मगर तस्वीर नहीं बदलती।

कानून को धत्ता बताकर दरिंदे दरिंदगी का तांडव कर रहे हैं। ऐसे दुष्कर्म सामाजिक मूल्यों का पतन दर्शाते हैं कि समाज में विकृत मानसिकता के लोगों का बोलबाला होता जा रहा है। इन मामलों से इन्सानियत तार-तार हो रही है। समाज को ऐसे आपराधिक प्रवृति के लोगों की पहचान करनी होगी। यदि अब भी समाज के लोगों ने इन दरिंदों को सबक नहीं सिखाया तो फिर से कोई और लड़कियां व महिलाएं दरिंदों की दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी। अब समाज को जागना होगा, दरिंदों का खात्मा करना होगा। कानून के रखवालों को भी समाज में घटित इन हादसों पर गहराई से चिंतन करना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे प्रकरणों पर विराम लग सके। ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत करना चाहिए। अगर यह प्रवृति बढ़ गई तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। पुलिस को भी अपने कर्त्तव्य का निर्वाह करना होगा ताकि पुलिस की छवि बरकरार रहे और समाज में ऐसे हादसे रुक सके। केंद्र सरकार को भी इन हादसों को बिना समय गंवाए रोकने के लिए कारगर कदम उठाने चाहिए ताकि देश में ऐसी वारदातों की पुनरावृति न हो सके। इनका नामोनिशन मिटाना होगा तभी बहू-बेटियां बेखौफ होकर घूम सकती हैं। हालातों को देखते हुए सरकार को प्राथमिक स्कूलों से लेकर कालेज स्तर तक की लड़कियों को आत्म रक्षा के गुर सिखाने होंगे ताकि दुरिंदों को सबक मिल सके। रेप कानूनों को व्यावहारिक रूप से लागू करना होगा तभी ऐसे अपराधों पर रोक लगेगी।

आदित्य नारायण चोपड़ा
Adityachopra@punjabkesari.com

जरा चलना संभलकर

"जरा चलना संभलकर आजकल गिरावट बहुत है,
"जरा चलना संभलकर आजकल गिरावट बहुत है,
भरोसा किस पर करे जनता हर दल में मिलावट बहुत हैं,,
अपने दल की विचारधारा पर अडिग नेता लेशमात्र ही मिलते हैं,
वास्तव में आवाम को दलबदलू नेताओं से शिकायत बहुत हैं...।।"

गीता पाढा

ज्ञानवापी : दोनों पक्ष मिलकर निकालें हल

खरी-खरी बात
-वीरेन्द्र कपूर

जिस गति से वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद बढ़ रहा है, उसे देखते हुए ज्यादा समय नहीं लगेगा जब मामला इतना गंभीर हो जाएगा कि मुस्लिम और हिंदू एक-दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। संक्षेप में कहें तो मुगल आक्रमणकारी औरंगजेब द्वारा 1669 में एक शिव मंदिर के ऊपर बनाई गई मस्जिद उसी तरह बन सकती है, जैसे बाबर द्वारा बनाई गई मस्जिद अयोध्या में बनाई गई थी और जिसका, सड़कों पर और एक के बाद एक केंद्र सरकारों के ऊपरी स्तरों पर लंबी लड़ाई के बाद देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा एक 'सौहार्दपूर्ण' समाधान खोजा गया।

चार साल पहले सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद बने भव्य राम मंदिर को 23 जनवरी को भक्तों के लिए खोल दिया गया था। इससे एक दिन पहले देश भर के चुनिंदा वीवीआईपी व वीआईपी और साधु संतों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यजमान की भूमिका निभाते हुए रामलला की भव्य और दिव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की थी। उधर, ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अदालतों ने हाल के हफ्तों में कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। वास्तव में, पिछले ही बृहस्पतिवार को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में प्रार्थना सुनी गई, क्योंकि एक दिन पहले वाराणसी जिला न्यायाधीश ने तीस साल के अंतराल के बाद पुजारियों के एक परिवार को यहां पूजा करने की अनुमति दी थी। इस आदेश के बाद जिला प्रशासन के अफसरों ने रात भर काम करके दक्षिणी तहखाने को घेरने वाले स्टील बेरिकेड्स को काटा था। मुकदमे के वादी शैलेन्द्र कुमार पाठक के परिवार के सदस्यों द्वारा यहां श्रृंगार गौरी एवं अन्य देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना की गई। दिलचस्प बात यह है कि वाराणसी के जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेसा, जिन्होंने पिछले सप्ताह पूजा की अनुमति दी, के लिए यह सेवानिवृत्ति से पहले आखिरी कार्य दिवस था।

निस्संदेह, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दोनों समुदायों के सद्भावना वाले पुरुषों और महिलाओं पर है कि ज्ञानवापी मामला रामजन्मभूमि की राह पर न चले। दरअसल, लंबे समय तक चला लेकिन सफल रहा रामजन्मभूमि अभियान, दोनों समुदायों के नेताओं के लिए एक सबक की तरह है।

हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सौहार्द के लिए यह जरूरी है कि एक और भीषण संघर्ष को सिर उठाते ही कुचल देने की आवश्यकता है। मुसलमानों को इस बात की सराहना करने की ज़रूरत है कि ज्ञानवापी नाम भी एक मस्जिद के लिए अलग है। यदि ऐतिहासिक सबूतों की कमी थी कि मस्जिद वास्तव में काशी विश्वनाथ मंदिर के आंशिक खंडहरों पर बनाई गई थी, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अदालत के आदेश पर किए गए सर्वेक्षण के हालिया निष्कर्षों ने इसे विधिवत रूप से प्रस्तुत किया है। दरअसल, वाराणसी में विवादित स्थल पर जाने वाला कोई भी आम आदमी हिंदू मंदिरों के पारंपरिक प्रतीकों को नोटिस किए बिना नहीं रह सकता।

यदि लखनऊ और नई दिल्ली के तत्कालीन शासकों ने दूरदर्शिता दिखाई होती तो यह विवाद लगातार कांग्रेस सरकारों के लिए इतना बड़ा सिरदर्द नहीं बन पाता। आजादी के तुरंत बाद मुस्लिम पक्ष ने वर्षों बाद भी सौहार्दपूर्ण रवैया अपनाया लेकिन मुस्लिम वोटों को एकजुट करने की कांग्रेस की आवश्यकता से उसकी हठधर्मिता और बढ़ गई। आसान भाषा में कहे तो ऐसे मामलों में टालमटोल करना अनुपयोगी है वास्तव में तर्कसंगत समाधान खोजना भी जोखिम भरा है। यह देखते हुए कि पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दोनों ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद अपने संबोधन में सांप्रदायिक सद्भाव पर जोर दिया था। अब उन्हें ज्ञानवापी विवाद को सुलझाने के लिए पहल करते हुए इसका पालन करना चाहिए। मोदी के इस स्वागत योग्य दावे के पीछे की भावना है कि राम 'समस्या नहीं बल्कि समाधान हैं", कि 'वह सबके हैं" को ज्ञानवापी विवाद को तर्कसंगत तरीके से समाप्त करना चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत मालिकाना हक के मुकदमों की स्थिरता के खिलाफ मस्जिद अधिकारियों की चुनौती को खारिज करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। यह कानून हिंदुओं को भूमि मालिकाना हक के मुकदमे दायर करने से नहीं रोकता है, चाहे वह कोई भी हो वाराणसी में ज्ञानवापी या मथुरा में शाही ईदगाह। यह निष्कर्ष निकालना आसान है कि अभी ज्ञानवापी विवाद और बाद में शाही ईदगाह विवाद, दोनों समुदायों को आमने-सामने टकराव की ओर अग्रसर करेगा। ऐसे में समझदारी इसी में है कि सांप्रदायिक सद्भाव के लिए इन संभावित खतरों को यथाशीघ्र टाला जाए। अंतत: इन संभावित बारूद के ढेरों को निष्क्रिय करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है।

नई दिल्ली और लखनऊ में मौजूदा शासनों द्वारा राजनीतिक कौशल की आवश्यकता है और मोदी-योगी टीम यह कर सकती है, अगर वे एकजुट हो जाएं।

नया तो नहीं दलबदल अन्तर्रात्मा का सिलसिला

डा. चन्द्र त्रिखा
chandertrikha@gmail.com

अंतर्रात्मा भी भारतीय राजनीति का एक पुराना खेल है। बड़े स्तर पर शुरूआत श्रीमती इन्दिरा गांधी के कार्यकाल में तब हुई थी जब उन्होंने अपनी ही पार्टी के राष्ट्रपति-पद के प्रत्याशी को इसी अंतर्रात्मा के नाम पर हरवा दिया था। तब कांग्रेस के अपने घोषित प्रत्याशी संजीवा रेड्डी को उन्होंने अंतर्रात्मा के नाम पर पराजित कराया था।

काश! अंतर्रात्माएं सही संदर्भों में जगी रहतीं तो देश को दशकों तक उठापटक न भोगनी पड़ती। मगर ऐसे आसार फिलहाल दिखाई नहीं देते।

दलबदल तो ब्रिटेन के बहुचर्चित प्रधानमंत्री विन्सटन चर्चिल ने भी किया था। उन्होंने तीन बार दल बदला। वर्ष 1904 में वह दलबदल कर ही लिबरल पार्टी में शामिल हुए थे। वर्ष 1924 में वह फिर से अपने पुराने दल 'कंज़रवेटिव पार्टी में लौट आए। इससे पहले वर्ष 1922 में चर्चिल ने निर्दलीय रूप में भी चुनाव लड़ा था।

हमारे देश में इक्का-दुक्का दलबदल तो शुरुआती दौर में भी चला लेकिन व्यापक स्तर पर, अंतर्रात्मा की आवाज का नारा देकर श्रीमती इन्दिरा गांधी ने राष्ट्रपति पद के लिए अपनी ही पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी संजीवा रेड्डी के विरुद्ध मतदान का नेतृत्व किया था और श्री वीवी गिरी को राष्ट्रपति बनवा दिया था। उसके पश्चात राष्ट्रीय स्तर पर यह सिलसिला थमा नहीं। आपातकाल ऐसी ही राजनीतिक परिस्थितियों में स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हुए श्रीमती गांधी को लागू करना पड़ा था। इससे भी पूर्व गैर- कांग्रेसवाद के नाम पर देश के विभिन्न प्रदेशों में बड़े स्तर पर दलबदल हुए।

स्वतंत्र भारत की राजनीति में यह सिलसिला वैसे वर्ष 1948 में आरंभ हो गया था। उस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नाम से व्यापक स्तर पर राजनेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी थी। उन सबने विधानसभाओं से त्याग पत्र दे दिए थे और नए-नए बैनरों के साथ चुनाव लड़ने की घोषणा की। तब 'जन कांग्रेस के नाम से नया संगठन सत्ता में आया था।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 1958 में 98 कांग्रेस विधायकों ने दल बदला और वहां की सम्पूर्णानंद सरकार का पतन करा डाला। वर्ष 1953 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता टी. प्रकाशम ने सदस्यता ले ली। इस दलबदल से वह आंध्र के मुख्यमंत्री बन गए। यही काम त्रावणकोर-कोचीन में पट्टम थानु मिल्लई ने किया था।

इस तरह वर्ष 1957-67 तक का विधायकों ने दलबदलू होने का श्रेय लिया और कांग्रेस छोड़ी। मगर इसी अवधि में 419 विधायक दलबदल कर कांग्रेस में आ गए।

वर्ष 1967 में देश के 16 राज्यों में चुनाव हुए। कांग्रेस को 8 राज्यों में बहुमत नहीं मिला। मगर शेष में भी कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में ही उभर पाई। स्पष्ट बहुमत के लिए दलबदल का सहारा लेना पड़ा।

इस राजनीतिक उठा-पटक में अनेक क्षेत्रीय दल उभरे। हरियाणा सर्वाधिक चर्चा में रहा और यहां की राजनीतिक उठापटक ने 'आया राम गया राम के मुहावरे को जन्म दिया। यह मुहावरा एक विधायक श्री गया लाल के नाम से जुड़ा था, जिन्होंने एक ही दिन में तीन-तीन बार दल बदला। उस वर्ष दलबदल के कई दौर चले। परिणामस्वरूप विधानसभा भंग करनी पड़ी। वर्ष 1968 में नए चुनाव हुए। श्री गया लाल दलबदल के आरोपों के बावजूद चुनावी मैदान में उतरते रहे। वर्ष 1974 में उन्होंने लोकदल प्रत्याशी के रूप में भी चुनाव जीता।

दरअसल, हरियाणा में वर्ष 1966 में नए प्रदेश के गठन के साथ ही यह रोग प्रवेश कर गया था। पूरे के पूरे विधायक दल के ही दलबदल करने के कीर्तिमान यहां स्थापित हुए। यहीं के एक विधायक ने होस्टल की पाइप के सहारे नीचे उतर कर ही दलबदल की गंगा में नहाने का अवसर लिया था। प्रदेश की पहली सरकार मात्र कुछ माह ही चल पाई और राव बीरेंद्र सिंह की सरकार बरासता दलबदल सत्ता में आई। इस रोग का वीभत्स रूप में चौधरी भजनलाल ने सत्ता में आने का समय मिला। मगर इस दौड़ में भी वह अकेले नहीं थे। पंजाब, हिमाचल, मध्यप्रदेश, राजस्थान व दक्षिण भारतीय राज्यों में भी यही होता रहा। सिलसिले तब तक चले जब तक वर्ष 1985 में दलबदल कानून नहीं बना।

मगर इस कानून के बावजूद तोड़ फोड़, दलबदल थमा नहीं। प्रार्थना करें कि लोकतंत्र किसी भी ढब, किन्हीं भी परिस्थितियां में सुरक्षित रहे।

संदेशखाली : नया नहीं है अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण

विनीत नारायण
www.vineetnarain.net

पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपी तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शाहजहां जिस तरह कोर्ट में पेश होता हुआ दिखाई दिया उससे उसको मिल रहे राजनीतिक संरक्षण से कोई इंकार नहीं कर सकता। इस कारण टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आरोपों के घेरे में हैं परंतु यहां सवाल उठता है कि ऐसी क्या मजबूरी होती है कि बिना अपवाद की सभी राजनीतिक पार्टियों को कुख्यात अपराधियों को संरक्षण देना पड़ता है? यह बात नई नहीं है कि भोले-भले वोटरों के बीच भय पैदा करने के उद्देश्य से सभी राजनीतिक दल स्थानीय अपराधियों और माफ़ियाओं को संरक्षण देते हैं। लोकतंत्र की दृष्टि से क्या यह सही है?

जैसे ही संदेशखाली के आरोपी शेख शाहजहां के मामले ने तूल पकड़ा उसे टीएमसी ने 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। पार्टी के इस फैसले का ऐलान करते हुए टीएमसी नेता डेरेक ओ' ब्रायन ने अन्य राजनीतिक दलों पर तंज कसते हुए कहा कि "एक पार्टी है, जो सिर्फ बोलती रहती है। तृणमूल जो कहती है, वो करती है।" परंतु यहां सवाल उठता है कि ये काम पहले क्यों नहीं किया? क्या कोर्ट में पेश होते समय शेख शाहजहां की जो चाल-ढाल थी उससे इस निष्कासन का कोई मतलब रह गया है? पश्चिम-बंगाल की पुलिस शेख शाहजहां के साथ अन्य अपराधियों की तरह बरताव क्यों नहीं कर रही थी? क्या शेख शाहजहां का निलंबन केवल एक औपचारिकता है और असल में उसे भी अन्य राजनीतिक अपराधियों की तरह जेल में वो पूरी 'सेवाएं' दी जाएंगी जो हर रसूखदार क़ैदी को मिलती है? जहां तक पश्चिम-बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सवाल है उनपर यह आरोप अक्सर लगते आए हैं कि वे अपने प्रदेश में अल्पसंख्यक वर्ग के अपराधियों को संरक्षण देती आई हैं। इतना ही नहीं कई बार तो वे ऐसे अपराधियों को अपनी पार्टी का कार्यकर्ता बताते हुए उसे पुलिस थाने से छुड़ाने भी गईं हैं यहाँ सवाल उठता है कि जब भी कभी आप अपने घर या कार्यालय में किसी को काम करने के लिए रखने की सोचते हैं तो उसके बारे में पूरी छानबीन अवश्य करते हैं। ठीक उसी तरह जब कोई राजनीतिक दल अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता या नेता को कोई ज़िम्मेदारी देता है तो भी वे इसकी जांच अवश्य करते होंगे कि वो व्यक्ति पार्टी और पार्टी के नेताओं के लिए कितना कामगार सिद्ध होगा, यदि ममता बनर्जी जैसी अनुभवी नेता से ऐसी भूल लगातार होती आई है तो इसे भूल नहीं कहा जाएगा वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए तो विपक्षी दलों का आरोप है कि भाजपा भी

अपराधियों को संरक्षण देने में किसी से पीछे नहीं है। चुनाव सुधार पर काम करने वाले संगठन 'एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' (एडीआर) की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 40% मौजूदा सांसदों के ख़िलाफ़ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 25% हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण और महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध जैसे गंभीर आपराधिक मामलों में लिप्त हैं। बावजूद इसके उन्हें सांसद या विधायक बनाकर सदन में बिठा दिया जाता है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 763 मौजूदा सांसदों में से 306 सांसदों ने अपने ख़िलाफ़ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इनमें से ही 194 सांसदों ने ख़ुद पर गंभीर आपराधिक मामले होने की घोषणा अपने नामांकन प्रपत्र में घोषित की है।

देश में अपराधियों को मिल रहे राजनीतिक संरक्षण पर आज तक अनेकों रिपोर्टें बनीं और उनमें इस समस्या से निपटने के लिए कई सुझाव भी दिए गए, परंतु अपराधियों, नेताओं और नौकरशाही के इस गठजोड़ के चक्रव्यूह को अभी तक भेदा नहीं जा सका, यदि कोई भी राजनीतिक दल ठान लें कि वो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को अपने दलों में संरक्षण नहीं देगा तो इस समस्या का समाधान अवश्य निकल सकता है जो भी राजनीतिक दल यदि केंद्र या राज्य में सत्ता में हों और यदि उसके समक्ष उसी के दल के किसी सदस्य या नेता के ख़िलाफ़ संगीन आरोप लगते हैं तो उन्हें इस पर उस दल के बड़े नेताओं को तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। देश की अदालतों के हस्तक्षेप का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, यदि कोई भी ऐसा दल अपने किसी कार्यकर्ता या नेता के ख़िलाफ़ कड़ा रुख़ अपनाएगा तो मतदाताओं की नज़र में उस दल का क़द काफ़ी ऊंचा उठेगा। इसके साथ ही वो दल दूसरे दलों पर अपराधियों को संरक्षण देने के मामले में बढ़-चढ़ कर शोर भी मचा सकेगा।

इसके साथ ही भारतीय पुलिस तंत्र में भी ठोस सुधार किए जाने चाहिए। राष्ट्रीय पुलिस आयोग व वोरा समिति द्वारा दिए गए सुझावों को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। ऐसे सुधारों के प्रति हर सरकार का ढुल-मुल रवैया रहा है जो ठीक नहीं है। पुलिस तंत्र को प्रभावी बनाना, उसे हर तरह के राजनीतिक दबाव से मुक्त रखना, नेताओं, अफसरों व पुलिस के गठजोड़ को खत्म करना सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में से एक होना चाहिए। हालिया मसले में देखें, तो जहां तक अदालत में पेश करने का मामला है, वह तो समझ में आता है, पर कोई व्यक्ति अगर किसी राजनीतिक दल संरक्षण में है, तो उसके साथ पुलिस का व्यवहार एक मामूली अपराधी की तरह होगा यह कहना मुश्किल है। यदि पुलिस राजनीतिक दबाव से बाहर रहे तो वो बिना किसी डर के राजनीतिक अपराधियों के साथ क़ानून के दायरे में रहकर अपना कर्तव्य निभाएगी।

देश के तमाम राजनीतिक दल भारत को अपराध मुक्त करने का दावा तो अवश्य करते हैं पर क्या इसे आचरण में लाते हैं? क्या अपने-अपने दलों में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करना और जनता के सामने अपराध मुक्ति के बड़े-बड़े दावे करना विरोधाभास नहीं हैं? यदि चुनाव आयोग या देश की सर्वोच्च अदालत कुछ कड़े कदम उठाए और राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों पर पूरी तरह रोक लग जाए तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी, परंतु ऐसा कब होगा देश के मतदाताओं को इसका इंतज़ार रहेगा।

भारतीय नौसेना को मिलेगा सीहॉक हेलीकॉप्टर स्क्वॉड्रन

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): एमएच 60 आर सीहॉक मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर (ब्लैकहॉक हेलीकॉप्टर का समुद्री संस्करण) 6 मार्च को भारतीय नौसेना में शामिल होगा। रक्षा मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि इसे नौसेना के कोच्चि स्थित बेस आईएनएस गरुड़ में अलग से एक नया स्क्वॉड्रन बनाकर कमीशन किया जायेगा। नौसेना ने कहा कि इस हेलीकॉप्टर का उसके बेड़े में शामिल होना देश की रक्षा आधुनिकीकरण यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण होगा। यह एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सर्फेस वॉरफेयर, खोज एवं बचाव अभियानों, मेडिकल इवैक्यूएशन और

जहाजों को बीच समुद्र में रसद की आपूर्ति के लिए डिजाइन किया गया है।

नौसेना के एक अधिकारी ने कहा कि सीहॉक हेलिकॉप्टरों को आईएनएएस (इंडियन नेवल एयर स्क्वॉड्रन) 334 नाम के नये स्क्वॉड्रन में कमीशन किया जाएगा और इसके शामिल होने के साथ ही नौसेना अपनी समुद्री ताकत में महत्वपूर्ण वृद्धि की गवाह बनेगी।

हेलीकॉप्टर का भारतीय परिस्थितियों में कड़ाई से परीक्षण किया गया है और यह बेड़े में पूरी तरह से एकीकृत है। उनके उन्नत हथियार, सेंसर और एवियोनिक्स सूट सीहॉक को भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए आदर्श बनाते हैं, जो पारंपरिक और असममित दोनों खतरों के लिए उन्नत क्षमताएं प्रदान करते हैं। यह देश की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाएगा, नौसेना की परिचालन पहुंच का विस्तार करेगा और स्पेक्ट्रम तथा विशाल समुद्री डोमेन में निरंतर नौसैनिक संचालन का समर्थन करेगा। आईओआर में सीहॉक की तैनाती भारतीय नौसेना की समुद्री उपस्थिति को मजबूत करेगी, संभावित खतरों को दूर करेगी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करेगी।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रेस, 2-प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

प्रवाह

महोत्सव विश्वास का 75

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

डर अंधविश्वास और क्रूरता के मुख्य स्रोतों में से एक है। डर पर विजय पाना ही ज्ञान की शुरुआत है। - बर्ट्रेंड रसेल

लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही भाजपा द्वारा 195 सीटों पर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करना उसके आत्मविश्वास के साथ यह भी दिखाता है कि एक राजनीतिक दल की चुनावी तैयारी कैसी होनी चाहिए। वहीं, सीट शेयरिंग में उलझे विपक्ष की तैयारी अभी प्रारंभिक स्तर पर ही दिखती है।

रणनीतिक बढ़त

राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के कामयाब फॉर्मूले को अपनाते हुए लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही भाजपा द्वारा सोलह राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों की 195 सीटों पर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करना अपनी जीत को लेकर उसके आत्मविश्वास को तो दर्शाता ही है, किसी राजनीतिक दल की चुनावों की तैयारी का ढंग क्या होना चाहिए, यह भी दिखाता है। 370 सीटें अकेले भाजपा और एनडीए द्वारा 400 से ज्यादा सीटें जीतने के लक्ष्य को दोहराते हुए विपक्षियों पर मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश करती पार्टी का हर वक्त चुनावी मोड में रहना चकित नहीं करता है, बल्कि दर्शाता है कि मजबूत स्थिति में होने के बावजूद वह किसी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। 195 प्रत्याशियों की सूची में 28 महिलाएं, 27 अनुसूचित जाति, 18 अनुसूचित जनजाति, 57 अन्य पिछड़ा वर्ग और 47 नाम युवाओं, यानी 50 वर्ष से कम उम्र वालों के हैं, जिससे भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग का भी पता चलता है, जिसके तहत सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़ी जातियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। हालांकि भाजपा की यह नीति नई नहीं है, क्योंकि केंद्र की सत्ता में आने के बाद से ही अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, किसान और युवा पार्टी की सामाजिक कल्याण नीतियों के केंद्र में रहे हैं। वाराणसी से लगातार दो बार सांसद रहे प्रधानमंत्री मोदी 2024 में तीसरी बार भी यहां से जीत कर देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू और तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरह उत्तर प्रदेश के एक निर्वाचन क्षेत्र से लगातार तीन चुनावी जीत के रिकॉर्ड की बराबरी जरूर करना चाहेंगे। वहीं, प्रधानमंत्री मोदी व दस केंद्रीय मंत्रियों सहित 44 मौजूदा सांसदों को फिर से मैदान में उतार कर भाजपा ने यह साफ करने की कोशिश भी की है कि मोदी सरकार के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है। विवादित टिप्पणियों से पार्टी को असहज करती रही साध्वी प्रज्ञा हों, संसद में अमर्यादित टिप्पणी करने वाले रमेश बिधूड़ी हों या नफरती भाषण के आरोपी प्रवेश वर्मा, इस बार भाजपा ने विवादित चेहरों से पल्ला झाड़ लिया है, जो अप्रत्याशित नहीं है। विपक्षी इंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश व दिल्ली में सीट शेयरिंग के मोर्चे पर आंशिक सफलता के साथ अभी वैचारिक मोड में दिखना दर्शाता है कि उनकी चुनावी तैयारी अभी प्रारंभिक स्तर पर ही है। वहीं, भाजपा द्वारा घोषित पहली सूची में कद्दावर व युवा नेताओं का संतुलन एक नई तरह की राजनीति की ओर इशारा करता है।

'फास्ट फूड नेशन' बनने की ओर

नवीनतम उपभोक्ता सर्वे की रिपोर्ट का यह कहना काफी गंभीर है कि देश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के आहार का पैटर्न बदल रहा है। आहार शैली में बदलाव को आर्थिक विकास का मुख्य संकेतक माना जाता है, लेकिन पैकेज्ड फूड के प्रति बढ़ते आकर्षण के खतरे ज्यादा हैं।

पत्रलेखा चटर्जी
वरिष्ठ पत्रकार

चाहे सत्ता में किसी भी दल की सरकार हो और आप चाहे जहां भी देखें, विरोधाभास भारतीय वास्तविकता के केंद्र में है। इसलिए शायद आश्चर्य की बात नहीं कि प्राचीन भारत, प्राचीन सभ्यता के आदर्श और मूल्यों की व्यापक चर्चा के बीच भारतीय खानपान की संस्कृति अति-प्रसंस्कृत खाद्य की ओर बढ़ रही है, जिसे कथित तौर पर 'आधुनिक' आहार का मुख्य आधार कहा जाता है और जिसका, हमारी सेहत पर बुरा असर भी पड़ रहा है।

हाल ही में जारी घरेलू उपभोग खर्च सर्वेक्षण (एचसीईएस) एक बार फिर उसी बात की पुष्टि कर रहा है, जिसके बारे में चिकित्सक और स्वास्थ्य पैरोकार लंबे समय से चेतावनी दे रहे थे। यह नवीनतम सर्वेक्षण अगस्त, 2022 से जुलाई, 2023 के बीच किया गया था। 11 वर्षों के अंतराल के बाद प्रकाशित नवीनतम सर्वेक्षण की तुलना पहले के सर्वेक्षणों से नहीं की जा सकती।

नवीनतम एचसीईएस में कई नई चीजें हैं, लेकिन बदलाव का व्यापक रुझान स्पष्ट है। एक उभरता हुआ रुझान भारतीय खानपान से संबंधित है। सर्वेक्षण के निष्कर्ष दिखाते हैं कि कुल खाद्य उपभोग खर्च में अनाज और दालों की हिस्सेदारी ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में तेजी से घट रही है। वर्ष 1999-2000 में ग्रामीण परिवारों में अनाज पर खर्च कुल उपभोग खर्च का 22.16 फीसदी था, जो कि अब घटकर 4.91 फीसदी रह गया है। शहरी परिवारों में अनाज पर खर्च इसी अवधि के दौरान 12 फीसदी से घटकर 3.64 फीसदी रह गया है। इसी तरह वर्ष 1999-2000 में ग्रामीण परिवारों में दालों पर खर्च कुल उपभोग खर्च का 3.81 फीसदी था, जो अब घटकर 1.77 फीसदी रह गया है और शहरी परिवारों में यह 2.84 फीसदी से घटकर 1.21 फीसदी रह गया है। ग्रामीण परिवारों में अनाज एवं दालों पर खर्च में गिरावट ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती है। इसका एक प्रमुख कारण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त और सब्सिडी वाले खाद्यान्नों

(अनाज एवं दालें) का वितरण हो सकता है।

नवीनतम घरेलू सर्वे से यह भी पता चलता है कि अब लोग दूध, अंडा, मछली एवं मांस, फल एवं सब्जियों के उपभोग पर ज्यादा खर्च करने लगे हैं। सर्वेक्षण के अनुसार, भारत के लोग सूखे मेवे (ड्राई फ्रूट्स) का अधिक सेवन कर रहे हैं। लेकिन ये आंकड़े पूरी कहानी बयां नहीं करते हैं। अन्य चिंताजनक संकेतक भी हैं-'पेय एवं प्रसंस्कृत खाद्य' पर खर्च का हिस्सा शहरी और ग्रामीण भारत में वर्ष 2011-12 के कुल मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च (एमपीसीई) के 7.9 फीसदी से बढ़कर 9.4 फीसदी हो गया है। वर्ष 1999-2000 में यह आंकड़ा 4.19 फीसदी था। इसके साथ ही पिछले दशक की इसी अवधि में ग्रामीण भारत में पान, तंबाकू एवं अन्य नशीले पदार्थों पर खर्च 3.21 फीसदी से बढ़कर 3.70 फीसदी हो गया है। वर्ष 1999-2000 में यह आंकड़ा 2.87 फीसदी था। इन आंकड़ों से रुझान स्पष्ट हैं।

भारतीय शहरों का आहार संबंधी आंकड़ा तो और भी चौंकाने वाला है। नवीनतम अनुमानों के अनुसार, शहरी भारत में कुल मासिक उपभोग खर्च का लगभग 11 फीसदी प्रसंस्कृत खाद्य पर खर्च होता है। यह तब हो रहा है, जब भारत में जीवन-शैली से जुड़ी बीमारियां महामारी की तरह बढ़ रही हैं, जिसकी एक प्रमुख वजह खराब आहार है। नवीनतम घरेलू उपभोग खर्च सर्वेक्षण ग्रामीण एवं शहरी, दोनों क्षेत्रों में बढ़ते चिकित्सीय उपचार (अस्पतालों में भर्ती और गैर-भर्ती, दोनों इलाजों पर) खर्च को दर्शाता है। स्वास्थ्य पैरोकार चेतावनी दे रहे हैं कि खराब आहार हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। वे बेहतर विनियमन की जरूरत बताते हैं, जिसमें व्यवहार परिवर्तन के साथ पैक लेबलिंग एवं उपभोक्ता जागरूकता शामिल हैं।

नवीनतम उपभोक्ता सर्वे से यह भी पता चलता है कि अति-प्रसंस्कृत खाद्य का उपभोग देश के शहरी एवं ग्रामीण, दोनों इलाकों में बढ़ा है। आहार-शैली में बदलाव का भारत के तीव्र आर्थिक विकास से गहरा संबंध है। कई अध्ययनों में रेखांकित किया गया है कि अति-प्रसंस्कृत खाद्य जीवन के प्रारंभिक चरण में गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के लिए एक प्रमुख जोखिम-कारक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने 2023 की अपनी रिपोर्ट में रेखांकित किया कि 'नमकीन स्नैक्स की उच्च वृद्धि दर चिंता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि ऐसे खाद्य पदार्थों की बढ़ती खपत से उपभोक्ताओं में उच्च रक्तचाप और अन्य एनसीडी के जोखिम बढ़ सकते हैं।' *द ग्रोथ ऑफ अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स इन इंडिया: एन एनालिसिस ऑफ ट्रेंड्स, इश्यूज, ऐंड पॉलिसी रिकमेंडेशन* शीर्षक डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट में भी बताया गया है कि 'खुदरा बिक्री की मात्रा के मामले में तैयार और सुविधाजनक भोजन उपश्रेणी में सॉस/ड्रेसिंग/मसालों का वर्चस्व है, इसके बाद इंस्टेंट नूडल्स और रेडी-टू-ईट (आरटीई) खाना पकाने की सामग्री का स्थान है। ये उत्पाद अक्सर चीनी, नमक और संतृप्त वसा से भरपूर होते हैं, जिसके कारण इनका नियमित आधार पर उपभोग ठीक नहीं है। खुदरा बिक्री मूल्य के संदर्भ में इन श्रेणियों की 2021 में बाजार हिस्सेदारी 90 फीसदी हो गई, जो 2011 में 88 फीसदी थी।'

इसके अलावा, उच्च शर्करा और उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स (कार्बोहाइड्रेट वाले आहार की पाचन एवं एक निश्चित समयावधि में शुगर लेवल नापने का तरीका) वाले नाश्ते का अनाज भी चिंता के विषय हो सकते हैं, क्योंकि भारत में मधुमेह के रोगियों की संख्या बढ़ रही है। उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स के परिणामस्वरूप रक्त शर्करा (ब्लड शुगर) के स्तर में अचानक वृद्धि हो सकती है, जिससे मधुमेह रोगियों के लिए स्वास्थ्य खतरा पैदा हो सकता है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि भारत में छोटे बच्चों और किशोरों में ब्लड शुगर का स्तर सामान्य से बहुत अधिक होने के मामलों में भी भारी वृद्धि हो रही है।

एरिक श्लॉसर ने 2001 में प्रकाशित अपनी पुस्तक *फास्ट फूड नेशन: द डार्क साइड ऑफ द ऑल-अमेरिकन मील* में अमेरिका के फास्ट फूड उद्योग के स्याह पक्ष को दर्शाया है, कि कैसे इसने अमेरिका के परिदृश्य को बदल दिया, अमीर और गरीब के बीच की खाई को बढ़ा दिया, मोटापे की महामारी को बढ़ावा दिया और दुनिया भर में खाद्य उत्पादन में बदलाव लाया। भारत को इसे ध्यान में रखना चाहिए।

edit@amarujala.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid

जीवन धारा

आचार्य रामचंद्र वर्मा

मनुष्य में चाहे कितने ही गुण क्यों न हों, पर जब तक वह समय की कद्र करना न सीखे, तब तक उसे कोई लाभ नहीं हो सकता। समय का दुरुपयोग करने वालों को कभी अच्छे अवसर मिल ही नहीं सकते।

समय का सदुपयोग ही अवसर का सही उपयोग है

यदि संसार में कोई ऐसा पदार्थ है, जो मनुष्य के हिस्से में बहुत ही थोड़ा आया है और जिसका सबसे अधिक अपव्यय और नाश होता है, तो वह समय ही है। जब हम इस बात का ध्यान करते हैं कि जीवन में हमें कितना कम समय मिला है, तो हमें उसके अपव्यय पर बड़ा ही आश्चर्य होता है। और बातों में तो हम लोग बहुत कुछ सचेत रहते हैं, पर समय को बड़ी बुरी तरह से नष्ट करते हैं। ऐसे लोग बहुत ही कम हैं, जो इस बात का ध्यान रखते हों कि उनका कितना समय आवश्यक और उपयोगी कामों में लगता है और कितना हंसी-दिल्लगी, सैर-तमाशे और दूसरे व्यर्थ के कामों में नष्ट होता है। यदि आप कभी अपने समय के सद् और असद् उपयोग का हिसाब लगाएं, तो केवल लज्जित और दुखी होने के अलावा आपसे और कुछ भी न बन पड़ेगा।

सब लोग कहा करते हैं कि दुनिया एक सराय है, जीवन पानी का बुलबुला या स्वप्न है, आदमी की जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं आदि-आदि। अधिकांश कवियों ने भी जीवन की अल्पता के ही गीत गाए हैं और प्रकारांतर से समय का महत्व ही सिद्ध किया है, फिर भी लोगों को ज्ञान नहीं होता, वे समय का कोई मूल्य नहीं समझते। यह सब देखते हुए हमें यही समझना पड़ता है कि बड़े-बड़े विद्वानों और महात्माओं ने हमें लाभ पहुंचाने के जो प्रयत्न किए थे, वे सब व्यर्थ हुए, शताब्दियों का प्राप्त किया हुआ अनुभव हमें कुछ भी लाभ न पहुंचा सका। संसार के अधिकांश लोगों को देखते हुए यही कहना पड़ता है कि न तो अब तक उन लोगों ने अपना उत्तरदायित्व समझा है और न समय का मूल्य। इसके दो कारण हो सकते हैं; एक तो विचारों की त्रुटि और दूसरे अपने कर्तव्यों के ज्ञान का अभाव। ये दोनों कारण बहुत से अंशों में एक-दूसरे से मिले हुए हैं और दोनों का फल या परिणाम भी सम्मिलित ही है। यह विश्वास करने को जी नहीं चाहता कि समय नष्ट करने वाले लोग इतने अपरिणामदर्शी हो गए हैं कि ऐसे अमूल्य पदार्थ का ऐसा दुरुपयोग करें। इसमें संदेह नहीं कि ऐसे लोगों में न तो उच्च विचार ही होते हैं और न महान उद्देश्य ही। उन लोगों को न तो समय का मूल्य मालूम होता है और न उसके भली-भांति उपयोग करने का ज्ञान। यदि सच पूछिए तो हम लोग अपने बालकों को इस बात की शिक्षा ही नहीं देते कि अपने वास्तविक धन का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। हम उन्हें भाषा, विज्ञान और कला आदि की शिक्षा तो अवश्य देते हैं, पर उन्हें यह नहीं सिखाते कि समय को किस प्रकार नष्ट होने से बचाना चाहिए।

मनुष्य जैसे ही समय की उपयोगिता समझने लगता है, उसमें महत्ता, योग्यता आदि अनेक गुण आने लगते हैं। मनुष्य में चाहे कितने ही गुण क्यों न हों, पर जब तक वह समय की कद्र करना न सीखे, उपस्थित अवसरों का उपयोग न करे, तब तक उसे कोई लाभ नहीं हो सकता। यदि सच पूछिए, तो समय का दुरुपयोग करने वालों को कभी अच्छे अवसर मिल ही नहीं सकते।

समय ही धन...

सूत्र

जिस समय को मनुष्य व्यर्थ गंवाता है, उसी समय में प्रयत्न करके वह बहुत कुछ सफलता प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य अपना कर्तव्य पालन करना चाहता हो, जो युवक जीवन में सफलता प्राप्त करने का इच्छुक हो, उसे सबसे पहले यही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि समय ही उसकी 'संपत्ति' है और उसी से लाभ उठाने के लिए उसे प्रयत्नशील होना चाहिए।

दूसरा पहलू

यह पहली बार है कि अमेरिका द्वारा निर्मित कोई अंतरिक्ष यान 50 से भी अधिक वर्ष बाद सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरा।

अमेरिका के चंद्र-अभियानों में जुड़ा नया अध्याय

कोविड महामारी ने कुछ ही वर्षों में हमारी दुनिया को बदल कर रख दिया। हाल के समय में चीन, जापान और भारत सभी चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतर चुके हैं। पिछले पांच वर्षों में कई रोबोटिक मिशन भी चंद्रमा पर भेजे जा चुके हैं, जिनमें से कुछ चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर चुके, तो कुछ दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इनमें दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात और एक इस्राइली गैर-लाभकारी संगठन द्वारा विकसित अंतरिक्ष यान भी शामिल है।

डेविड फ्लेनरी

पहली बार किसी निजी कंपनी ने चंद्रमा की सतह पर सामान को सफलतापूर्वक पहुंचाया है। इससे नासा को मंगल सहित पृथ्वी-चंद्रमा प्रणाली से अलग गंतव्यों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिला है।

हाल ही में अमेरिकी कंपनी इंटुएटिव मशीन्स ने नासा के सहयोग से अपने ओडीसियस अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा, जो दो कारणों से उल्लेखनीय है। पहला, यह पहली बार है कि अमेरिका द्वारा निर्मित कोई अंतरिक्ष यान 50 से भी अधिक वर्ष बाद चंद्रमा पर उतरा और दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है। दूसरी, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार किसी निजी कंपनी ने चंद्रमा की सतह पर सामान को सफलतापूर्वक पहुंचाया है। नासा ने हाल ही में मंगल सहित पृथ्वी-चंद्रमा प्रणाली से अलग गंतव्यों पर ध्यान केंद्रित किया है। लेकिन अपनी वाणिज्यिक चंद्र पेलोड सेवाओं (सीएलपीएस) के साथ इसने चंद्रमा पर उतरने के तरीकों को विकसित करने के लिए अमेरिका के निजी उद्योग को भी धन उपलब्ध कराया है, जिससे चंद्र पेलोड की लागत कम हो जाएगी और नासा के इंजीनियरों को अन्य चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद भी मिलेगी।

अपनी वाणिज्यिक चंद्र पेलोड सेवाओं के साथ अमेरिका ने चंद्रमा पर उतरने के तरीकों को विकसित करने के लिए निजी उद्योग को भी धन उपलब्ध कराया है।

नासा और इंटुएटिव मशीन्स ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से लगभग 300 किलोमीटर दूर एक लैंडिंग साइट का चयन किया, जहां उतरने के लिए चंद्रमा के चारों ओर एक ध्रुवीय कक्षा में प्रवेश करना आवश्यक है। इसमें अतिरिक्त ईंधन की खपत भी होती है।

नासा ने ओडीसियस पर छह वैज्ञानिक पेलोड उतारने के लिए लगभग 11.8 करोड़ डॉलर खर्च किए। यह अपेक्षाकृत सस्ता है, क्योंकि इसमें कम लागत वाले लैंडरों का उपयोग किया गया। हालांकि अंतरिक्ष क्षेत्र में अमेरिका का अनुकरण कर रहे दुनिया के कई देशों को देखना होगा कि क्या वे नासा और अमेरिकी निजी उद्योग के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए अपने सीमित संसाधनों को ऐसी परियोजनाओं पर आवंटित करना चाहते हैं या वैकल्पिक रूप से, वे खुद के वैज्ञानिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के जरिये विकसित की गई स्वदेशी तकनीकों से चंद्रमा पर पहुंचने के तरीकों को खोजना चाहेंगे।

(कन्वर्सेशन से)

आंकड़े

अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टार्ट-अप

अंतरिक्ष के क्षेत्र में वर्ष 2019 में जहां भारत के मात्र 11 स्टार्ट-अप थे, उनकी संख्या 2023 में बढ़कर 189 हो गई।

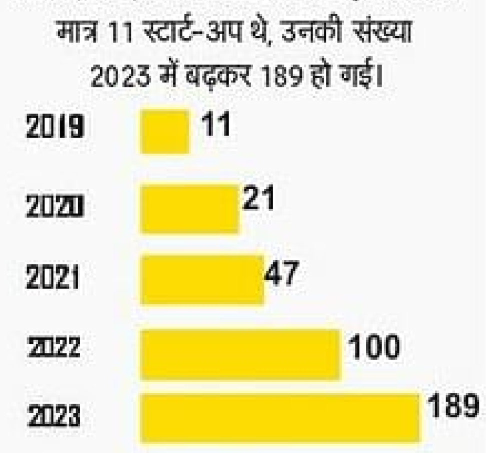

स्रोत : ISRO; News Reports

संत ने कहा, सेवा कार्यों में अहंकार का प्रदर्शन ही मन की अशांति का कारण बनता है। अहं व शांति, दोनों एक साथ नहीं रह सकते।

अहंकार से मुक्ति

अंतर्यात्रा
शिवकुमार गोयल

सुगंधपुर के राजा वज्रबाहु हर क्षण प्रजा की सुविधा तथा सेवा के लिए तत्पर रहते थे। उनकी कीर्ति पूरे देश में प्रजा-वत्सल शासक के रूप में फैल चुकी थी। एक बार कोई महान संत उनके राज्य में पधारे। वह जंगल में एक वृक्ष के नीचे ठहर गए। राजा को पता लगा, तो उन्होंने अपने मंत्री तथा पुत्र को उनके पास भेजा। राजकुमार ने प्रार्थना की, 'महात्मन, महाराजा ने आपको सादर आमंत्रित किया है। आप हमारे महल को अपने चरणों से पवित्र करने की कृपा करें।' संत ने उत्तर दिया, 'राजकुमार, संतों को एकांत में ही रहकर साधना करनी चाहिए। आप वापस लौट जाएं, राजा को हमारा आशीर्वाद पहुंचा दें।' राजा संत से और भी प्रभावित हुए तथा सवेरे रथ में सवार होकर स्वयं जा पहुंचे। उन्होंने संत को प्रणाम कर प्रश्न किया, 'महात्मन, मैंने यथाशक्ति प्रजाजनों की सेवा की है। फिर भी मेरा मन अशांत रहता है। इसका क्या कारण है?' संत ने समझाया, 'राजन, आपने तालाब, मंदिर बनवाए हैं, परंतु आपके अनुचरों ने उन पर आपके नाम के पट्ट लगवाकर आपके पुण्य को क्षीण कर दिया है। सेवा कार्यों में अहंकार का प्रदर्शन ही अशांति का कारण बनता है। अहं व शांति, दोनों एक साथ नहीं रह सकते।' उसी शाम राजा ने अपने नामपट्ट हटवाने के आदेश दे दिए।

(अमर उजाला आर्काइव से)

अमर उजाला
पुराने पन्नों से —— 26 जनवरी, 1990

प्रधान पर अवैध चंदा वसूली का आरोप

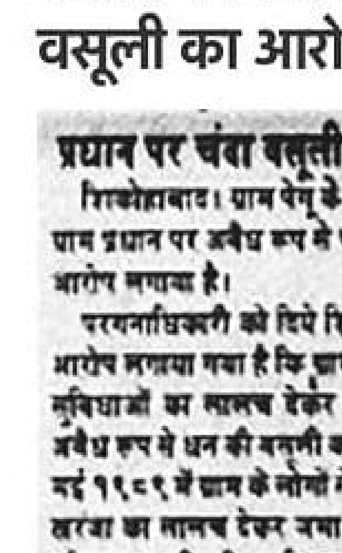
प्रधान पर चंदा वसूली...
शिकोहाबाद। ग्राम पेगू के ... ग्राम प्रधान पर अवैध रूप से ... आरोप लगाया है।
... आरोप लगाया गया है कि ग्राम ... सुविधाओं का लालच देकर ... अवैध रूप से धन की वसूली ... सन् १९८९ में ग्राम के लोगों से ... खरंजा का लालच देकर जमा ... हरिजन बस्ती की ...

शिकोहाबाद के पेगू ग्राम के लोगों ने आरोप लगाया है कि ग्राम के प्रधान सुविधाओं का लालच देकर चंदे के रूप में अवैध धन की वसूली करते हैं। उन्होंने जवाहर योजना की राशि के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया है।

बिहार के विकास में अंतिम व्यक्ति

विभिन्न सूचकांकों में बिहार की बदहाल स्थिति राज्य की शासन व्यवस्था की वास्तविक कहानी बयां करती है।

संतोष मेहरोत्रा
मुद्दा

यदि कोई राज्य सरकार लगभग दो दशकों से सत्ता में है, तो एक अपरिहार्य प्रश्न उठता है कि उसने आर्थिक विकास, मानव विकास और शासन के मानकों में कैसा प्रदर्शन किया? 2011-12 से 2021-22 तक, बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 5.9 फीसदी की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा, जो राष्ट्रीय औसत के काफी करीब है। लेकिन बिहार के जीएसडीपी का स्तर प्रमुख राज्यों में सबसे कम है, बावजूद इसके कि निचले आधार पर उच्च वृद्धि हासिल करना आसान होता है। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में 2011-12 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद गुजरात का 43, कर्नाटक का 41 और तमिलनाडु का 34 फीसदी था; 2021-22 में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद का हिस्सा घटकर गुजरात का 35, कर्नाटक का 33 और तमिलनाडु का 32 फीसदी रह गया।

बिहार की प्रति व्यक्ति आय भारत में सबसे कम है। 1960-61 में बिहार की प्रति व्यक्ति एनएसडीपी

राष्ट्रीय औसत का 70 फीसदी थी; जो 2005 तक घटकर राष्ट्रीय का 33 फीसदी हो गई, जब जेडीयू सरकार सत्ता में आई। 2005 से आज तक नीतीश कुमार की ही सरकार रही। 2020-21 में, बिहार की प्रति व्यक्ति एनएसडीपी राष्ट्रीय औसत का 33 फीसदी थी। इस प्रकार, उनकी सत्ता में लगभग दो दशकों के बाद भी राष्ट्रीय औसत के सापेक्ष बिहार का अभिसरण के बजाय थोड़ा विचलन ही हुआ है।

दूसरा मुद्दा बिहार के भीतर प्रति व्यक्ति उत्पाद में स्थानिक असमानता का है। 2020-21 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद पटना में 1,15,239 रुपये, जबकि बेगूसराय और मुंगेर में क्रमशः 45,497 और 42,793 रुपये था, यानी पटना के आधे से भी कम। 2020-21 में बिहार का प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद मात्र रुपये 31,522 था, जो पटना (1,15,239 रुपये) के एक-तिहाई से भी कम है। इसके अलावा, बिहार ने संरचनात्मक परिवर्तन के चिंताजनक उलटफेर का भी अनुभव किया है। 2017-18 और 2022-23 के बीच कृषि में कार्यबल 50 फीसदी बढ़कर 125 लाख से 190 लाख हो गया है; जबकि 2020 और 2023 के बीच कृषि में भारत के कार्यबल में छह करोड़ की वृद्धि हुई है, बिहार में यह वृद्धि बहुत अधिक है।

नीति आयोग की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग (2019) में बिहार 29 में से 26वें स्थान पर है। 2021 में बिहार को भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सिर्फ 0.29 फीसदी प्राप्त हुआ। बुनियादी मानव पूंजी की सक्षमता के बिना बिहार विदेशी निवेश आकर्षित करने में विफल रहा है।

बिहार की 2025 तक राष्ट्रीय निर्यात में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 10 फीसदी करना चाहता है, हालांकि, वर्तमान हिस्सेदारी सिर्फ 0.52 फीसदी है।

यहां तक कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 के संदर्भ में भी बिहार में 'बहुत कम सामाजिक प्रगति' हुई है, और इसमें 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में वह 35वें स्थान पर है। स्वास्थ्य प्रदर्शन सूचकांक (2019-20) में बिहार 19 राज्यों में 18वें स्थान पर है। बिहार में नवजात मृत्युदर केरल की तुलना में पांच गुना और राष्ट्रीय औसत से 3.5 गुना अधिक है। इसका मुख्य कारण यह है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में जरूरी कार्यबल के मुकाबले स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं की कमी के मामले में बिहार देश के राज्यों में शीर्ष पर है।

इसी तरह, शिक्षा के मामले में, नीति आयोग के स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 2019 में बिहार 20 बड़े राज्यों में 19वें स्थान पर है। फिर स्कूलों और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार कैसे हो सकता है? स्कूलों में 2.2 लाख शिक्षकों की कमी है, विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में डॉक्टरों और पैरा-मेडिक्स की कमी है।

सुशासन सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण घटक होता है। सुशासन सूचकांक में बिहार का नीचे के कुछ राज्यों में आना 'सुशासन' की वास्तविक कहानी बताता है। कुल मिलाकर, जब तक हम आर्थिक या सामाजिक परिवर्तन के बिना आर्थिक विकास का पीछा करते हैं, हम गांधी जी की नसीहत से दूर चले जाते हैं कि 'विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए!'

-साथ में डॉ. राकेश रंजन

दैनिक जागरण

परमात्मा के प्रति भक्ति ही मुक्ति दिलाने में सक्षम है

आवश्यक सख्ती

यह अच्छा हुआ कि निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के पहले ही राजनीतिक दलों को इसके लिए आगाह कर दिया कि उनकी बेजा बयानबाजी पर निगाह रखी जाएगी और तय नियमों को तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन उसके समक्ष केवल भाषा की मर्यादा का उल्लंघन रोकने की ही चुनौती नहीं है। इसके अतिरिक्त एक बड़ी चुनौती यह भी है कि मतदाताओं को गुपचुप तरीके से पैसे बांटकर वोट हासिल करने से कैसे रोका जाए। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पिछले कुछ समय से पैसे बांटकर वोट हासिल करने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। इसका प्रमाण यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं को वितरित की जाने वाली धनराशि की बरामदगी बढ़ती चली जा रही है। निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव प्रचार के दौरान करोड़ों रुपये की राशि जब्त की जाती है, लेकिन कोई भी समझ सकता है कि इस तरह की धनराशि का एक बड़ा हिस्सा उसकी पकड़ में नहीं आता होगा।

यह भी किसी से छिपा नहीं कि बड़ी संख्या में प्रत्याशी चुनाव खर्च की तय धनराशि से कहीं अधिक पैसा अपने प्रचार में खर्च करते हैं। प्रत्याशी भले ही कागजों पर यह दिखा देते हों कि उन्होंने तय सीमा के तहत ही चुनाव प्रचार में धन खर्च किया, लेकिन हर कोई यह जानता है कि आम तौर पर ऐसा नहीं होता। सच्चाई यह है कि चाहे विधानसभा के चुनाव हों अथवा लोकसभा के, उनमें निर्धारित धनराशि से कहीं अधिक पैसा खर्च किया जाता है। यही कारण है कि चुनाव लड़ना आम आदमी के वश की बात नहीं रह गया है। एक समय था जब चुनावों में बाहुबल के साथ धनबल की भी भूमिका देखने को मिलती थी। समय के साथ बाहुबल पर तो एक बड़ी हद तक लगाम लग गई, लेकिन धनबल की भूमिका बढ़ती ही चली जा रही है। चिंताजनक यह है कि बंगाल में बाहुबल की भूमिका पर भी रोक नहीं लग पा रही है। स्पष्ट है कि चुनाव आयोग को और अधिक सक्रियता और सख्ती का परिचय देना होगा। समस्या यह है कि चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ निर्वाचन आयोग कोई कठोर कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है। इसका कारण यह है कि उसके पास पर्याप्त अधिकार नहीं हैं। कुछ दिनों पहले निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों और प्रत्याशियों को यह चेतावनी दी थी कि उनकी ओर से चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। निःसंदेह ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि देश के कुछ हिस्सों में चुनाव जीतने के लिए या तो धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल किया जाता है या फिर धर्मगुरुओं का सहारा लिया जाता है। स्पष्ट है कि इन स्थितियों में निर्वाचन आयोग को सख्ती बरतने के लिए कमर कसने की जरूरत है।

आयुष्मान भारत

उत्तर प्रदेश यदि पांच करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है तो यह कीर्तिमान से अधिक उस संवेदनशीलता का परिचायक है जिसमें अंतिम पांत में खड़े व्यक्ति की चिंता सर्वोपरि दिखती है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सरकार की उन योजनाओं में शामिल है, जिसका सीधा संबंध उस वंचित वर्ग से है जिसके बारे में कहा जाता है कि यदि परिवार के किसी सदस्य को असाध्य रोग ने पकड़ा तो उसकी न केवल जीवन भर की बचत दांव पर लग जाती है, बल्कि जमीन और मकान बिकने की नौबत आ जाती है। अक्सर तो यह वर्ग किसी बड़ी बीमारी का इलाज कराने के बजाय उसके साथ ही जीना सीखना शुरू कर देता है। ऐसे में प्रदेश की लगभग एक चौथाई जनसंख्या का साल में पांच लाख रुपये तक के इलाज के लिए निश्चिंत हो जाना बड़ी उपलब्धि है। विशेष यह है कि जो कार्ड बनाए गए हैं उनमें से 1.94 करोड़ कार्ड केवल पिछले आठ महीनों के दौरान बने। बीती 17 सितंबर तक 3.06 करोड़ कार्ड ही बने थे, जो अभी पांच करोड़ हो गए हैं। न केवल कार्ड बनाने के काम में तेजी आई है, बल्कि कार्डधारकों की चिकित्सा के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करने में भी तेजी दिखाई गई है। यही कारण है कि इस योजना के तहत चिकित्सा का लाभ लेने वालों की संख्या भी बढ़ी है। डेढ़ साल पहले तक करीब तीन हजार अस्पतालों में आयुष्मान के माध्यम से इलाज की सुविधा उपलब्ध थी। अब कुल 5,351 अस्पतालों में इस योजना से मुफ्त उपचार किया जा रहा है। लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। पहले जहां प्रदेश में दो हजार लोग प्रतिदिन इस योजना का लाभ उठा रहे थे, वहीं अब आठ हजार लोग इसका फायदा ले रहे हैं। सरकार की इस योजना को गति देने में जनभागीदारी और तकनीक की भी भूमिका रही है। शासन ने सीधे राशन की दुकानों पर कार्ड बनाने की सुविधा दी। इसके अलावा कोई भी आयुष्मान एप के माध्यम से भी आसानी से कार्ड बनवा सकता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि स्वास्थ्य सुविधा अब सबकी पहुंच में होगी।

फिर बाइडन बनाम ट्रंप की तस्वीर

हर्ष वी. पंत

ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की ओर से नामांकन हासिल करने के बेहद करीब हैं। बाइडन के लिए ट्रंप की चुनौती न चार साल पहले आसान थी और न ही अब

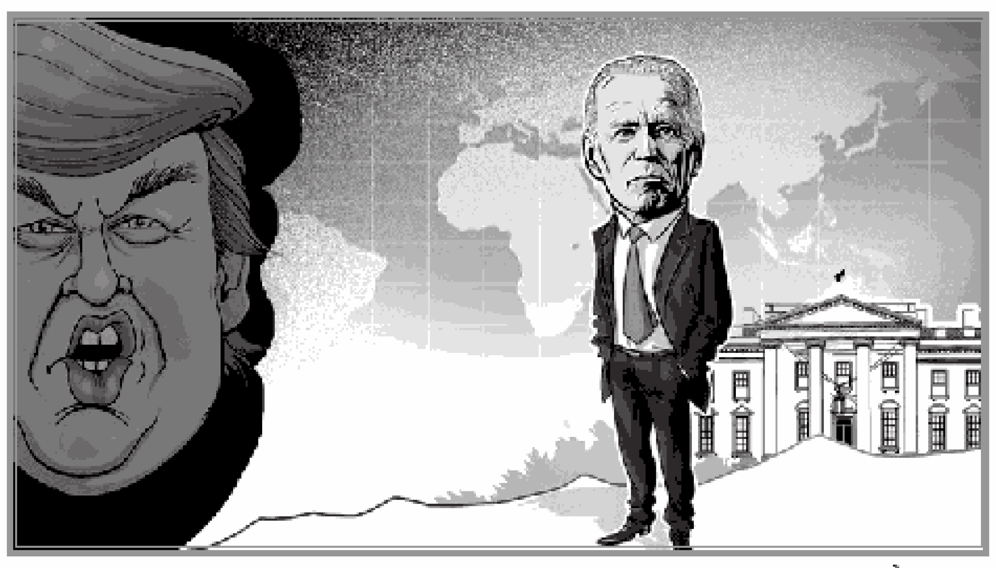

अवधेश राजपूत

इस मंगलवार के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारी पर एक प्रकार से मुहर लग जाएगी। हालांकि अब यह एक प्रकार की औपचारिकता ही है, क्योंकि मुकाबला मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने की पूरी स्थितियां बन गई हैं। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की ओर से नामांकन हासिल करने के बेहद करीब हैं। उम्मीदवारी की होड़ में उनकी पार्टी के कुछ अन्य प्रतिद्वंद्वी दावा छोड़कर ट्रंप के समर्थन में आ गए हैं। यहां तक कि एक समय कड़ी चुनौती पेश कर रहे विवेक रामास्वामी भी अब ट्रंप की उम्मीदवारी के पक्ष में आ गए हैं। ट्रंप के समक्ष अब केवल निक्की हेली ही अड़ी हुई हैं, लेकिन उनकी चुनौती खासी कमजोर है। यहां तक कि हेली अपने गृह राज्य साउथ कैरोलिना में भी ट्रंप की राह नहीं रोक पाईं। ऐसे में अमेरिकी चुनावों में संभवतः पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब किसी मौजूदा राष्ट्रपति को चुनाव में उस प्रत्याशी का सामना करना पड़ेगा, जो पहले भी चुनावों में आमने-सामने रह चुके हों। हालांकि इन चार वर्षों में परिस्थितियां काफी कुछ बदल चुकी हैं, लेकिन दोनों का मुकाबला पिछली बार की तरह कांटे की टक्कर जैसा रहने की उम्मीद है।

अमेरिकी मतदाताओं के लिए यह चुनाव कुछ अलग तरह का रहने वाला है। मतदाता दोनों ही प्रत्याशियों के व्यक्तित्व और नीतियों से भलीभांति परिचित हैं। ट्रंप अपने चिरपरिचित ढंग से बाइडन पर निजी हमले करने के साथ ही उनकी नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। बाइडन के लिए ट्रंप की चुनौती न चार साल पहले आसान थी और न ही अब। पिछले चुनाव तो कोविड महामारी की पृष्ठभूमि में हुए थे, जिसके चलते अमेरिका में बिगड़े हालात से बाइडन की राह कुछ आसान हो गई थी, लेकिन इस बार उन्हें ऐसी कोई स्वाभाविक बढ़त मिलती नहीं दिख रही है। पिछले चुनाव में ही बाइडन की उम्र को लेकर सवाल उठ रहे थे और अब तो ट्रंप भी 77 साल के हो गए हैं। इसी पहलू को देखते हुए राबर्ट कैनेडी जूनियर जरूर स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनौती पेश करने के प्रयास में हों, लेकिन उनकी कोशिश शायद ही कोई रंग लाए। बाइडन और ट्रंप की उम्र को देखते हुए लगता है कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ही राजनीतिक धड़े अतीत की खिड़की में कैद होकर रह गए हैं। ऐसे में यदि अमेरिकी मतदाताओं के उत्साह में कोई कमी दिखाई दे तो उस पर हैरत नहीं होनी चाहिए। यह प्राइमरी चुनाव में नजर भी आया है। प्राइमरी में 40 प्रतिशत स्वतंत्र रिपब्लिकनों ने ट्रंप के पक्ष में मतदान नहीं किया। यह असल में ट्रंप के कोर वोटर्स ही हैं, जो उन्हें उम्मीदवारी की होड़ में सबसे आगे बनाए हुए हैं। इस प्रकार देखें तो यह मुद्दाविहीन चुनाव है, जो दो व्यक्तित्वों की प्रतिद्वंद्विता पर ही कहीं अधिक केंद्रित है।

ट्रंप कह रहे हैं कि दोबारा सत्ता में न आने के चलते 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' का उनका नारा अधूरा ही रह गया। ऐसे में वह मतदाताओं से एक और मौका देने की अपील कर रहे हैं। वह बाइडन की असफलताएं गिनवा रहे हैं। इसके बावजूद फिलहाल अमेरिका की घरेलू राजनीति में कोई बड़ा मुद्दा नहीं दिख रहा है। अमेरिका की आर्थिक वृद्धि दर इस समय अपेक्षाकृत बेहतर है। मुद्रास्फीति से लेकर बेरोजगारी के आंकड़े भी कुछ राहत देने वाले हैं। एक प्रकार से बाइडन घरेलू मोर्चे पर स्थायित्व लाने में सफल रहे हैं, लेकिन वह अपनी सफलता को लेकर सही नैरेटिव नहीं गढ़ पा रहे हैं। जबकि ट्रंप अपनी बातों से बाइडन को घेरने में सफल होते दिख रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो बाइडन जहां अपनी सफलता का संदेश देने में भी सफल नहीं हो पा रहे, वहीं ट्रंप उनकी सफलता को भी असफलता के रूप में पेश करने में सक्षम दिख रहे हैं।

चूंकि घरेलू स्तर पर कोई मुद्दा प्रभावित करता नहीं दिख रहा तो इस चुनाव का फैसला संभवतः विदेश नीति से जुड़े निर्णय ही करेंगे। बाइडन प्रशासन में अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर तो निकल आया, लेकिन उसकी एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। जिन परिस्थितियों में अमेरिकी फौज की अफगानिस्तान से वापसी हुई उसने अंतरराष्ट्रीय पटल पर अमेरिका की बहुत किरकिरी कराई। अमेरिका जहां अफगानिस्तान से निकला तो वह एक प्रकार से यूक्रेन में फंस गया। इजरायल-हमास युद्ध के बाद से उसे लाल सागर में भी तगड़ी चुनौती मिल रही है। पश्चिम एशिया में भी उसके लिए समीकरण कुछ गड़बड़ हो गए हैं। चीन के साथ उसकी प्रतिद्वंद्विता और तनाव में कोई कमी नहीं आई है। हमास के खिलाफ संघर्ष में बाइडन ने जिस प्रकार इजरायल का समर्थन किया है, उससे उनकी पार्टी का ही एक वर्ग खासतौर से युवा नाराज हैं। ट्रंप इस आक्रोश को अपने पक्ष में भुना सकते हैं। अमेरिकी राजनीति में एक दिलचस्प रुझान दिख रहा है। वह यह कि रूढ़िवादी मानी जाने वाली रिपब्लिकन पार्टी के नेता का रवैया उदारवादी है तो उदारवादी दृष्टिकोण के लिए जानी जाने वाली डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति बाइडन का रुख-रवैया कुछ रूढ़िवादी।

ट्रंप के उत्साहित समर्थकों का यह भी मानना है कि पुतिन के साथ अपने संबंधों के चलते वह यूक्रेन संकट का भी कोई स्वीकार्य हल निकाल सकते हैं। हालांकि ट्रंप की अस्थिर प्रवृत्ति उनके प्रति कुछ संदेह भी बढ़ाती है। हाल में नाटो को लेकर उनके बयान से अमेरिका के पारंपरिक सहयोगियों में सही संदेश नहीं गया। ट्रंप का यह रवैया जापान और ताइवान जैसे पारंपरिक अमेरिकी सहयोगियों को परेशान कर सकता है। भारत के संदर्भ में देखें तो ट्रंप का पिछला राष्ट्रपति कार्यकाल भारत के लिए मिला-जुला रहा। उनके शासन में भारत के साथ अमेरिका का व्यापार समझौता अपेक्षा के अनुरूप सिरे नहीं चढ़ पाया और उन्होंने भारत पर कुछ बंदिशें भी लगाईं, लेकिन उन्होंने चीन के खिलाफ खुला आक्रामक रवैया भी अपनाया। यह भारत के लिए मददगार साबित हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी उनके आत्मीय रिश्ते रहे। ट्रंप रणनीतिक मोर्चे पर भारत की सहायता के लिए सक्रिय रहे। वहीं, बाइडन प्रशासन के दौरान भी कई स्तरों पर भारत-अमेरिका रिश्ते निरंतर प्रगाढ़ होते गए।

(लेखक आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

अंतरिक्ष में बड़े लक्ष्य साधता भारत

मनीष पुरोहित

सफल चंद्रयान-3 के बाद गगनयान मिशन भारत को एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित करेगा

मिशन के प्रतिभागियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी। फाइल

गगनयान मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वर्षों के अथक समर्पण का प्रमाण है। इसका लक्ष्य न केवल अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना है, बल्कि मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं में भारत के कौशल को प्रदर्शित करना भी है। यह मिशन भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण यात्रा में एक मील का पत्थर होगा। इस अभियान का उद्देश्य अंतरिक्ष में चार अंतरिक्ष यात्रियों के दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में तीन दिन के लिए भेजना और उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाना है। इसके लिए चुने गए चार अंतरिक्ष यात्रियों-ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला ने रूस और भारत में पांच साल के कठोर प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजर कर आने वाली चुनौतियों के लिए सावधानीपूर्वक तैयारी की है। रोबोटिक और मानव अंतरिक्ष अभियानों के बीच के अंतर को पहचानना महत्वपूर्ण है। जब मानव जीवन दांव पर होता है तो त्रुटि की गुंजाइश शून्य हो जाती है। इसके लिए सावधानीपूर्वक योजना, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। इसे स्वीकार करते हुए इसरो ने गगनयान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। विशेष रूप से इस मिशन के लिए डिजाइन किया गया एलवीएम3 लांच वाहन मानव अंतरिक्ष उड़ान को समायोजित करने के लिए सुधारों से गुजरा है। इसके अतिरिक्त एलवीएम3 के क्रायोजेनिक चरण को मानव अंतरिक्ष उड़ान के उद्देश्य से विकसित किया गया है। अब इसको एचएलवीएम3 का नाम दिया गया है। एचएलवीएम3 में चालक दल निष्कासन प्रणाली शामिल है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी आपात स्थिति में चाहे वह प्रक्षेपण स्थल पर हो या उड़ान चरण के दौरान चालक दल माड्यूल को चालक दल के साथ सुरक्षित दूरी पर ले जाया जा सके।

पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला आर्बिटल माड्यूल दो प्रमुख हिस्सों से मिलकर बना है-क्रू माड्यूल और सर्विस माड्यूल। मानवीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आर्बिटल माड्यूल अत्याधुनिक एवियोनिक्स (यान संचालन) प्रणालियों से लैस है, जिनमें अतिरिक्त बैकअप मौजूद है। क्रू माड्यूल अंतरिक्ष यात्रियों के रहने के लिए बनाया गया है। यह एक दोहरी दीवार वाला प्रकोष्ठ है। बाहरी दीवार ताप संरक्षण प्रणाली से सुसज्जित है। क्रू माड्यूल में चालक दल के उपकरण, दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं, जीवनरक्षक प्रणाली, एवियोनिक्स और गतिरोध प्रणालियां शामिल हैं। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अवतरण के समय चालक दल सुरक्षित रहे। इसके लिए यह पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने में सक्षम है। सर्विस माड्यूल का मुख्य कार्य कक्षा में रहते हुए क्रू माड्यूल को आवश्यक सहायता प्रदान करना है। इसमें ताप, प्रणोदन, ऊर्जा, एवियोनिक्स प्रणालियां और उपकरणों को तैनात करने के लिए आवश्यक तंत्र शामिल हैं।

हाल में चंद्रमा पर रोबोटिक साफ्ट लैंडिंग के दौरान जापान और अमेरिकी लैंडर्स को काफी तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि छोटी-सी मानवीय गलती भी राष्ट्रीय संकट बन सकती है। ये मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण की दिशा में प्रगति का प्रदर्शन करते हुए मामूली मानवीय त्रुटियों के संभावित दुष्परिणामों को भी रेखांकित करते हैं, जिनके मानव अंतरिक्ष अभियान में विनाशकारी परिणाम सामने आ सकते हैं। गगनयान भारत की एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में कार्य करेगा। इसरो के प्रमुख सोमनाथ ने कहा है कि 2024 को गगनयान का वर्ष नामित किया गया है। इस साल गगनयान मिशन के लिए कई परीक्षण उड़ानें होंगी। अंतरिक्ष में चालक दल रहित यानी रोबोटिक अंतरिक्ष यात्री 'व्योममित्र' की तैनाती भी होगी। जबकि मानवयुक्त मिशन गगनयान अगले वर्ष यानी 2025 में लांच किया जाएगा। यह रोबोट अंतरिक्ष यात्री माड्यूल मापदंडों की निगरानी, अलर्ट जारी करने और जीवन समर्थन कार्यों को निष्पादित करने की क्षमता से लैस है। यह प्रश्नों का उत्तर देने जैसे कार्य भी कर सकता है।

गगनयान के पीछे की बड़ी आकांक्षा अंतरिक्ष में मानव को प्रक्षेपित करने में आत्मनिर्भरता हासिल करना है, जो अंततः हमें भविष्य में नियोजित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और चंद्रमा पर मानव अभियानों की बड़ी योजनाओं के लिए तैयार करेगा। भारत ने वर्ष 2035 तक अपना खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और वर्ष 2040 तक चंद्रमा पर पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री को भेजने की योजना बनाई है। इस तरह के महत्वाकांक्षी मिशन के लिए आने वाले वर्षों में भारत को बड़े पैमाने पर क्षमता निर्माण की आवश्यकता होगी। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को लांच करने के लिए भारत को प्रक्षेपण यानों के लिए भारी लिफ्ट क्षमता की आवश्यकता है। मौजूदा यान बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त हैं। इसके लिए इसरो अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यानों पर काम कर रहा है, जो वर्तमान एलवीएम3 से बहुत अधिक बड़े पैमाने पर होंगे।

कुल मिलाकर गगनयान कार्यक्रम हमें अंतरिक्ष में बड़े लक्ष्यों को हासिल के लिए तैयार करेगा। इसरो इस सपने को साकार करने के लिए कई नवाचारों पर काम कर रहा है और नई क्षमताओं का विकास कर रहा है। यह प्रयास न केवल भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ाएगा, बल्कि देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा के रूप में भी कार्य करेगा, उनकी जिज्ञासा को जगाएगा, महत्वाकांक्षा को बढ़ाएगा। चंद्रयान-3 की सफलता के बाद गगनयान एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत को एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित करने का काम करेगा।

(लेखक इसरो के पूर्व विज्ञानी हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

संबंधों की शक्ति

व्यावहारिक जगत के कार्यों के सुचालन का आधार आपसी संबंध हैं। संबंध जितने निश्छल, गहरे और सुदृढ़ होंगे, सामाजिक दायित्व और व्यावसायिक गतिविधियां भी उसी अनुपात में बेहतर संपन्न होंगी। औपचारिक, कार्यस्थलीय या कारोबारी संबंध प्रायः सतही होते हैं और आवश्यकता अनुसार निर्मित किए जाते हैं। इनमें प्रतिबद्धता या आत्मीयता का अभाव रहता है। ये कालांतर में क्षीण नष्ट हो सकते हैं, इनकी सार्थकता निर्दिष्ट उद्देश्य सध जाने तक मान सकते हैं।

मात्र परिचय होने, मुलाकात जारी रखने या औपचारिकताएं निभाने से संबंध नहीं टिकते। गहरे और विश्वस्त संबंध वर्षों, बल्कि दशकों तक एक-दूसरे की मनोवृत्ति, दिशा समझने और अनुकूल बैठने के उपरांत बनते हैं और अनेक विवादों, मतांतरों के बाद भी जीवंत रहते हैं। इसके आलावा दुष्कर समय में एक-दूसरे का संबल बनते हैं। सच्चे और स्थायी संबंधों में महत्व संख्या का नहीं, बल्कि निष्ठा का होता है। इनमें संदेह या आडंबर का स्थान नहीं रहता। संबंधों में महत्व उसके ईमानदारी से निर्वहन का होता है। गहरे और स्थायी संबंध के निर्माण में भारी कीमत चुकानी होती है। यहां आशय धन से नहीं, अथाह प्रेम और दूसरे की बेहतरी के प्रबल भाव का है।

तुच्छ स्वार्थों या दिखावटी आचरण में लिप्त व्यक्ति अच्छे संबंध बनाने में असमर्थ रहता है। ऐसा व्यक्ति जीवन की संध्या में एकाकी और निरीह पड़ जाता है। अनेक अध्ययनों में पुष्टि हुई है कि निश्छल संबंधों के किरदार दीर्घजीवी, खुशनुमा और स्वस्थ रहते हैं। संबंध निर्माण की शुरुआत युवावस्था में की जाती है। सदाशयता और निःस्वार्थ भाव से जुड़े दो पक्षों के संबंध को परालौकिक कहना उचित होगा। ऐसे संबंध जीवन को अर्थ देते हैं। प्रभु से संबंध सर्वोच्च कोटि का होता है। आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टि से उच्च व्यक्ति ही इस अवस्था को प्राप्त करता है।

हरीश बड़थ्वाल

दलहन क्रांति की जरूरत

राघवन संपतकुमार

खाद्य सुरक्षा और पोषण प्रदान करने में दालें महत्वपूर्ण योगदान देती हैं

पिछले दिनों केंद्र सरकार ने किसानों को पांच साल के लिए जिन फसलों पर पांच साल के लिए एमएसपी की गारंटी देने की बात कही थी उनमें दालें भी थीं, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई। भारत की पहचान दुनिया के सबसे बड़े दाल उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक देश के रूप में है और इस पहचान की जड़ें इसकी कृषि धरोहर से गहराई से जुड़ी हैं। दालों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। खाद्य सुरक्षा और पोषण प्रदान करने में दालें महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। हालांकि इस शानदार विरासत के बावजूद इस क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें उपज में अंतर, अस्थिर बाजार का उतार-चढ़ाव, प्रसंस्करण के लिए सीमित बुनियादी ढांचा शामिल हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने आयात पर निर्भरता कम करने और 2027 तक दाल के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से दालों के घरेलू उत्पादन में वृद्धि के प्रति प्रतिबद्धता को व्यक्त किया है। दाल उत्पादन की वास्तविक क्षमता को सामने लाने और भारत के सतत विकास उद्देश्यों में उसके योगदान के लिए अनुसंधान, किसानों के सशक्तीकरण और मूल्यवर्धित प्रसंस्करण पर केंद्रित एक व्यापक रणनीति जरूरी है।

भारत की औसत दलहन उपज 814 किलोग्राम/हेक्टेयर और वैश्विक औसत 1,694 किलोग्राम/हेक्टेयर के बीच की असमानता को कम करने के लिए अनुसंधान की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त जलवायु के लिए हितकारी कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना जोखिमों को कम करने और संसाधनों के उपयोग को बेहतर करने के लिए आवश्यक है, जैसे ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देना, जो पानी की खपत को 40-50 प्रतिशत तक कम करती है और पैदावार को 20-30 प्रतिशत तक बढ़ाती है। बायोफोर्टिफिकेशन कार्यक्रमों में निवेश बढ़ाना होगा। जैसे आयरन-समृद्ध मसूर की किस्में प्रचलित पोषण संबंधी कमियों को दूर करती हैं। दाल उत्पादक किसान संगठनों (एफपीओ) के जरिये छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त बनाकर इस क्षेत्र को बदलने की अपार संभावनाएं रखते हैं। एफपीओ की 10,000 से अधिक संख्या के बावजूद दालों में उनकी भागीदारी सीमित है। केवल आठ प्रतिशत इसमें सक्रिय रूप से शामिल हैं। वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा दलहन उत्पादक होने के बावजूद भारत में प्रसंस्करण के माध्यम से मूल्यवर्धन का काफी कम उपयोग किया जाता है।

एक संपन्न, टिकाऊ दलहन क्षेत्र की परिकल्पना को साकार करने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। यह न केवल किसानों की आजीविका को बढ़ाएगा और खाद्य सुरक्षा में योगदान देगा, बल्कि स्वस्थ भोजन विकल्पों और पर्यावरणीय स्थिरता को भी बढ़ावा देगा।

(लेखक फेडरेशन आफ सीड इंडस्ट्री आफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक हैं)

मेलबाक्स

पाश्चात्य संस्कृति की देन है तलाक

'कठिन होता वैवाहिक रिश्तों का निर्वाह' शीर्षक से लिखे अपने आलेख में डा. ऋतु सारस्वत ने देश में वैवाहिक रिश्तों में आ रही दरार की बात उठाई है। तलाक एक ऐसा पाश्चात्य सामाजिक विकार है, जो आज भारत में भी तेजी से सिर उठा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण भारतीय युवाओं का पाश्चात्य संस्कृति के प्रति बढ़ता झुकाव है। पाश्चात्य संस्कृति में पुरुष-स्त्री संबंध को केवल यौन संबंध तक सीमित माना गया है। पाश्चात्य समाज मानव को भी एक पशु समान जीवजाति मानता है। वहीं भारतीय संस्कृति में पहले तो मानव को ही पशु नहीं माना गया है। दूसरे पुरुष-स्त्री संबंध को प्रजनन के रूप में देखा गया है, न कि यौन सुख के रूप में। यदि सूक्ष्मता से देखें तो यह पाएंगे कि पशु-पक्षी भी नित्य साथी नहीं बदलते। कई प्रजातियां तो जीवनपर्यंत एक साथी के साथ ही जीवन बिताती हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह एक बहुत ही पवित्र संबंध है, जिसका टूटना न केवल बच्चों, अपितु दोनों के परिवारों को भी बिखेर देता है। तमाम कारणों से भारत में आज पति-पत्नी के बीच दरारें उत्पन्न होने लगी हैं। भारतीय समाज को सही दिशा में लाना हमारा कर्तव्य है। युवाओं को हिंदू धर्म के सिद्धांतों से अवगत कराना होगा। भारतीय संस्कृति यदि तमाम विदेशी प्रहारों के बाद आज भी खड़ी है तो हिंदू धर्म की मजबूत बुनियाद के कारण।

एनके तवाक्ले, देहरादून

अत्यंत गरीबी से मुक्त होता देश

देश में गरीबी खत्म करने से जुड़ी कोशिशें रंग लाती हुई नजर आ रही हैं। अमेरिकन थिंक टैंक द ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट में कहा कि भारत में एक दशक में समावेशी विकास हुआ, जिसके कारण भारत अत्यंत गरीबी से मुक्त हो चुका है। आय असमानता के क्षेत्र में अभूतपूर्व गिरावट देखी गई है। उच्च वृद्धि दर और असमानता में बड़ी गिरावट ने मिलकर भारत में गरीबी को कम कर दिया है। सरकार की मजबूत सार्वजनिक वितरण नीतियों और संसाधनों के बेहतर वितरण से खासकर ग्रामीण इलाकों में उपभोग बढ़ा है जिससे गरीबी में तेजी से गिरावट आई है। शौचालय का निर्माण, बिजली का वितरण, उज्ज्वला गैस योजना, नल से जल और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने ग्रामीण आबादी को काफी हद तक प्रभावित किया है और उनको अत्यंत गरीबी क्षेत्र से मुक्ति दिलाने में व्यापक तौर पर मदद प्रदान की है। इसके साथ देश में आधारभूत संरचनाओं के विकास ने देश के विकास को नए आयाम प्रदान किए, जिसका लाभ आम ग्रामीणों तक पहुंचा। सरकार ने गरीबी को दूर करने के लिए जो उपाय किए, वे काफी सराहनीय हैं। ये योजनाएं सिर्फ आम लोगों तक पहुंची ही नहीं, बल्कि इन योजनाओं का सीधा लाभ भी मिला।

विजय किशोर तिवारी, नई दिल्ली

तलाक के बढ़ते आंकड़े

डा. ऋतु सारस्वत ने 'कठिन होता वैवाहिक रिश्तों का निर्वाह' आलेख में इस तथ्य पर विचार करने पर जोर दिया है कि विगत कुछ दशकों में वैवाहिक संबंधों में बिखराव के बढ़ते आंकड़ों के कारणों के विश्लेषण की आवश्यकता है। तलाक के बढ़ते मामले एक बड़े सामाजिक बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। उन नकारात्मकताओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जो सामाजिक ढांचे को ध्वस्त कर रहे हैं। इसके लिए पाश्चात्य सभ्यता का आंख बंद करके अनुसरण, आधुनिकता की दौड़ की होड़ में आगे रहने की मानसिकता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बढ़ती ललक और स्त्री को पुरुष से श्रेष्ठ साबित करने की बढ़ती मनोवृत्ति जिम्मेदार हैं। तलाक की बढ़ती दर इसलिए भी चिंताजनक है, क्योंकि इससे न केवल एक परिवार प्रभावित होता है अपितु समाज और देश भी प्रभावित होते हैं। तलाक लेने वाले दंपती की संतानें ज्यादा प्रभावित होती हैं। उनमें भटकाव की आशंका बढ़ जाती है। विवाह एक साझा उत्तरदायित्व है और किसी भी तलाक के मामले में किसी एक पक्ष को दोष देना अनुचित होगा। तलाक के मामलों को कम करने के लिए हम अपने सनातन मूल्यों को पुनर्स्थापित करें।

कृष्ण मोहन अग्रवाल, गौतम बुद्ध नगर

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

संपादकीय जागरण

सोमवार, 4 मार्च, 2024 : फाल्गुन कृष्ण – 8 वि. 2080

परमात्मा के प्रति भक्ति ही मुक्ति दिलाने में सक्षम है

आवश्यक सख्ती

यह अच्छा हुआ कि निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के पहले ही राजनीतिक दलों को इसके लिए आगाह कर दिया कि उनकी बेजा बयानबाजी पर निगाह रखी जाएगी और तय नियमों को तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन उसके समक्ष केवल भाषा की मर्यादा का उल्लंघन रोकने की ही चुनौती नहीं है। इसके अतिरिक्त एक बड़ी चुनौती यह भी है कि मतदाताओं को गुपचुप तरीके से पैसे बांटकर वोट हासिल करने से कैसे रोका जाए। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पिछले कुछ समय से पैसे बांटकर वोट हासिल करने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। इसका प्रमाण यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं को वितरित की जाने वाली धनराशि की बरामदगी बढ़ती चली जा रही है। निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव प्रचार के दौरान करोड़ों रुपये की राशि जब्त की जाती है, लेकिन कोई भी समझ सकता है कि इस तरह की धनराशि का एक बड़ा हिस्सा उसकी पकड़ में नहीं आता होगा।

यह भी किसी से छिपा नहीं कि बड़ी संख्या में प्रत्याशी चुनाव खर्च की तय धनराशि से कहीं अधिक पैसा अपने प्रचार में खर्च करते हैं। प्रत्याशी भले ही कागजों पर यह दिखा देते हों कि उन्होंने तय सीमा के तहत ही चुनाव प्रचार में धन खर्च किया, लेकिन हर कोई यह जानता है कि आम तौर पर ऐसा नहीं होता। सच्चाई यह है कि चाहे विधानसभा के चुनाव हों अथवा लोकसभा के, उनमें निर्धारित धनराशि से कहीं अधिक पैसा खर्च किया जाता है। यही कारण है कि चुनाव लड़ना आम आदमी के वश की बात नहीं रह गया है। एक समय था जब चुनावों में बाहुबल के साथ धनबल की भी भूमिका देखने को मिलती थी। समय के साथ बाहुबल पर तो एक बड़ी हद तक लगाम लग गई, लेकिन धनबल की भूमिका बढ़ती ही चली जा रही है। चिंताजनक यह है कि बंगाल में बाहुबल की भूमिका पर भी रोक नहीं लग पा रही है। स्पष्ट है कि चुनाव आयोग को और अधिक सक्रियता और सख्ती का परिचय देना होगा। समस्या यह है कि चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ निर्वाचन आयोग कोई कठोर कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है। इसका कारण यह है कि उसके पास पर्याप्त अधिकार नहीं हैं। कुछ दिनों पहले निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों और प्रत्याशियों को यह चेतावनी दी थी कि उनकी ओर से चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। निःसंदेह ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि देश के कुछ हिस्सों में चुनाव जीतने के लिए या तो धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल किया जाता है या फिर धर्मगुरुओं का सहारा लिया जाता है। स्पष्ट है कि इन स्थितियों में निर्वाचन आयोग को सख्ती बरतने के लिए कमर कसने की जरूरत है।

किसानों की कठिनाई

पंजाब में गत दो दिन में हुई वर्षा और ओलावृष्टि ने किसानों की कठिनाई बढ़ा दी है। मौसम की मार से खासतौर पर सरसों और गेहूं की फसल को भारी क्षति पहुंचने की आशंका व्यक्त की जा रही है। एक अनुमान के अनुसार सात सौ एकड़ रकबे में सरसों की पूरी फसल खराब हो गई है, जबकि बड़े रकबे में अगेती गेहूं की बालियां टूट गई हैं। किसानों की मुश्किलें इसलिए और बढ़ गई हैं, क्योंकि गत वर्ष मानसून के दौरान बाढ़ आने से भी कई जिलों में फसलें बर्बाद हो गई थीं। इसलिए यह आवश्यक है कि वर्षा और ओलावृष्टि से हुई क्षति से किसानों को उबारने के लिए सरकार शीघ्रता से प्रयास आरंभ करे। खराब हुई फसलों का आकलन करने के लिए शीघ्र गिरदावरी का प्रबंध किया जाना चाहिए। पहले ऐसा देखा गया है कि गिरदावरी करने में और उसकी रिपोर्ट आने में बहुत समय लग जाता है। इसके बाद मुआवजे के लिए भी किसानों को जूझना पड़ता है। ऐसे भी मामले सामने आ चुके हैं जब मुआवजे के नाम पर बहुत ही छोटी राशि देकर किसानों के साथ भद्दा मजाक किया गया है। समय पर सहायता नहीं मिलने पर किसान अक्सर कर्ज के जाल में फंसने पर मजबूर हो जाता है। सरकार और प्रशासन को इन बातों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। गिरदावरी तो शीघ्र शुरू की ही जानी चाहिए, मुआवजा बांटने की पूरी प्रक्रिया में भी पर्याप्त पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। सरकार और प्रशासन का प्रयास यही होना चाहिए कि किसानों को समय पर उचित सहायता मिल सके। इसके लिए केंद्र सरकार से भी यदि सहयोग अपेक्षित हो तो उसे लेने में संकोच नहीं किया जाना चाहिए।

> मुआवजा बांटने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रयास यही होना चाहिए कि किसानों को समय पर उचित सहायता मिल सके।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या गौतम गंभीर ने राजनीति से संन्यास लेकर ठीक किया?

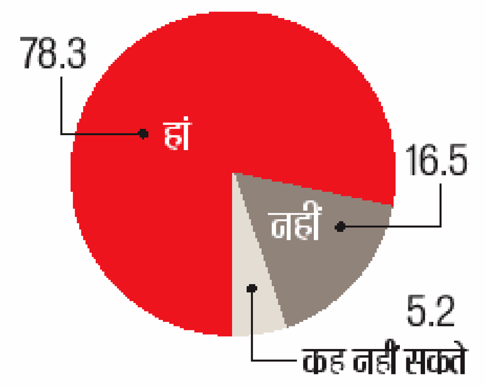

आज का सवाल
क्या अपनी पहली सूची से भाजपा विपक्षी दलों पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने में सफल रही है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

फिर बाइडन बनाम ट्रंप की तस्वीर

हर्ष वी. पंत

ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की ओर से नामांकन हासिल करने के बेहद करीब हैं। बाइडन के लिए ट्रंप की चुनौती न चार साल पहले आसान थी और न ही अब

इस मंगलवार के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारी पर एक प्रकार से मुहर लग जाएगी। हालांकि अब यह एक प्रकार की औपचारिकता ही है, क्योंकि मुकाबला मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने की पूरी स्थितियां बन गई हैं। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की ओर से नामांकन हासिल करने के बेहद करीब हैं। उम्मीदवारी की होड़ में उनकी पार्टी के कुछ अन्य प्रतिद्वंद्वी दावा छोड़कर ट्रंप के समर्थन में आ गए हैं। यहां तक कि एक समय कड़ी चुनौती पेश कर रहे विवेक रामास्वामी भी अब ट्रंप की उम्मीदवारी के पक्ष में आ गए हैं। ट्रंप के समक्ष अब केवल निक्की हेली ही अड़ी हुई हैं, लेकिन उनकी चुनौती खासी कमजोर है। यहां तक कि हेली अपने गृह राज्य साउथ कैरोलिना में भी ट्रंप की राह नहीं रोक पाईं। ऐसे में अमेरिकी चुनावों में संभवतः पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब किसी मौजूदा राष्ट्रपति को चुनाव में उस प्रत्याशी का सामना करना पड़ेगा, जो पहले भी चुनावों में आमने-सामने रह चुके हों। हालांकि इन चार वर्षों में परिस्थितियां काफी कुछ बदल चुकी हैं, लेकिन दोनों का मुकाबला पिछली बार की तरह कांटे की टक्कर जैसा रहने की उम्मीद है।

अमेरिकी मतदाताओं के लिए यह चुनाव कुछ अलग तरह का रहने वाला है। मतदाता दोनों ही प्रत्याशियों के व्यक्तित्व और नीतियों से भलीभांति परिचित हैं। ट्रंप अपने चिरपरिचित ढंग से बाइडन पर निजी हमले करने के साथ ही उनकी नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। बाइडन के लिए ट्रंप की चुनौती न चार साल पहले आसान थी और न ही अब। पिछले चुनाव तो कोविड महामारी की पृष्ठभूमि में हुए थे, जिसके चलते अमेरिका में बिगड़े हालात से बाइडन की राह कुछ आसान हो गई थी, लेकिन इस बार उन्हें ऐसी कोई स्वाभाविक बढ़त मिलती नहीं दिख रही है। पिछले चुनाव में ही बाइडन की उम्र को लेकर सवाल उठ रहे थे और अब तो ट्रंप भी 77 साल के हो गए हैं। इसी पहलू को देखते हुए राबर्ट कैनेडी जूनियर जरूर स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनौती पेश करने के प्रयास में हों, लेकिन उनकी कोशिश शायद ही कोई रंग लाए। बाइडन और ट्रंप की उम्र को देखते हुए लगता है कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ही राजनीतिक धड़े अतीत की खिड़की में कैद होकर रह गए हैं। ऐसे में यदि अमेरिकी मतदाताओं के उत्साह में कोई कमी दिखाई दे तो उस पर हैरत नहीं होनी चाहिए। यह प्राइमरी चुनाव में नजर भी आया है। प्राइमरी में 40 प्रतिशत स्वतंत्र रिपब्लिकनों ने ट्रंप के पक्ष में मतदान नहीं किया। यह असल में ट्रंप के कोर वोटर्स ही हैं, जो उन्हें उम्मीदवारी की होड़ में सबसे आगे बनाए हुए हैं। इस प्रकार देखें तो यह मुद्दाविहीन चुनाव है, जो दो व्यक्तित्वों की प्रतिद्वंद्विता पर ही कहीं अधिक केंद्रित है।

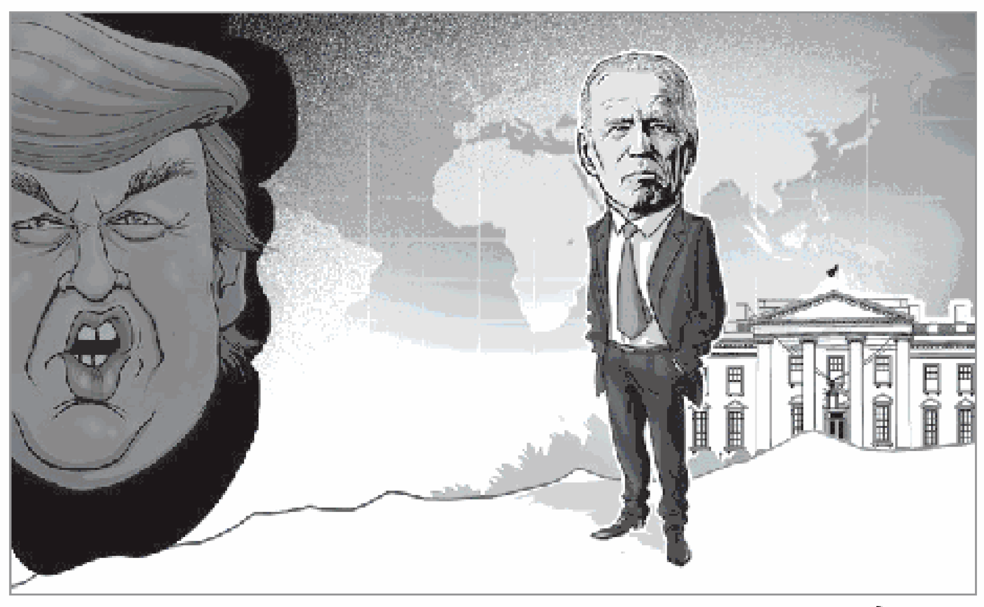

अवधेश राजपूत

ट्रंप कह रहे हैं कि दोबारा सत्ता में न आने के चलते 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' का उनका नारा अधूरा ही रह गया। ऐसे में वह मतदाताओं से एक और मौका देने की अपील कर रहे हैं। वह बाइडन की असफलताएं गिनवा रहे हैं। इसके बावजूद फिलहाल अमेरिका की घरेलू राजनीति में कोई बड़ा मुद्दा नहीं दिख रहा है। अमेरिका की आर्थिक वृद्धि दर इस समय अपेक्षाकृत बेहतर है। मुद्रास्फीति से लेकर बेरोजगारी के आंकड़े भी कुछ राहत देने वाले हैं। एक प्रकार से बाइडन घरेलू मोर्चे पर स्थायित्व लाने में सफल रहे हैं, लेकिन वह अपनी सफलता को लेकर सही नैरेटिव नहीं गढ़ पा रहे हैं। जबकि ट्रंप अपनी बातों से बाइडन को घेरने में सफल होते दिख रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो बाइडन जहां अपनी सफलता का संदेश देने में भी सफल नहीं हो पा रहे, वहीं ट्रंप उनकी सफलता को भी असफलता के रूप में पेश करने में सक्षम दिख रहे हैं।

चूंकि घरेलू स्तर पर कोई मुद्दा प्रभावित करता नहीं दिख रहा तो इस चुनाव का फैसला संभवतः विदेश नीति से जुड़े निर्णय ही करेंगे। बाइडन प्रशासन में अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर तो निकल आया, लेकिन उसकी एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। जिन परिस्थितियों में अमेरिकी फौज की अफगानिस्तान से वापसी हुई उसने अंतरराष्ट्रीय पटल पर अमेरिका की बहुत किरकिरी कराई। अमेरिका जहां अफगानिस्तान से निकला तो वह एक प्रकार से यूक्रेन में फंस गया। इजरायल-हमास युद्ध के बाद से उसे लाल सागर में भी तगड़ी चुनौती मिल रही है। पश्चिम एशिया में भी उसके लिए समीकरण कुछ गड़बड़ हो गए हैं। चीन के साथ उसकी प्रतिद्वंद्विता और तनाव में कोई कमी नहीं आई है। हमास के खिलाफ संघर्ष में बाइडन ने जिस प्रकार इजरायल का समर्थन किया है, उससे उनकी पार्टी का ही एक वर्ग खासतौर से युवा नाराज हैं। ट्रंप इस आक्रोश को अपने पक्ष में भुना सकते हैं। इस प्रकार देखें तो अमेरिकी राजनीति में एक दिलचस्प रुझान दिख रहा है। वह यह कि रूढ़िवादी मानी जाने वाली रिपब्लिकन पार्टी के नेता का रवैया उदारवादी है तो उदारवादी दृष्टिकोण के लिए जानी जाने वाली डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति बाइडन का रुख-रवैया कुछ रूढ़िवादी।

ट्रंप के उत्साहित समर्थकों का यह भी मानना है कि पुतिन के साथ अपने संबंधों के चलते वह यूक्रेन संकट का भी कोई स्वीकार्य हल निकाल सकते हैं। हालांकि ट्रंप की अस्थिर प्रवृत्ति उनके प्रति कुछ संदेह भी बढ़ाती है। हाल में नाटो को लेकर उनके बयान से अमेरिका के पारंपरिक सहयोगियों में सही संदेश नहीं गया। ट्रंप का यह रवैया जापान और ताइवान जैसे पारंपरिक अमेरिकी सहयोगियों को परेशान कर सकता है। भारत के संदर्भ में देखें तो ट्रंप का पिछला राष्ट्रपति कार्यकाल भारत के लिए मिला-जुला रहा। उनके शासन में भारत के साथ अमेरिका का व्यापार समझौता अपेक्षा के अनुरूप सिरे नहीं चढ़ पाया और उन्होंने भारत पर कुछ बंदिशें भी लगाईं, लेकिन उन्होंने चीन के खिलाफ खुला आक्रामक रवैया भी अपनाया। यह भारत के लिए मददगार साबित हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी उनके आत्मीय रिश्ते रहे। ट्रंप रणनीतिक मोर्चे पर भारत की सहायता के लिए सक्रिय रहे। वहीं, बाइडन प्रशासन के दौरान भी कई स्तरों पर भारत-अमेरिका रिश्ते निरंतर प्रगाढ़ होते गए।

(लेखक आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

अंतरिक्ष में बड़े लक्ष्य साधता भारत

मनीष पुरोहित

सफल चंद्रयान-3 के बाद गगनयान मिशन भारत को एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित करेगा

गगनयान मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वर्षों के अथक समर्पण का प्रमाण है। इसका लक्ष्य न केवल अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना है, बल्कि मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं में भारत के कौशल को प्रदर्शित करना भी है। यह मिशन भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण यात्रा में एक मील का पत्थर होगा। इस अभियान का उद्देश्य अंतरिक्ष में चार अंतरिक्ष यात्रियों के दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में तीन दिन के लिए भेजना और उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाना है। इसके लिए चुने गए चार अंतरिक्ष यात्रियों-ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला ने रूस और भारत में पांच साल के कठोर प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजर कर आने वाली चुनौतियों के लिए सावधानीपूर्वक तैयारी की है। रोबोटिक और मानव अंतरिक्ष अभियानों के बीच के अंतर को पहचानना महत्वपूर्ण है। जब मानव जीवन दांव पर होता है तो त्रुटि की गुंजाइश शून्य हो जाती है। इसके लिए सावधानीपूर्वक योजना, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। इसे स्वीकार करते हुए इसरो ने गगनयान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। विशेष रूप से इस मिशन के लिए डिजाइन किया गया एलवीएम3 लांच वाहन मानव अंतरिक्ष उड़ान को समायोजित करने के लिए सुधारों से गुजरा है। इसके अतिरिक्त एलवीएम3 के क्रायोजेनिक चरण को मानव अंतरिक्ष उड़ान के उद्देश्य से विकसित किया गया है। अब इसको एचएलवीएम3 का नाम दिया गया है। एचएलवीएम3 में चालक दल निष्कासन प्रणाली शामिल है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी आपात स्थिति में चाहे वह प्रक्षेपण स्थल पर हो या उड़ान चरण के दौरान चालक दल माड्यूल को चालक दल के साथ सुरक्षित दूरी पर ले जाया जा सके।

पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला आर्बिटल माड्यूल दो प्रमुख हिस्सों से मिलकर बना है-क्रू माड्यूल और सर्विस माड्यूल। मानवीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आर्बिटल माड्यूल अत्याधुनिक एवियोनिक्स (यान संचालन) प्रणालियों से लैस है, जिनमें अतिरिक्त बैकअप मौजूद है। क्रू माड्यूल अंतरिक्ष यात्रियों के रहने के लिए बनाया गया है।

मिशन के प्रतिभागियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ● फाइल

यह एक दोहरी दीवार वाला प्रकोष्ठ है। बाहरी दीवार ताप संरक्षण प्रणाली से सुसज्जित है। क्रू माड्यूल में चालक दल के उपकरण, दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं, जीवनरक्षक प्रणाली, एवियोनिक्स और गतिरोध प्रणालियां शामिल हैं। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अवतरण के समय चालक दल सुरक्षित रहे। इसके लिए यह पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने में सक्षम है। सर्विस माड्यूल का मुख्य कार्य कक्षा में रहते हुए क्रू माड्यूल को आवश्यक सहायता प्रदान करना है। इसमें ताप, प्रणोदन, ऊर्जा, एवियोनिक्स प्रणालियां और उपकरणों को तैनात करने के लिए आवश्यक तंत्र शामिल हैं।

हाल में चंद्रमा पर रोबोटिक साफ्ट लैंडिंग के दौरान जापान और अमेरिकी लैंडर्स को काफी तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि छोटी-सी मानवीय गलती भी राष्ट्रीय संकट बन सकती है। ये मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण की दिशा में प्रगति का प्रदर्शन करते हुए मामूली मानवीय त्रुटियों के संभावित दुष्परिणामों को भी रेखांकित करते हैं, जिनके मानव अंतरिक्ष अभियान में विनाशकारी परिणाम सामने आ सकते हैं।

गगनयान भारत की एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में कार्य करेगा। इसरो के प्रमुख सोमनाथ ने कहा है कि 2024 को गगनयान का वर्ष नामित किया गया है। इस साल गगनयान मिशन के लिए कई परीक्षण उड़ानें होंगी। अंतरिक्ष में चालक दल रहित यानी रोबोटिक अंतरिक्ष यात्री 'व्योममित्र' की तैनाती भी होगी। जबकि मानवयुक्त मिशन गगनयान अगले वर्ष यानी 2025 में लांच किया जाएगा। यह रोबोट अंतरिक्ष यात्री माड्यूल मापदंडों की निगरानी, अलर्ट जारी करने और जीवन समर्थन कार्यों को निष्पादित करने की क्षमता से लैस है। यह प्रश्नों का उत्तर देने जैसे कार्य भी कर सकता है।

गगनयान के पीछे की बड़ी आकांक्षा अंतरिक्ष में मानव को प्रक्षेपित करने में आत्मनिर्भरता हासिल करना है, जो अंततः हमें भविष्य में नियोजित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और चंद्रमा पर मानव अभियानों की बड़ी योजनाओं के लिए तैयार करेगा। भारत ने वर्ष 2035 तक अपना खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और वर्ष 2040 तक चंद्रमा पर पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री को भेजने की योजना बनाई है। इस तरह के महत्वाकांक्षी मिशन के लिए आने वाले वर्षों में भारत को बड़े पैमाने पर क्षमता निर्माण की आवश्यकता होगी। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को लांच करने के लिए भारत को प्रक्षेपण यानों के लिए भारी लिफ्ट क्षमता की आवश्यकता है। मौजूदा यान बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त हैं। इसके लिए इसरो अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यानों पर काम कर रहा है, जो वर्तमान एलवीएम3 से बहुत अधिक बड़े पैमाने पर होंगे।

कुल मिलाकर गगनयान कार्यक्रम हमें अंतरिक्ष में बड़े लक्ष्यों को हासिल के लिए तैयार करेगा। इसरो इस सपने को साकार करने के लिए कई नवाचारों पर काम कर रहा है और नई क्षमताओं का विकास कर रहा है। यह प्रयास न केवल भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ाएगा, बल्कि देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा के रूप में भी कार्य करेगा, उनकी जिज्ञासा को जगाएगा, महत्वाकांक्षा को बढ़ाएगा। चंद्रयान-3 की सफलता के बाद गगनयान एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत को एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित करने का काम करेगा।

(लेखक इसरो के पूर्व विज्ञानी हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

संबंधों की शक्ति

व्यावहारिक जगत के कार्यों के सुचालन का आधार आपसी संबंध हैं। संबंध जितने निश्छल, गहरे और सुदृढ़ होंगे, सामाजिक दायित्व और व्यावसायिक गतिविधियां भी उसी अनुपात में बेहतर संपन्न होंगी। औपचारिक, कार्यस्थलीय या कारोबारी संबंध प्रायः सतही होते हैं और आवश्यकता अनुसार निर्मित किए जाते हैं। इनमें प्रतिबद्धता, व्यक्तिगत निष्ठा या आत्मीयता का अभाव रहता है। ये कालांतर में क्षीण, परिवर्तित या नष्ट हो सकते हैं, इनकी सार्थकता निर्दिष्ट उद्देश्य सध जाने तक मान सकते हैं।

मात्र परिचय होने, मुलाकात जारी रखने या औपचारिकताएं निभाने से संबंध नहीं टिकते। गहरे और विश्वस्त संबंध वर्षों, बल्कि दशकों तक एक-दूसरे की मनोवृत्ति, दिशा समझने और अनुकूल बैठने के उपरांत बनते हैं और अनेक विवादों, मतांतरों के बाद भी जीवंत रहते हैं। इसके आलावा दुष्कर समय में एक-दूसरे का संबल बनते हैं। सच्चे और स्थायी संबंधों में महत्व संख्या का नहीं, बल्कि गहराई और निष्ठा का होता है। इनमें संदेह या आडंबर का स्थान नहीं रहता। संबंधों में महत्व उसके ईमानदारी से निर्वहन का होता है। गहरे और स्थायी संबंध के निर्माण में भारी कीमत चुकानी होती है। यहां आशय धन से नहीं, अथाह प्रेम और दूसरे की बेहतरी के प्रबल भाव का है।

तुच्छ स्वार्थों या दिखावटी आचरण में लिप्त व्यक्ति अच्छे संबंध बनाने में असमर्थ रहता है। ऐसा व्यक्ति जीवन की संध्या में एकाकी और निरीह पड़ जाता है। अनेक अध्ययनों में पुष्टि हुई है कि निश्छल संबंधों के किरदार दीर्घजीवी, खुशनुमा और स्वस्थ रहते हैं। संबंध निर्माण की शुरुआत युवावस्था में की जाती है। सदाशयता और निःस्वार्थ भाव से जुड़े दो पक्षों के संबंध को पारलौकिक कहना उचित होगा। ऐसे संबंध जीवन को अर्थ देते हैं। प्रभु से संबंध सर्वोच्च कोटि का होता है। आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टि से उच्च व्यक्ति ही इस अवस्था को प्राप्त करता है।

हरीश बड़थ्वाल

पाठकनामा

pathaknama@jal.jagran.com

पाश्चात्य संस्कृति की देन है तलाक

'कठिन होता वैवाहिक रिश्तों का निर्वाह' शीर्षक से लिखे अपने आलेख में डा. ऋतु सारस्वत ने देश में वैवाहिक रिश्तों में आ रही दरार की बात उठाई है। तलाक एक ऐसा पाश्चात्य सामाजिक विकार है, जो आज भारत में भी तेजी से सिर उठा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण भारतीय युवाओं का पाश्चात्य संस्कृति के प्रति बढ़ता झुकाव है। पाश्चात्य संस्कृति में पुरुष-स्त्री संबंध को केवल यौन संबंध तक सीमित माना गया है। पाश्चात्य समाज मानव को भी एक पशु समान जीवजाति मानता है। वहीं भारतीय संस्कृति में पहले तो मानव को ही पशु नहीं माना गया है। दूसरे पुरुष-स्त्री संबंध को प्रजनन के रूप में देखा गया है, न कि यौन सुख के रूप में। यदि सूक्ष्मता से देखें तो यह पाएंगे कि पशु-पक्षी भी नित्य साथी नहीं बदलते। कई प्रजातियां तो जीवनपर्यंत एक साथी के साथ ही जीवन बिताती हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह एक बहुत ही पवित्र संबंध है, जिसका टूटना न केवल बच्चों, अपितु दोनों के परिवारों को भी बिखेर देता है। तमाम कारणों से भारत में आज पति-पत्नी के बीच दरारें उत्पन्न होने लगी हैं। भारतीय समाज को सही दिशा में लाना हमारा कर्तव्य है। युवाओं को हिंदू धर्म के सिद्धांतों से अवगत कराना होगा। भारतीय संस्कृति यदि तमाम विदेशी प्रहारों के बाद आज भी खड़ी है तो हिंदू धर्म की मजबूत बुनियाद के कारण।

एनके तवाक्ले, देहरादून।

कांग्रेस व आप का बेमेल गठजोड़

कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली, हरियाणा, गुजरात व गोवा में एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पंजाब में दो-दो हाथ करेंगे। यह अजीबोगरीब है। देश में नई राजनीति का वादा कर सत्ता में आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वास्तव में पुराने ढर्रे की राजनीति ही कर रहे हैं। केंद्र में कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के आंदोलन से उपजी आप आज अवसरवादी राजनीति में किसी से पीछे नहीं दिख रही। चुनाव में पंजाब में कांग्रेस नेता भगवंत मान के नेतृत्व वाली आप सरकार को घेरेंगे। केजरीवाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप उछालेंगे। दूसरी तरफ, आप नेता कैप्टन सरकार के मंत्रियों के घपले-घोटालों पर तंज कसेंगे। एक मार्च को पंजाब विधानसभा के शुरू हुए बजट सत्र के दौरान कांग्रेस ने शंभू सीमा पर किसान आंदोलन में युवक शुभकरण की मौत को लेकर आप को घेरा तो सत्तापक्ष ने कांग्रेस पर राज्यपाल के अभिभाषण में विघ्न डालने का आरोप लगाया। आप-कांग्रेस का बेमेल गठबंधन उस कहानी की तरह है, जिसमें बाढ़ आने पर सभी पशु दुश्मनी भुलाकर ऊंचाई वाली जगह पर एकत्रित हो जाते हैं, लेकिन पानी उतरते ही एक-दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। देश में जिस तरह का राजनीतिक वातावरण है, उससे भाजपा की विजय की भविष्यवाणी करने वालों की संख्या बढ़ रही है। संभवतः भाजपा रूपी बाढ़ से बचने के लिए ही आप और कांग्रेस ने यह गठजोड़ किया है। विरोधी दलों में गठजोड़ होना नई बात नहीं है, लेकिन दो दल एक राज्य में गठबंधन में हों और दूसरे में एक-दूसरे से भिड़ते दिखें, ऐसे उदाहरण कम ही हैं। अब चुनाव में पंजाब की जनता ही कांग्रेस और आप के इस रिश्ते की परिणीति तय करेगी।

–राकेश सैन, गांव लिदड़ा, जालंधर

आम और खास में भेदभाव क्यों?

अकसर कहा जाता है कि कानून की दृष्टि में सब समान हैं। कानून किसी से भेदभाव नहीं करता। गहराई से देखा जाए तो यह बात एक छलावा प्रतीत होती है। साधारण और विशेष व्यक्ति को लेकर कानून अलग-अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। साधारण व्यक्ति यदि किसी कारणवश जेल चला जाए तो वह विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में वर्षों तक बंद रहता है। उसे जमानत तक मिलना मुश्किल हो जाता है। वहीं, मंत्रियों और बड़े नेताओं पर चाहे गंभीर से गंभीर आरोप लग जाएं, एजेंसियां समन भेजें, लेकिन वह जेल नहीं जाते। उलटे बाहर सरेआम घूमते हुए जनता के समक्ष दंभ भरते हैं। इसके कई उदाहरण हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव कई हजार करोड़ के चारा घोटाले, नौकरी के बदले जमीन घोटाले में सजा पा चुके हैं, लेकिन वे बीमारी के बहाने जेल से बाहर आनंद से घूम रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी कई करोड़ के नेशनल हेराल्ड घोटाले में जमानत पर हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी को बचाने के लिए पंजाब की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उसे एक वीआइपी की तरह रखा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से आठ बार समन भेजे जाने के बावजूद पेश भी नहीं हो रहे हैं। वह ईडी की कार्रवाई को ही गैरकानूनी बता रहे हैं। ऐसे कई मामले हैं, जिनसे यह अहसास होता है कि साधारण और विशेष व्यक्तियों के लिए कानून अलग-अलग है।

–कमल देव, रूपनगर

पोस्ट

भारतीय जनता पार्टी द्वारा रमेश बिधूड़ी, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और प्रवेश वर्मा के टिकट कटने का एक प्रमुख कारण है और वह है वाणी पर संयम न होना।

अमिताभ अग्निहोत्री@Aamitabh2

जहां एक ओर टिकट न मिलने पर अन्य पार्टियों में नेता मारकाट से लेकर गाली-गलौच पर उतर आते हैं, वहीं भाजपा के नेताओं की गरिमा देखिए। क्या अनुशासन है।

मीनाक्षी जोशी@IMinakshiJoshi

बंगाल के आसनसोल से पवन सिंह के टिकट का जब विरोध होने लगा तो 24 घंटे से भी कम समय में उनकी दावेदारी वापस हो गई। जबकि इसी राज्य में तृणमूल कांग्रेस का अपराधी नेता शाहजहां शेख 55 दिनों तक फरार रहा। दोनों राजनीतिक दलों में अंतर बताने के लिए यही एक पहलू पर्याप्त है।

अजीत दत्ता@ajitdatta

पिछले दस वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री आवास पर भाजपा संगठन की कोई आधिकारिक बैठक नहीं हुई। हर ऐसी बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अन्य पार्टी नेताओं की तरह भाजपा मुख्यालय आए। अब वह अन्य उम्मीदवारों की तरह टिकट मिलने के लिए पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद भी दे रहे हैं।

अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

जनपथ

'भारत जोड़ो' यात्रा का है लंबा रूट,
इसमें तो इंग्लैंड भी नहीं रहा है छूट।
नहीं रहा है छूट प्रेरणा नेहरू पाए,
अब राहुल भी जाय वहीं हाजिरी बजाए।
है विदेश से प्रेम प्रथम तो इसको छोड़ो,
जब फुर्सत मिल जाय शौक से 'भारत जोड़ो'!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचंद्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीरज शर्मा द्वारा एससीओ-127-128, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर-9 सी, मध्यमार्ग, चंडीगढ़ से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा दैनिक जागरण प्रेस, सी-178, फेज 8-बी, इंडस्ट्रियल एरिया, मोहाली से मुद्रित, संपादक (पंजाब) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय संपादक (पंजाब)-अमित शर्मा* दूरभाष : कार्यालय 0172-2741011, प्रेस: 0172-4650423, E-mail: chandigarh@chg.jagran.com, रजि. नं. CHAHIN/2013/50629 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा उनसे उत्पन्न समस्त विवाद चंडीगढ़ न्यायालय के अधीन होंगे। वर्ष 12 अंक 6

https://t.me/AllNewsPaperPaid

****

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –वाल्तेयर

राजस्थान पत्रिका
• संस्थापक •
कर्पूर चन्द्र कुलिश

आर्थिक मोर्चे पर उत्साह में वृद्धि करते आंकड़े

अमरीकी थिंक टैंक ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन की यह रिपोर्ट राहत देने वाली है कि भारत में 'अत्यधिक गरीबी' अब खत्म होने के कगार पर है। राष्ट्रीय नमूना सर्वे कार्यालय (एनएसएसओ) के खर्च और खपत डेटा के आधार पर तैयार इस रिपोर्ट में कहा गया है कि तेज विकास और असमानता में कमी के कारण भारत में अब अत्यधिक गरीबों की आबादी तीन फीसदी से कम रह गई है। गरीबी उन्मूलन के मोर्चे पर यह ऐतिहासिक उपलब्धि है। भारतीय राजनीति में आधी सदी पहले से लगाया जा रहा 'गरीबी हटाओ' का नारा अब सही अर्थों में धरातल पर उतर रहा है।

नीति आयोग ने भी पिछले महीने एक रिपोर्ट में बताया था कि सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों के कारण पिछले नौ साल में करीब 25 करोड़ लोगों को 'बहुआयामी गरीबी' से बाहर निकालने में मदद मिली है। गरीबों की आबादी के चिंताजनक आंकड़े कई साल से भारत को विकसित देश बनाने की राह में सबसे बड़ी बाधा बने हुए हैं। इस दृष्टि से 'अत्यधिक गरीबी' का करीब-करीब उन्मूलन बहुत महत्वपूर्ण है। इन उम्मीदों को नई जमीन मिली है कि भारत अब गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का स्तर ऊंचा करने की दिशा में भी ठोस कदम उठाएगा। संयुक्त राष्ट्र की 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2005-06 से 2019-21 तक के 15 साल में 41.5 करोड़ लोगों को गरीबी से उबारा गया। इस रिपोर्ट में भोजन, ईंधन, शौचालय और आवास की कमी को गरीबी के चार प्रमुख कारक बताया गया था। कोरोना काल के बाद सरकार गरीबों के लिए मुफ्त राशन के साथ उन्हें ईंधन, शौचालय और आवास सुलभ कराने के लिए भी योजनाएं चला रही है। सुखद संयोग है कि पिछले हफ्ते एक के बाद एक भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर उत्साहित करने वाली खबरें मिली हैं। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में अनुमान जताया गया कि अगले पांच साल में दुनिया में अति अमीर (अल्ट्रा रिच) लोगों की आबादी भारत में सबसे तेजी से बढ़ेगी। फिलहाल देश में ऐसे 13,263 लोग हैं, जो 2028 तक बढ़कर 19,908 हो जाएंगे।

इसी बीच, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़े जारी कर बड़ा धमाका किया। इनके मुताबिक 31 दिसंबर, 2023 को पूरी हुई तिमाही में देश की जीडीपी 8.4 फीसदी की दर से बढ़ी। अगर यही शानदार रफ्तार आगे भी कायम रहती है तो 2023-24 में जीडीपी की विकास दर आठ फीसदी रह सकती है। यह अनुमान आश्वस्त करता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था न सिर्फ निरंतर गतिशील है, बल्कि विकसित देश के लक्ष्य को और करीब लाने की दिशा में बढ़ रही है।

समाज : लोगों में देश की संस्कृति को जानने और समझने की ललक तेजी से बढ़ी

धार्मिक पर्यटन के प्रति बढ़ता रुझान देश की अर्थव्यवस्था के लिए बना वरदान

विजय गर्ग
आर्थिक विशेषज्ञ और भारतीय एवं विदेशी कर प्रणाली के जानकार
@patrika.com

भारत की अर्थव्यवस्था का धर्म और आस्था से सदियों पुराना नाता है। देश के कई शहर केवल मंदिरों के कारण अस्तित्व में आए। आज इन शहरों की अर्थव्यवस्था मंदिरों के कारण ही चलती है। देश में कई ऐसे मंदिर हैं, जिनकी सालाना आय लाखों-करोड़ों रुपए में है। यह आंकड़ा दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। विशेषकर अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में धार्मिक पर्यटन को जैसे पंख लग गए हैं। एक समय था कि जब देसी पर्यटक विदेशों में घूमने के लिए लालायित रहते थे, लेकिन अब यह ट्रेंड तेजी से बदल रहा है और बड़ी संख्या में हर उम्र और लिंग के लोग धार्मिक पर्यटक बन रहे हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक सुखद बात है।

जरा इन आंकड़ों पर नजर डालें। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 के दौरान 66 लाख से अधिक विदेशी श्रद्धालु भी भारत के तीर्थस्थलों तक पहुंचे। ऐसा नहीं है कि केवल अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है, काशी विश्वनाथ के जीर्णोद्धार के बाद वहां श्रद्धालुओं की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्ष 2020 में जहां काशी विश्वनाथ में 80 लाख पर्यटक आए थे, वहीं वर्ष 2021 में यह संख्या बढ़कर 7.30 करोड़ हो गई। काशी विश्वनाथ धाम का दान वर्ष 2022 में 500 गुना बढ़कर 100 करोड़ हो गया। अनुमान है कि अयोध्या में एक साल में 5 करोड़ श्रद्धालु आएंगे और यह आंकड़ा वेटिकन सिटी और मक्का को पीछे छोड़ देगा।

एक रिपोर्ट के अनुसार देशभर के तीर्थस्थलों की यात्रा में काशी शीर्ष पर है। तिरुपति, अमृतसर, पुरी और हरिद्वार में भी श्रद्धालुओं की संख्या में जबर्दस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वर्ष 2021 के मुकाबले वर्ष 2022 में शिरडी में 483 प्रतिशत, तिरुपति में 233 प्रतिशत और पुरी में 117 प्रतिशत श्रद्धालु ज्यादा पहुंचे, जबकि मथुरा, महाबलेश्वर और मदुरै उभरते आध्यात्मिक स्थानों में शामिल हैं। वर्ष 2022 में देश के मंदिरों की कुल कमाई 1.34 लाख करोड़ रुपए हुई, जबकि एक साल पहले वर्ष 2021 में मंदिरों की आय मात्र 65,000 लाख रुपए के आसपास थी। तिरुपति बालाजी में वर्ष 2022 में 2.37 करोड़ श्रद्धालु आए, जबकि वर्ष 2021 में मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 1.04 करोड़ थी। वर्ष 2022 में श्रद्धालुओं से चढ़ावे के रूप में 1,450 करोड़ रुपए मिले। इसी तरह, तमिलनाडु के रामेश्वरम में प्रति वर्ष एक करोड़ से अधिक श्रद्धालु हर वर्ष आते हैं। वर्ष 2023 का आंकड़ा अभी आना बाकी है। निश्चित रूप से यह आंकड़ा बहुत बड़ा रहने वाला है। एसबीआइ की एक रिपोर्ट के अनुसार अकेले उत्तर प्रदेश को वित्त वर्ष 2024-25 में 25,000 करोड़ रुपए के टैक्स कलेक्शन की उम्मीद है। इस राजस्व में सबसे बड़ा योगदान अयोध्या का रहने वाला है।

> धार्मिक पर्यटन न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने वाला है, बल्कि इससे दुनिया में भारत की ताकत भी बढ़ रही है। दुनिया के लोग आध्यात्मिक भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं। देशवासियों का बढ़ता धार्मिक विश्वास देश की अर्थव्यवस्था के लिए वरदान साबित हो रहा है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की वर्ष 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में धार्मिक पर्यटन से जुड़ी अर्थव्यवस्था करीब 3 लाख करोड़ रुपए थी। देश की जीडीपी में धार्मिक पर्यटन का योगदान 2.32 प्रतिशत था। ये आंकड़े पुराने हैं, जबकि 22 जनवरी को अयोध्या में राममंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान देश में एक लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था।

अकेले उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले एक साल में अयोध्या, काशी, मथुरा और आगरा की 32 करोड़ श्रद्धालुओं ने यात्रा की। धार्मिक पर्यटन के बल पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर करने का दावा कर रहे हैं। अयोध्या, काशी के अलावा शिरडी, उज्जैन, तिरुपति, पुरी, मथुरा, महाबलेश्वर, मदुरई, गुवाहाटी, उत्तराखंड में चार धाम यात्रा आदि में पिछले सालों में श्रद्धालुओं में बहुत बढ़ोतरी देखी गई है। वैष्णो देवी में वर्ष 2023 में 94 लाख तीर्थयात्री पहुंचे, जो पिछले 10 साल में सबसे अधिक हैं। देशभर में मंदिरों में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों का भी विशेष योगदान है।

केंद्र सरकार की वर्ष 2014-15 में शुरू की गई 'प्रसाद' यानी 'पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑग्मेंटेशन ड्राइव' स्कीम ने गंगोत्री से गंगासागर, द्वारकाधीश से जगन्नाथ पुरी, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा, बद्रीनाथ विशाल से सेतुबंध रामेश्वरम, चारधाम यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा, कांवड़ यात्रा, शक्ति पीठ जैसी धार्मिक यात्राओं को और बेहतर बनाया है। 'प्रसाद' स्कीम के तहत 10 साल में देशभर में 46 धार्मिक स्थलों के विकास के लिए पैसे दिए गए हैं। हाल में 26 नए प्रोजेक्ट और जोड़े गए हैं। बीकानेर के करणी माता मंदिर, दतिया के पीतांबर पीठ, मुरैना के शनिदेव मंदिर, अमृतसर के दुर्गायान मंदिर जैसे कई मंदिरों को 'प्रसाद' स्कीम के तहत विकसित किया जा रहा है। इन्हें पर्यटन के रोडमैप पर लाया जा रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश में बुद्धिस्ट सर्किट को भी विकसित किया जा रहा है। 'प्रसाद' स्कीम पर्यटन अर्थव्यवस्था को बूस्ट कर रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्य सरकारें धार्मिक स्थलों को पर्यटन के रोडमैप पर लाने में जुटी हैं। मंदिरों का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जा रहा है। इसी साल पेश किए गए राजस्थान के अंतरिम बजट में 20 मंदिरों के विकास के लिए 300 करोड़ रुपए दिए गए। देश की संस्कृति को जानने और समझने की ललक भी लोगों में तेजी से बढ़ रही है। धार्मिक पर्यटन से केवल मंदिरों की ही आय नहीं हो रही, इससे ट्रांसपोर्ट, होटल व फूड इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री भी फलफूल रही है। मंदिरों के आसपास के दुकानदारों और स्ट्रीट वेंडरों का भी घर चल रहा है। रोजगार सृजित हो रहे हैं।

बढ़ते धार्मिक पर्यटन का अंदाजा इस बात से लगता है कि नए साल के लिए गोवा और नैनीताल से ज्यादा अयोध्या में होटलों की बुकिंग हुई। एक कंपनी ने इस साल के अंत तक देश के कई धार्मिक स्थलों में 400 से अधिक होम स्टे और होटल खोलने की घोषणा की है। इनमें अयोध्या, पुरी, हरिद्वार, कटरा, वैष्णो देवी, शिरडी, वाराणसी, अमृतसर, चारधाम के रूट और तिरुपति शामिल हैं।

मुद्दा : अमरीकी वायु सैनिक के आत्मदाह का मामला

अतिवादी कदम, लेकिन हमले झेल रहे लोगों को मिला स्वर

एस. हामिद
स्तंभकार और 'द प्रॉब्लम ऑफ डेमोक्रेसी' पुस्तक के लेखक
द वाशिंगटन पोस्ट से विशेष अनुबंध के तहत

अमरीकी वायु सेना से जुड़े सैनिक आरोन बुशनेल ने वाशिंगटन में इजरायली दूतावास के बाहर खुद को आग लगा ली। झुलसने के कारण बाद में उसकी मौत हो गई। देश राजनीतिक द्वंद्व से जूझ रहा है, खासकर गाजा युद्ध में अमरीकी प्रशासन की नीतियों को लेकर। लोग इस कृत्य की व्याख्या अलग-अलग तरीके से कर रहे हैं। यरुशलम पोस्ट के माइकल स्टार ने इस आत्मघाती विरोध को 'हिस्टीरिया की स्थिति' बताया है तो पत्रकार मार्क जोसेफ स्टर्न ने कहा-'मानसिक बीमारी से पीड़ित लोग सहानुभूति के पात्र हैं, लेकिन जान देने की तारीफ करना बेहद गैरजिम्मेदाराना है।' बिना सबूत के इस कृत्य को मानसिक बीमारी मान लिया गया।

बुशनेल ने जो कदम उठाया, उसे आसानी से अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसे अरब स्प्रिंग आंदोलन से समझा जा सकता है। इसकी शुरुआत ट्यूनीशिया में 17 दिसम्बर 2010 को स्ट्रीट वेंडर मोहम्मद बौआजिजी के आत्मदाह के साथ हुई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उसे एक नायक बताते हुए उसकी तुलना नागरिक अधिकारों की प्रतीक रोजा पार्क्स से की थी। हमें बौआजिजी के राजनीतिक विचारों या उसके पारिवारिक जीवन के बारे में बहुत कम मालूम है और बहुत कम लोगों ने उनके बारे में जानने की जरूरत समझी है। उसकी मौत को शायद ही कभी पश्चिमी मीडिया ने महज आत्महत्या के रूप में वर्णित किया गया हो। उसका उद्देश्य न्यायसंगत था, और इससे पैदा हुई क्रांतियों के कारण यह और भी न्यायसंगत हो गया। हम कैसे निर्णय करें कि क्या उचित है और क्या नहीं? लगता है कि बुशनेल ने अपने चरम कदम के बारे में सावधानी से सोचा था, समाचार संगठनों को अपने विरोध के बारे में घंटों पहले सचेत किया था। जैसे ही उसने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डाला, उसने स्वीकार किया कि 'मैं विरोध के 'चरम कृत्य' में शामिल होने जा रहा हूं।' दार्शनिक माइकल चोलबी ने आत्महत्या पर अपनी लिखी पुस्तक में स्पष्ट लिखा है कि खुद को मारना बहुत मुश्किल भरा काम है। बुशनेल के राजनीतिक विचार अतिवादी हो सकते हैं। बहुत लोगों को सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए उनके विचार बेतुके, मूर्खतापूर्ण और निंदनीय भी लग सकते हैं। उसका मानना था कि विशेषाधिकार प्राप्त अमरीकी श्वेत व्यक्ति के रूप में यह सवाल करें कि फिलिस्तीनी और अन्य वंचित वर्ग अपने उत्पीड़न पर कैसे प्रतिक्रिया दे। बुशनेल के एक आलोचक का कहना है कि बौआजिजी अपनी ही सरकार का विरोध कर रहे थे, जबकि बुशनेल 'दूरस्थ जातीय-धार्मिक संघर्ष' से खुद को चिंता में डाले हुए था। उसका युद्धरत क्षेत्र से कोई पारिवारिक संबंध नहीं था। ऐसे मामले में इतनी तीव्र प्रतिक्रिया का क्या औचित्य।

> लगता है कि बुशनेल ने आत्मदाह जैसा कदम उठाने से पहले गंभीरता से सोचा था, समाचार संगठनों को भी अपने विरोध के बारे में पहले बता दिया था।

अमरीका, इजरायल का मुख्य सैन्य संरक्षक है और जरूरी आपातकालीन हथियार और सामग्री की आपूर्ति करता है। यूएस एयर फोर्स ने गाजा पर इजरायल को बमबारी के लिए खुफिया जानकारी भी दी है। दूसरी ओर बुशनेल ने आत्मदाह से पहले कहा कि- 'मैं यूएस एयर फोर्स का एक एक्टिव ड्यूटी सदस्य हूं। मैं अब नरसंहार में भागीदार नहीं बनूंगा। मैं विरोध के चरम कृत्य में शामिल होने जा रहा हूं।'

एक मृत व्यक्ति की मानसिक हालात पर अटकलों की बजाय, हमारे पास जो जानकारी है, उसके आधार पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बुशनेल गाजा युद्ध में अमरीका की भूमिका के बारे में ज्यादा निराश क्यों हो गया था। इस युद्ध में लगभग 30,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं।

गाजा में इजरायल का युद्ध 21वीं सदी में अब तक के सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक है। 2013 से 2016 तक अलेप्पो के लिए सीरियाई शासन की लड़ाई के दौरान और 2017 में अमरीका की अगुवाई में इस्लामिक स्टेट को हराने के लिए चले अभियान के मुकाबले इजरायल ने बहुत कम समय में ज्यादा इमारतों को तहस-नहस किया है। बुशनेल ने जो किया वह सनक भरा कदम हो सकता है, लेकिन उसने हमले झेल रहे निरीह लोगों की बेबसी को लेकर जो भावनाएं जताई हैं, उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती।

कामरूप से कच्छ तक ■ पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का भविष्य तृणमूल कांग्रेस के साथ होने वाले गठबंधन पर टिका

बंगाली अस्मिता और भ्रष्टाचार बन रहे प्रमुख चुनावी मुद्दे

देश का चुनावी मिजाज
लोकसभा चुनाव 2024

देवेंद्र गोस्वामी

पूरी दुनिया में शांति निकेतन का नाम प्रसिद्ध है। बंगाल को सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे ले जाने के कारण कविगुरु रवींद्रनाथ टैगोर को पूरे बंगाल में गुरु और ठाकुर का दर्जा प्राप्त है। बंगला में ठाकुर का मतलब भगवान होता है। पश्चिम बंगाल को समझने के लिए मैं बीरभूम जिले में बोलपुर पहुंचा। रात 2 बजे बोलपुर स्टेशन पर उतरा तो वहां रविंद्र दा की कलाकृति पूरे परिसर में दिख रही थी। छोटे से स्टेशन के बाहर चहल-पहल थी, पूछने पर एक ऑटो वाले ने बताया कि दुनियाभर के साहित्य और कला प्रेमी यहां आते हैं।

प. बंगाल

सुबह शांति निकेतन यानी विश्व भारती विश्वविद्यालय पहुंच गए। एक किलोमीटर के रास्ते में पैदल चलते विद्यार्थी, साइकिल से आते-जाते स्थानीय लोग और कुछ मोटर गाड़ियां नजर आईं। विश्वविद्यालय के फर्स्ट गेट के बाहर कुल्हड़ की चाय के साथ वहां मिले छात्र नेता सोमनाथ साव। उनसे राज्य के हालात पर चर्चा शुरू हुई। कहने लगे कोई भी पार्टी लोगों का जीवन स्तर सुधारने की दिशा में कार्य नहीं कर रही है। नया निवेश नहीं हो रहा है। चर्चा में पास खड़े असित दास बोले- जिस टैगोर ने पूर्वी और पश्चिमी दुनिया के बीच सेतु बनने का काम किया था, उन्हें अब भुलाया जा रहा है। जितना काम यहां होना चाहिए था, वह हो नहीं पाया। सारे संसाधन होने के बाद भी प. बंगाल बीमारू राज्यों की श्रेणी में शामिल होता जा रहा है।

विश्वविद्यालय राजनीति का अखाड़ा

यूनेस्को ने पिछले साल 17 सितंबर को शांति निकेतन को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। इसके बाद विश्व भारती विश्वविद्यालय में पट्टिकाएं लगाने पर विवाद हो गया था। कई जगह लगी पट्टिका में पदेन कुलाधिपति प्रधानमंत्री और कुलपति का नाम है, लेकिन विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले रविंद्र नाथ टैगोर का उल्लेख नहीं होने पर विरोध होने लगा।

शांति निकेतन स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय में विद्यार्थी। यहां शिक्षा लेने दुनियाभर से युवा आते हैं।

2019 में हुए लोकसभा चुनाव की स्थिति

कुल सीट 42

पार्टी	सीट
तृणमूल कांग्रेस	22
भाजपा	18
कांग्रेस	02

वोट प्रतिशत

पार्टी	वोट प्रतिशत
तृणमूल कांग्रेस	43.69%
भाजपा	40.64%
कांग्रेस	5.67%
सीपीआइ	6.34%

■ केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रशासन नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के साथ कानूनी विवाद में उलझा

भ्रष्टाचार का मुद्दा चर्चा में : छात्र राजनीति से जुड़े सोमनाथ ने बताया कि यहां की जनता किस तरफ जाएगी, यह तय नहीं है। संगठन को मजबूत बनाने के लिए भाजपा को यहां की संस्कृति को आदर देना होगा। अभी भाजपा को लेकर यह चर्चा है कि टीएमसी में जब तक कोई नेता है तो वह भ्रष्ट है, लेकिन भाजपा में जाते ही साफ हो जाता है। सुकांत ने कहा कि राज्य में सबसे बड़ा मद्दा भ्रष्टाचार है। पहले राज्य सरकार किसानों से सीधे अनाज खरीदती थी अब एजेंटों के माध्यम से खरीदी हो रही है। हर काम में कमीशनखोरी हो रही है।

बंगाली अस्मिता के अपमान का आरोप

विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा जिस तरह से आक्रमक थी, अब ऐसा माहौल नहीं है। प्रतीक चटर्जी बोले- तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ बंगाली अस्मिता को हथियार बनाया है। रविंद्र नाथ टैगोर को नजरअंदाज करने का मामला हो या अमर्त्य सेन के खिलाफ नोटिस, इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। प. बंगाल में इन दोनों नोबेल विजेताओं का बहुत सम्मान है। इनका अपमान कोई भी बंगाली बर्दाश्त नहीं करेगा। इस वजह से तृणमूल खुलकर मैदान में है। वहीं भाजपा के बंगाली नेता इस पर अपनी राय व्यक्त करने से बच रहे हैं। सारा पत्राचार और बयानबाजी विश्वविद्यालय प्रशासन और तृणमूल नेताओं के बीच हो रही है। विधानसभा चुनाव में भी तृणमूल की जीत का प्रमुख बंगाली अस्मिता का मुद्दा ही रहा।

सभी जिलों में नहीं बन पाया है संगठन

पश्चिम बंगाल में 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी थी। चुनाव से पहले कई सर्वेक्षणों ने तो सत्ता की चाबी भाजपा को दे दी थी, लेकिन 294 विधानसभा सीटों में से 77 पर संतोष करना पड़ा। हालांकि भाजपा तृणमूल के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और 37.97 प्रतिशत वोट पाने में सफल हुई। विपक्ष के रूप में भाजपा राज्य सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। भाजपा का सभी जिलों में अभी संगठन तैयार नहीं हो पाया है। विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल ने खुद को और मजबूत करने का प्रयास किया। इसका असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है।

कांग्रेस-लेफ्ट के लिए अस्तित्व की लड़ाई

प. बंगाल में 34 साल तक सरकार चलाने वाला वाम मोर्चा अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। पिछले लोकसभा और विधानसभा में एक सीट भी नहीं जीत पाने के कारण अब पार्टी की चर्चा भी नहीं होती। बोलपुर में मिले निजामुतुल्ला ने बताया कि लेफ्ट पार्टियों के नेता अब जाग रहे हैं। कई शहरों में इनके पार्टी ऑफिस फिर से खुल रहे हैं। फिलहाल लेफ्ट का यूथ विंग सक्रिय हो रहा है। यह पार्टी के लिए अच्छा संकेत है। वहीं कांग्रेस के लिए भी स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। फिलहाल दो सीटें हैं, लेकिन जनाधार नहीं बढ़ा है। कांग्रेस का भविष्य अब तृणमूल के साथ होने वाले गठबंधन पर टिका है।

भाजपा को करनी होगी कड़ी मेहनत

व्यवसायी धीरेन दास ने कहा कि ममता बनर्जी सीधे लोगों से जुड़कर बात करती हैं। वे भाषण नहीं देतीं। हर सप्ताह किसी क्षेत्र में जाती हैं और महिलाओं से सीधे संवाद करने लगती हैं। महिलाओं के नाम पर कई योजनाएं चला रखी हैं, जिनका सीधा लाभ मिल रहा है। लक्ष्मी भंडार स्कीम के तहत परिवार की महिला मुखिया को वित्तीय सहायता दी जाती है। हाल ही में इस योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है। तृणमूल के किले में सेंध लगाने के लिए भाजपा को बहुत मेहनत करनी होगी।

नेतृत्व

दूसरों की भावनाएं समझना मददगार

रिमोट वर्क के युग में सहानुभूति ज्यादा महत्त्वपूर्ण हो गई है

किसी भी संस्थान का नेतृत्व करते समय सहानुभूति का विकास नन्हे पौधे की देखभाल करने के समान है। इसके लिए समर्पण, अंतर्दृष्टि और उचित पोषण के साथ ही स्नेहिल स्पर्श की आवश्यकता होती है। इसकी यात्रा आत्म-प्रतिबिंब और आत्म-जागरूकता के अभ्यास से शुरू होती है। सामान्य शब्दों में, यह आत्मनिरीक्षण वह मिट्टी है जहां से सहानुभूति पनपती है और लीडर को दूसरों की भावनाएं समझने में भी मदद मिलती है।

प्रो. हिमांशु राय
निदेशक, आइआइएम इंदौर
@patrika.com

अगला कदम है सहानुभूतिपूर्ण संचार के लिए रणनीति विकसित करना। इससे लीडर समझ और अभिव्यक्ति के बीच के अंतर को समझ सकते हैं, जिससे वे दूसरों के अनुभवों को मान्यता देते हैं और स्वीकार करते हैं। यह प्रक्रिया एक नई बोली सीखने के समान है, जो सीधे टीम के सदस्यों के मन से हमें संवाद करने में सहायक होती है। अंतिम चरण है सहानुभूति प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करना। ये कार्यक्रम संस्थान के सभी सदस्यों को एक साथ सीखने का अनुभव प्राप्त करने, व्यक्तिगत कौशल विकसित करने और सहानुभूति की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार सहानुभूति विकसित करना सिर्फ एक व्यक्तिगत प्रयास नहीं है, क्योंकि यह पूरे संगठनात्मक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है।

इस पूरे प्रयास में हो सकता है कि लीडर भ्रमित हो कर सहानुभूति पर अत्यधिक जोर दे और उसे सर्वव्यापी समाधान के रूप में देखें। इससे निर्णायकता या मुखरता की कमी हो जाती है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि करुणा का भाव आपकी निर्णय लेने में आवश्यक दृढ़ता पर हावी न हो जाए। एक अन्य चुनौती पूर्वाग्रह से बचते हुए विविध दृष्टिकोणों को समझना है।

रिमोट वर्क और डिजिटल कम्युनिकेशन के युग में, सहानुभूति और भी महत्त्वपूर्ण हो गई है। यह सुनिश्चित करती है कि डिजिटल परिदृश्य में मानवीय संबंध न टूटें। लीडरों को सहानुभूति के कौशल को आभासी वातावरण के लिहाज से अनुकूलित करना चाहिए, सूक्ष्म संकेतों को समझना चाहिए जो अक्सर आमने-सामने की बातचीत में अधिक स्पष्ट होते हैं। उभरती गतिशीलता के लिए लीडरों को तैयार करने से जुड़े नेतृत्व विकास कार्यक्रमों में सहानुभूति के गुण को जोड़ना महत्त्वपूर्ण है।

आपकी बात

दलालों पर अंकुश जरूरी

जमीन की खरीद-बिक्री को नियंत्रित करना जरूरी है। इसके लिए दलालों पर अंकुश आवश्यक है, जो कमीशन के लिए जमीनों के दाम बढ़ाते रहते हैं। दलाली संबंधी नियम-कानून भी बनें। रहने के लिए घर खरीदा जाए, निवेश के लिए नहीं। खरीदी कीमत और रजिस्ट्री में दर्ज कीमत एक ही हो।

-मुकेश भटनागर, भिलाई, छत्तीसगढ़

संयुक्त परिवारों को मिले बढ़ावा

अगर समाज में संयुक्त परिवार को बढ़ावा देंगे तो नए मकानों की खपत कम होगी और अपने आप ही मकानों की कीमतें कम हो जाएंगी। इससे परिवार भी आपस में जुड़ेंगे और बुजुर्गों की भी देखभाल अच्छी तरीके से होगी। उनको वृद्धाश्रम नहीं भेजना पड़ेगा। यहां बच्चों को अच्छे संस्कार भी मिल जाएंगे।

-दिव्या भास्कर, कोटपुतली

आज का सवाल

निजी अस्पतालों के शुल्क को लेकर विवाद क्यों होते रहते हैं?

ईमेल करें
edit@epatrika.com

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की प्रतिक्रियाएं

पत्रिकायन का सवाल था, ' मकानों की कीमतें कैसे कम हो सकती हैं? ' इस मुद्दे पर कई प्रतिक्रियाएं आईं। इनमें से कुछ ऑनलाइन भी दी जा रही हैं।

इसे स्कैन करें
rb.gy/bjy9yg

https://t.me/AllNewsPaperPaid

चिंतन

'कश्मीर राग' की बजाय पाक को संभालें शाहबाज

पाकिस्तान कठिन आर्थिक व राजनीतिक दौर से गुजर रहा है। इस कठिन दौर में पीएमएल-एन नेता शाहबाज शरीफ ने पीएम के रूप में पाक की कमान संभाली है। सत्ता में आते ही दूसरी बार पीएम बनने वाले शरीफ ने अपने पहले संबोधन में उम्मीद के अनुरूप ही सबसे पहले कश्मीर व फिलीस्तीन का राग अलापा है। भाषण के दौरान शाहबाज ने कहा, 'इजराइल लगातार गाजा में बमबारी कर रहा है, वहीं कश्मीर में लोगों की हत्या हो रही है। फिलिस्तीनियों और कश्मीरियों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुदाय चुप्पी साधे हुए हैं। हम सबको साथ मिलकर कश्मीर और फिलिस्तीन की आजादी के लिए संसद में एक प्रस्ताव पास करना चाहिए।' शाहबाज के ऐसे बयान से साफ है कि पाक की नई सरकार भी अपने पड़ोसियों से संबंध बेहतर करने के प्रति सजग नहीं है। माना जा रहा था कि नवाज शरीफ के सत्ता में लौटने पर पाकिस्तान भारत से संबंध सुधारने का प्रयास करेगा। लेकिन जैसा पाकिस्तान की फौज व खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत से संबंध सुधारना नहीं चाहती है और इसलिए कश्मीर को लेकर अनर्गल बयानबाजी करती रहती है, शाहबाज ने साफ कर दिया कि उनकी सरकार भी पाकिस्तानी एस्टाब्लिशमेंट के इशारों पर ही चलेगी। पाकिस्तानी फौज, खुफिया एजेंसी आईएसआई, पाक की सुप्रीम अदालत और चीन जैसी विदेशी शक्तियों ने मिलकर पाकिस्तानी लोकतंत्र का क्या हश्र किया, जिसमें पूर्व पीएम इमरान खान व उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) को चुनाव से ही बाहर कर दिया। यह पाकिस्तान में ही हो सकता है कि एक व्यक्ति को सत्ता से दूर रखने के लिए उन पर आरोप लगाने के बाद उनकी पार्टी को ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया 'चुनाव' में भाग लेने से रोक दिया जाय, पर पाक आवाम की ताकत ऐसी कि, इमरान की पीटीआई समर्थित उम्मीदवार ही सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे, इससे फौज, आईएसआई, कोर्ट व विदेशी ताकतों की चौकड़ी की पाक आवाम के सामने पोल खुल गई, कि जनता की आवाज को दबाई नहीं जा सकती है। चौकड़ी की बिछाई बिसात के बाद पीएमएल-एन व पीपीपी की बेशक सरकार बनी हो, जिसमें सबने अपने-अपने हिस्से मुकर्रर किए हों, पर इस सरकार को पता है कि उसे जनादेश प्राप्त नहीं है, यह कैसे बनी है और किसके मुखौटे बन कर काम करेगी? शाहबाज शरीफ ने अपनी पहली तकरीर में कश्मीर राग अलाप कर अपने मुखौटे होने की झलक दिखा दी है। भारत का साफ संदेश है कि पहले पाकिस्तान अपने यहां आतंकवाद का सफाया करे, उसके बाद ही बातचीत संभव है। अब पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेना है, जिसमें वह आनाकानी करता रहा है। शाहबाज शरीफ ने शपथ के बाद आतंकवाद को खत्म करने का सरकारी बयान जरूर दिया है, लेकिन वे जमीन पर कितना एक्शन ले पाएंगे, यह पाक फौज व आईएसआई के इरादे पर निर्भर करेगा। पाक फौज व आईएसआई गुड टेरर व बैड टेरर में फर्क करती रही हैं और भारत में उपद्रव मचाने के लिए अपने हिसाब के आतंकवादी गुटों को पोषित करती रही हैं। पाक की नई शाहबाज सरकार को कश्मीर राग अलापने की बजाय अपने खस्ताहाल मुल्क को पटरी पर लाने का संकल्प लेना चाहिए, उन्हें समझना होगा कि शांति, विकास से खुशहाली आएगी, पाक आवाम को कश्मीर के सपने दिखाने से नहीं। नवनिर्वाचित पीएम शाहबाज शरीफ को पहले अपने देश में लोकतंत्र की स्थापना, सरकार की स्वतंत्र शक्तियां, आतंकवाद का विनाश, भूख व गरीबी उन्मूलन, समावेशी विकास और महंगाई नियंत्रण के लिए काम करना चाहिए, न कि 'मुखौटा' सरकार होने का परिचय देना चाहिए।

शाहबाज के समक्ष अनेक चुनौतियां

पाक चुनाव
प्रभात कुमार रॉय

> इस आम चुनाव में पाक फौज का संपूर्ण समर्थन नवाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग-नवाज को हासिल हुआ। इमरान खान तो काफी वक्त से पाक जेल में बंद रहे हैं, किंतु राजसत्ता के तमाम अवरोधों, मुश्किलों और जहमतों के बावजूद इमरान खान के हिमायती उम्मीदवार 93 की संख्या में चुनाव में जीतकर सबसे बड़े ब्लॉक के रूप में नेशनल असेंबली में पहुंचे गए हैं। इस तरह इमरान खान के समर्थक सदस्यों का सबसे बड़ा ब्लॉक वस्तुतः पाकिस्तान नेशनल असेंबली में उभरकर सामने आया है। पाकिस्तान फौज ने मुस्लिम लीग-नवाज को खुलकर समर्थन प्रदान किया गया, किन्तु मुस्लिम लीग-नवाज़ केवल 75 सीटों पर सिमट कर रह गई।

पाकिस्तान की सियासत एक दफा फिर से गहन गंभीर अस्थिरता की तरफ रवाना हो चुकी है। आठ फरवरी को संपन्न हुए आम चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत हासिल नहीं हो सका। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की कयादत वाली तहरीक ए इंसाफ पार्टी और उसके चुनाव निशान क्रिकेट बैट को चुनाव आयोग द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। पाकिस्तान की डीप स्टेट करार दिए जाने वाली वास्तविक हुक्मरान पाक फौज ने ही इमरान खान की हुकूमत को अप्रैल 2022 में बेदखल किया था।

इस आम चुनाव में पाक फौज का संपूर्ण समर्थन नवाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग-नवाज को हासिल हुआ। इमरान खान तो काफी वक्त से पाक जेल में बंद रहे हैं, किंतु राजसत्ता के तमाम अवरोधों, मुश्किलों और जहमतों के बावजूद इमरान खान के हिमायती उम्मीदवार 93 की संख्या में चुनाव में जीतकर सबसे बड़े ब्लॉक के रूप में नेशनल असेंबली में पहुंचे गए हैं। इस तरह इमरान खान के समर्थक सदस्यों का सबसे बड़ा ब्लॉक वस्तुतः पाकिस्तान नेशनल असेंबली में उभरकर सामने आया है। पाकिस्तान फौज ने मुस्लिम लीग-नवाज को खुलकर समर्थन प्रदान किया गया, किन्तु मुस्लिम लीग-नवाज़ केवल 75 सीटों पर सिमट कर रह गई।

इस चुनाव परिणाम को देखकर दुनिया के लोग विस्मित होकर रह गए। चुनाव में तमाम धांधलियों के बावजूद पाक फौज नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग को बहुमत नहीं दिला सकी और यह पहली दफा हुआ जबकि जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद पाक फौज को खुली चुनौती देने वाला कोई राजनीतिक लीडर पाकिस्तान में इतना लोकप्रिय होकर उभरा है। उल्लेखनीय है कि 2017 में नवाज शरीफ को बेदखल करके पाक फौज द्वारा इमरान खान को सत्तानशीन कराया गया था। पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद जो राजनीतिक चालें चली गई, वह भी कुछ कम चौंकाने वाला नहीं रही है।

शाहबाज शरीफ फिर से एक बार गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। शाहबाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग-नवाज ने बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपुल्स पार्टी के साथ बाकायदा हाथ मिला लिया है। सन 2022 में इमरान खान को सत्ता से बेदखल कर दिए जाने के बाद गठबंधन सरकार बनाई गई, तब भी शाहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। मरियम नवाज जो नवाज शरीफ की साहबजादी है, उनको पंजाब के मुख्यमंत्री का ओहदा हासिल हुआ है। उम्मीद है की पीपुल्स पार्टी के नेता आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान का अगला राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। वह इमरान खान की पार्टी के आरिफ अल्वी का स्थान ग्रहण करेंगे। इमरान खान ने कहा है कि उनकी पार्टी हुकूमत तशकील करने की कोशिश करेगी, यदि कामयाब नहीं हुई, तो फिर उनकी पार्टी विपक्ष में ही बैठेगी और हुकूमत को निरंतर चुनौती प्रदान करेंगे। इमरान खान ने अयूब खान को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान फौज अपनी तमाम बेजा कोशिशों और रिगिंग के बावजूद अपनी पसंदीदा पार्टी मुस्लिम लीग-नवाज़ को

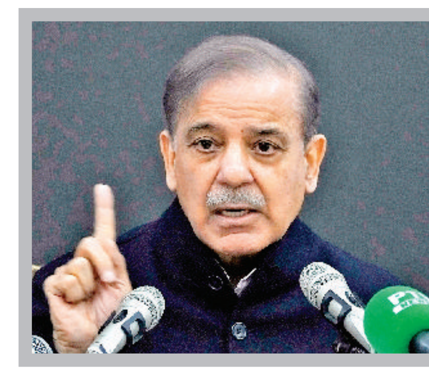

सत्तानशीन नहीं कर सकी और उसको आखिरकार गठबंधन सरकार का सहारा लेना पड़ा है।

पाकिस्तान की नई हुकूमत पुरानी वाली हुकूमत की प्रतिलिपि ही सिद्ध होगी। विगत सरकार में शाहबाज शरीफ बहुत ही अलोकप्रिय प्रधानमंत्री साबित हुए थे। शाहबाज के प्रधानमंत्री काल में पाकिस्तान की हुकूमत एकदम उस कगार पर पहुंच गई थी, जिसको आर्थिक दिवालियापन करार दिया जाता है। उनके कार्यकाल में इन्फ्लेशन रेट करीब तीस फीसदी पर कायम बना रहा। पाकिस्तान को दिवालिया हो जाने से आईएमएफ द्वारा तीन बिलियन डॉलर का कर्ज देकर ही बचाया जा सका। पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 8.2 बिलियन डॉलर से भी कम रहा है। पाकिस्तान की नई हुकूमत को आईएफएम से बेल आउट पैकेज देने की गुजारिश करनी पड़ सकती है, क्योंकि अगले ही वर्ष पाकिस्तान को 70 बिलियन डॉलर का कर्ज चुकाना है।

आर्थिक तबाही के साथ-साथ पाकिस्तान को सुरक्षा के मामलात को लेकर भी कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान प्रांतों में पाकिस्तान की फौज को विद्रोहियों का कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है। कभी पाकिस्तान के दोस्त रहे अफगान तालिबान खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान में विद्रोहियों की भरपूर सैन्य सहायता कर रहे हैं। एक दौर था जबकि नवाज शरीफ की भी पाकिस्तान फौज के साथ ठन गई थी और उनको भी सत्ता से इसी तरह बेदखल किया गया, जिस तरह से इमरान खान को किया गया था, इसलिए यह कहना बहुत मुश्किल होगा की नवाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग कितना कुछ पाक फौज की ख्वाहिशों के अनुसार काम कर सकेगी? इमरान खान को राजनीतिक तौर से एकदम दरकिनार करने की पाक फौज की मंशा एकदम नाकाम साबित हुई है और वह एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर इस आम चुनाव में उभरे हैं।

पाकिस्तानी राजसत्ता का चरित्र आज भी पूरी तरह से सामंती फितरत का है। सन 1956 से 1971 तक तथा 1977 से लेकर 1988 तक इसके साथ ही 1999 से लेकर 2008 तक पाकिस्तान सीधे फौजी के शासन के अधीन रहा। पाकिस्तानी फौज आज भी पूरी तरह से विदेश नीति पर अपना आधिपत्य कायम बनाए हुए है। पाक़ फौज द्वारा निर्धारित विदेश नीति से जो कोई भी नागरिक सरकार जरा सा भी इधर-उधर हटने का फैसला लेती है तो फिर फौज द्वारा उसको सत्ता से बेदखल कर दिया जाता है। इमरान खान के साथ भी वही व्यवहार हुआ जो कभी जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ फौज ने किया था। ऐसा ही ऐसा ही कुछ मामला नवाज शरीफ के साथ भी घटित हुआ था, जोकि तहेदिल से हिंदुस्तान के साथ दोस्ती कायम करना चाहते थे।

पाक फौज वस्तुत भारत के साथ मित्रता कायम करने के विरोध में रही है, क्योंकि पाकिस्तान में फौज की सर्वोच्च ताकत हिंदुस्तान से दुश्मनी कायम बने रहने के कारण ही बरकरार बनी रहती है। सौभाग्य से पाकिस्तान में पहली दफा इतिहास में लगातार दो दफा लोकतांत्रिक सरकार सत्तानशीन हुई। पाकिस्तान की सामंती सियासत के लिए यह अत्यंत शुभ संकेत है कि पहली दफा फौज को खुली चुनौती देकर इमरान खान की पार्टी इतनी बड़ी लोकप्रियता हासिल कर सकी है। विश्व के वर्तमान परिदृश्य में पाक़ फौज सीधे सत्तासीन होने से परहेज कर रही है, ताकि पश्चिमी देशों में पाकिस्तान को जेहादी आतंकवाद को प्रश्रय और परिपोषण प्रदान करने वाले मुल्क की श्रेणी से निकाला जा सके। हालांकि पाक़ फौज अप्रत्यक्ष तौर से सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखती। ग्रे लिस्ट से किसी तरह से बाहर आ चुका पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में कदापि जाना नहीं चाहेगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस
योगेश कुमार गोयल

श्रमिकों के लिए सुरक्षा संस्कृति विकसित करने की जरूरत

भारत में प्रतिवर्ष 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एनएससी) द्वारा 'राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस' मनाया जाता है। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित रहने के उपायों के बारे में बताया जाता है और औद्योगिक दुर्घटनाओं से बचने के तरीकों तथा उससे होने वाले गंभीर नुकसान के बारे में जागरूक करने का प्रयास जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाने का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किए जाने वाले सुरक्षा उपायों के बारे में जनता को जागरूक करना ही है। यह दिवस मनाए जाने की महत्ता इसीलिए है क्योंकि सुरक्षा उपायों को लेकर जागरूकता के अभाव में प्रतिवर्ष सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2017 से 2020 के बीच भारत के पंजीकृत कारखानों में प्रतिदिन तीन लोगों की जान दुर्घटना के कारण गई, साथ ही रोजाना 11 लोग घायल भी हुए। 2018 से साल 2020 के बीच 3331 मौतें दर्ज की गई, जिनका मुख्य कारण जरूरत से ज्यादा काम, प्रशिक्षण की कमी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं होना ही था। हालांकि विशेषज्ञों का स्पष्ट कहना है कि यह संख्या काफी कम है क्योंकि एक ओर जहां श्रमिक बड़े पैमाने पर अनौपचारिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर औपचारिक क्षेत्रों में होने वाली सभी घटनाओं की सूचना दर्ज नहीं की जाती। एनएचआरसी द्वारा एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए केन्द्र और राज्यों को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि देश की पंजीकृत फैक्ट्रियों में दुर्घटनाओं के कारण 2017 से 2022 के बीच हर दिन औसतन तीन लोगों की मौत हुई। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और सुरक्षा सप्ताह जैसे आयोजनों के जरिये कारखानों के मालिकों और कर्मचारियों को अधिक से अधिक जागरूक करके इन दुर्घटनाओं को कम करने में मदद मिल सकती है। यह दिवस मनाने के लिए हर साल एक विशेष कैंपेन या थीम जारी की जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2024 का विषय है 'ईएसजी उत्कृष्टता के लिए सुरक्षा नेतृत्व'। यहां ईएसजी से तात्पर्य पर्यावरण, सामाजिक और शासन (एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नमेंट) से है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2023 का विषय था 'हमारा लक्ष्य-शून्य नुकसान' जबकि 2022 में यह दिवस 'सुरक्षा संस्कृति के विकास के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करें' विषय के साथ मनाया गया था। प्रतिवर्ष 4 मार्च को ही राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाने का भी विशेष कारण है। दरअसल 'राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद' (एनएससी) की स्थापना 4 मार्च 1966 को श्रम मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थायी सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण आंदोलन विकसित करने के लिए की गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लागू किए गए सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता फैलाना है। स्थापना के बाद यह विचार उभरा कि इसके स्थापना दिवस को ही भारत के 'राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस' के रूप मनाया जाना चाहिए और आखिरकार 4 मार्च 1972 को पहली बार यह दिवस मनाने की शुरूआत हुई। इस एकदिवसीय प्रयास को भी जल्द ही एक सप्ताह के उत्सव में बदल दिया गया, जिसे 'राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह' नाम दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण (एसएचई) पर एक स्वैच्छिक आंदोलन को उत्पन्न करने और विकसित करने के लिए स्थापित किया गया एक गैर-लाभकारी, स्व-वित्तपोषण और स्वायत्त शीर्ष निकाय है, जो देशभर में विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और सेमिनारों का आयोजन कर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण आंदोलन को बढ़ावा देता है। कुल मिलाकर राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस देश में सभी श्रमिकों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण बनाने का प्रयास करते हुए सरकार, उद्योगों और श्रमिकों को एक साथ लाकर सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देने का एक सराहनीय प्रयास है। भारत में व्यावसायिक सुरक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह श्रमिकों को नुकसान से बचाती है, उत्पादकता को बढ़ावा देती है, नियमों का अनुपालन बढ़ाती है और कर्मचारियों के मनोबल में सुधार करती है। सुरक्षित कार्य वातावरण श्रमिकों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार लाता है, जिससे सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलता है। कार्यस्थल में दुर्घटनाओं से होने वाले नुकसान को कम करके यह देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी बड़ी भूमिका निभाता है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

एकनिष्ठ भक्ति

संकलित
दर्शन

अनेक महापुरुष हैं, अनेक देवी-देवता हैं, अनेक मार्ग हैं, किंतु एकनिष्ठता आवश्यक है। इसी कारण इष्ट देवता की अवधारणा है। घर की बहू सास, ससुर, जेठ, जेठानी सबका आदर सम्मान करती है, किसी की अवज्ञा या उपेक्षा नहीं करती। सबकी सेवा करती है, किंतु अपने पति को वह सबसे अधिक चाहती है। इसी तरह तुम भी अपने इष्ट देवता पर दृढ़ एकनिष्ठ भक्ति रखो, जबकि अन्य देवी-देवताओं का सम्मान करो, सबके प्रति श्रद्धा रखो। सभी देव एक ही परमेश्वर के रूप हैं। किंतु किसी एक के प्रति एकनिष्ठ रहो। चौसर के खेल में गोटी सब खानों का चक्कर लगाए बिना लक्ष्य पर नहीं पहुंचती। यदि दो गोटियां जोड़ी बांधकर इकट्ठी चलें तो उन्हें कोई काट नहीं सकता, नहीं तो अकेली गोटी लक्ष्य के पास पहुंचकर पकते-पकते भी कट जा सकती है। इसी प्रकार साधना के मार्ग पर भी यदि गुरु अथवा इष्ट के साथ युक्त होकर आगे बढ़ा जाए तो बाधा विघ्न का भय नहीं रहता, यात्रा निर्विघ्न रूप से सफल हो सकती है। एक बार किसी यात्री ने एक आदमी से कलकत्ता (अब कोलकाता) जाने का रास्ता पूछा। उस आदमी ने कहा, इस रास्ते से चले जाओ। थोड़ी दूर चलकर उसने और एक जन से रास्ता पूछा। उसने दूसरा रास्ता बताया। इस तरह वह थोड़ा सा आगे बढ़कर किसी से रास्ता पूछता तो पहले वाले का रास्ता छोड़ उस पर चल देता। ऐसा करते हुए वह रास्तों पर ही भटकता रहा, कलकत्ता नहीं पहुंच पाया।

रावण की वजह से बना बैद्यनाथ मंदिर

संकलित
प्रेरणा

त्रेता युग की घटना है। रावण शिव जी का परम भक्त था। रावण ने हिमालय क्षेत्र में शिवलिंग बनाकर कठोर तप किया था। इस तप से शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए। भगवान ने रावण से वरदान मांगने के लिए कहा। रावण ने शिव जी से कहा कि मैं आपका ये शिवलिंग लंका में स्थापित करना चाहता हूं। शिव जी ने रावण की इच्छा पूरी होने का वरदान दिया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि रास्ते में तुम ये शिवलिंग जहां रख दोगे, शिवलिंग वहीं स्थापित हो जाएगा। इसके बाद तुम ये शिवलिंग आगे नहीं ले जा पाओगे। रावण ने शिव जी का बात मान ली और शिवलिंग उठाकर लंका की ओर चल दिया। रास्ते में रावण ने गलती से एक जगह शिवलिंग रख दिया। थोड़ी देर बाद वह शिवलिंग फिर से उठाने लगा, लेकिन शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया था। बहुत कोशिश करने के बाद भी रावन शिवलिंग को उठा नहीं सका। अंत में हिम्मत हारकर रावण वहां से चला गया। रावण के जाने के बाद सभी देवी-देवता, ऋषि-मुनि और अन्य लोग इस शिवलिंग के पास पहुंचे और शिव पूजा की। सभी की पूजा से भगवान प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। सभी भक्तों ने शिव जी से प्रार्थना की कि अब से वे यहीं निवास करें, ताकि भक्त आसानी से दर्शन-पूजन कर सके और उनका कल्याण हो सके। भक्तों की बात सुनकर शिव जी इसी शिवलिंग में ज्योति स्वरूप में विराजित हो गए। बाद ये ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

अंतर्मन

आज की पाती

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एआई टैक्नोलॉजी अपनाओ

देश में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक की खबरें सुर्खियों में आती हैं। जिस देश में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हो चुकी हों, चंद पैसों की खातिर जहां लोग अपना ईमान बेच देते हों, वहां पेपर लीक के मामले शायद ही रुकें। बेशक सरकारें इसके लिए सख्त कानून ही क्यों न बना दें, हमारे देश में कानूनों का पालन कितना होता है, अगर होता तो आज न तो पेपर लीक के मामले बढ़ते, न ही भ्रष्टाचार। पेपर लीक के मामले शायद कुछ ऐसे भी होंगे जो सुर्खियों में न आए हों, अंदरखाते इसके लिए क्या घिनौना खेल किया जाता है, इसकी भनक किसी को नहीं लगती है। इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए, जिसमें पेपर इस ढंग से तैयार किए जाएं जो शत-प्रतिशत कंप्यूटर प्रोग्राम से तैयार हों।

- **मुकेश खंडेलवाल**, बिलासपुर

ट्रेंड

'मोदी की गारंटी'

मोदी जी के नेतृत्व में बीते एक दशक में केंद्र सरकार पिछड़ों और वंचितों के कल्याण को प्राथमिकता देकर उन्हें सशक्त बना रही है और अंत्योदय की कल्पना को साकार कर रही है। शोषित, पीड़ित और वंचित के सम्मान को बढ़ाती... 'मोदी की गारंटी'

-अमित शाह, गृह मंत्री

बहरापन बड़ी समस्या

बहरापन एक बड़ी समस्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आकलन के अनुसार विश्व भर में लगभग 360 मिलियन लोग बहरेपन का शिकार हैं। बहरे पन की समस्या के संदर्भ में एकजुटता के साथ जागरूकता की आवश्यकता है।

-अवधेशानंद, आध्यात्मिक गुरु

श्रवण देखभाल का हिस्सा बनें

अनुमान लगाया गया है कि 400 मिलियन से अधिक लोगों को श्रवण हानि के लिए पुनर्वास सेवाओं की आवश्यकता है। इस विश्व श्रवण दिवस पर, कानों की रक्षा करना सीखें और लोगों की श्रवण देखभाल का हिस्सा बनकर उनकी मदद करें।

-डॉ टेड्रोस, डब्ल्यूएचओ चीफ

'गरीबों की सवारी'

'हवाई चप्पल' वालों को हवाई जहाज की यात्रा का सपना दिखा, मोदी 'गरीबों की सवारी' रेलवे को भी उनसे दूर करते जा रहे हैं। हर साल 10% बढ़ता किराया और ऐसी 'एलीट ट्रेन' की तस्वीर दिखा बहलाया जा रहा है जिस पर गरीब पांव तक नहीं रख सकता।

-राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद

करंट अफेयर

अमेरिका में भाजपा समर्थकों का प्रचार अभियान शुरू

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा करने पर अमेरिका में रह रहे उसके समर्थकों ने चुनाव में 400 सीट जीतने के लक्ष्यों की ओर योगदान देने और स्वयंसेवा करने का संकल्प लेते हुए अपना 2024 का प्रचार अभियान शुरू किया है। भाजपा ने शनिवार को 195 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की है जिनमें से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वाराणसी समेत 51 सीट उत्तर प्रदेश से हैं। 'ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी (ओएफबीजेपी), यूएसए' के अध्यक्ष अदापा प्रसाद ने वाशिंगटन डीसी के मैरीलैंड उपनगर में शनिवार को चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने के बाद कहा, 'भारतीय प्रवासी समुदाय भारत में भाजपा को समर्थन देने जा रहा है।' इस कार्यक्रम में ओएफबीजेपी के करीब 100 कोर सदस्य शामिल हुए। भारत में लोकसभा के 543 सदस्यों को चुनने के लिए अप्रैल और मई 2024 के बीच आम चुनाव प्रस्तावित हैं। अभी तक 3,000 से अधिक स्वयंसेवियों ने ओएफबीजेपी द्वारा समन्वित विभिन्न चुनाव संबंधी गतिविधियों के लिए हस्ताक्षर किए हैं।

ऑफ बीट

शंघाई पर समुद्र में डूबने का खतरा

चीन का सबसे विकसित और अमीर शहर शंघाई पिछले कम से कम 100 साल से भूमि अवतलन की समस्या से जूझ रहा है। यह चीन के उन शुरुआती शहरों में से एक हैं, जिनमें गंभीर स्तर पर भू-अवतलन हो रहा है। शंघाई में 1921 से 2007 के बीच 22.94 मिमी प्रति वर्ष की औसत दर से भूमि अवलतन हुआ। बहरहाल, भू-अवतलन की यह दर 2010 में स्थिर हो गई, लेकिन वैश्विक तापमाना में वृद्धि की वजह से समुद्र के बढ़ते जलस्तर ने दो करोड़ 40 लाख की आबादी वाले शहर के लिए नया खतरा पैदा कर दिया है। भू-अवतलन के अब अपेक्षाकृत स्थिर होने का अनुमान है, लेकिन समुद्र में जलस्तर बढ़ने की दर जलवायु परिवर्तन के कारण भविष्य में तेज होने की आशंका है। इसके प्रमुख कारण महासागरों के गर्म होने के कारण पानी की मात्रा बढ़ना और हिमनद एवं बर्फ का पिघलना है। ऐसा माना जा रहा है कि अंटार्कटिक बर्फ की चादर पिघलना समुद्र में जल स्तर बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। सापेक्ष समुद्र स्तर की औसत वृद्धि 2050 तक 45 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच रहने का अनुमान है। कम्प्यूटर से की गई गणना के अनुसार, शंघाई में समुद्र का जल स्तर 2030 में लगभग दोगुना तेजी से बढ़ सकता है, 2050 तक यह तीन से पांच गुना तेजी और इस सदी के अंत में 50 गुना अधिक तेजी से बढ़ने की आशंका है।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-42422221 पर या सीधे मेल से **aapkepatra.haribhoomi@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid